



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 2004/पौष 16, 1925

No. 16]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 2004/PAUSA 16, 1925

मंत्रिमण्डल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2004

का.आ. 17(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ इकहत्तरवां संशोधन) नियम, 2004 है।
- (2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,—

(क) नियम 3 में, उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) विभागों में विषयों का वितरण ऐसा होगा जैसा इन नियमों की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और इसके अन्तर्गत सभी सहबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन, जिनमें उनके विषयों से संबंधित पब्लिक सेक्टर उपक्रम हैं तथा इस नियम के उपनियम (2), उपनियम (3) और उपनियम (4) भी हैं।”;

(ख) प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“प्रथम अनुसूची

(नियम 2)

मंत्रालय, विभाग, सचिवालय तथा कार्यालय

1. कृषि मंत्रालय
 - (i) कृषि और सहकारिता विभाग
 - (ii) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
 - (iii) पशुपालन और डेरी विभाग
2. कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय
3. रसायन और उर्वरक मंत्रालय
 - (i) रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग
 - (ii) उर्वरक विभाग
4. नागर विमानन मंत्रालय
5. कोयला मंत्रालय
6. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
 - (i) वाणिज्य विभाग
 - (ii) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
7. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
 - (i) दूरसंचार विभाग
 - (ii) डाक विभाग
 - (iii) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

8. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
 - (i) उपभोक्ता मामले विभाग
 - (ii) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
9. रक्षा मंत्रालय
 - (i) रक्षा विभाग
 - (ii) रक्षा उत्पादन विभाग
 - (iii) रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग
10. विनिवेश मंत्रालय
11. पर्यावरण और वन मंत्रालय
12. विदेश मंत्रालय
13. वित्त मंत्रालय
 - (i) आर्थिक कार्य विभाग
 - (ii) व्यय विभाग
 - (iii) राजस्व विभाग
 - (iv) कंपनी कार्य विभाग
14. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
15. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
 - (i) स्वास्थ्य विभाग
 - (ii) परिवार कल्याण विभाग
 - (iii) आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग
16. भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
 - (i) भारी उद्योग विभाग
 - (ii) लोक उद्यम विभाग

17. गृह मंत्रालय

- (i) आंतरिक सुरक्षा विभाग,
- (ii) राज्य विभाग
- (iii) राजभाषा विभाग
- (iv) गृह विभाग
- (v) जम्मू-कश्मीर कार्य विभाग
- (vi) सीमा प्रबंधन विभाग

18. मानव संसाधन विकास मंत्रालय

- (i) प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग
- (ii) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग
- (iii) महिला और बाल विकास विभाग

19. सूचना और संचार मंत्रालय

20. श्रम मंत्रालय

21. विधि और न्याय मंत्रालय

- (i) विधि कार्य विभाग
- (ii) विधायी विभाग
- (iii) न्याय विभाग

22. खान मंत्रालय

23. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

24. संसदीय कार्य मंत्रालय

25. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

- (i) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
- (ii) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- (iii) पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग

26. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

27. योजना मंत्रालय
28. विद्युत मंत्रालय
29. रेल मंत्रालय
30. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
31. ग्रामीण विकास मंत्रालय
 - (i) ग्रामीण विकास विभाग
 - (ii) भूमि संसाधन विभाग
 - (iii) पेयजल पूर्ति विभाग
32. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
 - (i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
 - (ii) विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
 - (iii) बायोटेक्नालॉजी विभाग
33. पोत परिवहन मंत्रालय
34. लघु उद्योग मंत्रालय
35. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
36. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
37. इस्पात मंत्रालय
38. वस्त्र मंत्रालय
39. पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय
 - (i) पर्यटन विभाग
 - (ii) संस्कृति विभाग
40. जनजातीय कार्य मंत्रालय

41. शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय
 - (i) शहरी विकास विभाग
 - (ii) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग
42. जल संसाधन मंत्रालय
43. युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
44. परमाणु ऊर्जा विभाग
45. महासागर विकास विभाग
46. अंतरिक्ष विभाग
47. मंत्रिमंडल सचिवालय
48. राष्ट्रपति सचिवालय
49. प्रधानमंत्री कार्यालय
50. योजना आयोग
51. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग

द्वितीय अनुसूची

(नियम 3)

विभागों में विषयों का वितरण

कृषि मंत्रालय

क. कृषि और सहकारिता विभाग

भाग-1

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची I के अंतर्गत आते

हैं:

1. अंतर्राष्ट्रीय कृषि संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के साथ संपर्क कोआपरेटिव फार अमेरिकन रिलीफ एवरीव्हेयर (सी0ए0आर0ई0) के कृषि आदि से संबंधित माल का प्रबंध करना ।

2. कृषि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों तथा अन्य निकायों में भाग लेना और वहां पर किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन ।
3. टिड्डी नियंत्रण का अभिसमय ।
4. पादप करंतीन ।
5. वे उद्योग जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, वहां तक जहां तक वे निम्नलिखित से संबद्ध हैं:
 - (क) कृषि उद्योग, जिसके अंतर्गत मशीनरी, उर्वरक और बीज हैं, किन्तु कपास, औटाई और दबाई नहीं हैं, इस परिसीमा के साथ कि उद्योगों, जिनके अंतर्गत मशीनरी और उर्वरक हैं, के विकास के बारे में कृषि और सहकारिता विभाग के कृत्य मांगों के आकलन और लक्ष्यों के नियतन से अधिक न हों ।
 - (ख) शल्क लाख उद्योग ।
6. कृषि गणना ।
7. प्राकृतिक विपत्तियों के कारण फसलों को हुए नुकसान संबंधी मामले ।
8. सूखे के कारण आवश्यक राहत उपायों का समन्वय ।
9. सूखे के कारण मानव जीवन को होने वाली हानि से संबंधित मामले ।
10. भारतीय जन प्राकृतिक आपदा न्यास ।
11. तिलहन व दलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन ।

भाग- II

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची III के अंतर्गत हैं (केवल विधान की बाबत):

12. खाद्यपदार्थों से भिन्न कृषि उत्पादों का अपमिश्रण ।
13. आर्थिक योजना (कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी) ।

14. वृत्तियाँ (जिनके अंतर्गत पशु चिकित्सा व्यवसाय नहीं है) ।
15. वनस्पति को हानि पहुँचाने वाले संक्रामक या सांसर्गिक रोगों या नाशक जीवों के, जिनके अंतर्गत टिट्डीयाँ भी हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने का निवारण ।
16. खाद्यान्न, शर्करा, वनस्पति, तिलहन, वनस्पति तेलों, खली और वसा, पटसन, रूई और चाय के सिवाय, कृषि वस्तुओं की कीमत का नियंत्रण ।
17. खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983 (1983 का 35) का प्रशासन ।

भाग- III

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपर्युक्त भाग I और भाग II में वर्णित विषय जहाँ तक वे इन राज्य की बाबत विद्यमान हैं, और इनके अतिरिक्त, निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम की सूची II के अंतर्गत हैं:

18. कृषि (कृषि शिक्षा और गवेषणा से भिन्न) नाशक जीवों से रक्षा और पादप रोगों का निवारण ।
 19. कृषि क्षेत्र में सहयोग, कृषि ऋण और ऋणग्रस्तता ।
 20. कृषि उत्पाद के विपणन संबंधी सामान्य नीति जिसमें कीमत निर्धारण, निर्यात आदि सम्मिलित हैं ।
 21. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मंडियों की स्थापना ।
 22. कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) ।
 23. बीमा (फसल) ।
 24. सहकारिता के क्षेत्र में साधारण नीति और सभी सेक्टरों में सहकारिता, क्रियाकलापों का समन्वय ।
- टिप्पणी: संबंधित मंत्रालय अपने-अपने क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के लिए उत्तरदायी हैं ।
25. राष्ट्रीय सहकारी संगठनों से संबंधित मामले ।
 26. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ।

27. ऐसी सहकारी सोसाइटियों, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है, का निगमन, विनियमन और परिसमापन ।
28. सहकारी विभागों और सहकारी संस्थाओं के कार्मिकों का प्रशिक्षण (जिसमें सदस्य, पदाधिकारियों और गैर-सरकारी व्यक्तियों की शिक्षा सम्मिलित है) ।

भाग- IV

साधारण और पारिणामिक

29. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग को आबंटित कार्यों की मदों के सिवाय, कृषि और सहबद्ध विषयों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता से संबंधित सभी मामले ।
30. कृषि और उद्यान कृषि ।
31. बायो एस्थेटिक योजना ।
32. कृषि उत्पादन-अधिक अन्न उपजाओ ।
33. भूमि पुनरुद्धार ।
34. कृषि और बागवानी के फसलोपरांत प्रबंधन हेतु अवसंरचना ।
35. राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड ।
36. कपास, पटसन और गन्ने का विकास ।
37. विकास कार्यक्रमों से संबद्ध मृदा सर्वेक्षण ।
38. राज्य भू-संरक्षण स्कीमों को वित्तीय सहायता ।
39. अखिल भारतीय, अंचल अथवा क्षेत्रीय स्तर पर उर्वरक और खाद मांगों का आकलन; अंचल या क्षेत्रवार लक्ष्यों का पोषणवार नियतन ।
40. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 का प्रशासन ।
41. राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशिष्टों की मानीटरी ।
42. कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) का प्रशासन ।

43. कृषि उपकरण और मशीनरी ।
44. देश में विस्तार शिक्षा और प्रशिक्षण का संगठन और विकास ।
45. फसल अभियान, फसल प्रतियोगिताएं और कृषक संगठन ।
46. तिलहनो का उत्पादन ।
47. भूमिहीन कृषि श्रमिकों को बसाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त स्कीमें ।
48. यांत्रिक फार्म ।
49. जैविक खेती (विकास एवं संवर्धन सहित सभी मामले, परन्तु इसमें निर्यात के प्रयोजन हेतु जैविक खाद्य/उत्पादों के प्रमाणीकरण से संबंधित मामले सम्मिलित नहीं हैं) ।
50. ऑन-फार्म जल प्रबंधन ।
51. ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण, जिसमें ग्रामीण गोदाम भी हैं ।
52. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित सभी सहबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन हैं किन्तु, इसमें कृषि विमानन निदेशालय सम्मिलित नहीं है ।
53. उर्वरकों का क्वालिटी नियंत्रण ।

ख. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग

भाग- I

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची I के अंतर्गत हैं:

1. कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता, जिसके अंतर्गत विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा संस्थाओं और संगठनों के साथ संबंध भी हैं ।
2. मूल अनुप्रयुक्त और संक्रियात्मक अनुसंधान तथा उच्चतर शिक्षा जिसमें ऐसे अनुसंधान का समन्वय तथा कृषि, कृषि वानिकी, पशुपालन, डेरी, मछली पालन, कृषि अभियांत्रिकी और उद्यान, जिसके अंतर्गत कृषि सांख्यिकी, अर्थशास्त्र एवं विपणन भी हैं, में उच्चतर शिक्षा सम्मिलित है ।

3. उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान संस्थाओं और वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्थाओं में समन्वय और मानकों का अवधारण जहां तक उनका संबंध खाद्य तथा कृषि से है जिसमें पशुपालन, डेरी तथा मछली पालन भी सम्मिलित है । कृषि अनुसंधान/विस्तार तथा शिक्षा में मानव संसाधन का विकास ।
4. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और चाय, काफी और रबड़ संबंधी कार्यक्रमों से भिन्न वस्तु अनुसंधान कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए उपकर ।
5. गन्ना अनुसंधान ।

भाग- II

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपर्युक्त भाग I में वर्णित विषय जहां तक वे इन राज्य क्षेत्रों की बाबत विद्यमान हैं, और इनके अतिरिक्त, निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची II के अंतर्गत हैं:

6. कृषि, शिक्षा और गवेषणा ।

भाग- III

साधारण और पारिणामिक

7. पादप, पशु और मछली प्रवर्तन तथा खोज ।
8. अनुसंधान प्रशिक्षण; सह-संबद्ध, वर्गीकरण, मृदा मानचित्रण और निर्वचन से संबंधित अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण ।
9. कृषि अनुसंधान और शैक्षिक स्कीमों तथा कार्यक्रमों की बाबत राज्य सरकारों और कृषि विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता ।
10. राष्ट्रीय निरूपण ।
11. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा इसके अंगीभूत संस्थानों, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों, परियोजना निदेशालयों, ब्यूरो तथा अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाएं ।

ग. पशुपालन और डेरी विभाग

भाग-I

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची I के अंतर्गत हैं:

1. वे उद्योग जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, वहां तक जहां तक उनका संबंध पशुधन, मछली और पक्षी-दाना

और डेरी, मुर्गीपालन, और मत्स्य उत्पादों के विकास से है, इस परिसीमा के साथ कि उद्योगों के विकास के संबंध में पशुपालन और डेरी विभाग के कृत्य, मांगों के आकलन और लक्ष्यों के नियतन से अधिक न हों ।

2. पशुधन, मुर्गीपालन और मछली पालन के विकास से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संपर्क और सहयोग ।
3. पशुधन गणना ।
4. पशुधन सांख्यिकी ।
5. प्राकृतिक विपत्तियों के कारण पशुधन को हुए नुकसान संबंधी मामले ।
6. पशुधन आयात का विनियमन, पशु करंतीन और प्रमाणीकरण ।
7. मछली पकड़ना और मछली पालन (अंतरदेशीय, सामुद्रिक तथा राज्यक्षेत्रीय सागर खंड के परे) ।
8. भारतीय मछली उद्योग सर्वेक्षण, मुंबई ।

भाग- II

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III के अंतर्गत हैं, केवल विधान की बाबत:

9. पशु चिकित्सा व्यवसाय वृत्ति ।
10. पशुओं, मछलियों व पक्षियों को हानि पहुंचाने वाले संक्रामक या सांसर्गिक रोगों या नाशक जीवों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने का निवारण ।
11. स्वदेशी प्रजातियों में परिवर्तन लाना; पशुधन की स्वदेशी प्रजातियों के लिए केन्द्रीय यूथ पंजी बनाना एवं उनका रखरखाव ।
12. राज्य अभिकरणों/सहकारी संघों के माध्यम से विभिन्न राज्य उपक्रमों, डेरी विकास स्कीमों को वित्तीय सहायता का स्वरूप ।

भाग- III

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपर्युक्त भाग I और भाग II में वर्णित विषय जहां तक वे इन राज्य क्षेत्रों की बाबत विद्यमान हैं, और इनके अतिरिक्त निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के अंतर्गत आते हैं:

13. पशु नस्ल का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति तथा पशु, मछली और पक्षी रोगों का निवारण, पशु-चिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय ।
14. प्रतिपाल्य अधिकरण ।
15. पशुधन, मछली और पक्षियों का बीमा ।

भाग IV

16. पशु उपयोग और वध से संबंधित मामले ।
17. चारा विकास ।

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

1. शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में ग्रामीण और कुटीर उद्योग, और बहुत छोटे/सूक्ष्म उद्यमों के विकास का समन्वय ।
2. सभी ग्रामीण उद्योगों से संबंधित मामलों का समन्वय ।
3. कयर उद्योग ।
4. कयर बोर्ड ।
5. प्रधानमंत्री रोजगार योजना (प्र0मं0रो0यो0) ।
6. खादी और ग्रामोद्योग आयोग ।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

क. रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग

1. औषधियां तथा फार्मास्यूटिकल्स, उनके सिवाय, जो अन्य विभागों को विनिर्दिष्टतया आबंटित की गई हैं ।
2. कीटनाशी (कीटनाशी अधिनियम, 1968)(1968 का 46) के प्रशासन के सिवाय)

3. शीरा ।

4. ऐल्कोहल-औद्योगिक और पेय, जिनका आधार शीरे पर हो ।
रंजक-द्रव्य और रंजक मध्यक ।

6. सभी कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, जो किसी अन्य मंत्रालय या विभाग को विनिर्दिष्टतया आबंटित नहीं किए गए हैं ।

7. विभाग द्वारा व्यवहृत सभी उद्योगों की योजना, विकास तथा नियंत्रण, और सहायता ।

8. भोपाल गैस रिसाव विभीषिका - तत्संबंधी विशेष विधियाँ ।

9. पेट्रो-रसायन ।

10. सेलूलोज रहित संश्लिष्ट फाइबर (नायलान, पोलिएस्टर, एकिलिक, आदि) के उत्पादन से संबंधित उद्योग ।

11. संश्लिष्ट रबड़ ।

12. प्लास्टिक, जिसमें प्लास्टिकों की विरचना और प्लास्टिक की ढली हुई वस्तुएं शामिल हैं ।

ख. उर्वरक विभाग

1. उर्वरक उत्पादन के लिए परियोजना तैयार करना, जिसके अंतर्गत किसी अभिहित सरणीकरण अभिकरण के माध्यम से उर्वरकों का आयात भी है ।

2. कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार, यूरिया के संचलन और वितरण के लिए आबंटन और पूर्ति संपर्क ।

3. नियंत्रित और अनियंत्रित उर्वरकों के लिए रियायत योजनाओं का प्रशासन और सब्सिडी का प्रबंध, जिसके अंतर्गत यूरिया के प्रतिधारण मूल्य, अनियंत्रित उर्वरकों की रियायत की मात्रा, ऐसे उर्वरकों की लागत और फास्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों का मूल्य निर्धारण भी है ।

4. उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1960 का प्रशासन ।

5. सहकारिता क्षेत्र में उर्वरक उत्पादन एकाई, अर्थात्, इंडियन फार्मर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफ्को) कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको) के लिए प्रशासनिक उत्तरदायित्व ।

6. इंडियन पोटैश लिमिटेड (आईपीएल) का प्रशासनिक उत्तरदायित्व ।

नागर विमानन मंत्रालय

1. वायुयान और वायु दिक्चालन; हवाई-अड्डों की व्यवस्था; हवाई यातायात और हवाई-अड्डों का, वायु दिक्चालन से संबंधित स्वच्छता नियंत्रण के सिवाय, विनियमन और संगठन ।
2. दिक्चालन और वायु दिक्चालन से संबंधित अन्य सहायक सामग्री की व्यवस्था ।
3. वायुमार्ग से यात्रियों और माल का वहन ।
4. सिविल उपयोग के लिए वायुयान और वायुयान घटकों का उत्पादन ।
5. सिविल वायुयान के उपयोग के लिए तकनीकी अनुज्ञप्तियां/प्रमाणपत्र/अनुमोदन जारी करना ।
6. निजी विमान परिवहन (स्थोरा सहित) उद्योग ।
7. राज्य सरकारों, निजी/संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों द्वारा ग्रीन फील्ड विमान-पत्तन से संबंधित मामले ।
8. इंटरनेशनल सिविल एवियेशन आर्गेनाइजेशन (आईसीओ) ।
9. इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) ।
10. कामनवेल्थ एयर ट्रांसपोर्ट काउंसिल (सीएटीसी) ।
11. कामनवेल्थ एडवाइजरी एरोनॉटिकल रिसर्च काउंसिल (सीएएआरसी) ।
12. एयर इंडिया लिमिटेड और उसकी समनुषंगी ।
13. इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड और उसकी समनुषंगी ।
14. भारतीय होटल निगम और उसकी समनुषंगी ।
15. रेल सुरक्षा आयोग ।
16. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) ।
17. पवन हंस हेलिकाप्टर्स लिमिटेड ।

18. नागर विमानन महानिदेशालय ।
19. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ।
20. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ।
21. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी से संबंधित संधियों और करारों का कार्यान्वयन ।
22. वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) का प्रशासन ।
23. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) का प्रशासन ।

कोयला मंत्रालय

1. भारत में कोकिंग और नान-कोकिंग कोयले तथा लिग्नाइट के भंडारों की खोज और विकास ।
2. कोयले के उत्पादन, पूर्ति, वितरण और कीमतों से संबंधित सभी मामले ।
3. उनसे भिन्न, जिनके लिए इस्पात विभाग उत्तरदायी है, कोयला धोवनशालाओं का विकास और प्रचालन ।
4. कोयले का निम्न ताप पर कार्बनीकरण और कोयले से संश्लिष्ट तेल का उत्पादन ।
5. कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) का प्रशासन ।
6. कोयला खान भविष्य निधि संगठन ।
7. कोयला खान कल्याण संगठन ।
8. कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन ।
9. कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) का प्रशासन ।

10. खानों से उत्पादित और प्रेषित कोक और कोयले पर उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण तथा बचाव निधि के प्रशासन के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 32) के अन्तर्गत नियम ।
11. कोयला-धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) का प्रशासन ।
12. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) तथा अन्य संघ विधियों का प्रशासन जहां तक कि उक्त अधिनियम और विधियों का संबंध कोयला और लिग्नाइट और भरणार्थ बालू से है, इस प्रकार के प्रशासन से आनुषंगिक कारबार, जिसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न भी है ।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

क. वाणिज्य विभाग

I अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्यिक नीति जिसमें टैरिफ और टैरिफ-इतर अवरोध भी है ।
2. व्यापार नीति से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण (जैसे कि अंकटाड, ई.एस.सी.ए.पी., ई.सी.ए., ई.सी.एल.ए., ई.ई.सी., ई.एफ.टी.ए., गैट/डब्ल्यू.टी.ओ., आई.टी.सी. और सी.एफ.सी.)।
3. गेहूं, चीनी, जूट और कपास से संबंधित करारों से भिन्न, अंतर्राष्ट्रीय वस्तु करार ।
4. टैरिफ आयोग से संबंधित अवशिष्ट कार्य सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क टैरिफ ब्यूरो ।

II विदेश व्यापार (माल और सेवाएँ)

5. विदेश व्यापार से संबंधित सभी विषय ।
6. आयात और निर्यात व्यापार नीति और नियंत्रण, जिसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित नहीं है:

(क) कथा-चित्रों का आयात;

(ख) भारतीय फिल्मों का निर्यात, दीर्घ और लघु कथाचित्र दोनों; और

- (ग) फिल्म उद्योग द्वारा अपेक्षित सिनेफिल्म (अनुभासित) और अन्य वस्तुओं का आयात और वितरण ।

III राज्य व्यापार

7. राज्य व्यापार नीतियां तथा इस प्रयोजन के लिए स्थापित संगठनों का कार्य निष्पादन जिसमें निम्नलिखित भी है :
- (क) हस्तशिल्प और हैंडलूम निर्यात निगम तथा केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम के सिवाय, भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड तथा उसकी समनुषंगी; भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड और स्पाइसेज ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड;
- (ख) प्रोजेक्ट्स एंड इन्विपमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीईसी);
- (ग) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन और उसकी समनुषंगी;
- (घ) खनिज और धातु व्यापार निगम तथा उसकी समनुषंगी;
8. बागान उपज, चाय, काफी, रबड़, मसाले, तंबाकू और काजू का उत्पादन, वितरण (देश में खपत और निर्यात के लिए) और विकास ।
9. देश में खपत और निर्यात के लिए इंस्टैट चाय और इंस्टैट काफी का संसाधन और वितरण।
10. (क) चाय बोर्ड ।
 (ख) काफी बोर्ड ।
 (ग) रबड़ बोर्ड ।
 (घ) इलायची बोर्ड ।
 (ङ) तम्बाकू बोर्ड ।

IV शत्रु के साथ व्यापार : शत्रु संपत्ति

11. शत्रु के साथ व्यापार; शत्रु फर्मों और शत्रु संपत्ति हानिपूर्ति (जर्मन औद्योगिक उपकरण से भिन्न); शत्रु व्यापार नियंत्रक; शत्रु फर्मों के नियंत्रक; भारत के लिए शत्रु संपत्ति अभिरक्षक ।

V भारतीय व्यापार सेवाओं का प्रबंध

12. भारतीय व्यापार सेवा का संवर्ग प्रबंध और इस सेवा के लिए प्रशिक्षण, वृत्ति योजना और जनशक्ति योजना से संबंधित सभी विषय ।
13. भारतीय पूर्ति सेवा का संवर्ग प्रबंध और इस सेवा के लिए प्रशिक्षण, वृत्ति योजना और जन शक्ति योजना से संबंधित सभी विषय ।
14. भारतीय निरीक्षण सेवा का संवर्ग प्रबंध और इस सेवा के लिए प्रशिक्षण, वृत्ति योजना और जन शक्ति योजना से संबंधित सभी विषय ।

VI. विशेष आर्थिक परिक्षेत्र

15. विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों में विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों और यूनियों के विकास, प्रचालन और अनुरक्षण से संबंधित सभी मामले, जिनके अंतर्गत निर्यात और आयात नीति, राजवित्तीय व्यवस्था, विनिधान नीति, अन्य आर्थिक नीति और विनियामक ढांचा भी है ।

टिप्पण: वित्तीय प्रभावों वाली सभी राजवित्तीय रियायतों और नीतिगत विषयों पर विनिश्चय आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय) की सहमति से या जिसके न होने पर मंत्रिमंडल के अनुमोदन से किया जाता है ।

VII. निर्यात उत्पाद और उद्योग एवं व्यापार को सुकर बनाना

16. निर्यात प्रसंस्करण परिक्षेत्रों/कृषि निर्यात परिक्षेत्रों तथा शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख ईकाइयों की स्थापना ।
17. रत्न एवं आभूषण ।
18. निर्यात संवर्धन बोर्ड, व्यापार बोर्ड और अंतराष्ट्रीय व्यापार सलाहकार समिति से संबंधित मामले ।
19. संबंधित निर्यात संवर्धन परिषदों/निर्यात संवर्धन संगठनों से संबंधित मामले ।
20. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान और भारतीय पैकेजिंग संस्थान ।

21. भारतीय हीरा संस्थान और फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान ।
 22. निर्यात अवसंरचना के लिए समन्वय ।
 23. सभी वस्तुओं, उत्पादों, विनिर्माताओं और अर्ध-विनिर्माताओं से संबंधित निर्यात उत्पाद का विकास और विस्तार जिसमें निम्नलिखित भी हैं :
 - (क) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) के अंतर्गत आने वाली कृषि उपज;
 - (ख) समुद्री उत्पाद;
 - (ग) औद्योगिक उत्पाद (इंजीनियरी माल, रसायन, प्लास्टिक, चमड़ा उत्पाद, आदि);
 - (घ) ईंधन, खनिज और खनिज उत्पाद;
 - (ङ.) विनिर्दिष्ट निर्यातोन्मुख उत्पाद (जिनमें बागान उपज, आदि तो आते हैं किन्तु पटसन उत्पाद और हस्तशिल्प नहीं आते हैं जो प्रत्यक्षतः इस विभाग के भारसाधन में हैं) ।
 24. वे सभी संगठन और संस्थाएं, जो निर्यात उद्यम से संबंधित सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित हैं, जिनमें निम्नलिखित भी हैं :
 - (क) निर्यात साख और निर्यात बीमा जिसमें निर्यात साख और प्रत्याभूति निगम लि० भी है।
 - (ख) निर्यात निरीक्षण परिषद; क्वालिटी नियंत्रण सहित मानक;
 - (ग) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय;
 - (घ) मुक्त व्यापार परिक्षेत्र ।
 25. निर्यात उद्यमों को प्रोत्साहन और सहायता देने के लिए परियोजनाएं और कार्यक्रम ।
- VIII. सहबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय ।**
26. विदेश व्यापार महानिदेशालय ।
 27. पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली का प्रशासन ।

28. डाइरेक्ट्रेट जनरल ऑफ एन्टी-डम्पिंग एंड अलाइड ड्यूटीज और संबंधित मामले ।
29. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय ।

IX. कानूनी निकाय

30. सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ।
31. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ।

X- प्रकीर्ण

32. केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, जिनके अंतर्गत उनके सहबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय और संघ राज्य क्षेत्र भी हैं, के लिए सामग्रियों का क्रय और भण्डार निरीक्षण, उन मदों से भिन्न, जिनका क्रय और सामग्रियों का निरीक्षण किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्य प्राधिकरणों को प्रत्यायोजित किया गया है ।

ख. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

I. औद्योगिक नीति

1. साधारण औद्योगिक नीति ।
2. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) का प्रशासन ।
3. औद्योगिक प्रबंध ।
4. उद्योग में उत्पादकता ।

II. उद्योग और औद्योगिक तथा तकनीकी विकास

5. सभी उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण तथा सहायता जिनमें किसी अन्य विभाग के अंतर्गत आने वाले उद्योग नहीं आते ।

6. नागर विमानन मंत्रालय तथा रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग के परामर्श से बनाए जाने वाले सिविल वायुयान के उत्पादन के लिए उद्योगों की स्थापना के लिए अनुज्ञप्तियां जारी करना ।
7. केबिल ।
8. हल्के इंजीनियरी उद्योग (उदाहरणार्थ सिलाई मशीनें, टाइपराइटर, तोलने की मशीनें, बाइसिकल आदि) ।
9. हल्के उद्योग (उदाहरणार्थ प्लाईवुड, लेखनसामग्री, दियासलाई, सिगरेट, आदि) ।
10. हल्के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी उद्योग ।
11. अप्रयुक्त फिल्में ।
12. हार्ड बोर्ड ।
13. कागज और अखबारी कागज ।
14. टायर और द्यूब ।
15. नमक ।
16. सीमेंट ।
17. सिरेमिक्स, टाइल्स और कांच ।
18. चमड़ा और चमड़ा माल उद्योग ।
19. साबुन और अपमार्जक ।
20. तकनीकी विकास, जिसके अंतर्गत टैरिफ आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन भी है ।
21. औद्योगिक और सेवा परियोजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी और अनिवासी भारतीय विनिधान ।
22. विदेशी विनिधान कार्यान्वयन प्राधिकरण (वि०वि०का०प्रा०)।

III औद्योगिक सहकारिता

23. भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) और तद्धीन बनाए गए विनियमों का प्रशासन; केन्द्रीय बायलर बोर्ड ।
24. विस्फोटक - विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) और तद्धीन बनाए गए नियमों का प्रशासन, किन्तु विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6) का नहीं ।
25. ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 (1952 का 20) ।

IV. उद्योग तथा औद्योगिक तथा तकनीकी विकास

26. राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद ।
27. इंडियन रबड़ मैनुफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई ।

V. बौद्धिक संपदा अधिकारों (औद्योगिक संपदा) का संरक्षण

28. अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों और कच्ची सामग्री का मानकीकरण ।
29. डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 16) ।
30. व्यापार और पण्य चिह्न अधिनियम, 1958 (1958 का 43) ।
31. पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) ।

VI. सामग्री योजना

32. उत्पादों के विशिष्ट समूहों और उपलब्ध क्षमताओं के संबंध में सेक्टरों, उद्योगों और बड़े एककों द्वारा की गई कच्चे माल की मांगों का समन्वित निर्धारण ।
33. माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (1999 का 48) ।
34. आयात. प्रतिस्थापन की साध्यता का सम्यक ध्यान रखते हुए देशी कच्चे माल की उपलब्धता का निर्धारण ।

35. तालिकाओं के लिए सम्यक छूट का ध्यान रखते हुए कच्चे माल के आयात की आवश्यकताओं का निर्धारण ।
36. कच्चे माल के आबंटन के लिए सिद्धांतों, पूर्विकताओं और प्रक्रियाओं का अवधारण ।
37. सामग्री योजना से संबंधित सभी अन्य मामले ।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

क. दूरसंचार विभाग

1. तार, टेलीफोन, बेतार, आंकड़े, प्रतिकृति संबंधी और टेलीमेटिक सेवाओं के नीति, अनुज्ञापन और समन्वय संबंधी विषय तथा संचार के ऐसे ही अन्य रूप ।
2. दूरसंचार से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिनके अंतर्गत इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (आईटीयू), इसका रेडियो रेगुलेशन बोर्ड (आरआरबी), रेडियो कम्युनिकेशन सेक्टर (आईटीयू-आर), टेलीकम्युनिकेशन स्टेन्डर्डराइजेशन सेक्टर (आईटीयू-टी), डेवलपमेंट सेक्टर (आईटीयू-डी), इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सेटलाइट आर्गेनाइजेशन (इंटरसेट), इंटरनेशनल मोबाइल सेटलाइट आर्गेनाइजेशन (इनमारसैट), एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिकेशन (एपीटी) जैसे दूरसंचार के संबंध में कार्रवाई करने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संबंधित मामले भी हैं।
3. दूरसंचार में मानकीकरण, अनुसंधान और विकास का संवर्धन ।
4. दूरसंचार में निजी निवेश का संवर्धन ।
5. दूरसंचार प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए तथा दूरसंचार कार्यक्रम के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने के लिए आर्थिक सहायता, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :

(क) उच्च वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान के लिए संस्थाओं को सहायता, वैज्ञानिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को सहायता; और

(ख) शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्तियां और व्यक्तियों को अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति भी हैं जो दूरसंचार के क्षेत्र में अध्ययन के लिए विदेश जा रहे हैं ।

6. दूर-संचार विभाग द्वारा अपेक्षित सामग्री और उपस्कर की उपाप्ति
7. दूरसंचार आयोग ।
8. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ।
9. दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण ।
10. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले की बाबत विधि का प्रशासन, अर्थात् :
 - (क) भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13);
 - (ख) भारतीय बेतार-तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17); और
 - (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) ।
11. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ।
12. मैसर्स हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड से संबंधित पश्च विनिधान संबंधी विषय ।
13. भारत संचार निगम लिमिटेड ।
14. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ।
15. विदेश संचार निगम लिमिटेड और टेलीकम्यूनिकेशंस कंसल्टेंट्स (इन्डिया) लिमिटेड ।
16. टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) से संबंधित सभी मामले ।
17. तत्कालीन दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार प्रचालन विभाग से संबंधित अवशिष्ट कार्य, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित से संबंधित विषय भी हैं :
 - (क) समूह 'क' और अन्य प्रवर्गों के कार्मिकों के भारत संचार निगम लिमिटेड में उनके आमेदन तक काडर नियंत्रण कृत्य;
 - (ख) सेवांत प्रसुविधाओं का प्रशासन और संदाय ।
18. दूरसंचार से संबंधित पूंजीगत बजट के प्रति विकलनीय संकर्मों का निष्पादन और भूमि का कय और अर्जन ।

ख. डाक विभाग

1. डाक विभाग के पूंजी बजट के प्रति विकलनीय संकर्मों का निष्पादन, जिसके अंतर्गत भूमि का कय भी है ।
2. डाक, जिसके अंतर्गत डाकघर बचत बैंक (प्रशासन), डाकघर प्रमाण-पत्र (प्रशासन), डाकघर जीवन-बीमा निधि (प्रशासन), सार्वजनिक डाक टिकट/डाक स्टेशनरी सहित संस्मारक टिकट, प्रीमियम पोस्टल प्रोडक्ट्स का मुद्रण और कोई अधिकरण कृत्य भी है ।
3. डाक संचार से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिनके अंतर्गत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन (एओपीओयू), कामनवैल्थ पोस्टल यूनियन जैसे डाक संचार के संबंध में कार्रवाई करने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संबंधित मामले भी हैं ।
4. डाकघर द्वारा सभी सेवाओं, जिनके अंतर्गत केबल, रेडियो और उपग्रह संचार चैनलों पर आधारित सेवाएं भी हैं, की पुरःस्थापना, विकास और अनुरक्षण से संबंधित मामले:

बशर्ते कि ये मामले प्रसारण, सीमित प्रसारण, केबल और रेडियो नेटवर्क सेवाओं से संबंधित न हों और भारतीय तार अधिनियम, 1885 और उसके अधीन बनाए गए नियमों से भी शासित न हों, और किसी अन्य विभाग को अनन्य रूप से आबंटित न किए गए हों ।

5. इस विभाग को आबंटित कार्यों के क्षेत्र में साध्यता सर्वेक्षण, अनुसंधान और विकास का संवर्धन।
6. भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 और तदधीन बनाए गए नियमों एवं डाक कार्यों से संबंधित अन्य विधियों अथवा अधिनियमितियों जो विशिष्टता, किसी अन्य विभाग को आबंटित न किए गए हों, के प्रशासन से संबंधित मामले ।

ग. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

1. सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतिगत मामले; इलैक्ट्रानिक्स; और इंटरनेट (इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के अनुज्ञापन से भिन्न सभी मामले) ।
2. इंटरनेट, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाओं का संवर्धन ।
3. ई-शासन, ई-कामर्स, ई-मेडीसिन, ई-इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि के संवर्धन में अन्य विभागों की सहायता ।

4. सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा का संवर्धन ।
5. साइबर कानूनों से संबंधित मामले, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) तथा अन्य सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कानून का प्रशासन ।
6. देश में सेमी-कंडक्टर डिवाइसिस के संवर्धन और विनिर्माण संबंधी मामले, जिनके अंतर्गत सेमीकंडक्टर कम्लेक्स लिमिटेड (एस.सी.एल) मोहाली से संबंधित सभी मामले भी हैं; अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 37)।
7. अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों और निकायों अर्थात् इंटरनेट फॉर विजनेस लिमिटेड (आईएफबी) इंस्टीट्यूट फॉर एज्युकेशन इन इनफोर्मेशन सोसाइटी (आई0बी0आई) और इंटरनेशनल कोड काउंसिल-ऑन लाइन (आई.सी.सी.)के साथ सूचना प्रौद्योगिकी विषयक मामलों में पारस्परिक क्रिया ।
8. डिजीटल डिवाइड पाटने के संबंध में पहल मीडिया लैब एशिया संबंधी मामले ।
9. सूचना प्रौद्योगिकी में मानकीकरण, परीक्षण और क्वालिटी का संवर्धन तथा सूचना प्रौद्योगिकी उपयोजन प्रक्रिया का मानकीकरण और कार्य ।
10. इलेक्ट्रानिक्स एक्सपोर्ट एण्ड कम्प्यूटर साफ्टवेयर प्रमोशन काउंसिल (ई.एस.सी.) ।
11. राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) ।
12. ज्ञान आधारित उद्यमों सहित हार्डवेयर/साफ्टवेयर उद्योग के विकास के लिए पहल, सूचना प्रौद्योगिकी निर्यातों तथा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता का संवर्धन करने के लिए उपाय ।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

क. उपभोक्ता मामले विभाग

1. आंतरिक व्यापार ।
2. अंतर्राष्ट्रिय व्यापार : स्प्रिटयुक्त निर्मिति (अंतर्राष्ट्रिय व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955 (1955 का 39) ।
3. वायदा व्यापार का नियंत्रण : अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) ।

4. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) (ऐसी आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय, कीमतें और वितरण, जो किसी अन्य विभाग द्वारा विनिर्दिष्टतः व्यवहृत नहीं किया गया है) ।
5. चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का 7); उसके अधीन निरोध के अध्यधीन व्यक्ति ।
6. पैक की हुई वस्तुओं का विनियमन ।
7. विधिक माप-विज्ञान में प्रशिक्षण ।
8. संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1952 (1952 का 12) ।
9. बाट और माप मानक; बाट और माप-मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) ।
10. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) ।
11. वायदा बाजार आयोग ।
12. उपभोक्ता सहकारी समितियां ।
13. आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की मानीटरिंग और उनकी उपलब्धता ।
14. राष्ट्रीय परीक्षण गृह ।
15. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) ।

ख. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

1. खाद्य से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों और अन्य निकायों अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय गोहूँ परिषद, विश्व खाद्य परिषद्, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, खाद्य सुरक्षा संबंधी आयोग/समितियों में भाग लेना और लिए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन ।
2. विदेशों से संधि और करार करना तथा खाद्यान्नों और अन्य खाद्य पदार्थों में व्यापार एवं वाणिज्य के संबंध में विदेशों से की गई संधियों, करारों और अभिसमयों को कार्यान्वित करना ।
3. खाद्यान्नों, जिनमें शर्करा भी है, के भंडारण के लिए गोदामों को भाड़े पर लेना और अर्जित करना तथा खाद्यान्न गोदामों के संनिर्माण के लिए भूमि को पट्टे पर लेना या अर्जित करना ।

4. भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम से संबंधित मामले ।
5. सिविल आवश्यकताओं के लिए खाद्य-पदार्थों का कय और वितरण तथा सेना के लिए भी शर्करा, चावल और गेहूं का कय ।
6. खाद्यानों और अन्य खाद्य-पदार्थों, जिसके अंतर्गत शर्करा भी है, के संबंध में अंतरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य ।
7. खाद्यानों का व्यापार और वाणिज्य तथा पूर्ति और वितरण ।
8. खाद्यानों से भिन्न, शर्करा और खाद्य पदार्थों का व्यापार और वाणिज्य तथा उत्पादन, पूर्ति और वितरण ।
9. शर्करा, खाद्यानों और खाद्य पदार्थों का कीमत नियंत्रण ।
10. सार्वजनिक वितरण प्रणाली ।
11. जहां तक कि खाद्यानों का संबंध है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) और चोर-बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का 7) ।
12. वनस्पति, तिलहन, वनस्पति तेलों, खली, वसा और शर्करा (जिसके अंतर्गत शर्करा खांडसारी का विकास भी है) से संबंधित उद्योग ।
13. वनस्पति, तिलहन, वनस्पति तेलों, खली, और वसा की कीमतों का नियंत्रण और उनमें अंतराज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य और उनकी पूर्ति एवं वितरण ।
14. वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय ।
15. शर्करा निदेशालय, नई दिल्ली ।
16. राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर ।
17. राष्ट्रीय शर्करा और गन्ना प्रौद्योगिकी संस्थान, मड ।
18. शर्करा उद्योग विकास परिषद्, नई दिल्ली से संबंधित मामले ।
19. अंतराष्ट्रीय शर्करा परिषद् ।
20. शर्करा विकास निधि ।

रक्षा मंत्रालय

क. रक्षा विभाग

1. भारत की तथा उसके प्रत्येक भाग की रक्षा, जिसके अंतर्गत रक्षा के लिए तैयारी तथा सारे ऐसे कार्य हैं, जो युद्धकाल में युद्ध को चलाने और उसकी समाप्ति के पश्चात सार्थक रूप से सैन्य-वियोजन में सहायक हों ।
2. संघ के सशस्त्र बल अर्थात् थल सेना, नौसेना और वायुसेना ।
3. रक्षा मंत्रालय का समेकित मुख्यालय, जिसके अंतर्गत सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, वायुसेना मुख्यालय और डिफेंस स्टाफ मुख्यालय हैं ।
4. सेना, जलसेना और वायुसेना के रिजर्व ।
5. प्रादेशिक थलसेना ।
6. राष्ट्रीय कैडेट कोर ।
7. सेना, जलसेना और वायुसेना से संबंधित कार्य ।
8. रिमाउन्ट, पशु-चिकित्सा और फार्म संगठन ।
9. कैण्टीन भंडार विभाग (भारत) ।
10. सिविलियन सेवाएं जिनके लिए रक्षा प्राक्कलनों से संदाय किया जाता है ।
11. जल-राशि सर्वेक्षण और नौ-परिवहन संबंधी चार्ट तैयार करना ।
12. छावनियों का स्थापन, छावनी क्षेत्रों का परिसीमन/आच्छेदन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन, ऐसे क्षेत्रों के अंदर छावनी बोर्डों और प्राधिकरणों का गठन और उनकी शक्तियां तथा ऐसे क्षेत्रों में गृह वासन का विनियमन (जिसके अंतर्गत किराए का नियंत्रण है) ।
13. रक्षा प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, अभिरक्षा और त्याग । रक्षा भूमि और संपत्ति से अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ।
14. भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित मामले, जिनके अंतर्गत पेंशनभोगी आते हैं ।

15. रक्षा लेखा विभाग ।

16. सैनिक आवश्यकताओं के लिए खाद्य सामग्रियों का क्रय और उनका व्ययन, उनको छोड़कर जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को सौंपे गए हैं ।

17. तट रक्षक संगठन से संबंधित सभी मामले, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित हैं:

- (क) तेल बिखराव से बचने के लिए सामुद्रिक परिक्षेत्रों की निगरानी;
- (ख) विभिन्न सामुद्रिक परिक्षेत्रों में तेल बिखराव की रोकथाम करना, सिवाय पत्तनों के जल, और अपतट खोज और उत्पादन प्लेटफार्मों, तटीय रिफाइनरियों और सिंगल बॉया मूरिंग (एस0बी0एम0), कूड ऑइल टर्मिनल (सी0ओ0टी0) और पाइपलाइनों जैसी संबद्ध सुविधाओं के 500 मीटर के भीतर के जलक्षेत्र के;
- (ग) विभिन्न सामुद्रिक परिक्षेत्रों के तटीय और समुद्रीय पर्यावरण में तेल प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए केन्द्रीय समन्वय अभिकरण;
- (घ) तेल बिखराव संबंधी विभीषिका के लिए राष्ट्रीय आकस्मिक योजना का कार्यान्वयन; और
- (ङ) देश में, तेल बिखराव के निवारण और नियंत्रण, पोतों तथा अपतट प्लेटफार्मों के निरीक्षण का जिम्मा लेना, सिवाय पत्तनों की उन सीमाओं के भीतर, जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) द्वारा सशक्त की गई हैं ।

18. देश में गोताखोरी और संबंधित क्रियाकलापों से संबंधित मामले ।

19. केवल रक्षा सेवाओं के लिए उपापन ।

20. निम्नलिखित का प्रशासन:

- (क) सेना पेंशन विनियम, 1961 (भाग 1 और भाग 2);
- (ख) वायुसेना पेंशन विनियम, 1961 (भाग 1 और भाग 2);
- (ग) नौसेना (पेंशन) विनियम, 1964; और
- (घ) सशस्त्र बल कार्मिक दुर्घटना पेंशनिक अधिनिर्णय विषयक हकदारी नियम, 1982 ।

ख. रक्षा उत्पादन विभाग

1. आर्डनेंस कारखाना बोर्ड और आर्डनेंस कारखाने ।

2. हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ।
 3. भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड ।
 4. मझगांव डाक लिमिटेड ।
 5. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ।
 6. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ।
 7. भारत डायनामिक्स लिमिटेड ।
 8. मिश्र धातु निगम लिमिटेड ।
 9. रक्षा गुणवत्ता आश्वासन संगठन, जिनके अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय तथा एरोनॉटिकल गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय भी है ।
 10. रक्षा उपकरण तथा सामग्रियों का मानकीकरण, जिसके अंतर्गत मानकीकरण निदेशालय भी है ।
 11. भारत अर्थ मुवर्स लिमिटेड ।
 12. वैमानिकी उद्योग का विकास और उनसे भिन्न उपभोक्ताओं के बीच, जो नागर विमानन मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग से संबंधित है, समन्वय ।
 13. रक्षा उपस्करों का स्वदेशीकरण, विकास और उत्पादन तथा रक्षा उपस्करों के विनिर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी ।
 14. रक्षा निर्यात और रक्षा उत्पादन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ।
- ग. रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग
1. विज्ञान और टेक्नालोजी में हो रहे विकास का राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव के बारे में रक्षा मंत्री को जानकारी देना, मूल्यांकन करना और सलाह देना ।

2. रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं तथा अंतः सेना संगठनों को हथियारों, हथियार-प्लेटफार्मों, फौजी कार्रवाइयों, निगरानी, सहायता और सैन्यतंत्र (लाजिस्टिक), संघर्ष के सभी संभावित क्षेत्रों में सभी वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में सलाह देना ।
3. ऐसी प्रौद्योगिकी के अर्जन के बारे में, जिनका भारत में निर्यात विदेशी सरकारों के नियंत्रण के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, संबंधित विदेशी सरकारों के साथ करार लिखितों के संबंध में सभी विषयों पर रक्षा मंत्रालय के नोडल समन्वय अधिकरण के रूप में, विदेश मंत्रालय की सहमति से कृत्य करना ।
4. राष्ट्रीय सुरक्षा से सुसंगत क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान और डिजाइन, विकास, परीक्षण और मूल्यांकन के कार्यक्रम तैयार करना और उनका निष्पादन करना ।
5. विभाग के अधिकरणों, प्रयोगशालाओं, स्थापनों, रेजों, प्रसुविधाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का निर्देशन और प्रशासन ।
6. वैमानिकी विकास अधिकरण ।
7. सैनिक विमानों, उनके उपकरण और यान सामग्रियों की उड़ान अनुकूलता डिजाइन के प्रमाणीकरण से संबंधित सभी विषय ।
8. विभाग की कार्यवाहियों से सृजित तकनीक के परीक्षण और अंतरण से संबंधित सभी विषय।
9. रक्षा मंत्रालय द्वारा अर्जित किए जाने के लिए प्रस्थापित सभी हथियार प्रणालियों और संबंधित तकनीकों के अर्जन और मूल्यांकन कार्रवाइयों का वैज्ञानिक विश्लेषण, समर्थन तथा उनमें भाग लेना ।
10. सशस्त्र सेवाओं के लिए उपकरण और सामग्रियों का विनिर्माण कर रहे या विनिर्माण करने की प्रस्थापना कर रहे उत्पादन एकाई और उपक्रमों द्वारा तकनीक के आयात के तकनीकी और बौद्धिक ज्ञान गुणधर्म के पहलुओं के बारे में सलाह देना ।
11. पेटेन्ट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 35 के अधीन किए गए संदर्भ का निपटारा ।
12. राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहलुओं की बाबत अध्ययन और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए व्यक्तियों, संस्थाओं और निगमित निकायों को वित्तीय तथा अन्य सामग्री संबंधी सहायता ।

13. राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में विदेश मंत्रालय के परामर्श से, सभी विषय जिसमें निम्नलिखित भी है:
 - (क) अन्य देशों के अनुसंधान संगठनों, और अंतर-सरकारी अभिकरणों, विशेष रूप से उनसे संबंधित, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी पहलुओं से संबंधित हैं, संबंधों की बाबत विषय;
 - (ख) विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारतीय वैज्ञानिक और तकनीकविदों को विदेशी छात्रवृत्तियों और प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए विदेशों में विश्वविद्यालयों, शैक्षिक और अनुसंधान उद्देश्य-जन्य संस्थाओं या निगमित निकायों के साथ व्यवस्था करना ।
14. विभाग के बजट के नामेखाते संकर्मों का निष्पादन और भूमि का कय ।
15. विभाग के नियंत्रण के अधीन कार्मिकों संबंधी सभी विषय ।
16. विभाग के बजट के नामेखाते सभी प्रकार की सामग्रियों, उपकरणों और सेवाओं का अर्जन ।
17. विभाग से संबंधित वित्तीय मंजूरियां ।
18. भारत सरकार के किसी अन्य ऐसे मंत्रालय, विभाग, अभिकरण के साथ, जिनके कार्यों का राष्ट्रीय सुरक्षा के वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं पर प्रभाव है, करारों या व्यवस्थाओं के माध्यम से विभाग को सौंपे गए और विभाग द्वारा स्वीकार किए गए कोई अन्य कार्य ।

विनिवेश मंत्रालय

1. केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से केन्द्रीय सरकार की इक्विटी के विनिवेश से संबंधित सभी मामले ।
2. विनिवेश के तौर-तरीकों, जिसके अंतर्गत पुनर्गठन भी है, के बारे में विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर निर्णय ।
3. विनिवेश संबंधी निर्णयों का कार्यान्वयन, जिसके अंतर्गत सलाहकारों की नियुक्ति, शेयरों का कीमत निर्धारण और विनिवेश की अन्य शर्तें भी हैं ।

4. विनिवेश आयोग ।
5. केवल सरकार की इक्विटी के विनिवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम ।

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय

1. पर्यावरण और परिस्थिति-विज्ञान, जिसमें तटीय समुद्र मैनग्रोवों और प्रवाल भित्तियों का पर्यावरण शामिल है, लेकिन खुले सागर में समुद्री पर्यावरण शामिल नहीं है ।
2. पर्यावरण अनुसंधान और विकास, शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना और जागरूकता ।
3. पर्यावरणीय स्वास्थ्य ।
4. पर्यावरणीय संघात निर्धारण ।
5. संरक्षण, प्रबंध और वनरोपण के लिए वन विकास अधिकरण तथा संयुक्त वन प्रबंध कार्यक्रम ।
6. प्राकृतिक संसाधनों, विशिष्टतया वन, वनस्पति, जीवजन्तु, पारिस्थितिकी-प्रणालियों, आदि का सर्वेक्षण और अन्वेषण ।
7. जैव-विविधता संरक्षण, जिसके अंतर्गत इसके झील और छम्ब क्षेत्र (वेटलैण्ड) भी है ।
8. नदियों, के संरक्षण, विकास प्रबंध और विकास प्रदूषण का उपशमन, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भी है ।
9. वन्य जीव संरक्षण परिरक्षण/संरक्षण, योजना, अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और ज्ञान, जिसके अंतर्गत परियोजना बाघ तथा परियोजना हाथी भी है ।
10. पर्यावरण, वानिकी और वन्य जीवों से संबंधित विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता ।
11. भारतीय वनस्पति-विज्ञान सर्वेक्षण तथा वनस्पति-विज्ञान गार्डन ।
12. भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण ।

13. प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय ।
14. जीव मंडल रिजर्व कार्यक्रम ।
15. राष्ट्रीय वन नीति और देश में सामाजिक वानिकी सहित वानिकी विकास ।
16. अंडमान और निकोबार द्वीप में वन और वन प्रशासन से संबंधित सभी मामले ।
17. भारतीय वन सेवा ।
18. वन्य जंतुओं का परिरक्षण तथा वन्य पक्षियों और जीव जंतुओं का संरक्षण ।
19. मौलिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान तथा प्रशिक्षण, जिसके अंतर्गत वानिकी में उच्च शिक्षा भी है ।
20. पदमाजा नायडू हिमालयन प्राणि-विज्ञान पार्क ।
21. वानिकी विकास स्कीमों को वित्तीय सहायता ।
22. भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर ।
23. वन-रोपण और पारिस्थितिकी विकास, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय वन-रोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड भी होगा ।
24. मरुस्थल और मरुस्थलीकरण ।
25. भारतीय वन सर्वेक्षण ।
26. भारतीय जैव-विविधता संस्थान, ईटानगर ।
27. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ।
28. जी०बी० पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान ।
29. भारतीय वन्य जीव संस्थान और भारतीय वन्य जीव बोर्ड ।

30. भारतीय वन प्रबंध संस्थान ।
31. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय प्राणी उद्यान भी है ।
32. भारतीय प्राणी संस्थान और शिक्षा परिषद ।
33. लडमान और निकोबार द्वीप वन और वन-रोपण विकास निगम लिमिटेड ।
34. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण ।
35. कांजीघास और पशु अतिचार से संबंधित मामले ।
36. गौशाला और गौसदन ।
37. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) ।
38. राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1995 (1995 का 27) ।
39. राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 22) ।
40. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) ।
41. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 (1977 का 36) ।
42. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) ।
43. भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) ।
44. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) ।
45. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) ।
46. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) ।
47. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1991 (1991 का 6) ।

विदेश मंत्रालय

1. वैदेशिक मामले ।
2. विदेशी राज्यों एवं राष्ट्रमंडल देशों के साथ संबंध ।
3. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ।
4. भारत में विदेशी राजनयिक और कौंसलीय अधिकारियों और संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों और उसके विशेषज्ञता प्राप्त अभिकरणों से संबंधित सभी मामले ।
5. पासपोर्ट और वीजा, जिनके अंतर्गत भारत में प्रवेश के लिये वीजाओं का प्रदान या पृष्ठांकन करना नहीं आता, किन्तु इसके अंतर्गत व्यतिकार (दक्षिण अफ्रीका) नियम, 1944 के अधीन अभारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकियों को प्रवेश अनुज्ञा-पत्रों का प्रदान करना और, मिशनरियों को छोड़कर, श्रीलंका के राष्ट्रियों के लिए प्रवेश वीजाओं का प्रदान करना आता है ।
6. अपराधियों और अभियुक्त व्यक्तियों का भारत से विदेशों और राष्ट्रमंडल देशों को और विदेशों और राष्ट्रमंडल देशों से भारत को प्रत्यर्पण तथा प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) का साधारण प्रशासन और राज्य-क्षेत्रातीतता ।
7. वैदेशिक तथा राष्ट्रमंडल मामलों से संबंधित राज्य कारणों से भारत में निवारक निरोध ।
8. विदेशों और राष्ट्रमंडल राज्यों के राष्ट्रियों का भारत से संप्रत्यावर्तन और विदेशों और राष्ट्रमंडल देशों के भारतीय राष्ट्रियों का भारत को विवासन और संप्रत्यावर्तन ।
9. दक्षिण अफ्रीका मंच या अन्य किसी देश से, जिस पर व्यतिकार अधिनियम, 1943 (1943 का 9) लागू होता हो, भारत में आप्रवासन ।
10. सभी कौंसलीय कृत्य ।
11. भारत से चीन के तिब्बत क्षेत्र में जाने वाले सभी व्यापारियों और तीर्थ-यात्रियों की यात्रा का प्रबंध ।
12. विभिन्न स्कीमों के अधीन विदेशी छात्रों को भारत में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति ।
13. विदेशी शरणार्थियों को तथा जिन लोगों ने विदेशों में सेवाएं की हैं उनके वंशजों को दी जाने वाली राजनीतिक पेशाने ।

14. विदेशी तथा राष्ट्रमंडलीय अतिथियों एवं राजनयिक कॉन्सुलीय प्रतिनिधियों से संबंधित समारोह कार्य ।
15. फ्रांस और पुर्तगाल के साथ संबंधों के संदर्भ में पांडिचेरी, गोवा, दमन और दीव विषयक मामले।
16. भारत के साथ विशेष संधि-संबंधों वाले राज्यों जैसे भूटान के साथ संबंध ।
17. हिमालय अभियान; ऐसे संरक्षित क्षेत्रों, जिनका संबंध गृह मंत्रालय से है, से भिन्न, संरक्षित क्षेत्रों में यात्रा करने के लिए विदेशियों को अनुज्ञा ।
18. संयुक्त राष्ट्र विशेषता प्राप्त-अभिकरण और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन ।
19. भारतीय विदेश सेवा ।
20. भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' ।
21. विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थान ।
22. विदेश प्रचार ।
23. विदेशों और राष्ट्रमंडल देशों के साथ राजनीतिक संधियां, करार और अभिसमय ।
24. (क) भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं, जिनमें हज समिति अधिनियम, 1959 (1959 का 51) तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों, और भारतीय तीर्थयात्री पोत नियम, 1933 का प्रशासन भी है, तथा भारत से पाकिस्तान स्थित धर्म-स्थानों को और पाकिस्तान से भारत स्थित धर्म-स्थानों को आने-जाने वाले तीर्थ यात्रीदल ।

(ख) 1955 के पंत-मिर्जा करार के निर्बंधनों के अनुसार, पाकिस्तान के गैर-मुस्लिम धर्म-स्थानों और भारत में मुस्लिम धर्म-स्थानों का संरक्षण और परिरक्षण ।
25. अपहृत व्यक्ति (प्रत्युद्धरण और प्रत्यावर्तन) ।
26. पड़ोसी देशों में अल्प-संख्यक समुदायों से संबंधित प्रश्न ।
27. बर्मा, मलाया, आदि से निष्क्रांतों को 1942-47 के दौरान दिए गए उधारों की वसूली तथा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जिन शरणार्थियों को भारत में शरण दी गई थी उनसे संबंधित अवशिष्ट कार्य।

28. युद्ध की स्थिति के प्रारंभ अथवा समाप्त होने के बारे में अधिसूचना ।
29. वैदेशिक अधिकारिता ।
30. भारत सरकार का आतिथ्य अनुदान ।
31. भारत के भू-सीमान्तों का सीमांकन ।
32. भारत की भू-सीमाओं पर सीमा छापे और घटनाएं ।
33. भारत से होकर जाने वाले विदेशी, सिविल और सैनिक वायुयानों की गैर-अनुसूचित चार्टर उड़ानों के लिए राजनयिक उड़ान निर्वाधन ।
34. समुद्र विधि, जिसके अंतर्गत भारतीय राज्यक्षेत्रीय समुद्र, संलग्न क्षेत्र महाद्वीपीय मग्नतट भूमि तथा अनन्य आर्थिक परिक्षेत्र (अ.आ.प.) से संबंधित मामले, खुले समुद्रों के संबंध में उत्पन्न होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रश्न, जिसके अंतर्गत मछली पकड़ने के अधिकार भी हैं; खुले समुद्रों या आकाश में किए गए जल दस्युताओं और अपराधों, स्थल या खुले समुद्रों अथवा आकाश में किए गए संप्रभुता संपन्न राज्यों की विधि के विरुद्ध अपराध, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सतह क्षेत्र तथा प्राधिकरण से संबंधित विधिक मामले ।
35. कोलम्बो योजना के अधीन भारत द्वारा नेपाल की सरकार को सहकारी आर्थिक विकास के लिए दी गई आर्थिक और तकनीकी सहायता ।
36. जिन स्टोरो का कय, निरीक्षण और उन्हें खाना करने का कार्य किसी साधारण या किसी असाधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्य प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित किया गया है, उनसे भिन्न स्टोरो का विदेश से केन्द्रीय सरकार के लिए कय, निरीक्षण और खाना करने का कार्य ।
37. नेपाल, भूटान और बंगलादेश को ऋण के अनुदान और पावनों से संबंधित सभी मामले ।
38. विशेष राष्ट्रमण्डलीय अफ्रीकन सहायता योजना कार्यक्रम के अधीन अफ्रीकन देशों को भारत द्वारा दी गई तकनीकी सहायता ।

टिप्पण: राष्ट्रमण्डल देशों में उनके अंतर्गत ब्रिटिश उपनिवेश, संरक्षित राज, और न्यास राज्यक्षेत्र आते हैं ।

39. मानव अधिकार :

- (क) विदेश में मानव अधिकार संगठनों से पारस्परिक प्रभाव;
- (ख) अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं, संधियां, अभिसमय और सम्मेलन; संयुक्त राष्ट्र और उसके अन्य विशिष्ट अभिकरणों और संगठनों से प्राप्त निर्देश;
- (ग) संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, जिनका भारत एक पक्षकार राज्य है, के अधीन अपेक्षित रिपोर्टिंग दायित्वों का, संबद्ध मंत्रालयों के समन्वय से कार्यान्वयन ।

टिप्पण: इन कृत्यों का प्रयोग विदेश मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय के निकट समन्वय से किया जाएगा, जो कि नीति और मानवाधिकारों से संबंधित सभी मामलों के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय होगा ।

- 40. विदेशों में रहने वाले भारतीयों के साथ संबंध, अन्य विभागों को विनिर्दिष्टता आबंटित प्रविष्टियों को छोड़कर ।
- 41. भारतीय विश्व कार्य परिषद ।

वित्त मंत्रालय

क. आर्थिक कार्य विभाग

I. विदेशी मुद्रा प्रबंध

- 1. राजस्व विभाग के अधीन वर्णित प्रवर्तन कार्य से भिन्न, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) का प्रशासन, तथा आतंकवादी कार्यों के वित्त-पोषण से निपटने की बाबत सभी विषय ।
- 2. रुपए की विनिमय दर संबंधी नीति ।
- 3. विदेशी मुद्रा स्रोतों का प्रबंधन, जिसमें विदेशी मुद्रा की दृष्टि से आयातों की प्रस्थापनाओं की संवीक्षा भी सम्मिलित है ।
- 4. विदेशी तथा अनिवासी भारतीय विनिधान (औद्योगिक तथा सेवा परियोजनाओं के प्रत्यक्ष विदेशी तथा अनिवासी भारतीय विनिधान को छोड़कर) तथा सरकारी और मूल संगठनों में विदेशी अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्तियों का योगदान ।

5. भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी विनिधान ।
6. विदेशों से वाणिज्यिक उधार लेने संबंधी मामले, जिसमें उसके निबंधन और शर्तें भी सम्मिलित हैं ।
7. स्वर्ण और चांदी संबंधी मामले ।
8. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्रियों, राज्य विधान मंडलों/संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों और राज्य सरकार के अधिकारियों की विदेशी यात्रा के लिए अनुमोदन ।
9. विदेशी ऋण का प्रबंध ।

II. आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता

10. निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले :

(क) भारत विकास फोरम;

(ख) विदेशी राष्ट्रों, विशेष अभिकरणों, गैर-सरकारी बुनियादी अभिकरणों और स्वैच्छिक निकायों से ऋण, उधार और अनुदान;

(ग) बहु-पक्षीय अभिकरणों से ऋण, उधार और अनुदान;

(घ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निकासियां और उधार;

(ङ.) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से प्राइवेट सेक्टर वित्तपोषण संबंधी नीति ।

11. निम्नलिखित के अधीन भारत द्वारा प्राप्त तकनीकी और आर्थिक सहायता :

(क) कोलम्बो योजना की तकनीकी सहकारिता स्कीम;

(ख) संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता प्रशासन कार्यक्रम;

(ग) विभिन्न विदेशी राष्ट्रों, विशेष अभिकरणों, गैर-सरकारी निकायों से तकनीकी सहायता के तदर्थ प्रस्ताव;

(घ) संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय ।

12. कोलम्बो योजना की तकनीकी सहकारिता स्कीम के अधीन कोलम्बो योजना के सदस्य देशों को भारत द्वारा दी गई तकनीकी सहायता ।
13. कोलम्बो योजना परिषद् और योजना के परामर्शदात्री समिति के अधिवेशनों से संबंधित सभी मामले ।
14. नेपाल, भूटान और बंगला देश को छोड़कर, अन्य देशों को भारत सरकार द्वारा दिए गए उधारों से संबंधित सभी मामले ।
15. विदेशी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों से भारत को प्राप्त होने वाली या उनको दी जाने वाली तकनीकी सहायता, उनके सिवाय जिनका संबंध किसी अन्य विभाग को आबंटित विषयों से हो ।
16. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू0एन0डी0पी0) से संबंधित सभी मामले, जिनमें ऐसे कार्यक्रम या परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं जिन्हें यू0एन0डी0पी0 बजट से निधि प्रदान की गई है ।
17. विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (वि.नि.सं.बो.) ।
18. यूनाइटेड नेशन्स फण्ड फार पोपुलेशन एक्टिविटीज (यू0एन0एफ0पी0ए0) से संबंधित और संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अधिकरणों तथा राष्ट्र संघ के अन्य निकायों के अंशदानों से संबंधित नीति संबंधी मामले ।
19. (यू0एन0वी0 के अंतर्गत बहिर्गामी वालंटियर्स के सिवाय) यूनाइटेड नेशन्स वालंटियर्स सहित भारत में विदेशी वालंटियर कार्यक्रम से संबंधित सभी विषय ।
20. संयुक्त राष्ट्र अधिकरणों द्वारा सभी वित्तपोषण ।
21. राष्ट्र मंडल तकनीकी सहकारिता निधि (सी.एफ.टी.सी.)

III. घरेलू वित्त

22. निम्नलिखित से संबंधित सभी विषय :

(क) करंसी और सिक्का निर्माण, जिसके अंतर्गत उसका डिजाइन भी है;

- (ख) प्रतिभूति और करेसी मुद्रण करने वाले मुद्रणालय, सिक्क्यूरिटी पेपर मिलें और टकसालें, इसके अंतर्गत परख विभाग और चांदी परिष्करणी, सोना परिष्करणी और स्वर्ण संग्रहण -सह-परिदान केन्द्र भी है;
- (ग) करेसी नोट कागज, करेसी और बैंक नोट तथा सिक्के, जिसके अंतर्गत स्मारक संबंधी सिक्के भी है, डाक लेखन-सामग्री, स्टाम्प और विभिन्न प्रतिभूति प्ररूपों/मदों का उत्पादन और पूर्ति ।
23. (क) प्रतिभूति बाजार और विनिधानकर्ता संरक्षण के विनियमन और विकास के लिए नीतिगत उपाय ।
- (ख) पूंजी बाजार से साधन जुटाने के लिए नए विनिधान और प्रतिभूतियां । विनिधान नीति, जिसके अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम की विनिधान नीति भी है ।
24. कर्मचारी भविष्य निधि और अन्य वैसी ही भविष्य निधियों के विनिधान पैटर्न ।
25. विनिवेश, जिसके अंतर्गत आगम निधि और आस्ति प्रबंध कंपनी भी है, की प्रक्रिया के बारे में वित्तीय नीति ।
26. कर मुक्त बॉण्ड संबंधी सभी मामले ।

IV. बजट

27. अर्थोपाय ।
28. रेल बजट को छोड़कर, केन्द्रीय बजट, जिसमें अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान भी है, तैयार करना और जब किसी राज्य अथवा राज्य क्षेत्र के संबंध में सांविधानिक तंत्र की विफलता के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा प्रवर्तनशील हो, तो ऐसे राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र का बजट तैयार करना ।
29. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त संस्थानों के बाजार उधार कार्यक्रम ।
30. केन्द्रीय सरकार द्वारा बाजार ऋण का लिया जाना और खजाना हुंडियों का निर्गमन और उन्मोचन ।
31. लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) का प्रशासन ।

32. केन्द्रीय सरकार के उधार लेने और ऋण देने के संबंध में ब्याज दरों का नियत किया जाना ।
33. लेखा और लेखा परीक्षण प्रक्रिया विषयक नीति, जिसके अंतर्गत संव्यवहारों का वर्गीकरण भी है ।
34. राज्यों के विभाजन, फेडरल वित्तीय एकीकरण और पुनर्गठन संबंधी वित्तीय मामले ।
35. भारतीय आकस्मिकता निधि और भारतीय आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (1950 का 49) का प्रशासन ।
36. केन्द्रीय सरकार की बजट संबंधी स्थिति की मानीटरिंग ।
37. स्टर्लिंग पेशन - यू0के0 सरकार के उत्तरदायित्व का अंतरण और अंतर्ग्रस्त दायित्व की वास्तविक गणना ।
38. लोक भविष्य निधि स्कीम ।
39. वित्त आयोग ।
40. पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं के स्रोत ।
41. केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय निक्षेप स्कीम, विशेष निक्षेप स्कीमें, अनिवार्य निक्षेप स्कीमें और अन्य निक्षेप स्कीमें ।
42. लघु बचतें, जिनके अंतर्गत राष्ट्रीय बचत संगठन का प्रशासन भी है ।
43. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां ।
44. संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन संसद के समक्ष लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पेश करना ।
45. वित्तीय आपात ।
46. सरकारी गारंटियां ।
47. भारतीय पूर्त विन्यास कोषाध्यक्ष के कृत्य ।

V. बीमा

48. साधारण बीमा से संबंधित नीति; बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) का प्रशासन; और संबंधित मामले, साधारण बीमा और पब्लिक सेक्टर में पुनर्बीमा कंपनियां ।
49. जीवन बीमा से संबंधित नीति; जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) का प्रशासन; और संबंधित मामले, भारतीय जीवन बीमा निगम ।
50. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) का प्रशासन तथा संबद्ध मामले ।
51. उक्त 48 से 50 तक की किसी भी प्रविष्टि की बाबत केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों से संबद्ध मामलों के विषय में केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व ।

VI. बैंककारी

52. भारतीय बैंकों, चाहे वे राष्ट्रीयकृत हों या नहीं, से संबंधित सभी मामले ।
53. विदेशी बैंक, जहां तक भारत में उनकी संक्रियाओं का संबंध है, से संबंधित सभी मामले ।
54. भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित सभी मामले ।
55. सहकारी बैंककारी से संबंधित सभी मामले ।
56. अखिल भारतीय विकास वित्त संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.), आई.एफ.सी.आई. लिमिटेड, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आई.आई.बी.आई) से संबंधित मामले ।
57. भारतीय आयात-निर्यात बैंक से संबंधित मामले ।
58. पोत परिवहन विकास निधि समिति (उत्सादन) अधिनियम, 1986 (1986 का 66) का प्रशासन ।
59. सिंधिया स्टीमशिप नैविगेशन कंपनी संबंधी मामले ।
60. अवसंरचना विकास वित्त निगम (आई.डी.एफ.सी) और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आई.एल.एफ.एस.) से संबंधित मामले ।

61. चिटफंड और निक्षेप स्वीकार करने वाली अन्य गैर-बैंककारी कंपनियां ।
62. भारत में बैंककारी से संबंधित अन्य मामले ।
63. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) संबंधी मामले ।
64. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) का प्रशासन ।
65. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) का प्रशासन ।
66. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) के कार्यान्वयन संबंधी मामले ।
67. रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के कार्यान्वयन से संबंधित मामले, जिनके अंतर्गत औद्योगिक वित्त पुनर्संरचना बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) और औद्योगिक वित्तीय पुनर्संरचना अपील प्राधिकरण (ए.ए.आई.एफ.आर.) भी आते हैं ।
68. राष्ट्रीय आवास बैंक संबंधी सभी मामले ।
69. संघ सूची की प्रविष्टि 38, 45 और 46 तथा समवर्ती सूची की प्रविष्टि 9 से संबंधित सभी अन्य कानूनों, विनियमों और अन्य विधियों का प्रशासन ।
70. प्रतिभूतिकरण और पुरोबंध संबंधी मामले ।
71. विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 (1992 का 27) का प्रशासन ।
72. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10), बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) और 1980 (1980 का 40), बैंकर्स बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 18) तथा बैंक सेवा आयोग अधिनियम, 1984 (1984 का 44) का प्रशासन ।
73. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) तथा भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) का प्रशासन ।
74. भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1953 (1953 का 54) ।
75. राज्य कृषि उधार निगम अधिनियम, 1968 (1968 का 60) का प्रशासन ।

76. लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 (1983 का 48) का प्रशासन ।
77. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) का प्रशासन ।
78. परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) का प्रशासन ।

VII. भारतीय आर्थिक सेवा प्रबंध

79. भारतीय आर्थिक सेवा प्रबंध- उसका काडर और उससे संबंधित सभी मामले ।

VIII. आर्थिक सलाह

80. उन मामलों पर सलाह, जो आर्थिक प्रबंध, जिसके अंतर्गत मूल्य भी है, के आंतरिक और बाह्य पहलुओं से संबंधित है ।
81. ऋण, राज-वित्त और मुद्रा संबंधी नीतियां ।

IX. प्रकीर्ण अधिनियम

82. सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) ।
83. भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 20, जो विनिधानों का संव्यवहार करती है ।
84. धातु सिक्का अधिनियम, 1889 (1889 का 1) ।
85. पूर्ण विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) ।
86. भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) ।
87. भारतीय प्रतिभूति अधिनियम, 1920 (1920 का 10) ।
88. करेसी अध्यादेश, 1940 (1940 का 4) ।

89. अंतराष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक अधिनियम, 1945 (1945 का 00) ।
90. वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) ।
91. सरकारी बचत-पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) ।
92. अनिवार्य निक्षेप स्कीम अधिनियम, 1963 (1963 का 21) ।
93. भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) ।
94. वैध निविदा (अंतरलिखित नोट) अधिनियम, 1964 (1964 का 28) ।
95. एशियाई विकास बैंक अधिनियम, 1966 (1966 का 18) ।
96. लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1968 का 23) ।
97. छोटे सिक्के (अपराध) अधिनियम, 1971 (1971 का 52) ।
98. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का 56) ।
99. अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 (1974 का 37) ।
100. अफ्रीकी विकास निधि अधिनियम, 1982 (1982 का 1) ।
101. अफ्रीकी विकास बैंक अधिनियम, 1983 (1983 का 13) ।
102. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) ।
103. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) का प्रशासन ।
104. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) ।
105. अंतराष्ट्रीय वित्त निगम (प्रास्थिति, उन्मुक्ति तथा विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 (1958 का 42) ।

ख. व्यय विभाग

1. वित्तीय नियम और विनियम और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन ।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और कार्यालयों से संबंधित वित्तीय मंजूरियाँ, जो नियमों द्वारा या किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों द्वारा प्रत्यायोजित या प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत नहीं आती हैं।
3. मितव्ययिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से, सरकारी स्थापनाओं के कर्मचारीवृन्द की संख्या का पुनर्विलोकन ।
4. लागत-लेखा विषयों पर मंत्रालयों और सरकारी उपक्रमों को सलाह और उनकी ओर से लागत अन्वेषण कार्य करना ।
5. भारतीय लेखा - परीक्षा और लेखा विभाग ।
6. लेखा महानियंत्रक से संबंधित मामले जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :
 - (क) संघ अथवा राज्य सरकारों से संबंधित सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धांत और लेखा-प्ररूप तथा उनसे संबंधित नियम और नियम-पुस्तिकाओं का निर्माण अथवा संशोधन करना;
 - (ख) रिजर्व बैंक के पास संघ सरकार के रोकड़ अतिशेष का, सामान्य रूप से, और सिविल मंत्रालयों अथवा विभागों से संबंधित रिजर्व निक्षेपों का, विशेष रूप से समाधान;
 - (ग) केन्द्रीय सिविल लेखा कार्यालयों द्वारा लेखाकरण के समुचित मानकों के प्रतिपालन का निरीक्षण;
 - (घ) मासिक लेखों का समेकन, राजस्व वसूली की प्रवृत्तियों तथा व्यय इत्यादि के महत्वपूर्ण लक्षणों की समीक्षा तैयार करना तथा संघ सरकार के मामलों में वार्षिक प्राप्तियों और संवितरणों को अपने-अपने शीर्षों के अंतर्गत दर्शाते हुए वार्षिक लेखे (सारांश, सिविल विनियोजन लेखों सहित) तैयार करना;
 - (ङ) केन्द्रीय खजाना नियमों और केन्द्रीय सरकार लेखा (प्राप्ति और संदाय नियम), 1983 का प्रशासन;
 - (च) सिविल मंत्रालयों अथवा विभागों में प्रबंध लेखाकरण प्रणाली लागू करने में, समन्वयन और सहायता;

- (छ) समूह 'क' (भारतीय सिविल लेखा सेवा) और समूह 'ख' केन्द्रीय सिविल लेखा कार्यालयों के अधिकारियों का काडर प्रबंध;
- (ज) समूह 'ग' और 'घ' से संबंधित केन्द्रीय सिविल लेखा कर्मचारीवृंद से संबंधित मामले;
- (झ) केन्द्रीय सिविल पेंशन भोगियों, स्वतंत्रता सेनानियों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, पूर्व-संसद सदस्यों और पूर्व राष्ट्रपतियों के संबंध में पब्लिक सेक्टर के बैंकों (पी.एस.बी.) के माध्यम से पेंशन का संवितरण ।

7. इनके लिए केन्द्रीय सहायता देना : राज्य की आर्थिक योजना, राज्य के आपदा राहत कोष का केन्द्रीय अंश, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से सहायता, उन्नति अनुदान और ग्रामीण/शहर स्थानीय निकायों के लिए अनुदान और आनुकूलिक वित्त आयोगों द्वारा सिफारिश किए गए अन्य अनुदान ।
8. राज्य वित्तों का विश्लेषण, राज्यों की दिन-प्रतिदिन की वित्तीय समस्याएं और राज्यों के राजकोषीय सुधार कार्यक्रम ।
9. केन्द्रीय मंत्रालयों और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों (पी.एस.यू.) की वार्षिक/पंचवर्षीय योजना तैयार करने में भागीदारी । योजना के वित्तपोषण के लिए केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों (पी.एस.यू.) के आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों का निर्धारण ।
10. वित्तीय और आर्थिक प्रभाव रखने वाले केन्द्रीय और राज्य विधान की संवीक्षा ।
11. केन्द्रीय मंत्रालयों और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के प्लान निवेश/व्यय प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन । व्यय वित्त समिति (ई0एफ0सी0)/लोक निवेश बोर्ड (पी.आई.बी.) प्रक्रियाओं और लोक निवेश बोर्ड के लिए सचिवालयीय कार्य संबंधी मामले ।
12. केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के पूंजी पुनर्संरचना/पुनर्जीवीकरण प्रस्तावों का मूल्यांकन/अनुमोदन ।

ग. राजस्व विभाग

1. निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले :

(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड;

(ख) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।

2. राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान को सहायता अनुदान ।

3. विनिमय-पत्रों, चैकों, वचनपत्रों, वहन-पत्रों, साख-पत्रों, बीमा-पालिसियों, शेरों का अंतरण, डिबेंचरों, परोक्ष-पत्रों और रसीदों पर स्टाम्प शुल्क ।
4. आयकर (आयकर अपील अधिकरण संबंधी प्रश्नों को छोड़कर), निगम कर, पूंजी अभिलाभ कर और सम्पदा शुल्क, धन कर, व्यय कर, और दान कर संबंधी सभी प्रश्न और रेल यात्री भाड़ा अधिनियम संबंधी प्रश्न भी ।
5. बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) का प्रशासन ।
6. संघ राज्य क्षेत्रों में उत्पाद शुल्क का प्रशासन, अर्थात् निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले:
 - (क) मानव उपभोग के लिए मद्यसारिक लिकर;
 - (ख) अफीम, केनेबिस (भारतीय भांग) और अन्य स्वापक औषधियां और स्वापक पदार्थ ।
7. औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16) का प्रशासन ।
8. अफीम पोस्त की खेती, और ऐसी अफीम से अफीम व्युत्पन्नों का विनिर्माण, ऐसी अफीम और अफीम व्युत्पन्नों का विक्रय और उन पर नियंत्रण के प्रयोग से संबंधित सभी मामले;
9. स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) का प्रशासन ।
10. स्वापक औषधियों, मनः प्रभावी पदार्थों और पूर्वगामी रसायनों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों, करारों, नयाचार, आदि से संबंधित सभी मामले, जिनके लिए राजस्व विभाग और इसके अंतर्गत संगठन कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत है, केवल उन मामलों को छोड़कर, जो गृह मंत्रालय को आबंटित मामले हैं ।
11. सीमा-शुल्क (समुद्र, वायु और भूमि), जिसके अंतर्गत सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) टैरिफ मूल्यांकन, सीमा-शुल्क सहकारिता परिषद, सीमा शुल्क नामपद्धति और ऐसे ही मामले हैं, आयात और निर्यात किए गए माल पर शुल्क; सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन आयातों और निर्यातों पर प्रतिषेध और निर्बन्धन; और सीमा शुल्क टैरिफ के निर्वचन से संबंधित सभी मामले ।
12. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी मामले, जिनके अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) और सेवा कर प्रशासन भी है ।

13. विक्रय कर :

- (क) विक्रय कर विधियां (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1956 (1956 का 7) का प्रशासन;
- (ख) अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रयों पर कर का उद्ग्रहण-केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के प्रशासन में उत्पन्न समस्याएं;
- (ग) संविधान के अनुच्छेद 286(3) के अधीन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व के माने जाने वाले माल की घोषणा, उन शर्तों और निर्बन्धनों का अधिकथन जिसके अधीन वे राज्य विधियां होंगी जो उन पर कर उद्ग्रहण के लिए उपबंध करती हैं;
- (घ) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क द्वारा विक्रय कर के प्रतिस्थापन से संबंधित सभी प्रश्न, जिनके अंतर्गत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) का प्रशासन है;
- (ङ) राज्यों में विक्रय कर के उद्ग्रहण से संबंधित वे सभी विधेयक, आदि जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेशों, सिफारिशों या अनुमति के लिए आए;
- (च) संघ राज्य क्षेत्रों में विक्रय कर से संबंधित विधायी मामले;
- (छ) राज्यों के गन्ना उपकर उद्ग्रहण के अविधिमान्य किए जाने से उत्पन्न समस्याएं, जिनके अंतर्गत ऐसे उद्ग्रहणों का विधिमान्यकरण आता है ।

14. अधीनस्थ संगठन:

- (क) आयकर विभाग;
- (ख) सीमा शुल्क विभाग;
- (ग) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग; और
- (घ) स्वापक पदार्थ विभाग (इसके अंतर्गत स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो नहीं है) ।

15. विदेशी मुद्रा के संरक्षण या संवर्धन और तस्करी क्रियाकलापों के निवारण और उसमें संबंधित मामलों के प्रयोजनों के लिए निवारक निरोध ।

16. प्रवर्तन, अर्थात् विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन भंगों से उद्भूत मामलों का अन्वेषण, और न्याय निर्णयन; राजस्व आसूचना महानिदेशालय और प्रवर्तन निदेशालय ।
17. आर्थिक आसूचना संबंधी सभी मामले ।
18. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपील अधिकरण से संबंधित मामले ।
19. तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) के अंतर्गत आने वाले सभी मामले ।
20. धन शोधन निवारण (पी0एम0एल0) अधिनियम, 2002 (2003 का 15) का प्रशासन ।

घ. कंपनी कार्य विभाग

1. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) का प्रशासन ।
2. कंपनी (राष्ट्रीय निधियों में दान) अधिनियम, 1951 (1951 का 54) का प्रशासन ।
3. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) का प्रशासन ।
4. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ।
5. लेखा-वृत्ति {चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38)}; लागत और संकर्म लेखावृत्ति {लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23)}; कंपनी सचिव वृत्ति {कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56)}।
6. कंपनियों से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण ।
7. भागीदारी विधि के संबंध में विधान और भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अध्याय 7 के अधीन केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में कतिपय कृत्यों का निर्वहन (अधिनियम का प्रशासन राज्य सरकारों में निहित है) ।
8. उपर्युक्त मदों में से किसी के बारे में केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों से संबंधित मामलों की बाबत केन्द्र का उत्तरदायित्व ।

9. केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण और कृत्यों के प्रयोग से संबंधित विधान ।
10. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ।
11. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2000 (2003 का 12) ।
12. गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

1. निम्नलिखित उद्योगों के संबंध में :
 - (क) कुछ कृषि उत्पादों (दुग्ध चूर्ण, शिशु दुग्ध आहार, माल्ट मिश्रित दुग्ध आहार, संघनित दुग्ध, घी और अन्य डेरी उत्पाद) कुक्कुट और अंडे, मांस और मांस उत्पादों का संसाधन और प्रशीतन;
 - (ख) मछलियों का संसाधन (जिसके अंतर्गत डिब्बाबंदी और हिमीकरण भी सम्मिलित हैं);
 - (ग) मत्स्य संसाधन उद्योग के लिए विकास परिषद की स्थापना और उसकी प्रबंध व्यवस्था;
 - (घ) मत्स्य संसाधन उद्योग को तकनीकी सहायता और सलाह;
 - (ङ.) फल और सब्जी संसाधन उद्योग (जिसके अंतर्गत हिमीकरण और निर्जलीकरण भी हैं); और
 - (च) खाद्यान्न पिसाई उद्योग ।
2. उन उद्योगों की योजना, विकास, नियंत्रण और सहायता, जो डबल रोटी, तिलहन, चूर्ण (खाने योग्य), नास्ते के आहार, बिस्कुट, मिष्ठान (जिसके अंतर्गत कोको संसाधन और चाकलेट बनाना भी हैं), माल्ट सार, पृथक्कृत प्रोटीन, उच्च प्रोटीन आहार, स्तनय त्याग आहार और उत्सारित खाद्य उत्पाद, (जिसके अंतर्गत तत्काल खाने योग्य अन्य आहार भी हैं) से संबंधित हैं ।
3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए विशिष्ट पैकेजिंग ।
4. बीयर जिसके अंतर्गत नान-अल्कोहली बीयर भी हैं ।

5. ऐसे एल्कोहली पेय जिनका आधार शीरे पर न हो ।
6. वातित जल और सुपेय ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

क. स्वास्थ्य विभाग

I. संघ कारबार

1. अनुसंधान के लिए या औषध और पोषण में विशेष अध्ययन के संप्रवर्तन के लिए संघ अधिकरण और संस्थान, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित से संबंधित मामले भी हैं:
 - (क) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान;
 - (ख) अखिल भारतीय आरोग्य संबंधी और लोक स्वास्थ्य संस्थान;
 - (ग) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान;
 - (घ) केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला;
 - (ङ.) राजकुमारी अमृतकौर नर्सिंग महाविद्यालय;
 - (च) लेडी रीडिंग स्वास्थ्य विद्यालय;
 - (छ) केन्द्रीय मनोविकार-विज्ञान संस्थान;
 - (ज) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और नर्सिंग होम;
 - (झ) सफदरजंग अस्पताल;
 - (ञ) आयुर्विज्ञान भण्डार संगठन;
 - (ट) बी०सी०जी० टीका प्रयोगशाला;
 - (ठ) जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान;
 - (ड) श्रीमती सुचेता कृपलानी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल और कलावती सरण बच्चों का अस्पताल;
 - (ढ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी०जी०एच०एस०);
 - (ण) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा;
 - (त) सीरम विज्ञानी और रसायन परीक्षक, भारत सरकार ।
2. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला ।

3. केन्द्रीय खाद्य और मानकीकरण प्रयोगशाला ।
4. केन्द्रीय भारतीय भेषज-संग्रहण प्रयोगशाला ।
5. अखिल भारतीय शारीरिक औषध और पुनर्वास संस्थान ।
6. राष्ट्रीय क्षय-रोग संस्थान ।
7. केन्द्रीय कुष्ठ अध्यापन और अनुसंधान संस्थान ।
8. प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र, रायपुर (उ०प्र०), असका (उड़ीसा), गौरीपुर (प०ब०), टिटुलमारी (बिहार) ।
9. पत्तन करन्तीन (समुद्र और वायु) नाविक और समुद्रीय अस्पताल और पत्तन करन्तीन से संबंधित अस्पताल ।
10. पत्तन और विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन ।
11. नाविकों की चिकित्सा परीक्षा ।
12. अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम ।
13. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू०एच०ओ०) ।
14. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) और उसके अधीन स्थापित की गई केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला ।
15. चिकित्सा-शास्त्र और सहबद्ध विषयों में विदेश में उच्चतर प्रशिक्षण ।
16. चिकित्सा और उससे संबंधित क्षेत्रों में भारत और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की बाबत कार्य का समन्वय ।
17. स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता ।
18. अंधेपन के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम ।
19. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम ।

20. राष्ट्रीय क्षय-रोग नियंत्रण कार्यक्रम ।
21. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ।
22. संचारी रोगों के नियंत्रण और उन्मूलन से संबंधित सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम ।
23. द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम - स्वास्थ्य संबद्ध घटकों का किद्मान्वयन ।
24. फेलोशिप - भारत और विदेश में विभिन्न चिकित्साशास्त्र और स्वास्थ्य से संबंधित विषयों में प्रशिक्षण के लिए ।
25. महामारी से संबंधित मामले : औषधियों के प्रदाय, कुपोषण का प्रभाव और प्राकृतिक विपत्तियों की वजह से पीने के पानी की कमी से होने वाले विभिन्न रोगों से संबंधित समस्याएं ।

II. संघ राज्य क्षेत्रों की बाबत विधायी और कार्यपालक प्रयोजनों के लिए कारबार की सूची ।

26. लोक स्वास्थ्य अस्पताल और डिस्पेंसरी ।
27. विभाग में व्यवहार में आने वाले विषयों से संबंधित वैज्ञानिक सोसाइटी और संगम ।
28. विभाग में व्यवहार में आने वाले विषयों से संबंधित पूर्ण और धार्मिक विन्यास ।

III. कारबार की सूची, जिसमें केन्द्रीय सरकार केवल संघ के लिए विधायी हैसियत में और सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधायी और कार्यपालक हैसियत दोनों में, व्यवहार करे ।

29. चिकित्सा वृत्ति और चिकित्सा शिक्षा ।
30. नर्सिंग वृत्ति और नर्सिंग शिक्षा ।
31. फार्मेसिस्ट और फार्मसी शिक्षा ।
32. दंत वृत्ति और दंत शिक्षा ।
33. मानसिक स्वास्थ्य ।

34. औषधि मानक ।
35. औषधि और औषध से संबंधित विज्ञापन ।
36. एक राज्य से दूसरे राज्य में मनुष्यों को प्रभावित करने वाले संक्रामक या सान्सारिक रोगों को फैलने से रोकना ।
37. खाद्य पदार्थ और औषधि अपमिश्रण निवारण ।

IV. प्रकीर्ण कारबार

38. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ।
39. केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् ।
40. भारतीय दंत परिषद ।
41. भारतीय नर्सिंग परिषद ।
42. भारतीय फार्मसी परिषद ।
43. भारतीय भेषज समिति ।
44. (i) जो रेल सेवा में है, (ii) जिन्हें रक्षा सेवा प्राक्कलन से संदाय किया जाता है, (iii) ऐसे अधिकारी जो अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1954 द्वारा शासित हैं, और (iv) ऐसे अधिकारी जो चिकित्सा परिचर्या नियम, 1956 द्वारा शासित हैं; से भिन्न, केन्द्रीय सरकारी सेवकों के लिए चिकित्सा परिचर्या और उपचार के लिए रियायत।
45. केन्द्रीय सिविल सेवाओं के लिए चिकित्सा परीक्षा और चिकित्सा बोर्ड (रेल विभाग द्वारा नियंत्रित व्यक्तियों और, सिविलियन सेवाओं को छोड़कर, जिन्हें रक्षा सेवा प्राक्कलन से संदाय किया जाता है, से भिन्न)।
46. वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट (दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन) को अनुदान ।
47. भारतीय रेडकास सोसाइटी को अनुदान ।
48. स्पास और स्वास्थ्य विभाग स्थल ।

49. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ।
50. राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ।
51. चितरंजन राष्ट्रीय कैसर अनुसंधान केन्द्र ।
52. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ।
53. चिकित्सा और जैव-चिकित्सा अनुसंधान ।
54. अखिल भारतीय वाक्शक्ति और श्रवणशक्ति संस्थान ।
55. भारतीय पेस्चयुर संस्थान ।
56. भौतिक चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र, किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल ।
57. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिकाणी ज्ञान संस्थान ।
58. हॉस्पिटल सर्विसेज कन्सलटेन्सी कारपोरेशन लिमिटेड ।

ख. परिवार कल्याण विभाग

1. परिवार कल्याण के लिए नीति और संगठन ।
2. जनन और शिशु स्वास्थ्य ।
3. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार अंतर-क्षेत्रीय समन्वय ।
4. जनसंख्या स्थिरता कोष और सशक्त कार्रवाई ग्रुप से संबंधित मामले ।
5. परिवार कल्याण के सभी पहलुओं की बाबत, जिसके अंतर्गत विदेश में उच्चतर प्रशिक्षण भी है, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान का संगठन और निदेशन ।
6. परिवार नियोजन के लिए सहायक सामग्री का निर्माण और प्रदाय ।

7. परिवार कल्याण से संबंधित मामलों की बाबत विदेशी राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ संपर्क ।
8. विदेशी सहायता से चलाई जाने वाली परिवार कल्याण स्कीमें और परियोजनाएं ।
9. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई ।
10. जनसंख्या और परिवार कल्याण से संबंधित विकास और श्रव्य दृश्य सहायता का निर्माण विस्तारण शिक्षा और जानकारी ।
11. परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए लोक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना ।
12. हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरुवनंथपुरम ।
13. राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली ।
14. प्रसव-पूर्व निदान-तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) - गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का 64) का कार्यान्वयन ।

ग. आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी
(आयुष) विभाग

1. संघ कारबार

1. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धति के विकास और प्रचार के लिए नीति और नीतिगत मुद्दे बनाना ।
2. विकास और कार्यक्रमों का कियान्वयन, जिसमें आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धति के विकास और प्रचार के लिए केन्द्रीय स्कीमें और केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें भी हैं ।
3. अनुसंधान और विकास का समन्वय और संवर्धन, जिसके अंतर्गत आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धति के लिए सहायता भी है ।

4. आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धति से संबंधित अनुसंधान और विकास, शिक्षा और मानकों के लिए केन्द्रीय संस्थाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना ।
5. निम्नलिखित के संबंध में सभी मुद्दे और विषय, जिनकी बाबत सरकार के स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है:
- (क) भारतीय औषधि भेषज प्रयोगशाला, गाजियाबाद;
 - (ख) होम्योपैथिक भेषज प्रयोगशाला, गाजियाबाद;
 - (ग) भारतीय औषध केन्द्रीय परिषद;
 - (घ) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद;
 - (ङ.) आयुर्वेदिक भेषज समिति;
 - (च) होम्योपैथी भेषज समिति;
 - (छ) यूनानी भेषज समिति;
 - (ज) सिद्ध भेषज समिति;
 - (झ) आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड;
 - (ञ) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद;
 - (ट) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद;
 - (ठ) केन्द्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद;
 - (ड) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद;
 - (ढ) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान;
 - (ण) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान;
 - (त) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान;
 - (थ) राष्ट्रीय योग संस्थान;
 - (द) राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान;
 - (ध) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान;
 - (न) स्नातकोत्तर अध्यापन और अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय;
 - (प) इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड;
 - (फ) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ।
6. भारतीय चिकित्सा पद्धति के सभी पहलुओं में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान, जिसके अंतर्गत विदेश में उच्चतर प्रशिक्षण भी है ।
7. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम के भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के डाक्टरों, जिसके अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के केन्द्रीय अस्पताल के डाक्टर भी है, के संबंध में काडर संरचना और नियंत्रण के मामले, जिसके अंतर्गत भर्ती नियम बनाने और उनमें संशोधन, भर्ती, प्रोन्नति और सभी अन्य सेवा मामले भी है, जिनकी बाबत

सरकारी स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है ।

टिप्पणी: दिन-प्रतिदिन का प्रशासन और प्रबंध, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम के निदेशक के पास ही रहेगा ।

8. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी से संबंधित मामलों की बाबत विदेशी राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संपर्क ।
9. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी से संबंधित वैज्ञानिक सोसाइटियों/संगमों और पूर्ण तथा धार्मिक विन्यासों से संबंधित मामले ।
10. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी में औषध की क्वालिटी और मानकों से संबंधित ऐसे मामलों की बाबत उस सीमा तक जिनमें ऐसे मामलों में सरकारी स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है ।
11. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के कार्य और कार्यक्रमों के पुनर्विलोकन के लिए राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं से परामर्श तथा समन्वय करना ।
12. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के विभिन्न पहलुओं से संबंधित आंकड़े ।
13. संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित ऐसे प्रस्ताव और मामले जिनमें भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के बारे में भारत सरकार की मंजूरी और सहमति अपेक्षित है ।
14. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी से संबंधित प्रत्येक राज्य के विधायी प्रस्ताव जिनकी बाबत भारत सरकार की मंजूरी और सहमति अपेक्षित है ।
15. औषधीय पादप बोर्ड ।

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

क. भारी उद्योग विभाग

1. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड ।
2. माइनिंग एंड ऐलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड ।
3. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड ।

4. भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड ।
5. एच०एम०टी० बियरिंग लिमिटेड ।
6. एच०एम०टी० लिमिटेड ।
7. एच०एम०टी० इंटरनेशनल लिमिटेड ।
8. स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ।
9. एन्ड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड ।
10. भारत ऑप्टिकल ग्लास लिमिटेड ।
11. भारत लैडर कारपोरेशन ।
12. सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ।
13. साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ।
14. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड ।
15. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड ।
16. हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ।
17. हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड ।
18. हुगली प्रिंटिंग कम्पनी लिमिटेड ।
19. इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड ।
20. मांड्या नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड ।
21. नागालैंड पल्प एंड पेपर कम्पनी लिमिटेड ।
22. नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ।

23. नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ।
24. नेशनल इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड ।
25. एन0ई0पी0ए0 लिमिटेड ।
26. राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एंड इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड ।
27. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड ।
28. दामोदर सीमेंट एंड स्लैग लिमिटेड ।
29. टेनरी एंड फुटबियर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ।
30. टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया ।
31. प्राग टूल्स लिमिटेड ।
32. रिहोबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ।
33. सांभर साल्ट्स लिमिटेड ।
34. फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट ।
35. भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड :

समनुषंगी :

(क) भारत ब्रेक्स एंड वाल्वज लिमिटेड;

(ख) भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड;

(ग) भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड;

(घ) ब्रेथवेट एंड कम्पनी लिमिटेड;

- (ड.) बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड;
- (च) जेसप एंड कम्पनी लिमिटेड;
- (छ) दि लैगन जूट मशीनरी कम्पनी लिमिटेड;
- (ज) ब्रेथवेट, बर्न एंड जैसप कंस्ट्रक्शन लिमिटेड;
- (झ) रेरोल बर्न लिमिटेड;
- (ञ) वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड;

36. भारत यंत्र निगम लिमिटेड ।

समनुषंगी :

- (क) दि त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०, इलाहाबाद;
- (ख) दि तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, दुर्गापुर;
- (ग) दि भारत हेवी प्लेट्स एंड वैसल्स लिमिटेड;
- (घ) भारत पंप्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड;
- (ड.) रिचर्डसन एंड कूडास (1972) लिमिटेड;
- (च) ब्रिज एंड रूफ कंपनी ।

37. मारुति उद्योग लिमिटेड ।

38. सभी उद्योगों के लिए भारी इंजीनियरिंग उपस्कर का विनिर्माण ।

39. भारी विद्युत इंजीनियरी उद्योग ।

40. मशीनरी उद्योग जिसके अंतर्गत मशीनी औजार और इस्पात विनिर्माण भी है ।

41. आटो उद्योग, जिसके अंतर्गत ट्रैक्टर और मिट्टी हटाने वाले उपस्कर भी है ।

42. सभी प्रकार के डीजल इंजन ।

43. आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन, पुणे ।

ख. लोक उद्यम विभाग

1. लोक उद्यम ब्यूरो जिसके अंतर्गत औद्योगिक प्रबंध पूल भी है ।
2. सभी पब्लिक सेक्टर और वाणिज्यिक उपक्रमों को प्रभावित करने वाले गैर-वित्तीय प्रकृति के साधारण नीतिगत विषयों का समन्वय ।
3. पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के कार्य-निष्पादन में सुधार के समझौता ज्ञापन तंत्र से संबंधित मामले ।
4. पब्लिक सेक्टर उद्यमों के लिए स्थायी माध्यस्थ तंत्र से संबंधित मामले ।
5. स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के अधीन केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के कर्मचारियों को परामर्श, प्रशिक्षण व उनका पुनर्वास ।

गृह मंत्रालय

क. आंतरिक सुरक्षा विभाग

I. पुलिस

1. असम राइफल्स ।
2. सीमा सुरक्षा बल ।
3. भारत तिब्बत सीमा पुलिस ।
4. विशेष सेवा ब्यूरो ।
5. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी और केन्द्रीय खुफिया प्रशिक्षण स्कूल ।

6. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ।
7. आसूचना ब्यूरो ।
8. केन्द्रीय न्याय-विज्ञान प्रयोगशालाएं और पूछे गए दस्तावेजों के सरकारी परीक्षक ।
9. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ।
10. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।
11. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ।
12. भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित मामले ।
13. भारतीय पुलिस सेवा और अर्ध-सैनिक बलों के अधिकारियों का विदेश में प्रशिक्षण, जिसके अंतर्गत द्विपक्षीय सहयोग के अधीन आने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हैं ।
14. भारत में विदेशी पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण से संबंधित सभी मामले ।
15. नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड से संबंधित सभी मामले ।
16. अंतर्राष्ट्रियक पुलिस बेतार प्रणाली से संबंधित मामले ।
17. पुलिस पदकों से संबंधित मामले ।

II. कानून और व्यवस्था

18. आतंकवाद का मुकाबला करने से संबंधित मामले ।
19. अति विशिष्ट महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा, धमकी के मद्देनजर व्यक्तिगत सुरक्षा, महत्वपूर्ण सरकारी भवनों, आदि की सुरक्षा ।
20. आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 - लंबित मामले ।

21. आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984 (1984 का 61)– इस अधिनियम से संबंधित सभी मामले ।
22. रजिस्ट्रीकरण और देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता देना ।
23. आप्रवास ब्यूरो से संबंधित सभी मामले ।
24. अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के नागरिकों को भारत में प्रवेश के लिए वीजा देना, जिसके अंतर्गत भारत में दीर्घावधि तक ठहरना भी है, और सभी विदेशियों के भारत में प्रवेश/ठहरने का विनियमन ।
25. दूसरे देशों के नागरिकों का भारत से विवासन ।
26. भारत में कैद विदेशियों का संप्रत्यावर्तन, जिसके अंतर्गत भारतीय जल सीमा में पकड़े गए विदेशी मछुआरे भी हैं ।
27. सरकारी सेवक जिनके कुटुंब पाकिस्तान में है – सरकारी सेवकों को पाकिस्तान जाने की अनुज्ञा दिए जाने के मामले ।
28. संगमों और व्यक्तियों द्वारा विदेशी अंशदान की स्वीकृति और उपयोग तथा विदेशी आतिथ्य का विनियमन ।
29. केन्द्रीय सचिवालय सुरक्षा ।
30. सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 11 के अधीन भारत में अवांछनीय साहित्य लाने का निवारण ।
31. आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 (1981 का 40) ।
32. संविधान के अनुच्छेद 352 के खण्ड (1) के अधीन जारी की गई किसी उद्घोषणा के प्रवर्तन की अवधि के दौरान सरकारी सेवकों के किसी कर्तव्य के लिए सेवाओं की अध्यापेक्षा ।
33. किसी अन्य केन्द्रीय मंत्रालय अथवा विभाग को विनिर्दिष्टतया आबंटित विस्तार तक को छोड़कर, निवारक निरोध ।

34. व्यक्तियों, अभियुक्त व्यक्तियों तथा निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों को एक राज्य से दूसरे राज्य को हटाया जाना ।
35. दंड विधि ।
36. दंड प्रक्रिया ।
37. महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों, जिनके अंतर्गत वे भी हैं जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति (अत्याचार-निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) , में आते हैं, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और अन्य सहजभेद्य समूहों के प्रति दांडिक अपराध ।
38. नागालैण्ड राज्य से संबंधित मामले ।
39. सिक्किम राज्य से संबंधित मामले ।
40. रेल संपत्ति के मूषण से संबंधित अपराधों से भिन्न, रेलों में अपराधों से संबंधित संसदीय प्रश्न ।
41. शस्त्र, आग्नेयास्त्र और गोला बारूद से संबंधित मामले ।

III. पुनर्वास

42. (क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (ख) भारत-पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध के परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों, और (ग) जम्मू-कश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों से विस्थापित व्यक्तियों को राहत/उनके पुनर्वास से संबंधित अवशिष्ट कार्य ।
43. प्रत्यावर्तित भारतीय राष्ट्रियों को राहत और उनका पुनर्वास ।
44. तिब्बती शरणार्थियों की सहायता और पुनर्वास ।
45. श्रीलंका से आए शरणार्थियों के लिए राहत ।
46. दण्डकारण्य विकास योजना और दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण ।

47. भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजे और उनके पुनर्वास की व्यवस्था से संबंधित अवशिष्ट कार्य, जिसके अंतर्गत सरकार निर्मित संपत्तियों की बाबत पट्टा या हस्तांतरण-पत्र जारी करना और ऐसी संपत्तियों से लगी हुई भूमि की अतिरिक्त पट्टियों और सुधारक क्षेत्रों के पट्टाविलेखों का संपरिवर्तन करना और आबंटन से भिन्न जिन्हें शहरी विकास मंत्रालय को आबंटित किया गया है ।
48. समय-समय पर प्रधानमंत्री द्वारा निर्दिष्ट किए गए विशेष क्षेत्रों का विकास ।
49. भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों की निष्क्रांत संपत्ति और मुआवजे तथा उनके पुनर्वास के प्रशासन से संबंधित अधिनियमों का प्रशासन ।
50. भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई निष्क्रांत संपत्ति के संबंध में पाकिस्तान के साथ बातचीत ।
51. भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से प्राप्त दावा न की गई चल संपत्ति के निपटारे से संबंधित अवशिष्ट कार्य ।
52. प्राकृतिक आपदाओं (सूखा या महामारियों से भिन्न) और मानव निर्मित विपदाओं की दशा में राहत उपायों का समन्वय, जिसके अंतर्गत अन्य मंत्रालयों/विभागों को आबंटित कार्य की विशिष्ट मद नहीं है ।
53. सूखा या महामारियों से भिन्न सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के कारण मानव जीवन और संपत्ति को होने वाली हानि से संबंधित मामले ।
54. स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 4 (3) के उपबंधों के अधीन स्थापित स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, तथा स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार को रोकने तथा उसके प्रतिरोध करने के सभी उपायों के समन्वय से संबंधित सभी मामले ।
55. स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और पूर्वगामी रसायनों में अवैध व्यापार के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों, करारों, न्याचारों, आदि से संबंधित सभी मामले, जिनके लिए गृह मंत्रालय और उसके अधीन संगठन कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत है, केवल उन मामलों को छोड़कर जो वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग को आबंटित है ।
56. निम्नलिखित अधिनियमों का प्रशासन, अर्थात्:
 - (क) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19);

- (ख) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37);
- (ग) दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 1961 (1961 का 23);
- (घ) अल्पवय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम, 1956 (1956 का 93);
- (ङ.) पंजाब विशेष शक्ति (प्रेस) अधिनियम, 1956 (1956 का 38);
- (च) सशस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1958 (1958 का 28);
- (छ) आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम, 1980 (1980 का 41);
- (ज) अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 (1983 का 39);
- (झ) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6);
- (ञ) आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 (2002 का 15);
- (ट) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31);
- (ठ) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 (1920 का 34);
- (ड) विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 (1939 का 16);
- (ढ) आप्रवास (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000 (2000 का 52);
- (ण) नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57);
- (त) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49);

ख. राज्य विभाग

(I) केन्द्र-राज्य संबंध

1. नए राज्यों की स्थापना और उनका बनाया जाना: उनसे उद्भूत होने वाले विषय (ऐसे विषयों को छोड़कर, जिनका संबंध सेवा-कार्मिकों के आबंटन से है); सेवाओं का एकीकरण तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को आबंटित राज्य सेवाओं से संबंधित अन्य मामले तथा विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन ।
2. संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (22) में निर्दिष्ट भूतपूर्व भारतीय राज्यों के शासकों और उनके कुटुम्बों से संबंधित मामले ।
3. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों की बाबत संविधान के अनुच्छेद 371 के विशेष उपबंध ।
4. राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित अधिनियमों का प्रशासन ।

(II) अंतर्राज्यिक संबंध

5. अंतर्राज्यिक परिषद् ।
6. अंतर्राज्यिक प्रवास ।

(III) संघ राज्य क्षेत्र

7. विधान-मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र :

(क) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली ।

(i) संविधान के भाग VIII में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार संघ सरकार के कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी विषय वहां तक जहां तक कि ये राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 पर लागू है, सिवाय उन मामलों के जिनका संबंध राज्य सूची की प्रविष्टि 18 से है और सभी ऐसे मामलों के जो इन नियमों के अधीन भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग को विनिर्दिष्टतः सौंपे गए हैं ।

(ii) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार की सभी शक्तियां और कृत्य, सिवाय उन मामलों के जिनका संबंध भूमि और भवन उप विधियों से है ।

(ख) पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र:

संविधान के भाग VIII में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी विषय वहां तक जहां तक कि इनका संबंध पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 से है, सिवाय सभी ऐसे मामलों के जो भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग को विनिर्दिष्टतः सौंपे गए हैं ।

8. (क) संघ राज्य क्षेत्रों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए संविधान के अनुच्छेद 240 के अधीन विनियम बनाना ।

- (ख) राज्य अधिनियमों का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार ।
- (ग) विभिन्न अधिनियमितियों के अधीन राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को प्रत्यायोजन ।
- (घ) संघ राज्य क्षेत्रों में लोक सेवाओं से संबंधित साधारण प्रश्न और ऐसे सेवा मामले जहां तक ये निम्नलिखित से संबंधित राज्य सरकारों के कार्य-क्षेत्र के भीतर आते हैं :
- (i) संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यों से संबंधित सेवारत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी;
 - (ii) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली, अंडमान व निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली सिविल और पुलिस सेवाएं (दानिक्स और दानिप्स);
 - (iii) पांडिचेरी सिविल और पुलिस सेवाएं ।
- (ङ.) संघ राज्य क्षेत्रों में उपराज्यपालों और प्रशासकों की नियुक्ति ।

टिप्पणी: संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित उपर्युक्त सभी मामले, सिवाय उन मामलों के जो विनिर्दिष्टतः किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को आबंटित किए गए हैं ।

9. विधान मण्डल रहित संघ राज्य क्षेत्र :

राज्य सूची और समवर्ती सूची में प्रगणित सभी मामले जहां तक कोई ऐसा मामला संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू है, सिवाय सभी ऐसे मामलों के जिन्हें इन नियमों के अधीन भारत सरकार के किसी मंत्रालय अथवा विभाग को विनिर्दिष्टतः सौंपा गया है, जिसके अंतर्गत (क) अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों की बाबत मुख्य भूमि-द्वीप और अंतर-द्वीपीय पोत परिवहन सेवाओं का संगठन और अनुरक्षण; और (ख) अंडमान और निकोबार द्वीप की बाबत वन, शिक्षा, सड़क और उन पर पुल संकर्म और पारघाट भी आते हैं ।

(IV) अन्य विषय

10. स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन और अन्य प्रसुविधाएं ।

11. मानव अधिकार :

- (i) “मानव अधिकार” के मामलों के संबंध में, साधारण नीतियों के लिए नोडल अधिकरण के रूप में कार्य करना, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, या इस संबंध में कोई अन्य संस्थागत व्यवस्था भी है ।
- (ii) पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कर्मिकों द्वारा की गई अभिकथित ज्यादतियों से संबंधित मानव अधिकारों के अतिक्रमण ।
- (iii) देश के भीतर मानव अधिकार संगठनों और अन्य संबंधित संगठनों से पारस्परिक प्रभाव और विभिन्न विभागों और राज्य सरकारों से समन्वय ।
- (iv) मानव अधिकारों के संबंध में नीति का समन्वय ।

टिप्पण: गृह मंत्रालय मानव अधिकारों से संबंधित समग्र नीति के लिए नोडल मंत्रालय होगा । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य, महिलाएं, अल्पसंख्यक, बच्चे और बंधुआ मजदूर जैसे विशिष्ट समूहों के कल्याण और सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए मुख्य रूप से संबंधित विभाग इन विशिष्ट समूहों के मानव अधिकारों को सुरक्षित रखने के संबंध में उत्तरदायी होंगे ।

- 12. पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, राष्ट्रीय सिविल रक्षा महाविद्यालय और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय से संबंधित विषय ।
- 13. अग्निशमन सेवाओं का विकास ।
- 14. किसी राज्य से संबंधित पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का उस राज्य के बाहर किसी क्षेत्र पर विस्तार किन्तु इससे एक राज्य की पुलिस उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र में उसकी शक्तियों और अधिकारिता का प्रयोग उस राज्य सरकार जिसमें वह क्षेत्र स्थित है, की सहमति के बिना नहीं कर सकेगी; किसी राज्य के पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का राज्य के बाहर रेल क्षेत्रों पर विस्तार ।
- 15. पुलिस सुधार ।
- 16. कारागार सुधार ।

ग. राजभाषा विभाग

1. संविधान के राजभाषा से संबंधित उपबंधों और राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) के उपबंधों का कार्यान्वयन, वहां तक के सिवाए, जहां तक इस प्रकार का कार्यान्वयन किसी अन्य विभाग को सौंप दिया गया है ।
2. राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी भाषा का सीमित प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन ।
3. संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों, जिनमें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी शिक्षण योजनाएं भी शामिल हैं, के लिए नोडल उत्तरदायित्व ।
4. संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए प्रचार साहित्य का प्रकाशन और वितरण ।
5. संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों, जिनमें प्रशासनिक शब्दावली, पाठ्य विवरण, पाठ्य-पुस्तक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और उनके लिए अपेक्षित उपस्कर (मानकीकृत लिपि सहित) शामिल हैं, में समन्वय ।
6. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन और संवर्ग प्रबंध ।
7. केन्द्रीय हिन्दी समिति, जिसमें इसकी उपसमितियां भी शामिल हैं, से संबंधित मामले ।
8. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्थापित हिन्दी सलाहकार समिति से संबंधित कार्य का समन्वय ।
9. केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित मामले ।

घ. गृह विभाग

1. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की अधिसूचना तथा राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह ।
2. मृत्यु दण्डादेश के संबंध में क्षमा, प्रविलम्बन, निलम्बन, परिहार या लघुकरण और जिस विषय पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है उससे संबंधी किसी विधि के विरुद्ध

अपराधों के लिए राज्यों के न्यायालयों द्वारा दण्डादिष्ट बंदियों से दण्डादेश के परिहार (मृत्यु से भिन्न) के लिए या क्षमा के लिए प्राप्त अर्जियां ।

3. प्रधानमंत्री और संघ के अन्य मंत्रियों और संसदीय सचिवों की नियुक्ति और पदत्याग की अधिसूचनाएं निकालना ।
4. राष्ट्रपति के नाम से कागज-पत्रों के अधिप्रमाणीकरण के लिए नियम ।
5. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए कामकाज संबंधी मानक नियम ।
6. राज्य सभा और लोक सभा के लिए नाम-निर्देशन ।
7. राज्यपालों की नियुक्ति, पदत्याग और हटाया जाना तथा संबंधित मामले ।
8. राज्यपालों द्वारा बनाए गए विनियम, जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित किए गए हों ।
9. (जम्मू-कश्मीर के सिवाय) राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा पारित विधेयक, जो राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किए गए हों; और राज्य विधान की बाबत राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार से पूर्व परामर्श ।
10. राज्यों के राज्यपालों द्वारा निकाले गए अध्यादेशों के प्रख्यापन के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन ।
11. राजगामी, व्यपगत या स्वामिहीनत्व होने से संघ प्रोद्भूत संपत्ति ।
12. किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त अनुपात द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध ।
13. संविधान के (वित्तीय आपात से संबद्ध मामलों से भिन्न) आपात-उपबंधों से संबद्ध मामले ।
14. न्यायिक मामलों में अन्य देशों के साथ हुए अभिसमय, जिनके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संबंधी प्रश्न और अश्लील प्रकाशनों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त निदेश व्यवहार आते हैं ।
15. विधायकों के लिए आचरण-संहिता से संबंधित मामले ।

16. मंत्रियों के लिए आचरण-संहिता ।
17. सरकारी सेवकों की पत्नियों या आश्रितों का भारत में विदेशी मिशनों में नियोजन ।
18. सिविल और सैनिक अधिकारियों का परस्पर आना-जाना ।
19. भारत सरकार या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा संगठित लाट्रियां ।
20. जनगणना, जिसके अंतर्गत जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) तथा जनगणना (संशोधन) अधिनियम, 1993 (1994 का 11) का प्रशासन भी है ।
21. शासकीय पोशाक ।
22. राष्ट्रपति और राज्यपालों की उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार और अनुपस्थिति छुट्टी विषयक अधिकार; संघ के मंत्रियों, उप-मंत्रियों और संसदीय सचिवों के वेतन और भत्ते ।
23. राष्ट्रगान ।
24. भारत का राष्ट्रीय ध्वज; राष्ट्रपति की और राज्यपाल की ध्वजाएं ।
25. राज्य संप्रतीक ।
26. अग्रता अधिपत्र ।
27. पुरस्कार और अलंकरण ।
28. राष्ट्रीय त्यौहार ।
29. राष्ट्रीय एकीकरण और सांप्रदायिक सौहार्द से संबंधित मामले ।
30. भौगोलिक नामों में परिवर्तन ।
31. उच्च पदस्थ अधिकारियों की मृत्यु पर की जाने वाली कार्रवाई ।
32. राजनीतिक पेशने ।
33. गदर के वीरों के आश्रितों को अनुकम्पा भत्ता ।

34. गृह मंत्री की वैवेकिक निधि ।
35. विष ।
36. जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) का प्रशासन भी है ।
37. समाचार-पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय ।
38. निम्नलिखित का प्रशासन :
 - (क) जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) - विधायी पक्ष,
 - (ख) राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (1971 का 69),
 - (ग) धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 (1988 का 41) ।
 - (घ) उपासना-स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 (1991 का 42) ।
 - (ङ.) अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम, 1993 (1993 का 33)।

ड. जम्मू-कश्मीर कार्य विभाग

1. जम्मू-कश्मीर राज्य की बाबत सांविधानिक उपबंध ।
2. जम्मू-कश्मीर राज्य से संबंधित सभी विषय, जिनके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रति आतंकवाद और किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को विनिर्दिष्टतः आबंटित विषयों/मामलों की बाबत समन्वय जैसा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य नियंत्रण रेखा पर तैनाती और प्रबंध के विषयक रक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय, परन्तु इसके अंतर्गत वे मामले नहीं हैं जिनका संबंध विदेश मंत्रालय से है ।
3. सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1990 (1990 का 21) का प्रशासन ।

टिप्पणी: जम्मू-कश्मीर कार्य विभाग विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय करेगा, मुख्य रूप से जिनका संबंध जम्मू-कश्मीर में विकास और कल्याण कार्यक्रमों से है, संबंधित मंत्रालय/विभाग उनको आबंटित विषयों की बाबत जिम्मेदार होंगे ।

च. सीमा प्रबंध विभाग

1. अंतर्राष्ट्रीय भूमि और तटीय सीमाओं का प्रबंध, उन विषयों के सिवाय जिन्हें रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को विनिर्दिष्टतः आबंटित किया गया है ।

2. इस सूची में निर्दिष्ट विषयों की बाबत राज्य सरकारों और भारत सरकार के अन्य विभागों के साथ समन्वय ।
3. सीमा पुलिस और सुरक्षा को सुदृढ़ करना ।
4. रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के समन्वय से सड़कों जैसी अवसंरचना का सृजन; सीमाओं पर बाड़ लगाना और परिप्रदीप्ति ।
5. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत -उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास विभाग को विनिर्दिष्ट: आबंटित विषय नहीं आते हैं ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

क. प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग

1. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा ।
2. प्रारंभिक शिक्षा ।
3. बुनियादी शिक्षा ।
4. बालभवन, बालचर संग्रहालय ।
5. सामाजिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा ।
6. इस सूची में प्रविष्टियों के संदर्भ में श्रव्य एवं दृश्य शिक्षा ।
7. इस सूची में मदों के बाबत पुस्तकें (उन पुस्तकों से भिन्न, जिनसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय का संबंध है) और पुस्तक विकास (लेखन-कागज और अखबारी कागज उद्योग, जिससे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संबंध है, को छोड़कर) ।
8. इस सूची में मदों के बाबत शैक्षिक अनुसंधान ।
9. इस सूची की मदों के संदर्भ में प्रकाशन, सूचना और आंकड़े ।

10. इस सूची की मदों के संदर्भ में शिक्षकों को प्रशिक्षण ।
11. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ।
12. इस विभाग द्वारा व्यवहृत विषयों से संबंधित पूर्त और पूर्त संस्थाएं, पूर्त व धार्मिक विन्यास।

ख. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग

1. माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक मार्गदर्शन ।
2. विश्वविद्यालय शिक्षा; केन्द्रीय विश्व विद्यालय; ग्रामीण उच्चतर शिक्षा; उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा; स्कूल शिक्षा की योजना और विकास से संबंधित विदेशी सहायता कार्यक्रम ।
3. उच्चतर विद्या (विश्वविद्यालय से भिन्न) की संस्थाएं ।
4. इस सूची में मदों के बाबत पुस्तकें (उन पुस्तकों से भिन्न, जिनसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय का संबंध है) और पुस्तक विकास (लेखन-कागज और अखबारी कागज उद्योग, जिससे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संबंध है, को छोड़कर) ।
5. इस सूची की मदों के संदर्भ में श्रव्य एवं दृश्य शिक्षा ।
6. प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य-पुस्तकें तैयार करना ।
7. प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) और प्रतिलिप्याधिकार विषयक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन ।
8. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वि०बो०सं०सं०) से संबंधित नोडल उत्तरदायित्व ।
9. शैक्षिक अनुसंधान ।
10. प्रकाशन, सूचना और सांख्यिकी ।
11. इस सूची की मदों के संदर्भ में शिक्षकों प्रशिक्षण ।
12. बहुभाषीय शब्दकोषों सहित हिन्दी का विकास और प्रसार ।

13. हिन्दी के शिक्षण और संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता देना ।
14. संस्कृत का प्रचार और विकास ।
15. विस्थापित अध्यापकों और विद्यार्थियों के पुनर्वास की तथा अन्य समस्याएं ।
16. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ।
17. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संघ (युनेस्को) और युनेस्को के सहयोगार्थ भारतीय राष्ट्रीय आयोग ।
18. इस विभाग में व्यवहृत विषयों में वे सभी छात्रवृत्तियों, जिनके अंतर्गत वे छात्रवृत्तियां भी हैं जो विदेशी राष्ट्रों और विदेशी अभिकरणों द्वारा प्रदान की जाती हैं, से संबंधित विषय, किन्तु इनमें उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों, अनअधिसूचित यायावर और अर्धयायावर जन-जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां और विदेशी विद्यार्थियों के लिए साधारण छात्रवृत्ति योजनाएं और छात्रवृत्तियां तथा विभिन्न योजनाएं नहीं हैं ।
19. विदेशस्थ भारतीय विद्यार्थियों की शिक्षा और कल्याण; विदेशस्थ भारतीय मिशनो के शिक्षा विभाग; विदेशस्थ शिक्षा संस्थाओं और भारतीय विद्यार्थी संगमों को वित्तीय सहायता ।
20. शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम; अध्यापकों, आचार्यों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, आदि का आदान-प्रदान; भारत और विदेशों के बीच विद्योपासकों के आदान-प्रदान का कार्यक्रम ।
21. विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों को विदेशों में नियुक्ति स्वीकार करने की अनुमति प्रदान करना ।
22. भारतीय संस्थाओं में विदेशी विद्यार्थियों का प्रवेश ।
23. पूर्त और पूर्त-संस्थाएं, इस विभाग में व्यवहृत विषयों के संबंध में पूर्त और धार्मिक विन्यास ।
24. विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं में उच्चतर गणित, न्यूक्लीय विज्ञान और परमाणु ऊर्जा में अनुसंधान से भिन्न, तदर्थ वैज्ञानिक अनुसंधान ।
25. विज्ञान मंदिर ।

26. गणित, न्यूक्लीय विज्ञान और परमाणु ऊर्जा से भिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले वैज्ञानिकों को आंशिक वित्तीय सहायता के बारे में साधारण नीति ।
27. तकनीकी शिक्षा का विस्तार, विकास और समन्वय ।
28. योजना और स्थापत्य स्कूल ।
29. प्रादेशिक मुद्रण स्कूल ।
30. तकनीकी शिक्षा के लिए राज्य सरकारों की संस्थाओं, गैर-सरकारी संस्थाओं, संघ राज्य क्षेत्रों के वृत्तिक निकायों और तकनीकी संस्थाओं को सहायता अनुदान । बुनियादी विज्ञानों में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए सहायता अनुदान; शैक्षिक संस्थाओं में उच्चतर वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय शिक्षा के विकास और अनुसंधान के लिए सहायता अनुदान; विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मूल अनुसंधान के लिए सहायता अनुदान; मूल अनुसंधान के लिए व्यक्तियों को अनुदान ।
31. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय डिप्लोमा और राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र परीक्षाएं संचालित करना भी है ।
32. इंजीनियरी और प्रौद्योगिकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधाएं ।
33. भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर भर्ती के प्रयोजन के लिए वृत्तिक तकनीकी अर्हता की मान्यता ।
34. राष्ट्रीय अनुसंधान आचार्य पद और अध्येतावृत्ति ।
35. भारत में वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों में विदेशी परीक्षा का आयोजन ।
36. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ।
37. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ।
38. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ।
39. भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद ।

40. भारतीय खान तथा अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान स्कूल, धनबाद ।
41. खड़गपुर, मुंबई, कानपुर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहटी और रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ।
42. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर ।
43. टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुंबई ।
44. भारत में और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी गृह ।
45. आधुनिक भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए योजनाएं ।

ग. महिला और बाल विकास विभाग

1. परिवार कल्याण ।
2. महिला और बाल कल्याण और इस विषय के संबंध में अन्य मंत्रालयों और संगठनों के कार्यकलापों का समन्वय ।
3. महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त संदर्भ ।
4. विद्यालय प्रवेश से पूर्व के शिशुओं की देखभाल ।
5. राष्ट्रीय पोषण नीति, पोषण और राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना ।
6. इस विभाग को आबंटित विषयों से संबंधित पूर्त और धार्मिक विन्यास ।
7. इस विभाग को आबंटित विषयों के संबंध में स्वैच्छिक उद्यम का संवर्धन और विकास ।
8. निम्नलिखित का कार्यान्वयन :

- (क) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1986 तक यथासंशोधित);
- (ख) स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 (1986 का 60);
- (ग) दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (1986 तक यथासंशोधित);
- (घ) सती (निवारण), अधिनियम, 1987 (1988 का 3)।

इन अधिनियमों के अधीन अपराधों के संबंध में दंडिक न्याय का प्रशासन नहीं है ।

9. शिशु दुग्ध प्रतिस्थानी, पिलाने की बोतल और शिशु आहार (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 41) का कार्यान्वयन ।
10. कोआपरेटिव फार असिसटेंट्स एण्ड रिलीफ एवरीवेयर (केयर) के क्रियाकलापों का समन्वय ।
11. महिलाओं और बच्चों के, जिसके अंतर्गत लिंग संवेदन आंकड़े आधार का विकास भी है, कल्याण और विकास से संबंधित योजना, अनुसंधान, मूल्यांकन, मानिटर करना, परियोजना बनाना, आंकड़े और प्रशिक्षण ।
12. संयुक्त राष्ट्र संघ बाल निधि (यूनिसेफ) ।
13. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (के0स0क0बो0) ।
14. राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान (एन0आई0पी0सी0सी0डी0) ।
15. खाद्य और पोषण बोर्ड ।
16. (i) समनुषंगी और संरक्षित खाद्य पदार्थों का विकास और उन्हें लोकप्रिय बनाना ।
(ii) पोषण का विस्तार ।
17. महिला सशक्तिकरण और लिंग समानता ।
18. राष्ट्रीय महिला आयोग ।
19. राष्ट्रीय महिला कोष ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

I. प्रसारण नीति और प्रशासन

1. संघ के भीतर रेडियो और टेलीविजन से प्रसारण संबंधी समस्त मामले, जिसमें लोक सभा और विधान सभा के निर्वाचनों के समय मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन के उपयोग का विनियमन तथा किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति की

मृत्यु पर राष्ट्रीय शोक की अवधि के दौरान सरकारी इलैक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया भी सम्मिलित है ।

2. प्राइवेट भारतीय कंपनियों या भारतीय राष्ट्रियों द्वारा भारत में रेडियो और टेलीविजन प्रसारण से संबंधित विधि का प्रारंभ और क्रियान्वयन ।
3. प्रसारण की मानीटरी तथा प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) ।
4. भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा तथा भारतीय प्रसारण (इंजीनियरी) सेवा से संबंधित सभी मामले, जब तक कि उन्हें प्रसार भारती को नहीं सौंपा जाता ।

II. केबल दूरदर्शन नीति

5. केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) ।

III. रेडियो

6. आकाशवाणी से संबंधित सभी कारबार, जिसमें घरेलू कार्यक्रम, विदेशी राष्ट्रों और विदेशस्थ भारतीयों के लिए कार्यक्रम, रेडियो पत्रिकाओं, प्रसारण इंजीनियरी के क्षेत्र में अनुसंधान, विदेशी प्रसारण को मानीटर करने, कार्यक्रम आदान-प्रदान और प्रतिलेखन सेवा, सामुदायिक श्रवण स्कीम, आदि के अधीन राज्य सरकारों को सामुदायिक रिसीविंग सेटों के प्रदाय में समाचार सेवा समाविष्ट है ।
7. संपूर्ण संघ में रेडियो प्रसारण का विकास, रेडियो स्टेशनों और ट्रांसमीटरों का संस्थापन और अनुरक्षण तथा प्रसारण सेवा का प्रचालन ।

IV. दूरदर्शन

8. आदान-प्रदान, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन कार्यक्रमों का सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी है ।
9. संपूर्ण संघ में दूरदर्शन का विकास, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों और ट्रांसमीटरों का संस्थापन, अनुरक्षण और प्रचालन तथा दूरदर्शन सेवाओं का प्रचालन भी है ।
10. दूरदर्शन से बाहर दूरदर्शन कार्यक्रमों के निर्माण का संवर्धन ।

V. फिल्में

11. संघ सूचो की प्रविष्टि 60 के अधीन विधान, अर्थात् 'प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों की मंजूरी' ।
12. चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) का प्रशासन ।
13. नाट्यशाला और नाट्यशालेतर फिल्में देखने के लिए फीचर तथा लघु फिल्मों का आयात ।
14. फीचर और लघु, दोनों भारतीय फिल्मों का निर्यात ।
15. फिल्म उद्योग द्वारा अपेक्षित अनुदूभाषित चलचित्र फिल्म और विविध प्रकार के उपस्करों का आयात ।
16. फिल्म उद्योग से संबंधित सभी मामले, जिसके अंतर्गत उससे संबंधित विकास और संवर्धन कार्यकलाप भी है ।
17. भारत में निर्मित फिल्मों के लिए राज्य पुरस्कारों की स्थापना करके तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड की सहायता से अच्छे सिनेमा का संवर्धन ।
18. अंतर्देशीय और विदेश में प्रचार के लिए वृत्त चित्रों और समाचार-चित्रों तथा अन्य फिल्मों और फिल्म-स्ट्रिप्स का निर्माण और वितरण ।
19. फिल्म तथा फिल्म से संबंधित सामग्रियों का परिरक्षण ।
20. भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का आयोजन तथा विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में भारत की भागीदारी ।
21. सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अंतर्गत फिल्मोत्सवों का आयोजन ।
22. फिल्म सोसायटी आंदोलन ।

VI. विज्ञापन और दृश्य प्रचार

23. भारत सरकार की ओर से विज्ञापनों का निर्माण और प्रकाशन ।

VII. प्रेस

24. भारत सरकार की नीतियों और क्रियाकलापों का प्रेस के माध्यम से निरूपण और निर्वचन ।
25. प्रेस से संबंधित सूचना समस्याओं पर सरकार को सलाह देना, प्रेस में यथा परावर्तित लोकमत की प्रमुख प्रवृत्तियों से सरकार को अवगत कराना तथा सरकार और प्रेस के बीच संपर्क स्थापित करना ।
26. सशस्त्र बलों का और उनके लिए प्रचार ।
27. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 95 और 96 के प्रशासन को छोड़कर, प्रेस के साथ सरकार के संबंधों का साधारण संचालन ।
28. प्रेस तथा पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) का समाचारपत्रों से संबद्ध प्रशासन ।
29. प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) का प्रशासन ।
30. समाचार-पत्रों को अखबारी कागज का वितरण ।

VIII. प्रकाशन

31. देश की तथा विदेशों की साधारण जनता को भारत के संबंध में अद्यतन और ठीक-ठीक जानकारी कराने की दृष्टि से, अंतर्देशीय तथा विदेश प्रचार के राष्ट्रीय महत्त्व के मामलों पर लोकप्रिय पुस्तिकाओं, पुस्तकों तथा जर्नलों का निर्माण, विक्रय तथा वितरण ।

IX. अनुसंधान और संदर्भ

32. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सूचना माध्यम एकाकों को हर उस सामग्री के संग्रहण, संकलन और तैयारी में सहायता करना जिसमें प्रकाशित कृतियों, आदि में अनुसंधान करना अंतर्गस्त है ।
33. मंत्रालय के सूचना माध्यम एकाकों के प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर ज्ञान का सार संग्रहण तैयार करना और सामयिक तथा अन्य विषयों पर मार्गदर्शन तथा पृष्ठभूमि टिप्पण तैयार करना ।

X. प्रकीर्ण

34. भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार ।
35. पत्रकार कल्याण निधि का प्रशासन ।
36. गायक और वादक, दोनों प्रकार, के प्रसिद्ध संगीतज्ञों को, नर्तक नर्तकियों को और नाटककारों को, जिन्होंने, आकाशवाणी और इस मंत्रालय के अन्य एकांकों की सफलता में सारभूत योगदान दिया है, या निर्धनावस्था वाले उनके उत्तरजीवियों को वित्तीय सहायता ।
37. एशियाई पैसिफिक प्रसारण यूनियन, राष्ट्रकुल प्रसारण एसोसिएशन और गुट-निरपेक्ष समाचार अभिकरण पूल से संबंधित सभी मामले ।
38. भारतीय सूचना सेवा (समूह 'क' और 'ख') का काडर प्रबंध ।

XI. संलग्न और अधीनस्थ संगठन

39. (क) आकाशवाणी;
- (ख) दूरदर्शन;
- (ग) प्रेस सूचना ब्यूरो;
- (घ) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय;
- (ङ.) प्रकाशन प्रभाग;
- (च) भारत के समाचार-पत्र रजिस्ट्रार का कार्यालय;
- (छ) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड;
- (ज) फिल्म प्रभाग;
- (झ) फिल्मोत्सव निदेशालय;
- (ञ) भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार;
- (ट) क्षेत्र प्रचार निदेशालय;
- (ठ) गीत और नाट्य प्रभाग;
- (ड) अनुसंधान, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग;
- (ढ) फोटो प्रभाग;
- (ण) प्रधान लेखा कार्यालय;
- (त) केन्द्रीय मानीटरी सेवा ।

XII. स्वायत्त संगठन

40. (क) भारतीय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान, पुणे;
- (ख) सत्यजीत रे फिल्म और दूरदर्शन संस्थान, कोलकाता;
- (ग) भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी;
- (घ) भारतीय जनसंपर्क संस्थान;
- (ङ.) भारतीय प्रेस परिषद्;
- (च) भारतीय फिल्म सोसाइटी परिसंघ ।

XIII. पब्लिक सेक्टर उपक्रम

41. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड ।
42. प्रसारण इंजीनियर्स परामर्शी (भारत) लिमिटेड ।

श्रम मंत्रालय

भाग I संघ विषय

1. संघ रेलों की बाबत-मजदूरी संदाय, व्यवसाय-विवाद, कारखाना अधिनियम के अंतर्गत न आने वाले कर्मचारियों के लिए काम के घंटे और बालकों के नियोजन का विनियमन ।
2. डॉक की बाबत-डॉक श्रम से संबंधित सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपायों का विनियमन ।
3. खानों और तेल-क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन ।

भाग II समवर्ती विषय

4. कारखाने ।
5. श्रम-कल्याण - श्रम की औद्योगिक, वाणिज्यिक और कृषि संबंधी दशायें; भविष्य निधियां, कुटुम्ब पेंशन, उपदान, नियोक्ता का दायित्व और कर्मकार प्रतिकर; स्वास्थ्य और रोग बीमा, जिसमें अशक्तता पेंशने, वार्धक्य पेंशने, कारखानों में कार्य दशाओं का सुधार सम्मिलित है; औद्योगिक उपक्रमों में कैंटीने ।

6. बेकारी बीमा ।
7. व्यवसाय संघ; उद्योग और श्रम संबंधी विवाद ।
8. श्रम संबंधी आंकड़े ।
9. ग्रामीण रोजगार और बेरोजगारी के सिवाय, रोजगार और बेरोजगारी ।
10. शिल्पकारों का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण ।

भाग- III हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा राज्यों और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए अतिरिक्त कार्य ।

11. उपर्युक्त भाग II में वर्णित मदें ।

भाग IV उपर्युक्त भाग I, II और III में वर्णित मामलों में से किसी के संबंध में आनुषंगिक कार्य ।

12. अन्य देशों से की गई संधियों और करारों का कार्यान्वयन ।
13. केन्द्रीय सरकार के सभी औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां ।

भाग V प्रकीर्ण कार्य

14. रोजगार कार्यालय ।
15. भारत में और विदेशों में दोनों जगह, पर्यवेक्षीय स्तर पर शिक्षकों, शिल्पकारों, तकनीशियनों और फोरमेन के प्रशिक्षण के लिए स्कीमें, शिक्षु प्रशिक्षण ।
16. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ।
17. त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन ।
18. युद्ध क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1943 (1943 का 23) और स्कीम ।

19. कोयला खानों से भिन्न, खानों में सुरक्षा और कल्याण से संबंधित विधियों का; और खान और अभ्रक खान कल्याण के मुख्य निरीक्षक के संगठनों का प्रशासन ।
20. भारतीय डॉक श्रमिक अधिनियम, 1934 और तद्धीन बनाए गए विनियम और डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) के अधीन निर्मित डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) स्कीम, 1961 का प्रशासन ।
21. चाय जिला उत्प्रवासी श्रम (निरसन) अधिनियम, 1970 (1970 का 50) और उत्प्रवासी श्रम नियंत्रक के संगठन का प्रशासन ।
22. उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) के अंतर्गत भारत से विदेशों को सभी उत्प्रवास और उत्प्रवासियों की वापसी ।
23. न्यूनतम मजूदरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) का प्रशासन ।
24. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34), कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) तथा उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) का प्रशासन ।
25. केन्द्रीय क्षेत्र के उपक्रमों में श्रम विषयक विधियों का प्रशासन ।
26. श्रम संबंधी आंकड़े; श्रम ब्यूरो के निदेशक का संगठन ।
27. मुख्य श्रम आयुक्त का संगठन और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, केन्द्रीय सरकार श्रम न्यायालयों, राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का गठन और प्रशासन ।
28. कारखानों के मुख्य सलाहकार का संगठन, कर्मचारिवृन्द प्रशिक्षण प्रभाग, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय श्रम संस्थान, उत्पादकता और उद्योग केन्द्रों के भीतर उत्पादकता और प्रशिक्षण तथा सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के प्रादेशिक संग्रहालय भी हैं ।
29. बागान श्रमिक और बागान श्रम अधिनियम, 1951 (1951 का 69) का प्रशासन ।
30. केन्द्रीय सरकार के श्रम अधिकारियों की भर्ती, तैनाती, स्थानांतरण और प्रशिक्षण ।
31. श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) का प्रशासन ।

32. कर्मकारों की शिक्षा संबंधी स्कीमें ।
33. प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के संबंध में स्कीमें ।
34. उद्योग में अनुशासन ।
35. अलग-अलग उद्योगों के लिए मजदूरी बोर्डों का गठन ।
36. मोटर परिवहन कर्मकारों के काम की दशाओं का विनियमन ।
37. देश में श्रम विषयक विधियों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन ।
38. सिनेमा कर्मकारों और सिनेमा थियेटर कर्मकारों के काम की दशाओं और उनके कल्याण से संबंधित विधियों का प्रशासन ।
39. प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खानों और कारखानों के लिए), राष्ट्रीय विश्वकर्मा पुरस्कार ।
40. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) और भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28) ।
41. बिक्की संवर्धन कर्मचारी (सेवा-शर्त) अधिनियम, 1976 (1976 का 11) ।

विधि और न्याय मंत्रालय

क. विधि कार्य विभाग

1. विधिक मामलों पर मंत्रालयों को सलाह देना, जिसके अंतर्गत संविधान और विधियों का निर्वचन, हस्तांतरण लेखन, और उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में, जहां भारत संघ एक पक्षकार है, भारत संघ की ओर से उपसंजात होने के लिए काउंसिल का नियोजन भी है ।
2. भारत का महान्यायवादी, भारत का महासालिसिटर तथा राज्यों के केन्द्रीय सरकार के ऐसे अन्य विधि अधिकारी, जिनकी सेवाओं का उपयोग भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा मिल-बांट कर किया जाता है ।

3. केन्द्रीय सरकार की ओर से और केन्द्रीय अधिकरण स्कीम में भाग लेने वाले राज्यों की सरकारों की ओर से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन ।
 4. सिविल वादों में सम्मनों की तामील, सिविल न्यायालयों की डिक्कियों के निष्पादन, भरण-पोषण आदेशों के प्रवर्तन, और भारत में निर्वसीयत मरने वाले विदेशियों की सम्पदाओं के प्रशासन के लिए विदेशों के साथ व्यक्तिकारी व्यवस्था ।
 5. संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अधीन राष्ट्रपति की ओर से संविदाओं और आश्वासनों और संपत्ति-संबंधी हस्तांतरण पत्रों के निष्पादन के लिए अधिकारियों का प्राधिकृत किया जाना और केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वादों में वाद-पत्रों या लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने और उनका सत्यापन करने के लिए अधिकारियों का प्राधिकृत किया जाना ।
 6. भारतीय विधि सेवा ।
 7. सिविल विधि के मामलों में विदेशों के साथ संधियां और करार ।
 8. विधि आयोग ।
 9. विधिक वृत्ति, जिसके अंतर्गत अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) और उच्च न्यायालयों के समक्ष विधि व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति भी है ।
 10. उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता का परिवर्धन और उसको अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करना; उच्चतम न्यायालय के समक्ष विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार व्यक्ति; भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश ।
 11. नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) का प्रशासन ।
 12. आय-कर अपील अधिकरण ।
 13. विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण ।
 14. निर्धनों के लिए विधिक सहायता ।
- ख. विधायी विभाग

1. विधेयकों का प्रारूपण, जिसके अंतर्गत प्रवर समितियों में प्रारूपकारों का कार्य भी है, अध्यादेशों और विनियमों का प्रारूपण और प्रख्यापन; जब भी अपेक्षित हो राज्य अधिनियमों

की राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में अधिनियमिति; कानूनी नियमों और आदेशों की समीक्षा ।

2. संविधान आदेश; संविधान (संशोधन) अधिनियमों को प्रवृत्त करने के लिए अधिसूचनाएं ।
3. (क) केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का प्रकाशन;
(ख) राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5(1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों और उप विधियों के प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन ।
4. अनिरसित केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और साधारण कानूनी नियमों और आदेशों के विनियमों का संकलन और प्रकाशन तथा अन्य समरूप प्रकाशन ।
5. संसद, राज्यों के विधान-मंडलों, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन; तथा निर्वाचन आयोग ।
6. यथासंभव, सभी राजभाषाओं में प्रयोग के लिए, मानक विधि शब्दावली तैयार करना तथा उसका प्रकाशन ।
7. सभी केन्द्रीय अधिनियमों और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों तथा उनके द्वारा बनाये गये सभी विनियमों और ऐसे अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये सभी नियमों, विनियमों और आदेशों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ तैयार करना ।
8. केन्द्रीय अधिनियमों और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों तथा उनके द्वारा बनाए गए विनियमों का राज्यों की राजभाषाओं में अनुवाद करने और सभी राज्य अधिनियमों और अध्यादेशों का, यदि ऐसे अधिनियम अथवा अध्यादेश हिन्दी से भिन्न किसी अन्य भाषा में हो, हिन्दी अनुवाद करने की व्यवस्था करना ।
9. विधि-पुस्तकों और विधि-पत्रिकाओं का हिन्दी में प्रकाशन ।
निम्नलिखित विषय, जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-III के अंतर्गत आते हैं (केवल विधान की बाबत):
10. विवाह और विवाह-विच्छेद; शिशु और अवयस्क; दत्तकग्रहण; विल; इच्छापत्र हीनता और उत्तराधिकार, अविभक्त कुटुम्ब और विभाजन ।

11. कृषि भूमि (जिसके अंतर्गत बेनामी संव्यवहार, विलेखों और दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण नहीं है) से भिन्न, संपत्ति का अन्तरण ।
12. संविदाये, किन्तु इनके अंतर्गत कृषि भूमि संबंधी संविदाये नहीं आती है ।
13. अनुयोज्य दोष ।
14. दिवाला और शोधन अक्षमता ।
15. न्यास और न्यासी, प्रशासक, साधारण और शासकीय न्यासी ।
16. साक्ष्य और शपथ ।
17. सिविल प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत परिसीमा और माध्यस्थम भी है ।
18. पूर्त और धार्मिक विन्यास तथा धार्मिक संस्थाएं ।

ग. न्याय विभाग

1. भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदत्याग और उनका हटाया जाना; उनके वेतन, अनुपस्थिति छुट्टी विषयक अधिकार (जिसके अंतर्गत छुट्टी के भत्ते हैं), पेंशने और यात्रा भत्ते ।
2. राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदत्याग और उनका हटाया जाना, आदि, उनके वेतन, अनुपस्थिति छुट्टी विषयक अधिकार (जिसके अंतर्गत छुट्टी भत्ते हैं), पेंशने और यात्रा भत्ते ।
3. संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक आयुक्तों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति ।
4. उच्चतम न्यायालय का गठन और संगठन (जिसके अंतर्गत अधिकारिता और शक्तियां नहीं आती, किन्तु ऐसे न्यायालयों का अवमान आता है) और उसमें ली जाने वाली फीसें ।
5. उच्च न्यायालयों और न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों से संबद्ध उपबंधों के सिवाय, इन न्यायालयों का गठन और संगठन ।
6. संघ राज्य क्षेत्रों में न्याय का प्रशासन और न्यायालयों का गठन और संगठन तथा ऐसे न्यायालयों में ली जाने वाली फीसें ।

7. संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालय फीस और स्टाम्प शुल्क ।
8. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन ।
9. संघ राज्य क्षेत्रों में जिला जजों तथा वहां की उच्चतर न्यायिक सेवा के अन्य सदस्यों की सेवा-शर्तें ।
10. किसी संघ राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार या किसी संघ राज्य क्षेत्र का किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता से अपवर्जन ।

खान मंत्रालय

1. (क) भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर खानों के विनियमन और खनिजों के विकास के लिए विधान, जिसके अंतर्गत राज्यक्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि या भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, के भीतर समुद्र अधःशायी खाने और खनिज भी है ।
- (ख) कोयला, लिग्नाइट और भरणार्थ बालू तथा संघ के नियंत्रणाधीन विधि द्वारा यथाघोषित परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के प्रयोजन के लिए विहित पदार्थों के रूप में घोषित कोई खनिज से भिन्न खानों का विनियमन और खनिजों का विकास, जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में खनिजों के विनियमन और विकास से संबंधित प्रश्न और उससे संसक्त या उसके आनुषांगिक मामले भी हैं ।
2. सभी ऐसे अन्य धातु और खनिज, जो विनिर्दिष्टतया किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को आबंटित नहीं हैं जैसे अल्युमिनियम, जस्ता, तांबा, सोना, हीरा, सीसा और निकल ।
3. इस विभाग द्वारा व्यवहृत सभी उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण तथा सहायता ।
4. भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण ।
5. भारतीय खान ब्यूरो ।
6. मेटलार्जिकल ग्रेड सिलिकॉन ।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

1. बायो गैस का अनुसंधान और विकास तथा बायो गैस यूनिटों से संबद्ध कार्यक्रम ।
2. अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत आयोग (अ.ऊ.स्रो.आ.) ।
3. सौर ऊर्जा, जिसके अंतर्गत प्रकाश बोल्टीय यंत्र एवं उनका विकास, उत्पादन और अनुप्रयोग भी है ।
4. 25 मेगावाट की और उससे कम क्षमता की लघु/मिनी/सूक्ष्म हाइड्रल परियोजनाओं से संबंधित सभी मामले ।
5. समुन्नत चूल्हों और उनके अनुसंधान तथा विकास से संबंधित कार्यक्रम ।
6. भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण ।
7. ऊर्जा के अन्य अपारंपरिक नवीकरणीय स्रोतों का अनुसंधान और विकास तथा उनसे संबद्ध कार्यक्रम ।
8. ज्वारीय ऊर्जा ।
9. एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (ए0ग्रा0ऊ0का0) ।
10. भूतापीय ऊर्जा ।

संसदीय कार्य मंत्रालय

1. संसद के दोनों सदनों के आह्वान और सत्रावसान की तारीखें, लोक सभा का विघटन, संसद के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण ।
2. दोनों सदनों की विधायी तथा अन्य शासकीय कार्य की योजना और समन्वय ।
3. जिन प्रस्तावों की सूचना सदस्यों ने दी है उनकी चर्चा के लिए संसद में सरकारी समय का आबंटन ।

4. संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं और सचेतकों के साथ संपर्क ।
5. विधेयकों संबंधी प्रवर और संयुक्त समिति के लिए सदस्य सूचियां ।
6. सरकार द्वारा स्थापित समितियों तथा अन्य निकायों में संसद-सदस्यों की नियुक्ति ।
7. विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसद-सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों का कार्यकरण ।
8. मंत्रियों द्वारा संसद में दिए गए आश्वासनों का कार्यान्वयन ।
9. प्राइवेट सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का दृष्टिकोण ।
10. मंत्रिमंडल की संसदीय समिति को सचिवीय सहायता ।
11. प्रक्रिया संबंधी तथा अन्य संसदीय मामलों पर मंत्रालयों को सलाह ।
12. संसदीय समितियों द्वारा की गई साधारण रूप से लागू होने वाली सिफारिशों पर मंत्रालयों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का समन्वय ।
13. संसद-सदस्यों द्वारा रोचक स्थानों का परिदर्शन जिसे राजकीय रूप से समर्थित किया गया हो ।
14. संसद-सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित मामले ।
15. संसदीय सचिव-कृत्य ।
16. संपूर्ण देश में विद्यालयों/महाविद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन ।
17. अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन ।
18. संसद-सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित प्रतिनिधिमंडलों का अन्य देशों के साथ आदान-प्रदान ।
19. लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों के नियम 377 के अधीन तथा राज्य सभा में विशेष उल्लेखों के माध्यम से उठाए जाने वाले मामलों के संबंध में नीति का अवधारण और अनुवर्ती कार्रवाई ।
20. मंत्रालयों/विभागों में संसदीय कार्य करने संबंधी निर्देशिका ।

21. संसद-अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 (1953 का 20) ।
22. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) ।
23. संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33) ।
24. संसद में मान्यता प्राप्त दल और समूह का नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998 (1999 का 5)।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

क. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

I. सेवाओं में भर्ती, प्रोन्नति और मनोबल ।

1. नागरिकों के कतिपय वर्गों के लिए सेवाओं में पदों का आरक्षण ।
2. रेल सेवाओं और परमाणु ऊर्जा विभाग, पूर्ववर्ती इलैक्ट्रानिक्स विभाग, अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रणाधीन सेवाओं और रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के नियंत्रणाधीन वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाओं के सिवाय, केन्द्रीय सेवाओं से संबंधित भर्ती, प्रोन्नति और ज्येष्ठता संबंधी साधारण प्रश्न ।
3. सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए आयु-सीमाओं, स्वास्थ्य मानकों, शैक्षिक अर्हताओं तथा अतकनीकी डिग्रियों/डिप्लोमाओं की मान्यता की बाबत साधारण नीति ।
4. रेल सेवाओं से भिन्न, सेवाओं के संबंध में पदों के वर्गीकरण और राजपत्रित हैसियत प्रदान करने के संबंध में साधारण नीति विषयक मामले ।
5. रेल विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, पूर्ववर्ती इलैक्ट्रानिक्स विभाग, और अंतरिक्ष विभाग में भर्ती के सिवाय, भारत सरकार के सचिवालय और उसके संलग्न कार्यालयों के लिए अनुसचिवीय कर्मचारियों की भर्ती ।
6. रेल विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, पूर्ववर्ती इलैक्ट्रानिक्स विभाग, और अंतरिक्ष विभाग के अधीन पदों के सिवाय भारत सरकार के अधीन सिविल पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति ।
7. विभिन्न देशों से आने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नियोजन संबंधी सहायता देने की बाबत साधारण नीति ।

8. सिविल पदों और सेवाओं में नियुक्ति की बाबत युद्ध सेवा-अभ्यर्थियों को रियायतें ।
9. जो क्षेत्र इस समय पाकिस्तान में हैं, उन क्षेत्रों से विस्थापित हुए सरकारी सेवकों और छंटनी किए गए अस्थायी कर्मचारियों के पुनः स्थापन के संबंध में साधारण नीति ।
10. लोक सेवाओं में प्रथम नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के विषय में राजनीतिक पीड़ितों को रियायतें ।
11. अधिवर्षिता-प्राप्त अधिकारियों के सेवा विस्तारण या पुनर्नियोजन के संबंध में साधारण नीति।
12. भारतीय नागरिकों से भिन्न, व्यक्तियों की बाबत संघ के अधीन सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए पात्रता के प्रमाण-पत्र देना ।
13. (क) विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अधीन और द्विपक्षीय आधार पर विदेशस्थ भारतीय विशेषज्ञों की एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों में प्रतिनियुक्ति ।
(ख) संयुक्त राष्ट्रसंघ और उसके सहबद्ध अभिकरणों के साथ तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य और कृषि संगठन इत्यादि जैसे उसके अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ नियोजन के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति ।
14. सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चरित्र तथा पूर्ववृत्त, उपयुक्तता संबंधी सत्यापन विषयक साधारण नीति ।
15. उच्चतर पदों के लिए रोजगार कार्यालयों में ऐसे कार्मिकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए, जो सेवा में हों, आपत्ति न होने संबंधी प्रमाणपत्रों को जारी करने के संबंध में नीति विषयक मामले ।
16. मंत्रियों के वैयक्तिक कर्मचारिवृन्द संबंधी मामले ।
17. निम्नलिखित के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अधिशेष हो गये कर्मचारियों का पुनः अभिनियोजन :
(क) प्रशासनिक सुधार;
(ख) कर्मचारिवृन्द निरीक्षण एकक द्वारा किये गए अध्ययन;
(ग) दीर्घकालिक किन्तु अस्थायी संगठनों का परिसमापन ।

18. मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन विभिन्न काडरों के समुचित प्रबंध के संबंध में मंत्रालयों को सलाह ।

II. प्रशिक्षण

19. (क) अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं के लिए प्रशिक्षण नीतियां तैयार करना और उनका समन्वय;
- (ख) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी तथा सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान;
- (ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम;
- (घ) प्रशिक्षण संबंधी सामग्री का और प्रशिक्षण तकनीकों, सुविधाओं और कार्यक्रमों की जानकारी का तैयार किया जाना और उसका प्रकाशन;
- (ङ.) राज्यों के भीतर की तथा विदेशों की प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ संपर्क;
- (च) मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधक के स्तरों के लिए पुनश्चर्या तथा विशेष पाठ्यक्रम;

III. सतर्कता और अनुशासन

20. (क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग;
- (ख) लोक सेवकों के मध्य सतर्कता और अनुशासन संबंधी सभी नीति विषयक मामले;
- (ग) संसद-सदस्यों और प्रशासन के बीच संबंध ।

IV. सेवा-शर्तें

21. रेल विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, पूर्ववर्ती इलैक्ट्रानिक्स विभाग और अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण के अधीन सेवाओं के सिवाय, अखिल भारतीय तथा संघ लोक सेवाओं संबंधी साधारण प्रश्न (उनसे भिन्न जिनका वित्त से संबंध है), जिनमें आचरण नियम भी आते हैं।
22. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, रेल विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, पूर्ववर्ती इलैक्ट्रानिक्स विभाग और अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रणाधीन कर्मचारियों, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग

के नियंत्रणाधीन वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों को छोड़कर, की वे सेवा-शर्तें जो उनसे भिन्न हैं जिनका वित्त से संबंध है, जहां तक उनसे सेवा के साधारण हितों के प्रश्न उत्पन्न होते हैं ।

23. (क) मूल नियमों, अनुपूरक नियमों और सिविल सेवा नियमों सहित (किन्तु इसमें पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ नहीं आते हैं) सभी सेवा नियमों का, निम्नलिखित को छोड़कर, प्रशासन :

- (i) कर्मचारियों के वेतन ढांचे के पुनरीक्षण संबंधी प्रस्ताव;
- (ii) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षणों के प्रस्ताव;
- (iii) वेतन आयोग की नियुक्ति, सिफारिशों पर कार्रवाई और उनका कार्यान्वयन;
- (iv) महंगाई भत्ता और अन्य प्रतिपूरक भत्ते और यात्रा भत्ते;
- (v) सेवा-शर्तों अथवा महत्वपूर्ण आवर्ती वित्तीय निहितार्थों वाले अनुषंगी हितलाभों के रूप में सरकारी कर्मचारियों को कोई नई सुविधा; और
- (vi) प्रमुखतः वित्तीय प्रकृति के सेवा-नियमों में संशोधन संबंधी मामले;

(ख) सेवा-शर्तों और महत्वपूर्ण आवर्ती वित्तीय निहितार्थों वाले अनुषंगी हितलाभों के रूप में सरकारी कर्मचारियों को नई सुविधा के प्रस्तावों का उपक्रमण;

(ग) खंड (क) की मद (vi) में निर्दिष्ट प्रमुखतः वित्तीय प्रकृति के सेवा-नियमों सहित सेवा-नियमों में संशोधन से संबंधित मामलों में भारत सरकार के औपचारिक आदेश जारी करना;

(घ) दीर्घावधिक वित्तीय निहितार्थों वाले किन्हीं भी सेवा-नियमों का वित्त मंत्रालय के परामर्श से शिथिलीकरण और उदारीकरण ।

24. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को अनुदान ।

25. रेल कर्मचारियों से भिन्न, सिविल कर्मचारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत सुविधाएं ।

26. केन्द्रीय सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1949 ।

27. रेल विभाग के अधीन अस्थायी सरकारी सेवकों के सिवाय, अस्थायी सेवकों की छंटनी और प्रत्यावर्तन संबंधी साधारण नीति ।

28. केन्द्रीय सेवा (राष्ट्रीय सुरक्षा को निरापद करना) नियमों का प्रशासन ।
29. केन्द्रीय सचिवालय और उसके संलग्न कार्यालयों में वर्ग 4 तथा अन्य सरकारी सेवकों के लिए वर्दियां ।
30. भारत सरकार के कार्यालयों के लिए काम के घंटे और अवकाश दिन ।
31. ऐसे सेवा नियमों का प्रशासन, जिसमें वित्त मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट प्रत्यायोजित वित्तीय बातें हों ।
32. वित्त मंत्रालय की बाबत ऐसी प्रस्थापनाओं पर सलाह, जिनका संबंध किसी सेवा के पदों की संख्या श्रेणी से अथवा उनकी सदस्य संख्या से अथवा सरकारी सेवकों के वेतन और भत्तों से अथवा उनकी सेवा की अन्य किन्हीं ऐसी शर्तों से हो जिसमें वित्तीय प्रश्न निहित हों ।
33. सरकारी सेवकों द्वारा किए गए विधिक व्ययों की प्रतिपूर्ति के संबंध में साधारण नीति ।
34. पदेन सचिवालय हैसियत प्रदान करने के लिए प्रस्थापनाएं ।
35. सिविल पदों पर व्यक्तियों की अवैतनिक नियुक्तियां ।
36. संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ।

V. ज्येष्ठ और मध्यवर्गीय प्रबंधन

37. ज्येष्ठ प्रबंधन (अर्थात् संयुक्त सचिव और उनसे ऊपर तथा उनके समकक्ष) के सभी पहलू, जिनके अंतर्गत उनके लिए कार्मिक की अभिवृद्धि भी है ।
38. (क) भारत सरकार का स्थापना अधिकारी;
(ख) मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति;
(ग) केन्द्रीय स्थापना बोर्ड;
(घ) मध्यवर्गीय प्रबंधकगण (अर्थात् निदेशकों, उप सचिवों और अवर सचिवों और उनके समकक्ष) के कैरियर का विकास ।

VI. सरकार-कर्मचारी संबंध, जिनमें कर्मचारिवृन्द की शिकायतें और कल्याण भी हैं ।

39. (क) भारत सरकार के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के सेवा संगम;
- (ख) संयुक्त परामर्शदाता तंत्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की विभागीय परिषद;
- (ग) कर्मचारिवृन्द की शिकायतें दूर करने के लिए तंत्र;
- (घ) कर्मचारिवृन्द कल्याण, जिसके अंतर्गत खेल-कूद, सांस्कृतिक क्रिया-कलाप, गृह कल्याण केन्द्र, कैंटीने, सहकारी स्टोर, आदि भी हैं;
- (ङ.) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरणों और राज्य प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित सभी मामले;
- (च) सरकार कर्मचारी संबंधों के बारे में अन्य मामले, जिनका इस मंत्रालय के संबंध में किसी अन्य प्रविष्टि के अंतर्गत विनिर्दिष्टतः उपबंध नहीं है ।

VII. संघ लोक सेवा आयोग

40. संघ लोक सेवा आयोग ।

VIII. भारतीय प्रशासनिक सेवा, अंतर मंत्रालय संवर्ग, जिसके अंतर्गत उसके सदस्यों की कैरियर विषयक योजना भी आती है, के प्रबंध के केन्द्रीयकृत पहलू ।

41. (क) नयी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन;
- (ख) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) के अधीन नियम और विनियम;
- (ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसके अंतर्गत भारतीय सिविल सेवा है, से संबद्ध सभी मामले;
- (घ) अखिल भारतीय सिविल सूची और सेवाओं का इतिहास;
- (ङ.) केन्द्रीय सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवाओं और केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा ।

IX. भविष्य विषयक योजना और जनशक्ति योजना

42. (क) अखिल भारतीय सेवा और केन्द्रीय सरकारी सेवाओं के लिए भविष्य विषयक योजना और जनशक्ति योजना के संबंध में साधारण नीति विषयक प्रश्न;
- (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के लिए भविष्य विषयक योजना और जनशक्ति योजना से संबद्ध सभी मामले ।

X. कार्मिक प्रबंध अधिकरण

43. विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के भीतर कार्मिक प्रबंध अधिकरणों के काम का समन्वय ।

XI. राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप कार्मिकों का आबंटन और सेवाओं का एकीकरण ।

44. (क) राज्यों के पुनर्गठन से प्रभावित सेवा कार्मिकों का आबंटन;
- (ख) संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न, राज्यों के पुनर्गठन से प्रभावित सेवा का विभाजन और एकीकरण;
- (ग) राज्यों के पुनर्गठन से प्रभावित कार्मिकों की सेवा-शर्तों का संरक्षण;
- (घ) राज्यों के पुनर्गठन से प्रभावित राज्य सेवाओं से संबद्ध अन्य मामले ।

XII. लोक उद्यम चयन बोर्ड

45. लोक उद्यम चयन बोर्ड (लो030च0बो0)

ख. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

1. प्रशासनिक सुधार, जिसमें ई-शासन और सर्वोत्तम व्यवहार का प्रसार भी है ।
2. संगठन और पद्धति ।
3. निम्नलिखित से संबंधित मामलों के बारे में नीति, समन्वय और मानीटरी :
 - (क) सामान्यतः लोक शिकायतों का निवारण; और
 - (ख) केन्द्रीय सरकारी अधिकरणों से संबंधित शिकायतें ।
4. (क) लोक प्रबंध में अनुसंधान;
- (ख) लोक प्रबंध के मामलों में राज्य सरकारों, वृत्तिक संस्थाओं, आदि के साथ संपर्क ।
5. केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम-पुस्तिका का प्रशासन ।

ग. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

1. नीति बनाना और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों (सिविल, रक्षा और रेल पेंशनभोगियों) के लिए सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित मामलों का समन्वय करना ।

2. निम्नलिखित का प्रशासन :

(क) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972; केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981; केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939; अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति प्रसुविधाएं) नियम, 1958; और

(ख) विभाग को सौंपी गई केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों से संबंधित कोई अन्य स्कीम ।

3. पेंशन ढांचा और पेंशन भोगियों को राहत ।

4. केन्द्रीय सरकार के पेंशन-भोगियों को नई सुविधाएं या अनुषंगी हितलाभ ।

5. पेंशन नियमों या सेवा-निवृत्ति लाभों से संबंधित किसी अन्य नियम के संशोधन या शिथिलीकरण से संबंधित मामले ।

6. केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों के कल्याण से संबंधित नीति और समन्वय ।

टिप्पण: उपर्युक्त 3 के संबंध में कार्रवाई वित्त मंत्रालय की सहमति से की जाएगी । अन्य मामलों, जिनमें आवर्ती वित्तीय निहितार्थ निहित हों, के संबंध में कार्रवाई, किसी नियम के शिथिलीकरण या उदारीकरण की कार्रवाई उन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन रहते की जाएगी जो पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग और वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के बीच करार पाए हों ।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

1. प्राकृतिक गैस और कोल बेड मेथेन सहित पेट्रोलियम संसाधन की खोज और उसका दोहन ।

2. प्राकृतिक गैस, कोल बेड मेथेन और पेट्रोलियम उत्पादों सहित पेट्रोलियम का उत्पादन, प्रदाय, वितरण, विपणन और मूल्य-निर्धारण ।

3. तेल परिष्करणियां, जिनमें स्नेहक संयंत्र शामिल हैं ।

4. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए योज्य ।

5. स्नेह मिश्रण और ग्रीसें ।

6. मंत्रालय द्वारा व्यवहृत सब उद्योगों की योजना, विकास तथा नियंत्रण और उनकी सहायता ।

7. तेल क्षेत्र सेवाओं की योजना, विकास और विनियमन ।

8. इस सूची में सम्मिलित किए गए विषयों के अंतर्गत आने वाली पब्लिक सेक्टर परियोजनाएं । इंजीनियर्स इंडिया लि० और इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कंपनी, जिसमें उनकी समनुषंगी भी शामिल है उन परियोजनाओं के सिवाए, जो किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को विनिर्दिष्टतया आबंटित की गई है, ।
9. तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) ।
10. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1993 (1993 का 65)।
11. पेट्रोलियम पाइपलाइन {(भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50)}।
12. एस्सो {(भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1974 (1974 का 4)} ।
13. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) ।
14. बर्मा-शैल [(भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1976 (1976 का 2)] ।
15. कालटैक्स [(कालटैक्स आयल रिफाईनिंग (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों तथा कालटैक्स (इंडिया) लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1977 (1977 का 17)]।
16. पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) और तद्धीन बनाए गए नियमों का प्रशासन ।

योजना मंत्रालय

राष्ट्रीय आयोजना के विषयों के संबंध में संसद के प्रति उत्तरदायित्व ।

विद्युत मंत्रालय

1. विद्युत शक्ति सेक्टर में साधारण नीति और ऊर्जा नीति से संबंधित मामले और उसका समन्वय । (किसी सेक्टर, ईंधन, क्षेत्र और पारदेशीय और अंतःदेशीय प्रवाह को ध्यान में रखे बिना, ऐसी नीतियां बनाने, स्वीकार करने, कार्यान्वित करने और उनका पुनर्विलोकन करने के संबंध में लघु, मध्यम और दीर्घावधिक नीतियों का ब्यौरा) ।
2. जल विद्युत शक्ति (25 मेगावाट और उससे कम क्षमता की लघु/अतिलघु/सूक्ष्म हाइडल परियोजनाओं के सिवाय) और तापीय शक्ति तथा पारेषण और वितरण प्रणाली नेटवर्क से संबंधित सभी मामले ।

3. राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों में जल विद्युत शक्ति और तापीय शक्ति, पारेषण प्रणाली नेटवर्क और वितरण प्रणाली से संबंधित अनुसंधान, विकास और तकनीकी सहायता ।
4. भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 का 9), विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54), विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का 14), ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52), दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 14) और भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड, जैसा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) में उपबंधित है, का प्रशासन ।
5. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत बोर्ड और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग से संबंधित सभी मामले ।
- 6.(क) ग्रामीण विद्युतीकरण;
 - (ख) विद्युत स्कीमों और राज्यो और संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय/विकास स्कीमों/कार्यक्रमों/विकेन्द्रीकृत और वितरित उत्पादन से संबंधित मामले ।
7. निम्नलिखित उपक्रमों, संगठनों, आदि से संबंधित मामले:
 - (क) दामोदर घाटी निगम;
 - (ख) भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (सिंचाई से संबंधित मामलों के सिवाय);
 - (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड;
 - (घ) राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड;
 - (ङ) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड;
 - (च) पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड;
 - (छ) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड;
 - (ज) विद्युत वित्त निगम लिमिटेड;
 - (झ) टिहरी जल विद्युत विकास निगम ;
 - (ञ) नाथपा झाकरी विद्युत निगम;

- (ट) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान;
 - (ठ) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान;
 - (ड) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो;
 - (ढ) भारतीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड;
 - (ण) नर्मदा जल विद्युत विकास निगम (संयुक्त उद्यम) ।
8. विद्युत सेक्टर से संबंधित ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता से संबंधित सभी मामले ।

रेल मंत्रालय

रेल बोर्ड

1. सरकारी रेलें- सभी विषय, जिनके अंतर्गत वे विषय भी हैं, जो रेल राजस्व और व्यय से संबंधित हैं किन्तु जिनमें रेल निरीक्षणालय और रेल लेखा-परीक्षा नहीं आते ।
2. गैर-सरकारी रेलें -वहां तक वे विषय जहां तक उनके लिए रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) में या सरकार और इन रेलों के बीच संविदाओं में या किन्हीं अन्य कानूनी अधिनियमितियों में, अर्थात् सुरक्षा, अधिकतम और न्यूनतम दरों और भाड़ा, इत्यादि विषयक विनियमों में जैसाकि उपबंध किया गया है कि उनका नियंत्रण रेल मंत्रालय, (रेल बोर्ड) करेगा, इसमें शहरी विकास विभाग को आबंटित कार्य मदे नहीं आती ।
3. रेल संपत्ति के मूषण से संबंधित अपराधों, सरकारी रेलों और गैर-सरकारी रेलों में अपराधों से संबंधित अपराधों से भिन्न, की बाबत संसदीय प्रश्न ।
4. रेल कर्मचारियों पर लागू पेंशन नियमों का प्रशासन ।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

- I. निम्नलिखित विषय, जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की पहली सूची में आते हैं:

1. मोटर यानों का अनिवार्य बीमा ।

2. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) का प्रशासन ।
3. संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किए गए राजमार्ग ।

II. संघ राज्य क्षेत्रों की बाबत :

4. राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न मार्ग ।
5. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) का प्रशासन और मोटर यानों का कराधान ।
6. यंत्रनोदित यानों से भिन्न यान ।

III. अन्य विषय, जिन्हें पिछले भागों में शामिल नहीं किया गया है :

7. केन्द्रीय सड़क निधि ।
8. सड़क संकर्मों से संबंधित समन्वय और अनुसंधान ।
9. केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः वित्तपोषित सड़क संकर्म, जिनके अंतर्गत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में किए जाने वाले सड़क संकर्म नहीं हैं ।
10. मोटर यान विधायन ।
11. मोटर परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन के क्षेत्र में परिवहन सहकारी समितियों का उन्नयन ।
12. सड़कों के अवसंरचना वाले क्षेत्रों में निजीकरण नीति का बनाया जाना ।
13. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ।

V. सोसाइटियां/संगम :

14. राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान ।

VI. पब्लिक सेक्टर उपक्रम :

15. भारतीय सड़क निर्माण निगम ।

VII. अधिनियम :

16. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) ।
17. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) ।
18. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) ।
19. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय

क. ग्रामीण विकास विभाग

1. पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामले ।
2. लोक सहकारिता, जिसके अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिए स्वयंसेवी अभिकरणों, लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कापाटी) और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि से संबंधित सभी विषय हैं, उन पहलुओं को छोड़कर, जो पेयजल आपूर्ति विभाग के कार्यक्षेत्र में आते हैं ।
3. इस सूची की मदों से संबंधित सहकारी समितियां ।
4. असम के उन जनजातीय क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित सड़क संकर्म जो संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 से उपाबद्ध सारणी के भाग-I और भाग-II में विनिर्दिष्ट हैं ।
5. दि सेंटर फार इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फार एशिया एंड पैसिफिक (सीआईआरडीएपी) तथा दि एफ्रो एशियन रूरल रिकंस्ट्रक्शन आर्गेनाइजेशन (एएआरओओ) के सहयोग से संबंधित सभी मामले ।
6. (क) ग्रामीण रोजगार या बेरोजगारी से संबंधित सभी विषय, जैसे ग्रामीण रोजगार के लिए नीतियां और कार्यक्रम, जिनके अंतर्गत विशेष संकर्म, मजदूरी या आय के स्रोत उत्पन्न करना भी है, तैयार करना और उससे संबंधित प्रशिक्षण देना;

(ख) समय-समय पर बनाए गए ग्रामीण रोजगार के विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ।

(ग) ग्रामीण रोजगार या बेरोजगारी से संबंधित सूक्ष्म स्तर आयोजना तथा उसके लिए प्रशासनिक ढांचा ।

7. समेकित ग्रामीण विकास, जिसके अंतर्गत लघु कृषक विकास अभिकरण, सीमांत कृषक और कृषि मजदूर, आदि भी हैं ।
8. ग्रामीण आवास, जिसके अंतर्गत ग्रामीण आवास नीति भी है और देश में उससे संबद्ध और अनुषांगिक सभी मामले या ग्रामीण आयोजना जहां तक कि उसका संबंध ग्रामीण क्षेत्रों से है ।
9. गांवों को सड़कों से जोड़ने से संबंधित सभी मामले, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी है ।

ख. भूमि संसाधन विभाग

1. भूमि-सुधार, भूधृति, भू-अभिलेख, जोत भूमि की चकबंदी तथा अन्य संबंधित विषय ।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) का प्रशासन और संघ के प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन संबंधी मामले ।
3. किसी राज्य में उस राज्य से बाहर पैदा हुए कर विषयक दावों तथा अन्य लोक मांगों, जिनके अंतर्गत भू-राजस्व बकाया और इस प्रकार वसूल की जाने वाली बकाया भी है, की वसूली ।
4. भूमि, अर्थात्, भाटक का संग्रहण, भूमि का अंतरण और अन्य संक्रामण, भूमि सुधार और कृषि संबंधी उधार जिनके अंतर्गत कृषि से भिन्न भूमि या भवन का अर्जन, नगर योजना सुधार नहीं है ।
5. भू-राजस्व, जिसके अंतर्गत राजस्व निर्धारण और संग्रहण, राजस्व प्रयोजनों के लिए सर्वेक्षण और राजस्व का अन्य संक्रामण भी है ।
6. कृषि भूमि के उत्तराधिकार की बाबत शुल्कें ।
7. राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड ।
8. राष्ट्रीय भूमि उपयोग और बंजर भूमि विकास परिषद् ।

9. बंजर भूमि विकास के माध्यम से ग्रामीण नियोजन का संवर्धन ।
10. निजी बंजर भूमि सहित वन-इतर भूमि पर ईधन लकड़ी, चारा और इमारती लकड़ी के उत्पादन का संवर्धन ।
11. दीर्घकालिक तरीकों से बंजरभूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कम लागत की समुचित प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान और विकास ।
12. बंजरभूमि विकास कार्यक्रम की कार्यक्रम योजना और उसके कार्यान्वयन में अंतरविभागीय और अंतरविषयक समन्वय, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण भी है ।
13. बंजरभूमि के विकास के लिए लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना और लोक सहकारिता तथा पंचायतों और स्वैच्छिक और गैर-सरकारी अभिकरणों के प्रयासों का समन्वयन ।
14. सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम ।
15. मरूस्थल विकास कार्यक्रम ।

ग. पेयजल पूर्ति विभाग

1. ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित ग्रामीण जल पूर्ति (जल संसाधन मंत्रालय को सौंपे गए जल योजना और समन्वय के संपूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अधीन रहते हुए), मल व्ययन, जल निकास और स्वच्छता; इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता ।
2. लोक सहकारिता, जिसके अंतर्गत स्वैच्छिक अभिकरणों से संबंधित मामले भी हैं जहां तक उनका संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण जल पूर्ति, मल-व्ययन, जल निकास और स्वच्छता से है ।
3. इस सूची की मदों से संबंधित सहकारी समितियां ।
4. शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पेय जल पूर्ति परियोजनाओं और मुद्दों से संबंधित विषयों के संबंध में समन्वय ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

क. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयक नीतियां बनाना ।
2. मंत्रिमंडल की वैज्ञानिक सलाहकार समिति (म.वै.स.स.) से संबंधित मामले ।
3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों का विकास, जिसके अंतर्गत उभरते हुए क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जाएगा ।
4. भविष्य विज्ञान ।
5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अन्तः क्षेत्रीय संपर्कों वाले क्षेत्रों का समन्वय और समेकन, जिनमें अनेक संस्थाओं और विभागों की रुचि और क्षमता हो ।
6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी सर्वेक्षण, अनुसंधान डिजाइन और विकास, जहां कहीं आवश्यक हो, के कार्यों को हाथ में लेना या वित्तीय तौर पर उन्हें समर्थन देना ।
7. वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं, वैज्ञानिक संगमों और निकायों को सहायता और सहायता अनुदान देना ।
8. निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले :

(क) विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान परिषद;

(ख) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और संबंधित अधिनियम जैसे कि अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम, 1986 (1986 का 32) और प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 (1995 का 44);

(ग) राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद;

(घ) राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड;

- (ड.) अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग, जिसके अंतर्गत विदेशों में वैज्ञानिक अताशियों की नियुक्ति भी है (ये कृत्य विदेश मंत्रालय के निकट सहयोग से किए जाएंगे);
 - (च) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन विषय से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्वायत्त संस्थाएं जिसमें खगोल भौतिकी संस्थान, भूचुम्बकत्व संस्थान और इंस्टीट्यूट आफ ट्रापिकल मीटिओरोलॉजी भी है;
 - (छ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संवर्धित और वित्त-पोषित वृत्तिक विज्ञान अकादमियां;
 - (ज) भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग और नेशनल एटलस तथा थीमेटिक मैपिंग अर्गनाइजेशन ।
 - (झ) नेशनल स्पेशियल डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर और जी.आई.एस का उन्नयन;
 - (ञ) नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, अहमदाबाद ।
9. वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विभागों/संगठनों/संस्थाओं पर सामान्य रूप से प्रभाव डालने वाले मामले, उदाहरणार्थ वित्तीय, कार्मिक, क्रय और आयात नीतियां तथा व्यवहार ।
 10. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए प्रबंध सूचना प्रणालियां और तत्संबंधी समन्वय ।
 11. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशनों के विकास के लिए अंतर अभिकरण/अंतरविभागीय समन्वय संबंधी मामले ।
 12. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अधीन प्रौद्योगिकी से भिन्न, देशी प्रौद्योगिकी से संबंधित मामले, खास तौर से वे मामले जिनमें ऐसी प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिकीकरण निहित हो ।
 13. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संवर्धन के लिए आवश्यक सभी अन्य उपाय तथा राष्ट्र के विकास और सुरक्षा के लिए उनको लागू करना ।
 14. संस्थागत विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण संबंधी मामले, जिनके अंतर्गत नई संस्थाओं और संस्थागत ढांचे की स्थापना भी है ।

15. राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों और अन्य तंत्रों की मारफत सबसे निचले स्तरों के विकास के लिए राज्य, जिला और ग्राम स्तरों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संवर्धन ।
16. समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं, और अन्य उपेक्षित वर्गों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग ।

ख. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

1. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् से संबंधित सभी मामले ।
2. राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम से संबंधित सभी मामले ।
3. सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से संबंधित सभी मामले ।
4. अनुसंधान और विकास ईकाइयों का रजिस्ट्रीकरण और उन्हें मान्यता प्रदान करना ।
5. संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मलेन (अंकटाड) तथा विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) से संबंधित तकनीकी मामले ।
6. विदेशी सहयोग के बारे में नेशनल रजिस्टर ।
7. भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की अस्थायी तैनाती के लिए एक पूल के सृजन से संबंधित मामले ।

ग. बायोटेकनालाजी विभाग ।

1. बायोटेकनालाजी में नीतियां और समेकित कार्यक्रम बनाना और उनका कार्यान्वयन तथा मानीटरी सुनिश्चित करना ।
2. जैविक और बायोटेकनालाजी में अनुसंधान और विकास तथा उनके विनिर्माण के विनिर्दिष्ट कार्यक्रम अभिज्ञात करना और संबंधित अनुसंधान के प्रारंभ और अन्वेषण तथा विनिर्माण क्रियाकलापों का निरीक्षण करना ।
3. बायोटेकनालाजी में अनुसंधान और विकास के लिए श्रेष्ठ केन्द्रों की पहचान, स्थापना और सहायता करना तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के अनुसार इन क्रियाकलापों का समुचित सामंजस्य सुनिश्चित करना ।

4. जैविक और बायोटेकनालाजी संबंधी उत्पादों और उनकी मध्यवर्ती वस्तुओं के विनिर्माण के लिए नई प्रौद्योगिकी के आयात और अंतरण के संबंध में सरकार के छानबीन करने, सलाह देने और अनुमोदन करने वाले अधिकर्ता के रूप में कार्य करना ।
5. भारत में बायोटेकनालाजी अनुसंधान और विकास तथा विनिर्माण के लिए सुरक्षा संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित करना ।
6. उत्पत्तिमूलक रूप में काम में लाई जाने वाली सामग्रियों, कल्चर, कोशाणुओं, नमूनों, टिशुओं और बायोटेक उत्पादों, जिसके अंतर्गत किसी प्रकार या आकार के डी0एन0ए0 और आर0एन0ए0 भी हैं, के आयात के लिए और देश में उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय अधिकरण के रूप में कार्य करना ।
7. बायोटेकनालाजी के क्षेत्र में सभी विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अनुसंधान और विकास संबंधी सहयोग और करारों के लिए अंतर मंत्रालय और अंतर अधिकरण आसंधि स्थल के रूप में बायोटेकनालाजी के क्षेत्र में सभी प्रौद्योगिकी अंतरणों के लिए आसंधि स्थल के रूप में सेवा करना ।
8. कोशाणु आधारित और डीएनए वैक्सीनों, डायग्नोस्टिक्स और अन्य बायो-टैकनालाजीकल उत्पादों का विनिर्माण करना और उनका उपयोजन सुनिश्चित करना ।
9. बायोटेकनालाजी के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के कार्यक्रम बनाना ।
10. बायोटेकनालाजी में राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से बनाए गए अधिकरणों, आयोगों, बोर्डों, आदि के प्रशासनिक और कार्यान्वयन विभाग के रूप में सेवा करना और बायो-इनफॉर्मेटिक्स, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण और अवसंरचना का सृजन तथा बायोटेकनालाजी से संबंधित जानकारी के संग्रहण, प्रसार और आदान-प्रदान भी है, के लिए आसंधि स्थल के रूप में भी सेवा करना ।
11. निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले:
 - (क) अंतर्राष्ट्रीय उत्पत्तिमूलक इंजीनियरी और बायोटेकनालाजी केन्द्र, नई दिल्ली;
 - (ख) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-विज्ञान संस्थान (एन0आई0आई0), नई दिल्ली;
 - (ग) राष्ट्रीय कोषीय विज्ञान केन्द्र (एन0सी0सी0एस0), पुणे;
 - (घ) सेन्टर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स (सी.डी.एफ.डी.), हैदराबाद ।
 - (ङ.) नेशनल सेंटर फार प्लांट जेनोम रिसर्च, नई दिल्ली;
 - (च) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, गुड़गांव;

(छ) इंस्टीट्यूट फॉर बायोसोर्स एंड ससटेनेबल डेवलपमेंट (आई.बी.एस.डी.), इम्फाल ।

12. निम्नलिखित से संबंधित मामले:

(क) भारत इम्यूनोलॉजिकलस एंड बायोलॉजिकल कारपोरेशन लि० (बी.आई.बी.सी.एल.), बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश;

(ख) इन्डियन वैक्सीन कारपोरेशन लि०, मानेसर, गुड़गांव ।

पोत परिवहन मंत्रालय

1. भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची । के भीतर आने वाले निम्नलिखित विषय:

1. समुद्री पोतपरिवहन और नौपरिवहन; वाणिज्यिक समुद्री बेड़े के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था।
2. दीपस्तम्भ और दीपपोत ।
3. भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) और महापत्तन के रूप में घोषित पत्तनों का प्रशासन ।
4. पोतपरिवहन और नौपरिवहन, जिसके अंतर्गत ऐसे अंतर्देशीय जल मार्गों पर यात्रियों और माल का वहन है, जो संसद द्वारा विधि द्वारा यंत्रनोदित जलयानों के विषय में राष्ट्रीय जलपथ घोषित किए गए हैं, ऐसे जलमार्गों पर मार्ग-नियम ।
5. पोत-निर्माण और पोत-सुधार उद्योग ।
6. मत्स्य ग्रहण जलयान उद्योग ।
7. प्लवमान-यान उद्योग ।

II. संघ राज्य क्षेत्र की बाबत :

8. अंतर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात ।

III. अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में :

9. मुख्यभूमि द्वीपों और द्वीपों के बीच पोत परिवहन सेवाओं का गठन और अनुरक्षण ।

IV. अन्य विषय जिन्हें पूर्ववर्ती भागों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है:

10. अंतर्देशीय जलमार्गों पर यंत्रनोदित जलयान विषयक पोतपरिवहन और नौपरिवहन तथा अंतर्देशीय जलमार्गों पर यात्रियों और माल के वहन के संबंध में विधायन ।
11. लघु और महापत्तनों के विकास के समन्वय और उससे संबंधित विधायन ।
12. डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) स्कीम, 1961 से भिन्न, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) तथा उसके अधीन बनाई गई स्कीम का प्रशासन ।
13. पोत पर्यन्त निशुल्क/घाट तक स्थौरा के निशुल्क आयात तथा लागत एवं भाड़ा/लागत बीमा एवं भाड़ा आधार पर निर्यात के संबंध में. भारत सरकार/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/ राज्य सरकारों/राज्य सरकारों के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों तथा स्वशासी निकायों के लिए और उनकी ओर से पोत परिवहन का प्रबंध करना ।
14. अंतर्देशीय जल परिवहन की योजना ।
15. पत्तनों, पोत परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में निजीकरण विषयक नीति बनाना ।
16. गांधीधाम नगरी का विकास ।
17. प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण :

- (क) समुद्र में पोतों, जिनके अंतर्गत पत्तन क्षेत्र भी है, ध्वस्त पोतों और परित्यक्त पोतों से उत्पन्न प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण;

(ख) पोतों से उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण, निवारण तथा रोकथाम से संबंधित विधान का अधिनियमन तथा प्रशासन; और

(ग) पत्तन क्षेत्रों में तेल प्रदूषण की मानीटरी तथा उसकी रोकथाम ।

V. अधीनस्थ कार्यालय :

18. पोत परिवहन महानिदेशालय ।

19. अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म ।

20. दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय ।

21. लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन ।

VI स्वाशासी निकाय:

22. महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण (टी.ए.एम.पी.) ।

23. मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, कांडला, चेन्नई, मोरमुगाव, जवाहर लाल नेहरू (न्हावा शेवा), पारादीप, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम और न्यू मंगलोर स्थित पत्तन न्यास ।

24. कोलकाता, कांडला और विशाखापट्टनम स्थित गोदी श्रम बोर्ड ।

25. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ।

26. नाविक भविष्य निधि संगठन ।

VII सोसाइटियां/संगम :

27. राष्ट्रीय पत्तन प्रबंध संस्थान ।

28. राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केन्द्र ।

29. सागर गामी वृत्तिक कल्याण निधि सोसाइटी ।

VIII पब्लिक सेक्टर उपक्रम :

30. शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया ।
31. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड।
32. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ।
33. सेंट्रल इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड ।
34. ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया ।
35. हुगली डॉक एंड पोर्ट्स इंजीनियर्स लिमिटेड ।
36. एन्नोर पोर्ट लिमिटेड ।

IX. अंतर्राष्ट्रीय पहलू :

37. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ।

X. अधिनियम :

38. भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) ।
39. अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) ।
40. डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) ।
41. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) ।
42. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) ।
43. नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 (1966 का 4) ।
44. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) ।
45. माल बहु-विध परिवहन अधिनियम, 1993 (1993 का 28) ।

लघु उद्योग मंत्रालय

1. लघु उद्योगों, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को छोड़कर, तथा अल्प/सूक्ष्म उद्यमों के विकास का समन्वयन ।
2. लघु उद्योग बोर्ड ।
3. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ।
4. सहकारी गन्ना कारखानों के सिवाय, औद्योगिक क्षेत्र में सहकारिता ।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भाग-I

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची -I के अंतर्गत आते हैं:

1. दान सहायता आपूर्तियों/वस्तुओं की शुल्क-मुक्त प्राप्ति हेतु भारत-संयुक्त राज्य, भारत-यूनाइटेड किंगडम, भारत-जर्मनी, भारत-स्विटजरलैंड और भारत-स्वीडन करारों का संचालन और उनके अंतर्गत आने वाली आपूर्तियों के वितरण से संबंधित मामले ।

भाग-II

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची --III के अंतर्गत आते हैं: (केवल विधान की बाबत):

2. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा उस सीमा के सिवाय जितनी कि किसी अन्य विभाग को आबंटित की गई है ।

भाग-III

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची -II या सूची III के अंतर्गत आते हैं जहां तक वे इन राज्य क्षेत्रों की बाबत विद्यमान हैं:

3. निःशक्त और अनियोज्य व्यक्तियों की सहायता और सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा से संबंधित उपाय, उस सीमा के सिवाय जितनी कि किसी अन्य विभाग को आबंटित की गई है ।

भाग-IV

साधारण और पारिणामिक

4. समाज कल्याण; समाज कल्याण योजना, परियोजना निरूपण, अनुसंधान, मूल्यांकन, सांख्यिकी और प्रशिक्षण ।
5. सामाजिक सुरक्षा से संबद्ध मामलों पर अन्य देशों के साथ कन्वेंशन्स और अपराध निवारण तथा अपराधियों के उपचार के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ से निर्देश ।
6. जरूरतमंद बालकों की, जिनमें अनाथालय और अनाथ बालक सम्मिलित हैं, देखभाल और विकास के लिए संस्थागत और गैर-संस्थागत सेवाएं तथा अनाथालय ।
7. शारीरिक और मानसिक रूप से निःशक्तों की शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास और कल्याण ।
8. शारीरिक रूप से निःशक्त और मंदितमना लोगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान ।
9. निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों का पुनर्वासन तथा मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का पुनर्वासन ।
10. राष्ट्रीय अंध केन्द्र, जिसमें केन्द्रीय ब्रेल मुद्रणालय, देहरादून सम्मिलित है, वयस्क बधिर प्रशिक्षण केन्द्र तथा आंशिक रूप से बधिर बालकों का विद्यालय, हैदराबाद; मंदितमना बालकों का माडल विद्यालय, नई दिल्ली और अन्य राष्ट्रीय संस्थान ।
11. सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य कार्यक्रम ।
12. भिक्षावृत्ति, किशोर आवागमन, अपचारिता और सी0ए0आर0ई0 के अन्य कार्यक्रम ।
13. किशोर अपराधियों की परीक्षा ।
14. दत्तक-ग्रहण, केन्द्रीय दत्तकग्रहण स्रोत अभिकरण और शिशु हेल्पलाइन (चाइल्डलाइन) संबंधी मुद्दे ।
15. सामाजिक सुरक्षा के सभी मामलों पर अनुसंधान, मूल्यांकन, प्रशिक्षण, सूचना का आदान-प्रदान और तकनीकी मार्गदर्शन ।
16. ऐल्कोहली तथा पदार्थ (औषध) दुरुपयोग और व्यसनियों/कुटुम्बों के पुनर्वास संबंधी सभी विषय ।
17. वृद्ध व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक प्रयासों सहित प्रयासों का उन्नयन ।

18. नशाबंदी संबंधी सभी मामले ।
19. मादक द्रव्य व्यसन के शिक्षा और समाज कल्याण से संबंधित पहलू ।
20. इस मंत्रालय को आबंटित विषयों से संबंधित पूर्त और धार्मिक विन्यास ।
21. इस विभाग को आबंटित विषयों के संबंध में स्वैच्छिक प्रयासों का उन्नयन और विकास ।
22. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान ।
23. शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों का संस्थान, नई दिल्ली ।
24. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि ओरथोपैडिकली हेन्डिकेप्ड, कोलकाता ।
25. राष्ट्रीय पुनर्वासि, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, कटक ।
26. मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान, सिकन्दराबाद ।
27. बधिर व्यक्तियों का अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई ।
28. दृष्टि विहीन व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान, देहरादून ।
29. राष्ट्रीय निःशक्त व्यक्ति वित्त और विकास निगम, फरीदाबाद ।
30. आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, कानपुर ।
31. भारतीय पुनर्वासि परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34) और उसके अधीन गठित की गई पुनर्वासि परिषद ।
32. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 71) ।
33. राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) ।
34. मुख्य आयुक्त, निःशक्तता ।

35. अनुसूचित जातियाँ और अन्य पिछड़े वर्ग, जिसके अंतर्गत ऐसी जातियों और वर्गों के विद्यार्थियों को सी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ भी हैं ।
36. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
37. अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का विकास ।

टिप्पण: अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नोडल मंत्रालय होगा । इन समुदायों के विकास के क्षेत्रीय कार्यक्रमों और स्कीमों के संबंध में नीति, योजना, मानीटरी, मूल्यांकन, इत्यादि एवं उनके समन्वय की भी जिम्मेदारी संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संबंधित क्षेत्रों के प्रशासन की रहेगी । प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय और विभाग अपने-अपने क्षेत्र के लिए नोडल मंत्रालय अथवा विभाग होगा ।

38. पिछड़े वर्गों की दशाओं में अन्वेषण करने के लिए आयोग की रिपोर्ट ।
39. भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों और भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग आयुक्त के कार्यालय से संबंधित मामले ।
40. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए आयोग से संबंधित मामले ।
41. वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) ।
42. निष्क्रान्त संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) के अधीन निष्क्रान्त वक्फ संपत्तियों से संबंधित कार्य ।
43. आंग्ल-भारतीय समाज के लिए प्रतिनिधित्व ।
44. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग और उससे संबंधित सभी मामले ।
45. विधि और व्यवस्था से संबंधित मामलों को छोड़कर, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित सभी मामले ।
46. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन, ऐसे अपराधों, जहाँ तक उनका संबंध अनुसूचित जातियों से है, से संबंधित आपराधिक न्याय के प्रशासन को छोड़कर ।

47. निम्नलिखित अधिनियमों का प्रशासन :

- (क) अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20);
- (ख) बालक अधिनियम, 1960 (1960 का 60);
- (ग) दरगाह ख्वाजा साहिब अधिनियम, 1955 (1955 का 36);
- (घ) किशोर न्याय (बालकों देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56)।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

1. सांख्यिकी स्कंध

1. देश में सांख्यिकी प्रणाली के एकीकृत विकास की योजना बनाने के लिए एक केन्द्रीय (नोडल) अभिकरण के रूप में कार्य करना ।
2. भारत सरकार के विभागों और राज्य सांख्यिकी ब्यूरो (एसएसबी) के सांख्यिकी या आंकड़ों की उपलब्धता की अतारतम्यता या उनकी पुनरावृत्ति का पता लगाने की दृष्टि से सांख्यिकीय कार्य में समन्वय करना तथा आवश्यक उपचारात्मक उपाय सुझाना ।
3. सांख्यिकी के क्षेत्र में आंकड़ों के, जिसमें संग्रहण, प्रसंस्करण की संरचना और परिभाषाएं, कार्य प्रणाली और परिणामों का प्रसार भी है, सन्नियमों तथा मानकों को अधिकथित करना और उनका अनुरक्षण ।
4. भारत सरकार के विभागों को सांख्यिकीय पद्धति और आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण के बारे में सलाह देना ।
5. राष्ट्रीय लेखा तैयार करना और साथ ही राष्ट्रीय आय, सकल/निवल घरेलू उत्पाद, सरकारी और निजी अंतिम उपभोग व्यय, पूंजी निर्माण, बचत, पूंजीगत स्टाक और नियत पूंजी की उपभोग, सकल घरेलू उत्पाद का तिमाही प्राक्कलन, राष्ट्रीय निवेश उत्पाद संव्यवहार तालिका, घरेलू उत्पाद के राज्य स्तरीय प्राक्कलन तथा उपरि क्षेत्रीय (सुपरा-रीजनल) सेक्टरों का नियत पूंजी निर्माण का वार्षिक प्राक्कलन प्रकाशित करना तथा चालू कीमतों पर राज्य घरेलू उत्पाद (एस0डी0पी) के तुलनात्मक प्राक्कलन तैयार करना ।

6. तुरंत प्राक्कलन के रूप में प्रतिमास औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (औ0उ0सू0) संकलित करना और जारी करना; उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (उ0का0वा0सर्वे0) करना; और संगठित विनिर्माणकारी (कारखाना) सेक्टर की वृद्धि, संरचना और ढांचे में परिवर्तनों के निर्धारण और मूल्यांकन के लिए सांख्यिकीय जानकारी उपलब्ध कराना ।
7. पर्यावरण सांख्यिकी का विकास, कार्य-पद्धति का विकास तथा भारत के लिए राष्ट्रीय संसाधन लेखों की अवधारणाएं और उनको तैयार करना ।
8. अखिल भारतीय कालिक आर्थिक संगणना का आयोजन और संचालन करना और नमूना सर्वेक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना ।
9. रोजगार, उपभोक्ता व्यय, आवासन परिस्थितियां, ऋण और विनिधान, भूमि तथा पशुधन संपत्तियां, साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, असंगठित विनिर्माण तथा सेवाएं आदि जैसे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं का विकास, अनुसंधान, नीति निर्माण और आर्थिक नियोजन के लिए आवश्यक डाटा बेस उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रव्यापी नमूना सर्वेक्षण कराना ।
10. क्वालिटी जांचों का संचालन तथा तकनीकी संवीक्षा और नमूना जांच के माध्यम से सांख्यिकी सर्वेक्षणों और डाटा सेटों की लेखा-परीक्षा और यदि अपेक्षित हों तो, संशोधनकारी कारकों और वैकल्पिक प्राक्कलन तैयार करना ।
11. विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के माध्यम से संग्रहीत किए गए सर्वेक्षण आंकड़ों का प्रसंस्करण करना और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन तथा केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अनुवर्ती आर्थिक गणना व उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण के सर्वेक्षण करना ।
12. सरकारी, अर्ध-सरकारी या निजी डाटा प्रयोगकर्ताओं/अधिकरणों को अनेक नियमित या तदर्थ प्रकाशनों के माध्यम से सांख्यिकीय सूचना का प्रसार करना; और संयुक्त राष्ट्र अधिकरणों जैसे यूनाइटेड नेशन्स स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, एकोनामिक एण्ड सोशल कमीशन फार एशिया एण्ड दि पेशिफिक, इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन और अन्य सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय अधिकरणों को, उनके अनुरोध पर, डाटा प्रसारित करना ।
13. विशेष अध्ययन या सर्वेक्षण, सांख्यिकीय रिपोर्टों का मुद्रण और शासकीय सांख्यिकीय के विभिन्न विषय क्षेत्रों से संबंधित वित्त संगोष्ठी, कार्यशाला अथवा सम्मेलन करने के लिए प्रख्यात रजिस्ट्रीकृत गैर-सरकारी संगठनों और अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान देना ।

14. संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में कार्य करना तथा भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रबंधन, जिसमें प्रशिक्षण, व्यवसाय नियोजन और जनशक्ति नियोजन से संबंधित सभी मामले हैं, के सभी पहलुओं की बाबत कार्रवाई करना ।
15. भारतीय सांख्यिकी संस्थान और उसके कृत्यकरण भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम, 1959 (1959 का 57) के उपबंधों के अनुसार, सुनिश्चित करना ।
16. शहरी गैर-श्रमिक कर्मचारियों के लिए मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्याओं का संकलन तथा उन्हें जारी करना ।
17. लघु क्षेत्र प्राक्कलनों सहित बेहतर नमूना तकनीक और प्राक्कलन प्रक्रियाएं विकसित करने के लिए प्रणाली-विज्ञान अध्ययन और आरंभिक सर्वेक्षण करना ।

II. कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध

18. बीस सूत्री कार्यक्रम की मानीटरी करना ।
19. बीस करोड़ रुपए और उससे अधिक की परियोजनाओं की मानीटरी करना ।
20. अव-संरचना सेक्टरों के कार्य-निष्पादन की मानीटरी करना ।
21. संसद-सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (संसद-स्थानीय क्षेत्र विकास योजना) ।

इस्पात मंत्रालय

1. इलैक्ट्रिक आर्क फरनेस (इओआओफओ) यूनिटें, इन्डक्शन फरनेस (इओफओ) यूनिटें, रि.रोलर, फ्लैट (गर्म/ठंडी रोलिंग यूनिट), कोटिंग यूनिट, वायर ड्राइंग यूनिट तथा स्टील स्कैप प्रोसेसिंग जैसी प्रोसेसिंग प्रसुविधाओं सहित, लोहा और इस्पात उत्पादन प्रसुविधाएं स्थापित करने की योजना, विकास और सरलीकरण ।
2. पब्लिक सेक्टर में लोह अयस्क खानों तथा अन्य अयस्क खानों (मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, चूना पत्थर, सिलिमेनाइट, कायनाइट तथा लोहा और इस्पात उद्योग में प्रयुक्त किए जाने वाले अन्य खनिज परन्तु जिसमें खनन पट्टे या उससे संबंधित मामले नहीं हैं) का विकास ।
3. लोहा तथा इस्पात तथा लोहा मिश्रित धातुओं का उत्पादन, वितरण, कीमते, आयात और निर्यात ।

4. स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड और उसकी समनुषंगी कंपनियां ।
5. निम्नलिखित उपक्रमों से संबंधित मामले, अर्थात् :-

- क. विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लि० ।
- ख. दि बोलानी ओर्स (इंडिया) लिमिटेड ।
- ग. दि मैगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड ।
- घ. दि मेटल्स स्कैप ट्रेडिंग कारपोरेशन ।

वस्त्र मंत्रालय

I. साधारण नीति

1. सभी वस्त्रों, जिनमें सूती, ऊनी, पटसन, रेशम, हाथ से बने, हथकरघों और पावरलूमों पर बने, तैयार वस्त्र और सूती, ऊनी, पटसन, रेशम और सेलूलोसिक तंतुओं से संबंधित उद्योग भी हैं, लेकिन गैर-सेलूलोसिक संश्लिष्ट तंतू (नायलान, पोलिएस्टर, ऐकेलिक आदि) नहीं हैं, का उत्पादन, वितरण (देश में खपत और निर्यात के लिए) अनुसंधान और विकास ।
2. कपास, जिसके अंतर्गत उसकी ओटाई और दबाई, घरेलू पूर्ति, निवेश और कीमतों का स्थिरीकरण कार्य भी है ।
3. रेशम उत्पादन ।
4. वस्त्रों, ऊनी वस्त्रों, पावरलूमों हथकरघा, सिलेसिलाए वस्त्रों, रेशम और सेलूलोसिक वस्तुएं, जूट और जूट उत्पादों और हस्तशिल्पों के संबंध में निर्यात संवर्धन का विकास और विस्तार ।
5. पटसन और पटसन उत्पाद ।
6. हस्तशिल्प ।

II. कार्यालय

7. विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय, नई दिल्ली ।

8. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय, नई दिल्ली ।
9. पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता ।
10. संदाय आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली ।
11. संदाय आयुक्त का कार्यालय (पटसन), कोलकाता ।
12. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई ।

III. कानूनी/स्वायत्त निकाय

13. पटसन विनिर्माता विकास परिषद, कोलकाता ।
14. केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर ।
15. भारतीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली ।
16. राष्ट्रीय जूट विविधीकरण केन्द्र, कोलकाता ।
17. भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही ।
18. राष्ट्रीय डिजाइन और उत्पाद विकास केन्द्र, दिल्ली ।
19. धातु हस्तशिल्प सेवा केन्द्र, मुरादाबाद ।
20. भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी, जोधपुर, सलेम और वाराणसी ।
21. वस्त्र समिति, मुंबई ।

IV. पब्लिक सेक्टर उपक्रम

22. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ ।

23. भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कोलकाता ।
24. राष्ट्रीय पटसन विनिर्माता निगम लिमिटेड, कोलकाता और इसकी समनुषंगी ।
25. राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, और इसकी समनुषंगी ।
26. भारतीय कपास निगम लिमिटेड, मुंबई ।
27. हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम, नई दिल्ली ।
28. केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम, नई दिल्ली ।
29. ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर और इसकी समनुषंगी ।

V. बोर्ड

30. केन्द्रीय रेशम बोर्ड ।
31. केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड ।
32. कपास सलाहकार बोर्ड ।
33. अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड ।
34. अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ।
35. अखिल भारतीय पावरलूम बोर्ड ।
36. पटसन सलाहकार बोर्ड ।

VI. सलाहकार/विकास परिषद्

37. केन्द्रीय वस्त्र उद्योग सलाहकार परिषद् ।
38. पटसन विनिर्माण विकास परिषद्, कोलकाता ।

39. वस्त्र उद्योग विकास परिषद् ।
40. वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण संबंधी स्थायी परिषद् ।
41. वस्त्र अनुसंधान संगमों संबंधी समन्वय परिषद् ।

VII. परिषदे

42. हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद्, चेन्नई ।
43. भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद्, मुम्बई ।
44. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली ।
45. पावरलूम विकास और निर्यात संवर्धन परिषद्, मुंबई ।
46. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, मुम्बई ।
47. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली ।
48. सिंथेटिक और रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, मुंबई ।
49. ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली ।
50. परिधान निर्यात संवर्धन परिषद्, मुंबई ।

VIII. संगम

51. भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संगम, कोलकाता ।
52. अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संगम, अहमदाबाद ।
53. बंबई वस्त्र अनुसंधान संगम, मुंबई ।
54. मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान संगम, सूरत ।

55. दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संगम, कोयम्बटूर ।
56. उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संगम, गाजियाबाद ।
57. रेशम और कृत्रिम रेशम मिल्स अनुसंधान संगम, मुंबई ।
58. ऊन अनुसंधान संगम, मुंबई ।
59. हथकरघा विभाग और शीर्षस्थ सोसाइटियों का संगम, नई दिल्ली ।

IX. अंतर्राष्ट्रीय पहलू

60. अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति ।
61. अंतर्राष्ट्रीय कपास संस्थान ।
62. एशिया-प्रशान्त वस्त्र और वस्त्र उद्योग मंच ।
63. अंतर्राष्ट्रीय पटसन अध्ययन समूह ।

X. अधिनियम

64. केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) ।
65. कपड़ा समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41)।
66. जूट विनिर्मित विकास परिषद, अधिनियम, 1983 (1983 का 27)।
67. जूट विनिर्मित उपकर अधिनियम, 1983 (1983 का 28)।
68. हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 (1985 का 22) ।
69. जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) ।

पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय

क. पर्यटन विभाग

1. पर्यटन का विकास और संवर्धन ।
2. पर्यटन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ।
3. भारत पर्यटन विकास निगम और स्वायत्त संस्थान ।

ख. संस्कृति विभाग

1. पुस्तकालय विकास संबंधी नीतिगत मामले ।
2. राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता; केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता; केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय, नई दिल्ली; रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर; दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली; खुदाबख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना; राजाराम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता; भारत कार्यालय पुस्तकालय, लंदन ।
3. राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपत्ति संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ ।
4. राष्ट्रीय पांडुलिपि परिरक्षण मिशन ।
5. भारत पुरातत्त्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली; पुरातत्त्वीय स्थल संग्रहालय; ऐतिहासिक और पुरातत्त्वीय अवशेषों का उत्खनन और खोज ।
6. ऐतिहासिक और पुरातत्त्वीय अवशेषों के उत्खनन और खोज कार्य के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं को अनुदान ।
7. सशस्त्र संघर्ष की दशा में सांस्कृतिक सम्पत्ति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय ।
8. स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास ।

9. गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली; नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली; जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक न्यास; मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता; भारतीय युद्ध स्मारक ।
10. ललित कलाओं, अभिनय कलाओं की अभिवृद्धि ।
11. साहित्य अकादमी; ललित कला अकादमी; संगीत नाटक अकादमी ।
12. राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली; भारतीय संग्रहालय, कोलकाता; सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद; इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद; राष्ट्रीय नव कला दीर्घा नई दिल्ली, मुंबई और बंगलौर; विक्टोरिया स्मारक हाल, कोलकाता; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल; राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता; रत्न और आभूषण संग्रहालय; संग्रहालयों का व्यापक विकास ।
13. राष्ट्रीय कला, संरक्षण और संग्रहालय-विज्ञान इतिहास संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली ।
14. भारतीय और विदेशी कला वस्तुओं का अर्जन ।
15. ग्रामीण क्षेत्रों में खुली नाट्यशालाएं और राज्यों की राजधानियों में नाट्यशालाएं ।
16. निर्धनावस्था वाले ऐसे लेखकों और कलाकारों अथवा उनके उत्तरजीवियों, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की स्कीम के अधीन नहीं आते, को वित्तीय सहायता; सांस्कृतिक संगठनों और संस्थाओं को अनुदान; इस विभाग में व्यवहृत विषयों के संबंध में छात्रवृत्तियां और अध्येतावृत्ति, जिनमें विदेशी सरकारों और विदेशी अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां और अध्येतावृत्ति भी हैं; बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक प्रक्षेत्र स्थापित करने के लिए अनुदान ।
17. दान और पूर्त संस्थाएं, इस विभाग में व्यवहृत विषयों से संबद्ध दान और धार्मिक विन्यास ।
18. इस विभाग में व्यवहृत विषयों के संबंध में छात्रवृत्तियां जिसके अंतर्गत विदेशी सरकारों और विदेशी अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी हैं ।
19. दुर्लभ हस्तलेखों का प्रकाशन ।
20. परंपरागत संस्कृति और लोक संस्कृति की सुरक्षा ।
21. भारतीय विदेशी सांस्कृतिक सोसाइटियों को अनुदान ।

22. विदेशों के साथ सांस्कृतिक करार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सी.ई.पी.) और मैत्री संधियां ।
23. विदेशों से दान में प्राप्त पुस्तकों का वितरण ।
24. विदेशों में सांस्कृतिक अताशियों की नियुक्ति ।
25. समर्थित और असमर्थित सांस्कृतिक शिष्टमंडलों, आदि द्वारा भारत का परिदर्शन ।
26. विदेश परिदर्शन के लिए सरकार द्वारा समर्थित व्यक्ति (जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक व्याख्याता भी हैं) ।
27. विदेशों को पुस्तकें भेंट करना ।
28. विदेशों में पुस्तकालयों की स्थापना ।
29. भारतीय वरेण्य ग्रंथों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद ।
30. शासकीय प्रकाशनों का विदेशी सरकारों और संस्थाओं के साथ विनिमय और ऐसे विनिमयों के लिए करार ।
31. विदेशों में भारतीय कला वस्तुओं का प्रदर्शन ।
32. पुरावशेषों का निर्यात ।
33. सांस्कृतिक संस्थाओं में विदेशी विद्यार्थियों का प्रवेश ।
34. सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अधीन कलाकारों, नर्तकों, संगीतज्ञों, आदि का विनिमय ।
35. विदेशों में भारत पर्व ।
36. गजेटियरों का पुनरीक्षण ।
37. महत्वपूर्ण व्यक्तियों की शताब्दियां और वार्षिकोत्सव और घटनाओं को मनाना ।
38. सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली ।

39. इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरियंटलिस्ट्स ।
40. भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता ।
41. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली; गजेटीयर्स; एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता ।
42. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ।
43. रवीन्द्र रंगशाला ।
44. आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्र ।
45. राष्ट्रीय संस्कृति परिषद ।
46. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली ।
47. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली; राष्ट्रीय नाट्यगृह ।
48. राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि ।
49. गांधी शांति पुरस्कार ।
50. केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ; केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह; नव नालन्दा महाविद्यालय, नालन्दा ।
51. कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई ।
52. निम्नलिखित अधिनियमों का कार्यान्वयन और प्रवर्तन, अर्थात् :
 - (क) भारतीय निखात निधि अधिनियम, 1878 (1878 का 6);
 - (ख) पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 (1972 का 52);
 - (ग) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24);
 - (घ) प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (1904 का 4) ।
 - (ङ) पुस्तक और समाचार पत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954 (1954 का 27) ;

- (च) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) (जहां तक कि केन्द्रीय सरकार को पुस्तकें और सूची पत्र देने का संबंध है);
- (छ) लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 (1993 का 69)।

जनजातीय कार्य मंत्रालय

1. अनुसूचित जनजातियों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा ।
2. जनजातीय कल्याण : जनजातीय कल्याण आयोजना, परियोजना निर्माण, अनुसंधान, मूल्यांकन, सांख्यिकी और प्रशिक्षण ।
3. जनजातीय कल्याण के बारे में स्वयंसेवी प्रयासों का संवर्धन और विकास ।
4. अनुसूचित जनजातियां, जिनमें ऐसी जनजातियों से संबंधित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति शामिल है।
5. अनुसूचित जनजातियों का विकास ।

टिप्पण: अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय के लिए अनुसूचित जनजातीय कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय होगा । इन समुदायों के विकास के क्षेत्रीय कार्यक्रमों और विकास स्कीमों के संबंध में नीति, योजना, मानीटरी, मूल्यांकन, आदि एवं उनके समन्वय की भी जिम्मेदारी संबद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होगी । प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग अपने-अपने क्षेत्र के लिए नोडल मंत्रालय अथवा विभाग होगा ।

6. (क) अनुसूचित क्षेत्र;
 - (ख) सड़कों और उन पर पुल संकर्मों और पारघाटों को छोड़कर, असम के स्वायत्तशासी जिलों से संबद्ध मामले; और
 - (ग) अनुसूचित क्षेत्रों के लिए और संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 के साथ संलग्न सारणी के भाग 'क' में विनिर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों के लिए राज्यों के राज्यपालों द्वारा विरचित विनियम ।
7. (क) अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के विषय में रिपोर्ट करने के लिए आयोग; तथा

(ख) किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक स्कीमों की संरचना और निष्पादन की बाबत निदेश जारी करना ।

8. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ।

9. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) का कार्यान्वयन, ऐसे अपराधों, जहां तक उनका संबंध अनुसूचित जातियों से है, से संबंधित आपराधिक न्याय के प्रशासन को छोड़कर ।

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

क. शहरी विकास विभाग

1. निम्नलिखित के सिवाय संघ की सम्पत्तियां, चाहे वे भूमि हो अथवा भवन, अर्थात् :

(क) वे जो रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के हों;

(ख) ऐसे भवन अथवा भूमि, जिनके संनिर्माण अथवा अर्जन के लिए धनराशि सिविल संकर्म बजट से भिन्न किन्हीं अन्य साधनों से जुटाई गई हो;

(ग) ऐसी भूमि अथवा भवन, जिसका नियंत्रण, उनके संनिर्माण अथवा अर्जन के समय अथवा बाद में, स्थायी रूप से दूसरे मंत्रालयों और विभागों को सौंप दिया गया हो ।

2. सभी सरकारी सिविल संकर्म और भवन, जिनके अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के संकर्म और भवन तो हैं, किन्तु सड़कें और रेल मंत्रालय, डाक विभाग, दूरसंचार विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग द्वारा निष्पादित संकर्म या उनके भवन नहीं हैं ।

3. उद्यान कृषि संकियाएं ।

4. केन्द्रीय लोक निर्माण संगठन ।

5. इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी होस्टलों सहित सरकारी सम्पदाओं का प्रशासन । महानगरों में कार्यालयों का अवस्थापन या वहां से उनका विसर्जन ।

6. विज्ञान भवन में जगह का आबंटन ।

7. चार पुनर्वास बाजारों, अर्थात् सरोजिनी नगर मार्केट, शंकर मार्केट, प्लेजर गार्डन मार्केट और कमला मार्केट का प्रशासन ।
8. विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) के अधीन दिल्ली और नई दिल्ली में सरकार निर्मित सम्पत्तियों की बाबत पट्टा या हस्तांतरण पत्र जारी करना और पट्टा विलेखों का संपरिवर्तन करना तथा ऐसी सम्पत्तियों से लगी हुई भूमि की अतिरिक्त पट्टियों और सुधारक क्षेत्रों का आबंटन ।
9. भारत सरकार के लिए लेखन सामग्री और मुद्रण, जिसके अंतर्गत शासकीय प्रकाशन भी है ।
10. रेल मंत्रालय, रेल बोर्ड को आबंटित कार्य-मदों के अधीन रहते हुए रेल आधारित प्रणालियों की तकनीकी योजना सहित शहरी परिवहन प्रणालियों की योजना और समन्वय ।
11. भारतीय रेल द्वारा निधिबद्ध प्रणालियों को छोड़कर, रेल आधारित शहरी परिवहन प्रणालियों के लिए अधिकतम और न्यूनतम दरों तथा भाड़ों का नियतन ।
12. ट्रामवे जिसके अंतर्गत नगर निगम सीमाओं अथवा किसी अन्य संलग्न क्षेत्र के भीतर उन्नत द्रुतगामी ट्राम भी शामिल है ।
13. नगर और ग्राम योजना; महानगरीय क्षेत्रों के विकास और योजना से संबंधित मामले, इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता ।
14. दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास और निपटान की स्कीम ।
15. दिल्ली विकास प्राधिकरण ।
16. दिल्ली का मास्टर प्लान, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में मास्टर प्लान तथा गन्दी बस्ती सफाई विषयक काम का समन्वय ।
17. स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में स्मारकों का परिनिर्माण ।
18. सरकारी बस्तियों का विकास ।
19. स्थानीय शासन, अर्थात् नगर निगमों का (जिनके अंतर्गत दिल्ली नगर निगम नहीं आता है), नगर पालिकाओं का (जिनके अंतर्गत नई दिल्ली नगर पालिका समिति नहीं आती है) और अन्य स्थानीय स्वायत्त प्रशासनों का, जिनके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाएं नहीं आती है, गठन और उनकी शक्तियां ।

20. दिल्ली नगर निगम का दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन उपक्रम ।
21. शहरी क्षेत्रों से संबंधित (जल संसाधन मंत्रालय को सौंपे गए जल योजना और समन्वय के सम्पूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अर्धीन रहते हुए) जल प्रदाय, मल, जल-निकास तथा स्वच्छता और आबंटित जल संसाधनों से अनुबंध । इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता ।
22. केन्द्रीय स्व-शासन परिषद् ।
23. दिल्ली में सरकारी भूमि का आबंटन ।
24. राजघाट समाधि समिति का प्रशासन ।
25. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजना और विकास तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) के प्रशासन से संबंधित सभी विषय ।
26. भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास (इनटैक) से संबंधित विषय ।
27. शहरी अवसंरचना से संबंधित आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) के मामले ।
28. स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 का 30) का प्रशासन ।
29. दिल्ली होटल (वास-सुविधा-नियंत्रण) अधिनियम, 1949 (1949 का 24) का प्रशासन ।
30. सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) ।
31. दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) का प्रशासन ।
32. दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 (1958 का 59) ।
33. नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33) ।
34. दिल्ली नागरी कला आयोग, दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 (1973 का 1) ।

ख. शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग

1. आवास नीति और कार्यक्रम तैयार करना (ग्रामीण आवास को छोड़कर, जिसे ग्रामीण विकास विभाग को सौंपा गया है), योजना स्कीमों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन, आवास, निर्माण सामग्री और निर्माण तकनीक संबंधी आंकड़ों का संग्रहण और प्रसारण, निर्माण लागत घटाने के लिए साधारण उपाय और राष्ट्रीय आवास नीति का केन्द्रीय उत्तरदायित्व ।

2. मानव बस्तियां, जिसके अंतर्गत यूनाइटेड नेशन्स कमीशन फार ह्यूमन सेटलमेन्ट्स आवासन और मानव-बस्ती के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता भी है ।
3. नगर विकास, जिसके अंतर्गत गंदी बस्ती सफाई स्कीमें तथा झुग्गी-झोंपड़ी हटाने की स्कीमें भी है । इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता ।
4. राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ ।
5. शहरी रोजगार और शहरी गरीबी उपशमन संबंधी विशिष्ट कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, जिसके अंतर्गत समय-समय पर बनाए गए अन्य कार्यक्रम भी है ।
6. शहरी संरचना से संबंधित मामलों से भिन्न, आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) से संबंधित सभी मामले ।

जल संसाधन मंत्रालय

I. साधारण

1. राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जल का विकास, संरक्षण और प्रबंध; जल के विविध उपयोगों के संबंध में जल योजना और समन्वय का संपूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य ।
2. राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् ।
3. साधारण नीति, तकनीकी सहायता, अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण और सिंचाई से संबंधित सभी मामले, जिनके अंतर्गत बहुउद्देशीय, बड़े, मध्यम, लघु और आपातकालिक सिंचाई संकर्म भी आते हैं; नौवहन और जल विद्युत संबंधी जलीय संरचनाएं; नलकूप और भूमिगत जल का अन्वेषण एवं दोहन; भूमिगत जल संसाधनों का संरक्षण और परिरक्षण; धरातलीय और भूमिगत जल का संयुक्त उपयोग, कृषि प्रयोजनों के लिए सिंचाई, जल प्रबंध, कमान क्षेत्र विकास; जलाशयों और जलाशय अवसादन का प्रबंध; बाढ़ (नियंत्रण) प्रबंध, जल-निकास, सूखा नियंत्रण, जल-जमाव और समुद्री कटाव समस्याएं; बांध सुरक्षा ।
4. अंतर्राष्ट्रीय नदियों और नदी घाटियों का विनियमन और विकास । स्कीमों के माध्यम से अधिकरणों के अधिनिर्णय का कार्यान्वयन, नदी बोर्ड ।
5. जल विधि, विधायन ।

6. जल गुणवत्ता निर्धारण ।
7. केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा (समूह क) का काडर नियंत्रण और प्रबंध ।

II. अंतर्राष्ट्रीय पहलू

8. जल संसाधन विकास और प्रबंध, जल निकास और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आयोग और सम्मेलन ।
9. अंतर्राष्ट्रीय जल विधि ।
10. भारत और पड़ोसी देशों की साझी नदियों से संबंधित मामले; बंगलादेश के साथ संयुक्त नदी आयोग, सिंधु जल संधि, 1960; स्थायी सिंधु आयोग ।
11. जल संसाधन विकास के क्षेत्र में द्विपक्षीय और बाह्य सहायता तथा सहयोग कार्यक्रम ।

III. मंत्रालय के अधीन संगठन और निकाय

12. केन्द्रीय जल आयोग ।
13. केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केन्द्र ।
14. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ।
15. केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण ।
16. केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र ।
17. फरक्का बैराज परियोजना ।
18. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ।
19. फरक्का बैराज परियोजना नियंत्रण बोर्ड ।
20. सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति ।
21. ब्रह्मपुत्र बोर्ड ।

22. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ।
23. बेतवा नदी बोर्ड ।
24. राष्ट्रीय जल-विज्ञान संस्थान ।
25. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ।
26. बाणसागर नियंत्रण बोर्ड ।
27. तुंगभद्रा बोर्ड ।
28. ऊपरी यमुना नदी बोर्ड ।
29. जल और विद्युत परामर्शी सेवा (इंडिया) लिमिटेड (वापकोस) ।
30. राष्ट्रीय परियोजना संनिर्माण निगम लिमिटेड ।

IV. अधिनियमों का प्रशासन

31. उत्तरी भारत नहर और जल-निकास अधिनियम, 1873 (1873 का 8) ।
32. अंतर-राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) ।
33. नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 (1956 का 49) ।
34. बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1976 (1976 का 63) ।
35. ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) ।

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

1. क्रीड़ा नीति ।
2. क्रीड़ा और खेल ।

3. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि ।
4. नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान ।
5. भारतीय क्रीड़ा प्राधिकरण ।
6. भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन और राष्ट्रीय खेल परिसंघ से संबंधित मामले ।
7. विदेशों में टूर्नामेंट में भारतीय क्रीड़ा टीमों द्वारा भाग लेना और भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में विदेशी क्रीड़ा टीमों द्वारा भाग लेना ।
8. राष्ट्रीय क्रीड़ा पुरस्कार, जिसके अंतर्गत अर्जुन पुरस्कार भी है ।
9. क्रीड़ा छात्रवृत्तियाँ ।
10. विदेशों के साथ खिलाड़ियों, युवा प्रतिनिधि मंडल, विशेषज्ञों और टीमों का आदान-प्रदान ।
11. क्रीड़ा अवसंरचना, जिसके अंतर्गत ऐसी अवसंरचना के सृजन और विकास के लिए वित्तीय सहायता भी है ।
12. कोचिंग, टूर्नामेंट, उपस्कर, आदि के लिए वित्तीय सहायता ।
13. संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित क्रीड़ा मामले ।
14. युवा कार्य/युवा नीति ।
15. नेहरू युवा केन्द्र संगठन ।
16. राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर स्कीम ।
17. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान ।
18. ग्रामीण युवा और क्रीड़ा क्लबों को दी जाने वाली सहायता संबंधी स्कीम ।
19. राष्ट्रीय युवा आयोग ।
20. राष्ट्रीय सेवा स्कीम ।
21. स्वयंसेवी युवा संगठन, जिनके अंतर्गत उनको दी जाने वाली वित्तीय सहायता भी है ।

22. राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवी स्कीम ।
23. राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक ।
24. युवा कल्याण क्रियाकलाप, युवा उत्सव, वर्क कैम्प, आदि ।
25. ब्वाय-स्काउट और गर्ल-गाइड ।
26. युवा हॉस्टल ।
27. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार ।
28. भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुशासन स्कीम का अवशिष्ट कार्य ।
29. शारीरिक शिक्षा ।

परमाणु ऊर्जा विभाग

1. निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले:

- (क) परमाणु ऊर्जा आयोग (प0ऊ0आ0);
- (ख) परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (प0ऊ0वि0बो0) ।

2. भारत में परमाणु ऊर्जा से संबंधित सभी मामले, अर्थात् :

- (क) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) का प्रशासन, जिसके अंतर्गत रेडियो-एक्टिव पदार्थों का नियंत्रण और उनके कब्जे, उपयोग, व्ययन और परिवहन का विनियमन भी है;
- (ख) अनुसंधान, जिसके अंतर्गत परमाणु ऊर्जा से संबंधित मामलों में मौलिक अनुसंधान और कृषि, जीवविज्ञान, उद्योग और आयुर्विज्ञान में उसके उपयोगों का विकास भी है;
- (ग) परमाणु खनिज-सर्वेक्षण, पूर्वक्षण, बरमाना, विकास, खनन, अर्जन और नियंत्रण;
- (घ) परमाणु ऊर्जा के विकास और उपयोग से संबंधित सभी क्रियाकलाप, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं :

- (i) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के अधीन विहित पदार्थों और खनिजों से संबंधित परियोजनाएं और उद्योग; उनके उत्पाद और उपोत्पाद;
 - (ii) परमाणु ऊर्जा के उपयोग से बिजली का उत्पादन;
 - (iii) अनुसंधान और विद्युत रिक्टरों का डिजाइन, सन्निर्माण और प्रचालन; और
 - (iv) निम्नलिखित के विविध रूपण सहित सुविधाओं और संयंत्रों की स्थापना और संक्रियण;
 - (क) परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में और उनके उपयोग के लिए तथा न्यूक्लीय विज्ञानों में अनुसंधान के लिए अपेक्षित सामग्री और उपस्कर के उत्पादन के लिए; और
 - (ख) समस्थानिकों के पृथक्करण के लिए, जिसमें मुख्य या गौण उत्पाद के रूप में भारी पानी के उत्पादन और उपोत्पाद के रूप में समस्थानिकों के पृथक्करण के लिए अनुकूलनीय संयंत्र शामिल है ।
- (ड.) विहित या रेडियो-एक्टिव पदार्थों से संबंधित राज्य उपक्रमों का पर्यवेक्षण जिनके अंतर्गत निम्नलिखित हैं :
- (i) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड(आई0आर0ई0एल0);
 - (ii) इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि0 (ई0सी0आई0एल0);
 - (iii) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि0(यू0सी0आई0एल0);
 - (iv) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड(एन0पी0सी0आई0एल0);
 - (v) नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जहां तक भारी पानी के उत्पादन का संबंध है ।

3. न्यूक्लीय विज्ञानों के अध्ययन को बढ़ावा देने और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित जन-शक्ति के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं:

- (क) वैज्ञानिक कार्य में लगी हुई संस्थाओं तथा संगमों को और न्यूक्लीय विज्ञानों में उच्च अध्ययन और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता;
- (ख) विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थाओं के विद्यार्थियों को वैज्ञानिक विषयों में छात्रवृत्तियों का प्रदान और व्यस्तियों को, जिनके अंतर्गत न्यूक्लीय विज्ञानों के अध्ययनार्थ विदेश जाने वाले विद्यार्थी भी हैं, अन्य रूप में वित्तीय सहायता; और

- (ग) विकिरण औनकोलोजी में न्यूक्लीय औषध को बढ़ावा देने और अनुसंधान के लिए अस्पतालों तथा अनुसंधान केन्द्रों को सहायता ।
4. परमाणु ऊर्जा और नाभिकीय विज्ञान से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित हैं:
- (क) संयुक्त राष्ट्र संघ विशिष्टता प्राप्त अधिकरणों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण, अन्य अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठनों, जिसमें यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन भी है, में परमाणु ऊर्जा और नाभिकीय विज्ञान से संबंधित मामले तथा अन्य देशों से संबंध; और
- (ख) विदेशी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, आदि के साथ विदेशी अध्येतावृत्तियों और भारतीय वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण के संबंध में पत्र-व्यवहार ।
5. परमाणु ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिक संबंधी सभी मामले ।
6. परमाणु ऊर्जा विभाग के पूंजी बजट के प्रति विकलनीय संकर्मों का निष्पादन और भूमि का कय ।
7. परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अपेक्षित सामान और उपस्कर का प्राप्त किया जाना ।
8. परमाणु ऊर्जा विभाग के संबंध में वित्तीय मंजूरियां ।
9. उच्चतर गणित की उन्नति से संबंधित सभी मामले, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित हैं :
- (क) उच्च अध्ययन और अनुसंधान के संवर्धन और समन्वय संबंधी मामले;
- (ख) उच्चतर गणित में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारतीय राष्ट्रीय गणित समिति और अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ;
- (ग) उच्चतर गणित की उन्नति में लगे हुए विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और संगमों को अनुदान; और
- (घ) उच्च अध्ययन और अनुसंधान के लिए छात्रवृत्तियों का प्रदान और अन्य रूपों में वित्तीय सहायता ।
10. परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित सहायता प्राप्त संस्थानों के संबंध में सभी मामले, अर्थात्:
- (क) टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, मुंबई;

- (ख) टाटा मेमोरियल केन्द्र, मुंबई;
 - (ग) साहा नाभिकीय भौतिक-विज्ञान संस्थान, कोलकाता;
 - (घ) परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी, मुंबई;
 - (ङ.) गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई;
 - (च) भौतिक-विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर;
 - (छ) हरिश्चन्द्र अनुसंधान संस्थान (एच0आर0आई0), इलाहाबाद;
 - (ज) प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर ।
11. अन्य सहायता अनुदान वाले संस्थानों, जिनका संबंध परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा वित्त-पोषित क्रिया-कलापों से है, से संबंधित सभी मामले ।

महासागर विकास विभाग

1. महासागर से संबंधित ऐसे मामले जो किसी अन्य विभाग/मंत्रालय को विनिर्दिष्टता आबंटित न किए गए हों ।
2. महासागर और ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित नीति, समन्वय, और स्कीमों जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है :
 - (क)(i) अनुसंधान (मौलिक अनुसंधान सहित) और उससे संबंधित उपयोगों का विकास ;
 - (ii) प्रौद्योगिकीय विकास;
 - (iii) सजीव और निर्जीव समुद्री संसाधनों की उपलब्धता का पता लगाने और उनका मानचित्रांकन करने के लिए सर्वेक्षण;
 - (iv) समुद्री संसाधनों का परिरक्षण, संधारण और संरक्षण;
 - (v) समुचित कौशल और जनशक्ति का विकास;
 - (vi) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहकारिता ;

(ख) उपर्युक्त से संबंधित कानून और विनियामक संबंधी उपाय ।

3. खुले सागर में समुद्री पर्यावरण ।
4. महासागर आयोग ।
5. सर्वभारतीय समुद्र विज्ञान संगम ।
6. महासागर विज्ञान और प्रौद्योगिकीय अभिकरण अथवा बोर्ड ।
7. राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ओ.टी.)
8. राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागर अनुसंधान केन्द्र (एन.सी.ए.ओ.आर.)
9. भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (आई.एन.सी.ओ.आई.एस.)

अंतरिक्ष विभाग

1. अंतरिक्ष आयोग और उससे संबंधित सभी मामले ।
2. अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष उपयोजन से संबंधित सभी मामले, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है,

(क) अंतरिक्ष और इसके उपयोजन से संबंधित मामलों में अनुसंधान (जिसमें मूलभूत अनुसंधान भी है);

(ख) अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी मामले;

(ग) अंतरिक्ष उपयोजन से संबंधित सभी मामले; और

(घ) बाह्य अंतरिक्ष के विकास और उपयोग से संबंधित सभी क्रियाकलाप, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है :

(i) बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग से संबंधित परियोजनाएं और उद्योग, जिसमें अंतरिक्ष का वाणिज्यिक दोहन भी है;

(iii) राकेट और सेटेलाइट्स का डिजाइन, विनिर्माण और प्रमोचन; और

(iv) अंतरिक्ष उपयोजन से संबंधित कार्य ।

3. अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष उपयोजन में अनुसंधान और अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए और अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है:
 - (क) वैज्ञानिक कार्य में लगी हुई संस्थाओं और संगमों को और अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष उपयोजन में उच्च अध्ययन और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता;
 - (ख) अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष उपयोजन के क्षेत्र में अध्ययन के लिए शिक्षा संस्थाओं में छात्रों को छात्रवृत्तियां देना और व्यक्तियों को जिनमें विदेश जाने वाले व्यक्ति भी हैं, अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता देना ।
4. अंतरिक्ष से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :
 - (क) संयुक्त राष्ट्र के विशिष्टियां प्राप्त अभिकरणों में अंतरिक्ष से संबंधित और अन्य देशों के साथ संबंध विषयक मामले; और
 - (ख) विदेशी छात्रवृत्तियों और भारतीय वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण के संबंध में विदेश स्थित विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं से पत्र-व्यवहार ।
5. विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिकों से संबंधित सभी मामले ।
6. अंतरिक्ष विभाग के बजट के प्रति विकलनीय संकर्मों का निष्पादन और भूमि का क़य ।
7. अंतरिक्ष विभाग द्वारा अपेक्षित सामान और उपस्कर अधिप्राप्त करना ।
8. अंतरिक्ष विभाग से संबंधित वित्तीय मंजूरियां ।
9. भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद से संबंधित सभी मामले ।
10. राष्ट्रीय सुदूर सुग्राह्यता अभिकरण (एन0आर0एस0ए0) से संबंधित सभी मामले ।
11. राष्ट्रीय प्राकृतिक संपदा प्रबंध प्रणाली से संबंधित सभी विषय, जिसके अंतर्गत सुदूर सुग्राह्यता पर मुख्य रूप से आधारित समेकित आंकड़ों की तैयारी और ऐसी जानकारी के विश्लेषण और प्रसारण में सहायता भी है ।
12. राष्ट्रीय मध्यमण्डल समताप मंडल और क्षोभमंडल राडार सुविधा से संबंधित सभी मामले।

13. अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड ।

14. पूर्वोत्तर अंतरिक्ष उपयोजन केन्द्र ।

मंत्रिमंडल सचिवालय

1. मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय समितियों के लिए अनुसचिवीय सहायता ।

2. कामकाज के नियम ।

3. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (1947 का 2); केन्द्रीय जांच ब्यूरो (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन, जिसके अंतर्गत विधि प्रभाग, तकनीकी प्रभाग, नीति प्रभाग और प्रशासन प्रभाग भी हैं); खाद्य अपराध स्कंध; और आर्थिक अपराध स्कंध ।

राष्ट्रपति सचिवालय

1. राष्ट्रपति के लिए सचिवीय सहायता की व्यवस्था करना ।

प्रधानमंत्री कार्यालय

1. प्रधानमंत्री के लिए सचिवीय सहायता की व्यवस्था करना ।

योजना आयोग

1. तकनीकी कार्मिक सहित देश के भौतिक, पूंजी संबंधी और मानव साधनों का निर्धारण तथा जो साधन कम पाए जाएं उनकी वृद्धि के लिए प्रस्थापनाओं का तैयार किया जाना ।

2. देश के साधनों के अधिकतम प्रभावशाली और संतुलित उपयोग के लिए योजनाओं का तैयार किया जाना ।

3. उन प्रक्रमों का परिनिश्चय करना, जिनमें योजना पूर्विकताओं के अवधारण पर, कार्यान्वित की जानी चाहिए और हर एक प्रक्रम की पूर्ति के लिए साधनों का आबंटन ।

4. योजना के सभी पहलुओं के कार्यान्वयन के लिए जिस प्रकार का तंत्र आवश्यक है उसका अवधारण करना ।

5. ऐसे कारकों का पता लगाना जिनसे आर्थिक विकास की गति धीमी हो रही हो तथा वर्तमान सामाजिक, और राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, ऐसी दशाओं का अवधारण करना जिन्हें योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए स्थापित किया जाना चाहिए ।

6. योजना के हर एक प्रक्रम के निष्पादन में हुई प्रगति को समय-समय पर आंकना तथा नीतियों के समायोजन एवं उपायों, जो ऐसे आकलन में आवश्यक बताए गए हों, की सिफारिश करना ।
7. राष्ट्रीय विकास में जन सहयोग ।
8. समय-समय पर अधिसूचित क्षेत्र विकास के लिए विनिर्दिष्ट कार्यक्रम ।
9. परिप्रेक्षी योजना ।
10. अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान ।
11. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का समग्र समन्वय ।

टिप्पण: प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (प्र0मं0ग्रा0यो0) के समग्र समन्वय की जिम्मेदारी योजना आयोग की होगी। तथापि, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत सेक्टर संबंधी कार्यक्रमों के समग्र प्रबंध और मानीटरी की जिम्मेदारी संबंधित नोडल मंत्रालय/विभाग की होगी ।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग

1. उत्तर पूर्वी क्षेत्र की विकास संबंधी योजनाओं और परियोजनाओं, जिनके अंतर्गत विद्युत, सिंचाई, सड़क और संचार के क्षेत्र भी हैं, की आयोजना, कार्यान्वयन और मानीटरी से संबंधित मामले ।
2. उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा सीमा-क्षेत्र विकास कार्यक्रम ।
3. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए गैर-व्यपगत निधि ।
4. नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ।
5. नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (एन0ई0डी0एफ0आई0) ।
6. नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एन0ई0आर0ए0एम0सी0) ।
7. दि सिक्किम माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड ।
8. उत्तर-पूर्वी हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम (एन0ई0एच0एच0डी0सी0) शिलांग ।
9. उत्तर पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः वित्त-पोषित सड़क संकर्म ।
10. उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सड़क और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन की योजना ।" ।

आ.प.जै. अब्दुल कलाम
राष्ट्रपति।

[फा. सं. 1/22/1/2003-कैय]
बी.बी. जैन, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th January, 2004

S.O. 17(E).— In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and seventy - first Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,-

(a) in rule 3, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) The distribution of subjects among the departments shall be as specified in the Second Schedule to these rules and shall include all attached and subordinate offices or other organisations including Public Sector Undertakings concerned with its subjects and sub-rules (2), (3) and (4) of this rule.”;

(b) for the First Schedule and the Second Schedule, the following Schedules shall be substituted, namely:-

“THE FIRST SCHEDULE

(Rule 2)

**MINISTRIES, DEPARTMENTS, SECRETARIATS AND OFFICES
(MANTRALAYA, VIBHAG, SACHIVALAYA TATHA KARYALAYA)**

1. Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya)
 - (i) Department of Agriculture and Cooperation (Krishi aur Sahkarita Vibhag)
 - (ii) Department of Agricultural Research and Education (Krishi Anusandhan aur Shiksha Vibhag)
 - (iii) Department of Animal Husbandry and Dairying (Pashupalan aur Dairy Vibhag)
2. Ministry of Agro and Rural Industries (Krishi Evam Gramin Udyog Mantralaya)

3. Ministry of Chemicals and Fertilizers (Rasayan aur Urvarak Mantralaya)
 - (i) Department of Chemicals and Petro-Chemicals (Rasayan aur Petro-Rasayan Vibhag)
 - (ii) Department of Fertilizers (Urvarak Vibhag)
4. Ministry of Civil Aviation (Nagar Vimanan Mantralaya)
5. Ministry of Coal (Koyala Mantralaya)
6. Ministry of Commerce and Industry (Vanijya aur Udyog Mantralaya)
 - (i) Department of Commerce (Vanijya Vibhag)
 - (ii) Department of Industrial Policy and Promotion (Audyogik Niti aur Samvardhan Vibhag)
7. Ministry of Communications and Information Technology (Sanchar aur Sookhana Praudyogiki Mantralaya)
 - (i) Department of Telecommunications (Doorsanchar Vibhag)
 - (ii) Department of Posts (Dak Vibhag)
 - (iii) Department of Information Technology (Sookhana Praudyogiki Vibhag)
8. Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Upbhokta Mamle, Khadya aur Sarvajanic Vitaran Mantralaya)
 - (i) Department of Consumer Affairs (Upbhokta Mamle Vibhag)
 - (ii) Department of Food and Public Distribution (Khadya aur Sarvajanic Vitaran Vibhag)
9. Ministry of Defence (Raksha Mantralaya)
 - (i) Department of Defence (Raksha Vibhag)
 - (ii) Department of Defence Production (Raksha Utpadan Vibhag)
 - (iii) Department of Defence Research and Development (Raksha Anusandhan aur Vikas Vibhag)
10. Ministry of Disinvestment (Vinivesh Mantralaya).
11. Ministry of Environment and Forests (Paryavaran aur Van Mantralaya)
12. Ministry of External Affairs (Videsh Mantralaya)

13. Ministry of Finance (Vitta Mantralaya)
 - (i) Department of Economic Affairs (Arthik Karya Vibhag)
 - (ii) Department of Expenditure (Vyaya Vibhag)
 - (iii) Department of Revenue (Rajaswa Vibhag)
 - (iv) Department of Company Affairs (Kampany Karya Vibhag)
14. Ministry of Food Processing Industries (Khadya Prasanskaran Udyog Mantralaya).
15. Ministry of Health and Family Welfare (Swasthya aur Parivar Kalyan Mantralaya)
 - (i) Department of Health (Swasthya Vibhag)
 - (ii) Department of Family Welfare (Parivar Kalyan Vibhag)
 - (iii) Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) (Ayurveda, Yoga aur Prakraatik Chikitsa, Unani, Siddha aur Homoeopathy (AYUSH) Vibhag)
16. Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises (Bhari Udyog aur Lok Udyam Mantralaya)
 - (i) Department of Heavy Industry (Bhari Udyog Vibhag)
 - (ii) Department of Public Enterprises (Lok Udyam Vibhag)
17. Ministry of Home Affairs (Grih Mantralaya)
 - (i) Department of Internal Security (Antarik Suraksha Vibhag)
 - (ii) Department of States (Rajya Vibhag)
 - (iii) Department of Official Language (Raj Bhasha Vibhag)
 - (iv) Department of Home (Grih Vibhag)
 - (v) Department of Jammu and Kashmir Affairs (Jammu tatha Kashmir Vibhag)
 - (vi) Department of Border Management (Seema Prabandhan Vibhag)
18. Ministry of Human Resource Development (Manav Sansadhan Vikas Mantralaya)
 - (i) Department of Elementary Education and Literacy (Prarambhik Shiksha aur Saksharta Vibhag)
 - (ii) Department of Secondary and Higher Education (Madhyamk aur Uchchatar Shiksha Vibhag)
 - (iii) Department of Women and Child Development (Mahila aur Bal Vikas Vibhag)

19. Ministry of Information and Broadcasting (Soochana aur Prasara Mantralaya)
20. Ministry of Labour (Shram Mantralaya)
21. Ministry of Law and Justice (Vidhi aur Nyaya Mantralaya)
 - (i) Department of Legal Affairs (Vidhi Karya Vibhag)
 - (ii) Legislative Department (Vidhayee Vibhag)
 - (iii) Department of Justice (Nyaya Vibhag)
22. Ministry of Mines (Khet. Mantralaya)
23. Ministry of Non-Conventional Energy Sources (Apamparik Oorja Srot Mantralaya)
24. Ministry of Parliamentary Affairs (Sansadiya Karya Mantralaya)
25. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Karmik Lok Shikayat tatha Pension Mantralaya)
 - (i) Department of Personnel and Training (Karmik aur Prashikshan Vibhag)
 - (ii) Department of Administrative Reforms and Public Grievances (Prashasanik Sudhar aur Lok Shikayat Vibhag)
 - (iii) Department of Pensions and Pensioners Welfare (Pension aur Pension Bhogi Kalyan Vibhag)
26. Ministry of Petroleum and Natural Gas (Petroleum aur Prakritik Gas Mantralaya)
27. Ministry of Planning (Yojana Mantralaya)
28. Ministry of Power (Vidyut Mantralaya)
29. Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
30. Ministry of Road Transport and Highways (Sarak Parivahan aur Raj Marg Mantralaya)
31. Ministry of Rural Development (Gramin Vikas Mantralaya)
 - (i) Department of Rural Development (Gramin Vikas Vibhag)
 - (ii) Department of Land Resources (Bhumi Sansadhan Vibhag)
 - (iii) Department of Drinking Water Supply (Peya Jal Poorti Vibhag)

32. Ministry of Science and Technology (Vigyan aur Praudyogiki Mantralaya)
 - (i) Department of Science and Technology (Vigyan aur Praudyogiki Vibhag)
 - (ii) Department of Scientific and Industrial Research (Vigyan aur Audyogik Anusandhan Vibhag)
 - (iii) Department of Bio-Technology (Biotechnology Vibhag)
33. Ministry of Shipping (Pot Parivahan Mantralaya).
34. Ministry of Small Scale Industries (Laghu Udyog Mantralaya).
35. Ministry of Social Justice and Empowerment (Samajik Nyaya aur Adhikarita Mantralaya)
36. Ministry of Statistics and Programme Implementation (Sankhyiki aur Karyakram Karyanayan Mantralaya)
37. Ministry of Steel (Ispat Mantralaya)
38. Ministry of Textiles (Vastra Mantralaya)
39. Ministry of Tourism and Culture (Paryatan aur Sanskriti Mantralaya)
 - (i) Department of Tourism (Paryatan Vibhag)
 - (ii) Department of Culture (Sanskriti Vibhag)
40. Ministry of Tribal Affairs (Janjatiya Karya Mantralaya)
41. Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation (Shahari Vikas aur Garibi Upshaman Mantralaya)
 - (i) Department of Urban Development (Shahari Vikas Vibhag)
 - (ii) Department of Urban Employment and Poverty Alleviation (Shahari Rozgar aur Garibi Upshaman Vibhag)
42. Ministry of Water Resources (Jal Sansadhan Mantralaya)
43. Ministry of Youth Affairs and Sports (Yuvak Karyakram aur Khel Mantralaya)
44. Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag)

45. Department of Ocean Development (Mahasagar Vikas Vibhag)
46. Department of Space (Antariksh Vibhag)
47. Cabinet Secretariat (Mantrimandal Sachivalaya)
48. President's Secretariat (Rashtrapati Sachivalaya)
49. Prime Minister's Office (Pradhan Mantri Karyalaya)
50. Planning Commission (Yojana Ayog)
51. Department of Development of North Eastern Region (Uttar Poorvi Kshetra Vikas Vibhag).

THE SECOND SCHEDULE
(Rule 3)

DISTRIBUTION OF SUBJECTS AMONG THE DEPARTMENTS (VIBHAG)

MINISTRY OF AGRICULTURE
(KRISHI MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION
(KRISHI AUR SAHKARITA VIBHAG)

PART I

The following subjects which fall within List I of the Seventh Schedule to the Constitution of India :

1. Liaison with international Agri-Organisations like Food and Agriculture organisation of the United Nations, handling of CARE goods concerning agriculture, etc.
2. Participation in international conferences, associations and other bodies concerning agriculture and implementation of decisions made thereat.
3. Convention on Locust Control.
4. Plant Quarantine.
5. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in Public interest; as far as these relate to:-

- (a) Development of agricultural industries including machinery, fertilizer and seeds but excluding cotton, ginning and pressing with the limitation that in regard to the development of agricultural industries, including machinery and fertilizer, the functions of the Department of Agriculture and Cooperation do not go further than the formulation of demands and the fixation of targets;
 - (b) Shellac Industry.
- 6. Agricultural Census.
 - 7. Matters relating to damage to crops due to natural calamities.
 - 8. Co-ordination of relief measures necessitated by drought.
 - 9. Matters relating to loss of human life due to drought.
 - 10. Indian People's Natural Calamity Trust.
 - 11. Technology Mission on Oilseeds and Pulses.

PART II

The following subjects which fall within List III of the Seventh Schedule to the Constitution of India (as regards legislation only):

- 12. Adulteration of agricultural products other than foodstuffs.
- 13. Economic Planning (Agricultural Economics and Statistics).
- 14. Professions (excluding Veterinary Practice).
- 15. Prevention of the extension from one State to another of infectious or contagious diseases or pests affecting plants including locusts.
- 16. Price control of agricultural commodities except foodgrains, sugar, vanaspati, oil seeds, vegetable oils, cakes and fats, jute, cotton and tea.
- 17. Administration of the Dangerous Machine (Regulation) Act, 1983 (35 of 1983).

Part III

For the Union Territories the subjects mentioned in Parts I and II above, so far as they exist in regard to these territories and, in addition, to the following subjects which fall within List II of the Seventh Schedule to the Constitution of India:

18. Agriculture (Other than agricultural education and research) protection against pests and prevention of plant diseases.

19. Co-operation in agricultural sector, agricultural credit and indebtedness.

20. General Policy relating to the marketing of agricultural produce including pricing, exports etc.

21. Setting up of agricultural markets in rural areas.

22. The Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937).

23. Insurance (Crop).

24. General Policy in the field of Co-operation and Co-ordination of co-operation activities in all sectors.

Note:- The Ministries concerned are responsible for Co-operatives in the respective fields.

25. Matters relating to National Co-operative Organisation.

26. National Co-operative Development Cooperation.

27. Incorporation, regulation and winding up of Co-operative societies with objects not confined to one State.

28. Training of personnel of co-operative departments and co-operative institutions (including education of members, office bearers and non-officials).

PART IV

General and Consequential:

29. All Matters relating to international cooperation and assistance in agriculture and allied subjects other than the items of work allocated to Department of Agricultural Research and Education.

30. Agriculture and horticulture.

31. Bio-aesthetic Planning.

32. Agricultural Production-Grow more food .

33. Land Reclamation.
34. Infrastructure for post harvest management of agriculture and horticulture.
35. National Land Use and Conservation Board.
36. Development of Cotton, Jute and Sugarcane.
37. Soil Survey in connection with development programmes.
38. Financial assistance to State Soil Conservation Schemes.
39. Projection of demand of fertilizers and manures at all-India, zone or region level; fixation of targets, nutrient-wise, for zones or regions.
40. Administration of the Fertilizer (Control) Order, 1957.
41. Monitoring of Pesticides Residues at National Level.
42. Administration of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968).
43. Agricultural Implements and Machinery.
44. Organisation and Development of extension education and training in the country.
45. Crop campaigns, crop competitions and farmers organisations.
46. Production of oil seeds.
47. Schemes received from States and Union Territories for the settlement of landless agricultural labourers.
48. Mechanised Farms.
49. Organic Farming (all matters including development and promotion but excluding matters relating to certification of organic foods/products for export purpose).
50. On Farm Water Management.
51. Warehousing in rural areas including rural godowns.
52. All attached and Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list except the Directorate of Agricultural Aviation.

53. Quality control of fertilizers.

**B. DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION
(KRISHI ANUSANDHAN AUR SHIKSHA VIBHAG)**

PART I

The following subjects which fall within List I of the Seventh Schedule to the Constitution of India:

1. International cooperation and assistance in the field of agricultural research and education including relations with foreign and international agricultural research and education institutions and organisations.
2. Fundamental, applied and operational research and higher education including coordination of such research and higher education in agriculture, agroforestry, animal husbandry, dairying, fisheries, agricultural engineering and horticulture including agricultural statistics, economics and marketing.
3. Coordination and determination of standards in institutions for higher education or research and scientific and technical institutions in so far as they relate to food and agriculture including animal husbandry, dairying and fisheries. Development of Human Resources in Agricultural Research/Extensions and Education.
4. Cess for financing to the Indian Council of Agricultural Research and the Commodity Research Programmes other than those relating to tea, coffee and rubber.
5. Sugarcane research.

PART II

For Union Territories the subjects mentioned in Part I above, so far as they exist in regard to these Territories and in addition the following subject which falls within List II of the Seventh Schedule to the Constitution of India:

6. Agricultural Education and Research.

PART III

General and Consequential:

7. Plant, animal and fish introduction and exploration.

8. All India Soil and Land Use Survey relating to research training, co-relation, classification, soil mapping and interpretation.
9. Financial assistance to State Governments and Agricultural Universities in respect of agricultural research and educational schemes and programmes.
10. National Demonstrations.
11. Indian Council of Agricultural Research and its constituent Institutes, National Research Centres, Project Directorates, Bureaux and All India Coordinated Projects.

**C. DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING
(PASHUPALAN AUR DAIRY VIBHAG)**

PART I

The following subjects which fall within List I of the Seventh Schedule to the Constitution of India:

1. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in Public interest as far as these relate to Development of Livestock, fish and birds feed and dairy, poultry and fish products with the limitation that in regard to the development of industries, the functions of the Department of Animal Husbandry and Dairying do not go further than the formulation of the demand and fixation of targets.
2. Liaison and cooperation with international organizations in matters relating to livestock, poultry and fisheries development.
3. Livestock Census.
4. Livestock Statistics.
5. Matters relating to loss of livestock due to natural calamities.
6. Regulation of Livestock importation, Animal Quarantine and Certification.
7. Fishing and fisheries (inland, marine and beyond territorial waters).
8. Fishery Survey of India, Mumbai.

PART II

The following subjects which fall within List III of the Seventh Schedule to the Constitution of India (as regards legislation only):

9. Profession of Veterinary Practice.
10. Prevention of the extension from one State to another or infectious or contagious diseases or pests affecting animals, fish and birds.
11. Conversion of indigenous breeds; introduction and maintenance of Central Herd Books for indigenous breeds of livestock.
12. Pattern of financial assistance to various State Undertakings, Dairy Development Schemes through State agencies/Co-operative Unions.

PART III

For the Union Territories the subjects mentioned in parts I and II above, so far as they exist in regard to these territories and, in addition, to the following subjects which fall within List II of the Seventh Schedule to the Constitution of India:

13. Preservation, protection and improvement of stocks and prevention of diseases of animals, fish and birds, Veterinary training and practice.
14. Courts of Wards.
15. Insurance of livestock, fish and birds.

PART IV

16. Matters relating to cattle utilisation and slaughter.
17. Fodder development.

**MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES
(KRISHI EVAM GRAMIN UDYOG MANTRALAYA)**

1. Coordination of the development of Village and Cottage Industries, and Tiny/Micro Enterprises in both urban and rural areas.
2. Coordination of matters relating to all Rural Industries.

3. Coir Industry.
4. The Coir Board.
5. Prime Minister's Rozgar Yojana (PMRY).
6. Khadi and Village Industries Commission.

**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(RASAYAN AUR URVARAK MANTRALAYA)**

**A. DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETRO-CHEMICALS
(RASAYAN AUR PETRO-RASAYAN VIBHAG)**

1. Drugs and Pharmaceuticals, excluding those specifically allotted to other departments.
2. Insecticides (excluding the administration of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968)).
3. Molasses.
4. Alcohol – industrial and potable from the molasses route.
5. Dye-stuffs and dye-intermediates.
6. All organic and inorganic chemicals, not specifically allotted to any other Ministry or Department.
7. Planning, development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Department.
8. Bhopal Gas Leak Disaster-Special Laws relating thereto.
9. Petro-chemicals.
10. Industries relating to production of non-cellulosic synthetic fibres (Nylon Polyester, Acrylic etc.).
11. Synthetic rubber.
12. Plastics including fabrications of plastic and moulded goods.

**B. DEPARTMENT OF FERTILIZERS
(URVARAK VIBHAG)**

1. Planning for fertilizer production including import of fertilizer through a designated canalising agency.

2. Allocation and supply linkages for movement and distribution of urea in terms of assessment made by the Department of Agriculture and Cooperation.
3. Administration of concession schemes and management of subsidy for controlled as well as decontrolled fertilizers including determination of retention price for urea, quantum of concession of decontrolled fertilizers costing of such fertilisers and pricing of Phosphatic and Potassic fertilizers.
4. Administration of the Fertilizers (Movement Control) Order, 1960.
5. Administrative responsibility for fertilizer production units in the cooperative sector, namely, Indian Farmers Cooperative Limited (IFFCO), Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO).
6. Administrative responsibility for the Indian Potash Limited (IPL).

**MINISTRY OF CIVIL AVIATION
(NAGAR VIMANAN MANTRALAYA)**

1. Aircraft and air navigation; provision of aerodromes; regulation and organisation of air traffic and of aerodromes excepting sanitized control of air navigation.
2. Provision of navigational and other aids relating to air navigation.
3. Carriage of passengers and goods by air.
4. Production of aircraft and aircraft components for civil use.
5. Issuing of technical licences/certificates/approval for the use of civil aircraft.
6. Private Air Transport (including Cargo) Industry.
7. Matters relating to Greenfield airport by State Governments, Private/Joint Sector Companies.
8. International Civil Aviation Organisation (ICAO).
9. International Air Transport Association (IATA).
10. Commonwealth Air Transport Council (CATC).
11. Commonwealth Advisory Aeronautical Research Council (CAARC).

12. Air India Limited and its subsidiaries.
13. Indian Airlines Limited and its subsidiaries.
14. Hotel Corporation of India and its subsidiaries.
15. Commission of Railway Safety.
16. Airports Authority of India (AAI).
17. Pawan Hans Helicopters Limited .
18. Directorate General of Civil Aviation.
19. Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi.
20. Bureau of Civil Aviation Security.
21. Implementation of treaties and agreements relating to any of the matters specified in this list.
22. Administration of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934).
23. Administration of the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994).

**MINISTRY OF COAL
(KOYALA MANTRALAYA)**

1. Exploration and development of coking and non-coking coal and lignite deposits in India.
2. All matters relating to production, supply, distribution and prices of coal.
3. Development and operation of coal washeries other than those for which the Department of Steel is responsible.
4. Low Temperature carbonisation of coal and production of synthetic oil from coal.
5. Administration of the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974 (28 of 1974).
6. The Coal Mines Provident Fund Organisation.
7. The Coal Mines Welfare Organisation.

8. Administration of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1948 (46 of 1948).

9. Administration of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947).

10. Rules under the Mines Act, 1952 (32 of 1952) for the levy and collection of duty of excise on coke and coal produced and despatched from mines and administration of rescue fund.

11. Administration of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957).

12. Administration of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and other Union Laws in so far the said Act and Laws relate to coal and lignite and sand for stowing, business incidental to such administration including questions concerning various States.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (VANIJYA AUR UDYOG MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF COMMERCE (VANIJYA VIBHAG)

I. INTERNATIONAL TRADE

1. International Trade and Commercial Policy including tariff and non-tariff barriers.
2. International Agencies connected with Trade Policy (e.g. UNCTAD, ESCAP, ECA, ECLA, EEC, EFTA, GATT/WTO, ITC and CFC).
3. International Commodity Agreements other than agreements relating to wheat, sugar, jute and cotton.
4. International Customs Tariff Bureau including residuary work relating to Tariff Commission.

II. FOREIGN TRADE (GOODS & SERVICES)

5. All matters relating to foreign trade.
6. Import and Export Trade Policy and Control excluding matters relating to-

- (a) import of features films;
- (b) export of Indian films- both feature length and shorts; and
- (c) import and distribution of cine-film (unexposed) and other goods required by the film industry.

III. STATE TRADING

7. Policies of State Trading and performance of organisations established for the purpose and including-

(a) The State Trading Corporation of India Limited and its subsidiaries excluding Handicrafts and Handlooms Export Corporation and Central Cottage Industries Corporation; the Tea Trading Corporation of India Limited and the Spices Trading Corporation of India Limited;

(b) Projects & Equipment Corporation of India Limited (PEC);

(c) India Trade Promotion Organisation and its subsidiaries;

(d) Minerals and Metals Trading Corporation and its subsidiaries.

8. Production, distribution (for domestic consumption and exports) and development of plantation crops, tea, coffee, rubber, spices, tobacco and cashew.

9. Processing and distribution for domestic consumption and exports of Instant Tea and Instant Coffee.

10. (a) Tea Board.
(b) Coffee Board.
(c) Rubber Board.
(d) Cardamom Board.
(d) Tobacco Board.

IV. TRADING WITH THE ENEMY : ENEMY PROPERTY

11. Trading with the enemy; enemy firms and enemy property reparations (other than German industrial equipment); Controller of Enemy Trading; Controller of Enemy firms; Custodian of Enemy Property for India.

V. MANAGEMENT OF THE INDIAN TRADE SERVICES (ITS)

12. Cadre Management of the Indian Trade Service and all matter pertaining to training, career planning and manpower planning for the service.

13. Cadre Management of Indian Supply Service and all matter pertaining to training, career planning and manpower planning for the Service.

14. Cadre Management of Indian Inspection Service and all matter pertaining to training, career planning and manpower planning for the Service.

VI. SPECIAL ECONOMIC ZONES

15. All matters relating to development, operation and maintenance of special economic zones and units in special economic zones, including export and import policy, fiscal regime, investment policy, other economic policy and regulatory framework.

Note: All fiscal concessions and policy issues having financial implications are decided with the concurrence of the Department of Economic Affairs (Ministry of Finance) or failing such concurrence with the approval of the Cabinet.

VII. EXPORT PRODUCTS AND INDUSTRIES AND TRADE FACILITATION

16. Setting up of Export Processing Zones (EPZ)/Agricultural Export Zones (AEZ) and 100% Export Oriented Units (EOUs).

17. Gems and Jewellery.

18. Matters relating to Export Promotion Board, Board of Trade and International Trade Advisory Committee.

19. Matters relating to concerned Export Promotion Councils/Export Promotion Organisations.

20. Indian Institute of Foreign Trade and Indian Institute of Packaging.

21. Indian Diamond Institute and Footwear Design and Development Institute.

22. Coordination for export infrastructure.

23. Development and expansion of export production in relation to all commodities, products, manufacturers and semi-manufacturers including-

- (a) agricultural produce within the meaning of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);

- (b) marine products;
- (c) industrial products (engineering goods, chemicals, plastics, leather products, etc.);
- (d) fuels, minerals and mineral products;
- (e) specific export oriented products (including plantation crops, etc. but excluding jute products and handicrafts which are directly under the charge of this Department).

24. All organisations and institutions connected with the provision of services relating to the export effort including-

- (a) Export Credit and Export Insurance including Export Credit and Guarantee Corporation Limited;
- (b) Export Inspection Council; Standards including Quality Control;
- (c) Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics;
- (d) Free Trade-Zones.

25. Projects and programmes for stimulating and assisting the export efforts.

VIII. ATTACHED AND SUBORDINATE OFFICES

26. Directorate General of Foreign Trade.

27. Administration of Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi.

28. Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties and related matters.

29. Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics.

IX. STATUTORY BODIES

30. Marine Products Export Development Authority.

31. Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority.

X. MISCELLANEOUS

32. Purchase and inspection of stores for Central Government Ministries/ Departments including their attached and subordinate offices and Union Territories, other than the items of purchase and inspection of stores which are delegated to other authorities by general or special order.

**B. DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION
(AUDYOGIK NITI AUR SAMVARDHAN VIBHAG)****I. INDUSTRIAL POLICY.**

1. General Industrial Policy.
2. Administration of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).
3. Industrial Management.
4. Productivity in industry.

**II. INDUSTRIES AND INDUSTRIAL AND TECHNICAL
DEVELOPMENT**

5. Planning, development and control of and assistance to, all industries other than those dealt with by any other Department.
6. Issue of licences for establishment of industries for production of civil aircraft to be made in consultation with the Ministry of Civil Aviation and Department of Defence Production.
7. Cables.
8. Light Engineering Industries (e.g. Sewing machines, typewriters, weighing machines, bicycles, etc.).
9. Light industries (e.g. Plywood, stationary, matches, cigarettes, etc.).
10. Light Electrical Engineering Industries.
11. Raw films.
12. Hard Board.

14. Tyres and Tubes.
15. Salt.
16. Cement.
17. Ceramics, Tiles and Glass.
18. Leather and Leather Goods Industry.
19. Soaps and Detergents.
20. Technical Development including Tariff Commission and United Nations Industrial Development Organisation.
21. Direct foreign and non-resident Indian investment in industrial and service projects.
22. Foreign Investment Implementation Authority (FIIA).

III. INDUSTRIAL CO-OPERATION

23. Administration of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923) and the regulations made thereunder; Central Boilers Board.
24. Explosives-Administration of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), and the rules made thereunder, but not the Explosive Substances Act, 1908 (6 of 1908).
25. The Inflammable Substances Act, 1952 (20 of 1952).

IV. INDUSTRIES AND INDUSTRIAL AND TECHNICAL DEVELOPMENT

26. National Council for Cement and Building Materials.
27. Indian Rubber Manufacturers' Research Association, Mumbai.

V. PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (INDUSTRIAL PROPERTY)

28. Standardisation of international products and raw materials.
29. The Designs Act, 2000 (16 of 2000).

30. The Trade and Merchandise Marks Act, 1958 (43 of 1958).
31. The Patents Act, 1970 (39 of 1970).

VI. MATERIALS PLANNING

32. Coordinated assessment of demands for raw materials by sectors, industries and large-units in relation to particular groups of products and to available capacities.

33. The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 (48 of 1999).

34. Assessment of domestic availability of raw materials with due regard to the feasibility of import substitution.

35. Assessment of requirements of imports of raw materials, with due allowance for inventories.

36. Determination of principles, priorities and procedures for allocation of raw materials.

37. All other matters connected with materials Planning.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SANCHAR AUR SOOCHANA PRAUDYOGIKI MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS (DOOR SANCHAR VIBHAG)

1. Policy, Licensing and Coordination matters relating to telegraphs, telephones, wireless, data, facsimile and telematic services and other like forms of communications.

2. International cooperation in matters connected with telecommunications including matters relating to all international bodies dealing with telecommunications such as International Telecommunication Union (ITU), its Radio Regulation Board (RRB), Radio Communication Sector (ITU-R), Telecommunication Standardization Sector (ITU-T), Development Sector (ITU-D), International Telecommunication Satellite Organization (INTELSAT), International Mobile Satellite Organization (INMARSAT), Asia Pacific Telecommunication (APT).

3. Promotion of standardization, research and development in telecommunications.

4. Promotion of private investment in Telecommunications.
5. Financial assistance for the furtherance of research and study in telecommunications technology and for building up adequately trained manpower for telecom programme, including-
 - (a) assistance to institutions, assistance to scientific institutions and to universities for advanced scientific study and research; and
 - (b) grant of scholarships to students in educational institutions and other forms of financial aid to individuals including those going abroad for studies in the field of telecommunications.
6. Procurement of stores and equipment required by the Department of Telecommunications.
7. Telecom Commission.
8. Telecom Regulatory Authority of India.
9. Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal.
10. Administration of laws with respect to any of the matters specified in this list, namely:-
 - (a) The Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);
 - (b) The Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933); and
 - (c) The Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997).
11. Indian Telephone Industries Limited.
12. Post disinvestment matters relating to M/s Hindustan Teleprinters Limited.
13. Bharat Sanchar Nigam Limited.
14. Mahanagar Telephone Nigam Limited
15. Videsh Sanchar Nigam Limited and Telecommunications Consultants (India) Limited.

16. All matters relating to Centre for Development of Telematics (C-DOT).

17. Residual work relating to the erstwhile Department of Telecom Services and Department of Telecom Operations, including matters relating to-

- (a) cadre control functions of Group 'A' and other categories of personnel till their absorption in Bharat Sanchar Nigam Limited;
- (b) administration and payment of terminal benefits.

18. Execution of works, purchase and acquisition of land debitable to the capital Budget pertaining to telecommunications.

**B. DEPARTMENT OF POSTS
(DAK VIBHAG)**

1. Execution of works, including purchase of land debitable to the Capital Budget pertaining to the Department of Posts.

2. Posts, including Post Office Savings Banks (Administration), Post Office Certificate (Administration), Post Office Life Insurance Fund (Administration), printing of public postage stamps/commemorative stamps including postal stationery, premium postal products and any agency function.

3. International cooperation in matters connected with postal communications, including matters relating to all international bodies dealing with postal communications such as Universal Postal Union, Asia Pacific Postal Union (APU), Commonwealth Postal Union.

4. Matters relating to introduction, development and maintenance of all services by the Post Office including those based on cable, radio and satellite communications channels:

Provided that these matters do not amount to broadcasting, narrowcasting, cable and radio networking services and are also not governed by the Indian Telegraph Act, 1885 and the rules made thereunder, and not exclusively allotted to any other Department.

5. Promotion of feasibility survey, research and development in the field of activities allotted to the Department.

6. Matters relating to administration of the Indian Post Office Act, 1898 and rules made thereunder as well as other laws or enactments

having a bearing on postal activities, not specifically allotted to any other Department.

**C. DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY
(SOOCHANA PRAUDYOGIKI VIBHAG)**

1. Policy matters relating to information technology; Electronics; and Internet (all matters other than licensing of Internet Service Provider).
2. Promotion of internet, IT and IT enabled services.
3. Assistance to other departments in the promotion of E-Governance, E- Commerce, E- Medicine, E- Infrastructure, etc.
4. Promotion of Information Technology education and Information Technology-based education.
5. Matters relating to Cyber Laws, administration of the Information Technology Act. 2000 (21 of 2000) and other IT related laws.
6. Matters relating to promotion and manufacturing of Semiconductor Devices in the country including all matters relating to Semiconductor Complex Limited (SCL) Mohali; The Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Act, 2000 (37 of 2000).
7. Interaction in IT related matters with international agencies and bodies e. g. Internet for Business Limited (IFB), Institute for Education in Information Society (IBI) and International Code Council – on line (ICC).
8. Initiative on bridging the Digital Divide: Matters relating to Media Lab Asia.
9. Promotion of Standardization, Testing and Quality in IT and standardization of procedure for IT application and Tasks.
10. Electronics Export and Computer Software Promotion Council (ESC).
11. National Informatics Centre (NIC).
12. Initiatives for development of Hardware/Software industry including knowledge-based enterprises, measures for promoting IT exports and competitiveness of the industry.

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC
DISTRIBUTION (UPBHOKTA MAMLE, KHADYA AUR SARVAJANIK
VITARAN MANTRALAYA)**

**A. DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS
(UPBHOKTA MAMLE VIBHAG)**

1. Internal Trade.
2. Inter-State Trade: The Spirituous Preparation (Inter-State Trade and Commerce) Control Act, 1955 (39 of 1955).
3. Control of Future Trading : The Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952).
4. The Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) (Supply, Price and Distribution of Essential Commodities not dealt with specifically by any other Department).
5. Prevention of the Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 (7 of 1980); persons subjected to detention thereunder.
6. Regulation of Packaged Commodities.
7. Training in Legal Meterology.
8. The Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1952 (12 of 1952).
9. Standards of Weights and Measures; The Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976).
10. The Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).
11. Forward Markets Commission.
12. Consumer Cooperatives.
13. Monitoring of prices and availability of essential commodities.
14. National Test House.
15. The Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986).

**B. DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(KHADYA AUR SARVAJANIK VITRAN VIBHAG)**

1. Participation in international Conferences, Associations and other bodies concerning food, i.e. International Wheat Council, World Food Council, International Food Policy Research Institute, Commission/Committees on Food Security and implementation of decisions made thereat.
2. Entering into treaties and agreements with foreign countries and implementing treaties, agreements, conventions with foreign countries relating to trade and commerce in foodgrains and other foodstuffs.
3. Hiring and acquisition of godowns for storage of foodgrains including sugar, taking on lease or acquiring land for construction of foodgrains godowns.
4. Matters relating to the Food Corporation of India and the Central Warehousing Corporation.
5. Purchase of foodstuffs for civil requirements and their disposal and also for military requirements of sugar, rice and wheat.
6. Inter-State trade and commerce in respect of foodgrains and other foodstuffs including sugar.
7. Trade and commerce in, and supply and distribution of, foodgrains.
8. Trade and commerce in, and the production, supply and distribution of sugar and foodstuffs other than foodgrains.
9. Price control of sugar, foodgrains and foodstuffs.
10. Public Distribution System.
11. The Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and the Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 (7 of 1980), in so far as foodgrains are concerned.
12. Industries relating to Vanaspati, Oil seeds, Vegetable oils, Cakes, Fats and Sugar (including development of sugar khandsari).
13. Price Control of and inter-state trade and commerce in and supply and distribution of Vanaspati, Oilseeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats.

14. Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats.
15. Directorate of Sugar, New Delhi.
16. National Sugar Institute, Kanpur.
17. National Institute of Sugar and Sugarcane Technology, Mau.
18. Matters relating to the Development Council of Sugar Industry, New Delhi.
19. International Sugar Council.
20. Sugar Development Fund.

**MINISTRY OF DEFENCE
(RAKSHA MANTRALAYA)**

**A. DEPARTMENT OF DEFENCE
(RAKSHA VIBHAG)**

1. Defence of India and every part thereof including preparation for defence and all such acts as may be conducive in times of war to its prosecution and after its termination to effective demobilisation.
2. The Armed Forces of the Union, namely, Army, Navy and Air Force.
3. Integrated Headquarters of the Ministry of Defence comprising of Army Headquarters, Naval Headquarters, Air Headquarters and Defence Staff Headquarters.
4. The Reserves of the Army, Navy and Air Force.
5. The Territorial Army.
6. The National Cadet Corps.
7. Works relating to Army, Navy and Air Force.
8. Remounts, Veterinary and Farms Organisation.
9. Canteen Stores Department (India).
10. Civilian Services paid from Defence Estimates.
11. Hydrographic surveys and preparation of navigational charts.

12. Formation of Cantonments, delimitation/excision of Cantonment areas, local self-government in such areas, the constitution and powers within such areas of Cantonment Boards and authorities and the regulation of house accommodation (including the control of rents) in such areas.
13. Acquisition, requisitioning, custody and relinquishment of land and property for defence purposes. Eviction of unauthorised occupants from defence land and property.
14. Matters relating to ex-Servicemen including pensioners.
15. Defence Accounts Department.
16. Purchase of food stuffs for military requirements and their disposal excluding those entrusted to Department of Food and Public Distribution.
17. All matters relating to Coast Guard Organisation, including-
 - (a) surveillance of maritime zones against oil spills;
 - (b) combating oil spills in various maritime zones, except in the waters of ports and within 500 metres of off-shore exploration and production platforms, coastal refineries and associated facilities such as Single Buoy Mooring (SBM), Crude Oil Terminal (COT) and pipelines;
 - (c) Central Coordinating Agency for Combating of Oil Pollution in the coastal and marine environment of various maritime zones;
 - (d) implementation of National Contingency Plan for oil spill disaster; and
 - (e) undertaking oil spill prevention and control, inspection of ships and offshore platforms in the country, except within the limits of ports as empowered by the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958).
18. Matters relating to diving and related activities in the country.
19. Procurement exclusive to the Defence services.
20. Administration of-
 - (a) the Pension Regulations for the Army, 1961 (Parts I and II);
 - (b) the Pension Regulations for the Air Force, 1961 (Parts I and II);

- (c) the Navy (Pension) Regulations, 1964; and
- (d) the Entitlement Rules to Casualty Pensionary Awards to the Armed Forces Personnel, 1982.

**B. DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION
(RAKSHA UTPADAN VIBHAG)**

1. Ordnance Factory Board and Ordnance Factories.
2. Hindustan Aeronautics Limited.
3. Bharat Electronics Limited.
4. Mazagon Dock Limited.
5. Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited.
6. Goa Shipyard Limited.
7. Bharat Dynamics Limited.
8. Mishra Dhatu Nigam Limited.
9. Defence Quality Assurance Organisations including Directorate General Quality Assurance and Directorate General Aeronautical Quality Assurance.
10. Standardisation of defence equipment and stores including Directorate of Standardisation.
11. Bharat Earth Movers Limited.
12. Development of the aeronautics industry and coordination among users other than those concerned with the Ministry of Civil Aviation and the Department of Space.
13. Indigenisation, development and production of defence equipment and participation of the private sector in the manufacture of defence equipment.
14. Defence exports and international Cooperation in defence production.

**C. DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT
(RAKSHA ANUSANDHAN TATHA VIKAS VIBHAG)**

1. Apprising, assessing and advising Raksha Mantri on the influence on National Security of emerging developments in Science and Technology.

2. Rendering advice to Raksha Mantri and to the three services and inter services organisations on all scientific aspects of weapons; weapon-platforms; military operations; surveillance; support and logistics in all likely theatres of conflict.
3. To function, with the concurrence of the Ministry of External Affairs, as the nodal coordinating agency of the Ministry of Defence on all matters relating to Instruments of Accord with foreign Governments relating to the acquisition of technologies whose export to India is the subject of national security related controls of foreign Governments.
4. Formulation and execution of programmes of scientific research and design, development, test and evaluation, in fields of relevance to national security.
5. Direction and administration of agencies, laboratories, establishments, ranges, facilities, programmes and projects of the Department.
6. Aeronautical Development Agency.
7. All matters relating to certification of the design air worthiness of military aircraft, their equipment and stores.
8. All matters relating to the protection and transfer of technology generated by the activities of the Department.
9. Scientific analysis support and participation in the acquisition and evaluation proceedings of all weapon systems and related technologies proposed to be acquired by the Ministry of Defence.
10. To render advice on the technological and intellectual property aspects of the import of technology by production units and enterprises manufacturing, or proposing to manufacture, equipment and stores for the Armed Services.
11. To deal with reference made under section 35 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970).
12. Financial and other material assistance to individuals, institutions and bodies corporate, for study and for the training of manpower on aspects of Science and Technology that bear on national security.
13. In consultation with the Ministry of External Affairs, international relations in matters connected with the role of Science and Technology in national security including-

- (a) matters relating to relations with Research Organisations of other countries and with Inter-governmental agencies, particularly those which concern themselves, inter alia, with the scientific and technological aspects of national security;
 - (b) arrangements with Universities, educational and research-oriented institutions or bodies corporate abroad to provide for foreign scholarships and the training of Indian scientists and technologists under the administrative control of the Department.
14. Execution of works and purchase of lands debitable to the budget of the Department.
15. All matters relating to personnel under the control of the Department.
16. Acquisition of all types of stores, equipment and services debitable to the budget of the Department.
17. Financial sanctions relating to the Department.
18. Any other activity assigned to, and accepted by, the Department through understandings or arrangements with any other Ministry, Department, Agency of the Government of India whose activities have a bearing on the scientific and technological aspects of national security.

MINISTRY OF DISINVESTMENT (VINIVESH MANTRALAYA)

1. All matters relating to disinvestment of Central Government equity from Central Public Sector Undertakings.
2. Decisions on the recommendations of the Disinvestment Commission on the modalities of disinvestment, including restructuring.
3. Implementation of disinvestment decisions, including appointment of advisers, pricing of shares, and other terms and conditions of disinvestment.
4. Disinvestment Commission.
5. Central Public Sector Undertakings for purposes of disinvestment of Government equity only.

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
(PARYAVARAN TATHA VAN MANTRALAYA)**

1. Environment and Ecology, including environment in coastal waters, in mangroves and coral reefs but excluding marine environment on the high seas.
2. Environment Research and Development, education, training, information and awareness.
3. Environmental Health.
4. Environmental Impact Assessment.
5. Forest Development Agency and Joint Forest Management Programme for conservation, management and afforestation.
6. Survey and Exploration of Natural Resources particularly of Forest, Flora, Fauna, Ecosystems etc.
7. Bio-diversity Conservation including that of lakes and Wetlands.
8. Conservation, development, management and abatement of pollution of rivers which shall include National River Conservation Directorate.
9. Wildlife conservation, preservation, protection planning, research, education, training and awareness including Project Tiger and Project Elephant.
10. International co-operation on Issues concerning Environment, Forestry and Wildlife.
11. Botanical Survey of India and Botanical Gardens.
12. Zoological Survey of India.
13. National Museum of Natural History.
14. Biosphere Reserve Programme.
15. National Forest Policy and Forestry Development in the country, including Social Forestry.
16. All matters relating to Forest and Forest Administration in the Andaman Nicobar Islands.
17. Indian Forest Service.

18. Wild Life Preservation and protection of wild birds and animals.
19. Fundamental and applied research and training including higher education in forestry.
20. Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park.
21. National Assistance to Forestry Development Schemes.
22. Indian Plywood Industries Research and Training Institute, Bangalore.
23. Afforestation and Eco-Development which shall include National Afforestation and Eco-Development Board.
24. Desert and Desertification.
25. Forest Survey of India.
26. Indian Institute of Bio-diversity, Itanagar.
27. Central Pollution Control Board.
28. G.B.Pant Institute of Himalayan Environment & Development.
29. Wildlife Institute of India and Indian Board for Wildlife.
30. Indian Institute of Forest Management.
31. Central Zoo Authority including National Zoo Park.
32. Indian Council of Forestry Research & Education.
33. Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development Corporation Limited.
34. Prevention of cruelty to animals.
35. Matters relating to pounds and cattle trespass.
36. Gaushalas and Gausadans.
37. The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960).
38. The National Environment Tribunal Act, 1995 (27 of 1995).
39. The National Environment Appellate Authority Act, 1997 (22 of 1997).

40. The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974).
41. The Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977 (36 of 1977).
42. The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981).
43. The Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927).
44. The Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972)
45. The Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980).
46. The Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).
47. The Public Liability Insurance Act, 1991 (6 of 1991).

**MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
(VIDESH MANTRALAYA)**

1. External affairs.
2. Relations with foreign States and Commonwealth Countries.
3. Indian Council for Cultural Relations.
4. All matters affecting foreign diplomatic and consular officers, U.N. officers and its specialised agencies in India.
5. Passports and visas excluding the grant of visas or endorsements for entry into India but including the grant of entry permits to South Africans of Non-Indian origin under the Reciprocity (South Africa) Rules, 1944 and the grant of entry visas for SriLankan nationals except missionaries.
6. Extradition of criminals and accused persons from India to foreign and commonwealth countries and vice versa and general administration of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962) and extra-territoriality.
7. Preventive detention in India for reasons of State connected with External and Commonwealth affairs.
8. Repatriation of the nationals of foreign and Commonwealth States from India and deportation and repatriation of Indian nationals of foreign and Commonwealth countries to India.

9. Immigration to India from the Republic of South Africa or any other country to which the Reciprocity Act, 1943 (9 of 1943) may apply.
10. All Consular functions.
11. Travel arrangements for traders and pilgrims from India to Tibet region of China.
12. Scholarship to foreign students for study in India under different schemes.
13. Political pensions paid to foreign refugees and descendants of those who rendered services abroad.
14. Ceremonial matters relating to foreign and Commonwealth Visitors and Diplomatic and Consular Representatives.
15. Matters in respect of Pondicherry, Goa, Daman and Diu, involving relations with France and Portugal.
16. Relations with States in special Treaty relations with India such as Bhutan.
17. Himalayan expeditions; permission to foreigners to travel to Protected Areas other than those with which the Ministry of Home Affairs is concerned.
18. United Nations, Specialised Agencies and other International Organisations and Conferences.
19. Indian Foreign Service.
20. Indian Foreign Service Branch 'B'.
21. Foreign Service Training Institute.
22. External Publicity.
23. Political treaties, agreements and conventions with foreign and Commonwealth countries.
24. (a) Pilgrimages to places outside India, including the administration of the Haj Committee Act, 1959 (51 of 1959) and the rules made thereunder and the Indian Pilgrim Ship Rules, 1933, and Pilgrim parties from India to Shrines in Pakistan and vice versa.

- (b) Protection and preservation of Non-Muslim shrines in Pakistan and Muslim shrines in India in terms of Pant-Mirza Agreement of 1955.
25. Abducted Persons (Recovery and Restoration).
26. Questions relating to minority communities in neighbouring Countries.
27. Recovery of advances granted to the evacuees from Burma, Malaya, etc., during the years 1942-47 and residual work relating to refugees given asylum in India during World War II.
28. Notification regarding commencement or cessation of a state of war.
29. Foreign Jurisdiction.
30. Hospitality Grant of the Government of India.
31. Demarcation of the land frontiers of India.
32. Border raids and incidents on the land borders of India.
33. Diplomatic flight clearances for non-scheduled chartered flights of foreign, civil and military aircraft transiting India.
34. Matters relating to Law of the Sea, including the Indian Territorial Waters, Contiguous Zone, Continental Shelf and Exclusive Economic Zones (EEZ), questions of international law arising on the high seas including fishery rights; piracies and crimes committed on the High Seas or in the air; offences against the Law of Sovereign States committed on land or the High seas or in the air; legal matters concerning the International Seabed Area and Authority.
35. Economic and technical assistance given by India to the Government of Nepal under the Colombo Plan for Co-operative Economic Development.
36. Purchase, inspection and shipment of Stores from abroad for the Central Government other than those the purchase, inspection and shipment of which are delegated to other authorities by a general or special order.
37. All matters relating to grant of loans and credits to Nepal, Bhutan and Bangladesh.

38. Technical assistance given by India to African countries under the Special Commonwealth African Assistance Plan Programme.

NOTE:- Commonwealth countries should be taken to include British Colonies, Protectorates and Trust Territories.

39. Human Rights:

- (a) interaction with Human Rights Organisations abroad;
- (b) international declarations, treaties, conventions and conferences; references received from the United Nations and other specialised agencies and organisations thereof;
- (c) implementation of reporting obligations, in coordination with the concerned Ministries, required under the United Nations and international conventions, to which India is a State party.

Note:- These functions will be exercised by the Ministry of External Affairs in close co-ordination with the Ministry of Home Affairs, which shall be the nodal Ministry for policy and for coordination of all matters relating to Human Rights.

40. Relations with Overseas Indians excluding entries specifically allotted to other departments.

41. Indian Council of World Affairs.

**MINISTRY OF FINANCE
(VITTA MANTRALAYA).**

**A. DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS
(ARTHIK KARYA VIBHAG)**

I. FOREIGN EXCHANGE MANAGEMENT

1. Administration of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), other than enforcement work mentioned under the Department of Revenue, and all matters relating to combating financing of terrorist acts.
2. Policy relating to exchange rates of Rupee.
3. Management of the foreign exchange resources including scrutiny of proposals for imports from the foreign exchange point of view.

4. Foreign and Non-Resident Indian Investment (excluding Direct Foreign and Non-Resident Indian Investment in Industrial and Service projects) and foreign Non-Resident Indian and PIO contributions to Government and parental organizations.
5. Indian Direct Overseas Investment.
6. Matters concerning commercial borrowing from abroad, including terms and conditions thereof.
7. Matters concerning gold and silver.
8. Approval for foreign travel of Ministers of State Governments/Union Territories, Members of State Legislature/Union Territories and State Government Officials.
9. Management of external debt.

II. FOREIGN AID FOR ECONOMIC DEVELOPMENT

10. All matters relating to-
 - (a) India Development Forum;
 - (b) loans, credits and grants from foreign countries, special agencies, non-governmental foundations agencies and voluntary bodies;
 - (c) loans and credits and grants from multilateral agencies;
 - (d) withdrawals and borrowings from International Monetary Fund;
 - (e) policy for private sector financing from International Finance Corporation.
11. Technical and Economic assistance received by India as under-
 - (a) Technical Cooperation Scheme of the Colombo Plan;
 - (b) The United Nations Technical Assistance Administration Programmes;
 - (c) Ad-hoc offers of technical Assistance from various foreign countries, special agencies, non-Government entities;
 - (d) United Nations Office of Project Services.

12. Technical assistance given by India to the member countries of the Colombo Plan under Technical Cooperation Scheme of the Colombo Plan.
13. All matters relating to the meetings of the Colombo Plan Council and the Consultative Committee of the Plan.
14. All matters relating to credits extended by Government of India to other countries except Nepal, Bhutan and Bangladesh.
15. Technical assistance received by India from or given to foreign governments, international institutions and organisations, except such as are relatable to subjects allocated to any other Department.
16. All matters concerning United Nations Development Programme (UNDP) including Programmes or Projects funded out of UNDP Budget.
17. Foreign Investment Promotion Board (FIPB).
18. Policy issues relating to the United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) and contributions to the specialised agencies of the United Nations and other U.N. Bodies.
19. All matters relating to the Foreign Volunteers Programmes in India including the United Nations Volunteers (except outgoing volunteers under UNV).
20. All funding by United Nations agencies.
21. Commonwealth Fund for Technical Cooperation (CFTC).

III. DOMESTIC FINANCE

22. All matters relating to –
 - (a) currency and coinage including its designing;
 - (b) the Security and Currency Printing Presses, the Security Paper Mills and the Mints including the Assay Department and Silver Refinery, Gold Refinery, and Gold collection-cum-delivery centres;
 - (c) production and supply of Currency Note Paper, Currency and Bank Notes and Coins including Commemorative coins, postal stationary, stamps and various security forms/items.
23. (a) Policy measures for the regulation and development of the securities market and investor protection.

- (b) New Investments and Securities for mobilising resources from the Capital Markets. Investment Policy including investment policy of Life Insurance Corporation of India, and General Insurance Corporation of India.

24. Investment pattern for Employees' Provident Fund and other like Provident Funds.

25. Financial Policy in regard to the process of disinvestments including Disinvestments Proceeds Fund and Asset Management Company.

26. All matters relating to Tax Free Bonds.

IV. BUDGET

27. Ways and means.

28. Preparation of Central Budget other than Railway Budget including supplementary excess grants and when a proclamation by the President as to failure of Constitutional machinery is in operation in relation to a State or a Union Territory, preparation of the Budget of such State or Union Territory.

29. Market Borrowing Programme of Central and State Governments and Government Guaranteed Institutions.

30. Floatation of Market Loans by Central Government and issue and discharge of Treasury bills.

31. Administration of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944).

32. Fixation of interest rates for Central Government's borrowings and lending.

33. Policy regarding Accounting and Audit procedures including classification of transactions.

34. Financial matters relating to Partition, Federal Financial integration and Reorganisation of States.

35. Contingency Fund of India and administration of the Contingency Fund of India Act, 1950 (49 of 1950).

36. Monitoring of budgetary position of the Central Government.

37. Sterling Pensions-Transfer of responsibility of U.K. Government and actual calculations of liability involved.

38. Public Provident Fund Scheme.
39. Finance Commission.
40. Resources of Five Year and Annual Plans.
41. National Deposit Scheme, Special Deposit Schemes, Compulsory Deposit Scheme, Other Deposit Schemes of the Central Government.
42. Small Savings, including the administration of the National Savings Organisation.
43. Duties and Powers of the Comptroller and Auditor General.
44. Laying of Audit Reports before the Parliament under article 151 of the Constitution.
45. Financial emergency.
46. Government guarantees.
47. Functions of the Treasurer of Charitable Endowments for India.

V. INSURANCE

48. Policy relating to general insurance; administration of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972); and related matters, General Insurance and Reinsurance Companies in Public Sector.
49. Policy relating to life insurance; Administration of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956); and related matters, Life Insurance Corporation of India.
50. Administration of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) and related matters.
51. The responsibility of the Central Government relating to matters concerning centrally administered areas in respect of any of the entries from 48 to 50 above.

VI BANKING

52. All matters relating to Indian banks, whether nationalised or not.
53. All matters relating to foreign banks so far as their operations in India are concerned.

54. All matters relating to Reserve Bank of India.
55. All matters relating to Cooperative Banking.
56. Matters relating to All India Development Financial Institutions, namely, Industrial Development Bank of India (IDBI), IFCI Limited, Small Scale Industrial Development Bank of India (SIDBI) and Industrial Investment Bank of India (IIBI).
57. Matters relating to Export-Import Bank of India.
58. Administration of the Shipping Development Fund Committee (Abolition) Act, 1986 (66 of 1986).
59. Matters relating to Scindhia Steamship Navigation Company.
60. Matters relating to Infrastructure Development Finance Corporation (IDFC) and Infrastructure Leasing and Financial Services (ILFS).
61. Chit Fund and other non-banking companies accepting deposits.
62. Other matters relating to Banking in India.
63. Matters relating to National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).
64. Administration of the Regional Rural Bank Act, 1976 (21 of 1976).
65. Administration of the Recovery of Debt Due to Bank and Financial Institutes Act, 1993 (51 of 1993).
66. Matters relating to implementation of the State Financial Corporation Act, 1951 (63 of 1951).
67. Matters relating to implementation of the Sick Industrial Companies (Special Provision) Act, 1985 including matters relating to Board for Industrial Financial Reconstruction (BIFR) and Appellate Authority for Industrial Financial Reconstruction (AAIFR).
68. All matters relating to National Housing Bank.
69. Administration of all other statutes, regulations and other laws connected with entries 38, 45 and 46 of the Union List and entry 9 of the Concurrent List.
70. Matters concerning Securitisation and Foreclosure.

71. Administration of the Special Court (Trial of Offences relating to Transaction in Securities) Act, 1992 (27 of 1992).
72. Administration of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Banking Companies (Acquisition and transfer of Undertaking) Act, 1970 (5 of 1970) and 1980 (40 of 1980), the Bankers Book Evidence Act, 1891 (18 of 1891) and the Banking Service Commission Act, 1984 (44 of 1984) .
73. Administration of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955) and the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959).
74. The Reserve Bank of India (Amendment and Miscellaneous Provisions) Act, 1953 (54 of 1953).
75. Administration of the State Agricultural Credit Corporation Act, 1968 (60 of 1968).
76. Administration of the Public Financial Institutions (Obligation as to Fidelity and Secrecy Act), 1983 (48 of 1983).
77. Administration of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (47 of 1961).
78. Administration of the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881).

VII. MANAGEMENT OF THE INDIAN ECONOMIC SERVICE

79. Management of Indian Economic Service – its cadre and all matters pertaining thereto.

VIII. ECONOMIC ADVICE

80. Advice on matters which have a bearing on internal and external aspects of economic management including prices.
81. Credit, fiscal and monetary policies.

IX. MISCELLANEOUS ACTS

82. The Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873).
83. Section 20 of the Indian Trustes Act, 1882 (2 of 1882) dealing with investments.
84. The Metal Tokens Act, 1889 (1 of 1889).

85. The Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890).
86. The Indian Coinage Act, 1906 (3 of 1906).
87. The Indian Security Act, 1920 (10 of 1920).
88. The Currency Ordinance, 1940 (4 of 1940).
89. The International Monetary Fund and Bank Act, 1945 (00 of 1945).
90. The Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951 (33 of 1951).
91. The Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959).
92. The Compulsory Deposit Scheme Act, 1963 (21 of 1963).
93. The Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963).
94. The Legal Tender (Inscribed Notes) Act, 1964 (28 of 1964).
95. The Asian Development Bank Act, 1966 (18 of 1966).
96. The Public Provident Fund Act, 1968 (23 of 1968).
97. The Small Coins (Offences) Act, 1971 (52 of 1971).
98. The Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act' 1971 (56 of 1971).
99. The Additional Emoluments (Complusory Deposit) Act, 1974 (37 of 1974).
100. The African Development Fund Act, 1982 (1 of 1982).
101. The African Development Bank Act, 1983 (13 of 1983).
102. The Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).
103. The Administration of Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).
104. The Depositories Act, 1996 (22 of 1996).
105. The International Finance Corporations (Status, Immunities and Privileges) Act 1958 (42 of 1958).

**B. DEPARTMENT OF EXPENDITURE
(VYAYA VIBHAG)**

1. Financial rules and regulations and delegation of financial powers.
2. Financial sanction relating to all Ministries and offices of the Government of India, which are not covered by powers delegated or conferred by the rules or by any general or special orders.
3. Review of the staffing of Government establishments with a view to securing economy.
4. Advice to Ministries and Government Undertakings on Cost Accounts matters and attending to Cost Investigation work on their behalf.
5. Indian Audit and Accounts Department.
6. Matters relating to the Controller General of Accounts including-
 - (a) general principles of Government accounting relating to Union or State Governments and form of accounts, and framing or revision of rules and manuals relating thereto;
 - (b) reconciliation of cash balance of Union Government with Reserve Bank in general and, in particular, of Reserve Deposits pertaining to Civil Ministries or Departments;
 - (c) overseeing the maintenance of adequate standards of accounting by Central Civil Accounts Offices;
 - (d) consolidation of monthly accounts, preparation of review of trends of revenue realisation and significant features of expenditure etc. and preparation of annual accounts (including Summary, Civil Appropriation Accounts) showing under the respective heads, the annual receipts and disbursements for the purpose of the Union Government;
 - (e) administration of Central Treasury Rules and Central Government Account (Receipts and Payments Rules 1983);
 - (f) coordination and assistance in the Introduction of management accounting system in Civil Ministries or Departments;
 - (g) cadre management of Group 'A' (Indian Civil Accounts Service) and Group 'B' Officers of the Central Civil Accounts Offices;

- (h) matters relating to the Central Civil Accounts staff belonging to Group 'C' and 'D';
 - (i) disbursement of Pension through Public Sector Banks (PSBs) in respect of Central Civil Pensioners, Freedom Fighters, High Court Judges, Ex-M.P.s and Ex-Presidents.
7. Release of Central Assistance for : the State's Annual Plan, Centre's share of State's Calamity Relief Funds, Assistance from National Calamity Contingency Fund, up-gradation grants and grants for rural/urban local bodies and other grants as recommended by the successive Finance Commissions.
8. Analysis of the States' Finances, day to day financial problems of States and Fiscal Reforms Programmes of the States.
9. Participation in formulation of Annual/Five Year Plan of Central Ministries and Public Sector Undertakings (PSUs). Assessment of Internal and Extra Budgetary Resources of Central Public Sector Undertakings (PSUs) for funding the Plan.
10. Scrutiny of Central and State Legislation having financial and economic implications.
11. Appraisal and approval of Plan Investment/expenditure proposals of Central Ministries/PSUs. Matters relating to Expenditure Finance Committee(EFC) /Public Investment Board (PIB) procedures and Secretariat work for the PIB.
12. Appraisal/Approval of Capital Restructuring/revival proposals of Central Public Sector Undertakings (PSUs).

**C. DEPARTMENT OF REVENUE
(RAJASWA VIBHAG)**

1. All matters relating to-
- (a) Central Board of Excise and Customs;
 - (b) Central Board of Direct Taxes.
2. Grants-in-aid to the National Institute of Public Finance and Policy.
3. Stamp duties on bills of exchange, cheques, promissory notes, bills of lading, letters of credit, policies of insurance, transfer of shares, debentures, proxies and receipts.

4. All questions relating to income tax (except questions relating to the Income-tax Appellate Tribunal), corporation tax, capital gains tax and estate duty, wealth tax, expenditure tax and gift tax and also questions relating to Railway Passenger Fares Act.
5. Administration of the Benami Transactions (Prohibition) Act 1988 (45 of 1988).
6. Administration of excise in the Union Territories, i.e. all questions relating to-
 - (a) alcoholic liquors for human consumption;
 - (b) opium, Cannabis (Indian Hemp) and other Narcotic Drugs and Narcotics.
7. Administration of the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955 (16 of 1955).
8. All matters relating to cultivation of opium poppy, manufacture of opium derivatives from such opium, sale of such opium and opium derivatives and exercise of control thereon.
9. Administration of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985).
10. All matters relating to international conventions, agreements, protocols, etc., in respect of narcotic drugs, psychotropic substances and precursor chemicals which the Department of Revenue and organizations under it are authorized to deal with except matters allocated to the Ministry of Home Affairs.
11. All matters relating to Customs (Sea, Air and Land) including the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), Tariff Valuations, Customs Cooperation Council, Customs nomenclature and similar matters, duties on goods imported or exported; prohibitions and restrictions on imports and exports under the Customs Act; and interpretation of Customs Tariff.
12. Matters relating to Central Excise including Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) and service tax administration.
13. Sales Tax:
 - (a) administration of the Sales-Tax Laws Validation Act, 1956 (7 of 1956);

- (b) levy of tax on the course of inter-State trade or commerce-problems arising out of the administration of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956);
- (c) declaration of goods as of special importance in inter-state trade or commerce under article 286(3) of the Constitution, laying down of the conditions and restrictions to which the State laws providing for the levy of tax on them would be subjected;
- (d) all questions relating to replacement of sales tax by additional excise duty including administration of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957);
- (e) all Bills, etc. relating to sales-tax levy in States coming up for the previous instructions, recommendations or assent of the President;
- (f) legislative matters concerning sales-tax in the Union Territories;
- (g) Problems arising out of the invalidation of sugarcane cess levies of States including Validation of such levies.

14. Subordinate Organisations:

- (a) Income Tax Department;
- (b) Customs Department;
- (c) Central Excise Department; and
- (d) Narcotics Department (excluding Narcotics Control Bureau).

15. Preventive detention for the purposes of conservation of augmentation of foreign exchange and prevention of smuggling activities and matters connected therewith.

16. Enforcement, viz., investigation, and adjudication of cases arising out of breaches under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999); Directorate General of Revenue Intelligence and Directorate of Enforcement.

17. All matters relating to Economic Intelligence.

18. Matters relating to the Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal.

19. All matters covered by the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976).

20. Administration of the Prevention of Money Laundering (PML) Act, 2002 (15 of 2003).

**D. DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS
(KAMPANI KARYA VIBHAG)**

1. Administration of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).
2. Administration of the Companies (Donations of National Funds) Act, 1951 (54 of 1951).
3. Administration of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969).
4. Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission.
5. Profession of Accountancy [The Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949)]; Profession of Costs and Works Accountancy [The Cost and Works Accountants Act, 1959(23 of 1959)]; Profession of Company Secretaries [The Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980)].
6. Collection of Statistics relating to Companies.
7. Legislation relating to law of Partnership and the exercise of certain functions under Chapter VII of the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) in centrally administrated areas. (The administration of the Act vests in the State Governments).
8. The responsibility of the Centre relating to matters concerning centrally administered areas in respect of any of the above items.
9. Legislation in relation to societies registration and exercise of functions under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) in centrally administered areas.

10. Competition Commission of India.

11. The Competition Act, 2000 (12 of 2003).

12. Serious Frauds Investigation Office.

**MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES
(KHADYA PRASANSAKARAN UDYOG MANTRALAYA)**

1. Industries relating to-

- (a) processing and refrigeration of certain agricultural products (Milk powder, Infant milk food, Malted milk food,

Condensed milk, Ghee and other dairy products), Poultry and eggs, Meat and Meat products;

- (b) processing of fish (including canning and freezing);
- (c) establishment and servicing of Development Council for fish processing industry;
- (d) technical assistance and advice to fish processing industry;
- (e) fruit and vegetable processing industry (including freezing and dehydration); and
- (f) foodgrains milling industry.

2. Planning, development and control of, and assistance to, industries relating to bread, oilseeds, meals (edible), breakfast foods, biscuits, confectionery; (including Cocoa processing and Chocolate making), malt extract, protein isolate, high protein food, weaning food and extruded food products (including other ready-to-eat foods).

3. Specialised packaging for food processing industry.

4. Beer including non-alcoholic beer.

5. Alcoholic drinks from non-molasses base.

6. Aerated water and soft drinks.

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(SWASTHYA AUR PARIVAR KALYAN MANTRALAYA)**

**A. DEPARTMENT OF HEALTH
(SWASTHYA VIBHAG)**

I. UNION BUSINESS

1. Union agencies and institutes for research or for the promotion of special studies in medicine and nutrition including all matters relating to -

- (a) Central Research Institute;
- (b) All India Institute of Hygiene and Public Health;
- (c) National Institute of Communicable Diseases;

- (d) Central Drugs Laboratory;
 - (e) Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing;
 - (f) Lady Reading Health School;
 - (g) Central Institute of Psychiatry;
 - (h) Dr. Ram Manohar Lohia Hospital and Nursing Home;
 - (i) Safdarjang Hospital;
 - (j) Medical Stores Organisation;
 - (k) B.C.G. Vaccine Laboratory;
 - (l) Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research;
 - (m) Smt. Sucheta Kirpalani Medical College and Hospital and Kalawati Saran Children's Hospital;
 - (n) Central Government Health Scheme (CGHS);
 - (o) Central Health Service;
 - (p) Serologist and Chemical Examiner to the Government of India.
2. Central Food Laboratory.
 3. Central Food and Standardisation Laboratory.
 4. Central Indian Pharmacopoeia Laboratory.
 5. All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation.
 6. National Tuberculosis Institute.
 7. Central Leprosy Teaching and Research Institute.
 8. Regional Leprosy Training and Research Centre, Raipur (UP), Aska (Orissa), Gauripur (W.B.), Teetulmari (Bihar).

9. Port Quarantine (sea and air) seamen's and marine hospitals and hospitals connected with port quarantine.
10. Port and Air Port Health Organisations.
11. Medical Examination of seamen.
12. International Health Regulations.
13. World Health Organisation (WHO).
14. Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) and the Central Food Laboratory set up thereunder.
15. Higher training abroad in medical and allied subjects.
16. Coordination of work in respect of International Conferences in India and abroad in medical and related fields.
17. International aid for Health Programmes.
18. National Programme for Control of Blindness.
19. National Leprosy Eradication Programme.
20. National Tuberculosis Control Programme.
21. National Malaria Eradication Programme.
22. All National Programmes relating to control and eradication of communicable diseases.
23. Bilateral Cultural Exchange Programmes-Implementation of health related components.
24. Fellowships-for training in India and abroad in various medical and health subjects.
25. Matters relating to epidemics:- Problems connected with supply of medicines, effects of malnutrition and shortage of drinking water leading to various diseases as a result of natural calamities.

II. LIST OF BUSINESS FOR LEGISLATIVE AND EXECUTIVE PURPOSES IN RESPECT OF UNION TERRITORIES.

- 26. Public Health hospitals and dispensaries.
- 27. Scientific societies and associations pertaining to subjects dealt with in the Department.
- 28. Charitable and religious endowments pertaining to subjects dealt with in the Department.

III. LIST OF BUSINESS WITH WHICH THE CENTRAL GOVERNMENT DEAL IN A LEGISLATIVE CAPACITY ONLY FOR THE UNION AND IN BOTH LEGISLATIVE AND EXECUTIVE CAPACITIES FOR ALL UNION TERRITORIES.

- 29. The Medical profession and medical education.
- 30. The nursing profession and nursing education.
- 31. Pharmacists and Pharmacy education.
- 32. The dental profession and dental education.
- 33. Mental Health.
- 34. Drugs Standards.
- 35. Advertisements relating to drugs and medicines.
- 36. Prevention of the extension from one State to another of infectious or contagious diseases affecting human beings.
- 37. Prevention of adulteration of foodstuffs and drugs.

IV. MISCELLANEOUS BUSINESS

- 38. The Medical Council of India.
- 39. The Central Councils of Health and Family Welfare.
- 40. Dental Council of India.
- 41. Indian Nursing Council.

42. Pharmacy Council of India
43. Indian Pharmacopoeia Committee.
44. Concession of medical attendance and treatment for Central Government servants other than (i) those in Railway Service (ii) those paid from Defence Service Estimates (iii) officers governed by the All India Services (Medical Attendance) Rules, 1954 and (iv) officers governed by the Medical Attendance Rules, 1956.
45. Medical Examination and Medical Boards for Central Civil Services [other than those controlled by the Department of Railways and those paid from Defence Services Estimates excepting Civilian Services.].
46. Grants to Vallabhbhai Patel Chest Institute (under Delhi university).
47. Grants to Indian Red Cross Society.
48. Spas and Health resorts.
49. The Indian Council of Medical Research.
50. National Board of Examination.
51. Chittaranjan National Cancer Research Centre.
52. All India Institute of Medical Sciences.
53. Medical and Bio-medical research.
54. All India Institute of Speech and Hearing.
55. Pasteur Institute of India.
56. Physiotherapy Training Centre, King Edward Memorial Hospital.
57. National Institute of Mental Health and Neuro Sciences.
58. Hospital Services Consultancy Corporation Limited.

**B. DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE
(PARIVAR KALYAN VIBHAG)**

1. Policy and organisation for Family Welfare.

2. Reproductive and Child Health.
3. Inter-sectoral coordination in accordance with the National Population Policy.
4. Matters related to Janasankhya Sthiarta Kosh and Empowered Action Group.
5. Organisation and direction of education, training and research in all aspects of family welfare including higher training abroad.
6. Production and supply of aids to Family Planning.
7. Liaison with foreign countries and international bodies as regards matters relating to family welfare.
8. Family Welfare Schemes and projects with external assistance.
9. International Institute of Population Sciences, Mumbai.
10. Development and production of audiovisual aids, extensional education and information in relation to population and family welfare.
11. Promoting Public Private Partnership for the Family Welfare Programme.
12. Hindustan Latex Limited, Thiruvananthapuram.
13. National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi.
14. Implementation of Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 (57 of 1994) – Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Act, 2002 (64 of 2002).

C. DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (AYURVEDA, YOGA AUR PRAKRATIK CHIKITSA, UNANI, SIDDHA AUR HOMOEOPATHY (AYUSH) VIBHAG)

I. UNION BUSINESS

1. Formulation of policy and policy issues for development and propagation of Ayurveda, Siddha, Unani, Homoeopathy, Yoga and Naturopathy systems.

2. Development and implementation of programmes including Central schemes and Centrally sponsored schemes for development and propagation of Ayurveda, Siddha, Unani, Homoeopathy, Yoga and Naturopathy systems.
3. Co-ordination and promotion of research and development including assistance therefor in Ayurveda, Siddha, Unani, Homoeopathy, Yoga and Naturopathy systems.
4. Setting up and maintenance of Central institutions for research and development, education and standards relating to Ayurveda, Siddha, Unani, Homoeopathy, Yoga and Naturopathy systems.
5. All issues and matters requiring action at the level of Government in regard to-
 - (a) Pharmacopoeial Laboratory for Indian Medicine, Ghaziabad;
 - (b) Homoeopathic Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad;
 - (c) Central Council of Indian Medicines;
 - (d) Central Council of Homoeopathy;
 - (e) Ayurvedic Pharmacopoeia Committee;
 - (f) Homoeopathic Pharmacopoeia Committee;
 - (g) Unani Pharmacopoeia Committee;
 - (h) Siddha Pharmacopoeia Committee;
 - (i) Ayurvedic, Siddha and Unani Drugs Technical Advisory Board;
 - (j) Central Council for Research in Ayurveda and Siddha;
 - (k) Central Council for Research in Homoeopathy;
 - (l) Central Council for Research in Unani Medicine;
 - (m) Central Council for Research in Yoga and Naturopathy;

- (n) National Institute of Ayurveda;
- (o) National Institute of Homoeopathy;
- (p) National Institute of Naturopathy;
- (q) National Institute of Yoga;
- (r) National Institute of Unani Medicine;
- (s) National Institute of Siddha;
- (t) Institute of Post-Graduate Teaching and Research, Gujarat Ayurveda University;
- (u) Indian Medicines and Pharmaceuticals Corporation Limited;
- (v) Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth.

6. Education, Training and Research in all aspects of Indian Systems of Medicine including higher training abroad.

7. Matters of cadre formation and control including formation and amendment of recruitment rules, recruitment, promotion and all other service matters relating to ISM&H doctors of Central Government Health Scheme including doctors in ISM&H central hospitals requiring action at Government level.

Note:- Day-to-day administration and management will continue to be with the Director, Central Government Health Scheme.

8. Liaison with foreign countries and international bodies as regards matters relating to Indian Systems of Medicine and Homoeopathy.

9. Matters relating to scientific societies/associations and charitable and religious endowments relating to Indian Systems of Medicine and Homoeopathy.

10. Matters relating to quality and standards for drugs in Indian Systems of Medicine & Homoeopathy to the extent such matters require action at the level of Government.

11. Consultation and coordination with State Governments, Non-Government Organisations and institutions for review of work and programmes in Indian Systems of Medicine & Homoeopathy.
12. Statistics relating to various aspects of Indian Systems of Medicine & Homoeopathy.
13. Proposals and matters concerning Union Territories requiring sanction and concurrence of Government of India in regard to Indian Systems of Medicine and Homoeopathy.
14. Legislative proposals pertaining to Indian Systems of Medicine and Homoeopathy of individual states requiring sanction and concurrence of Government of India.
15. Medicinal Plant Board.

**MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES
(BHARI UDYOG AUR LOK UDYAM MANTRALAYA)**

**A. DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY
(BHARI UDYOG VIBHAG)**

1. The Heavy Engineering Corporation Limited.
2. The Mining and Allied Machinery Corporation Limited.
3. The Engineering Projects (India) Limited.
4. Bharat Heavy Electricals Limited.
5. H.M.T. Bearing Limited.
6. H.M.T. Limited.
7. H.M.T. International Limited.
8. Scooters India Limited.
9. Andrew Yule and Company Limited.
10. Bharat Ophthalmic Glass Limited.
11. Bharat Leather Corporation.

12. Cement Corporation of India Limited.
13. Cycle Corporation of India Limited.
14. Hindustan Cables Limited.
15. Hindustan Paper Corporation Limited.
16. Hindustan Photo Films Manufacturing Company Limited.
17. Hindustan Salts Limited.
18. Hooghly Printing Company Limited.
19. Instrumentation Limited.
20. The Mandya National Paper Mills Limited.
21. Nagaland Pulp and Paper Company Limited.
22. National Bicycle Corporation of India Limited.
23. The National Industrial Development Corporation Limited.
24. National Instruments Limited.
25. N.E.P.A. Limited.
26. Rajasthan Electronics and Instruments Limited.
27. Hindustan Newsprint Limited.
28. Damodar Cement and Slag Limited.
29. Tannery and Footwear Corporation of India Limited.
30. Tyre Corporation of India.
31. Praga Tools Limited.
32. Rehabilitation Industries Corporation.
33. Sambhar Salts Limited.

34. Fluid Control Research Institute.

35. Bharat Bhari Udyog Nigam Limited:

SUBSIDIARIES

- (a) Bharat Brakes and Valves Limited;
- (b) Bharat Process and Mechanical Engineers Limited;
- (c) Bharat Wagon and Engineering Company Limited;
- (d) Braithwaite and Company Limited;
- (e) Burn Standard Company Limited;
- (f) Jessop and Company Limited;
- (g) The Lagan Jute Machinery Company Limited;
- (h) Braithwaite, Burn and Jessop Construction Limited;
- (i) Reyrolle Burn Limited;
- (j) Weighbird (India) Limited.

36. Bharat Yantra Nigam Limited.

SUBSIDIARIES

- (a) The Triveni Structurals Limited, Allahabad;
- (b) The Tungabhadra Steel Products (India) Limited, Durgapur;
- (c) The Bharat Heavy Plates and Vessels Limited;
- (d) Bharat Pumps and Compressors Limited;
- (e) Richardson and Cruddas (1972) Limited;
- (f) Bridge and Roof Company.

37. Maruti Udyog Limited.

38. Manufacture of heavy engineering equipment for all industries.
39. Heavy electrical engineering industries.
40. Machinery Industries including Machine Tools and Steel Manufactures.
41. Auto Industries, including tractors and earth moving equipment.
42. All types of diesel engines.
43. Automotive Research Association, Pune.

**B. DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES
(LOK UDYAM VIBHAG)**

1. Bureau of Public Enterprises including Industrial Management Pool.
2. Coordination of matters of general policy of non-financial nature affecting all public sector industrial and commercial undertakings.
3. Matters relating to Memorandum Of Understanding mechanism of improving the performance of Public Sector Undertakings.
4. Matters relating to Permanent Machinery of Arbitration for the Public Sector Enterprises.
5. Counselling, training and rehabilitation of employees in Central Public Sector Undertakings under Voluntary Retirement Scheme.

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(GRIH MANTRALAYA)**

**A. DEPARTMENT OF INTERNAL SECURITY
(ANTRIK SURAKSHA VIBHAG)**

I. POLICE

1. Assam Rifles.
2. Border Security Forces.
3. Indo-Tibetan Border Police.

4. Special Services Bureau.
5. National Police Academy and Central Detective Training Schools.
6. National Crime Records Bureau.
7. Intelligence Bureau.
8. Central Forensic Science Laboratories and Government Examiners of Questioned Documents.
9. Central Industrial Security Force.
10. Central Reserve Police Force.
11. National Security Guard.
12. Matters relating to Indian Police Service.
13. Foreign training of IPS and officers of Para-military Forces including training programmes under bilateral cooperation.
14. All matters relating to training of Foreign Police Officers in India.
15. All matters relating to Civil Defence and Home Guards.
16. Matters relating to Inter-State Police Wireless System.
17. Matters relating to Police Medals.

II. LAW AND ORDER

18. Matters relating to Counter terrorism.
19. VVIP security, personal security on threat perception basis, security of important Government buildings etc.
20. The Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1985 – Pending cases.
21. The Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984 (61 of 1984) – All matters relating to the Act.
22. Grant of Indian citizenship by registration and naturalization.

23. All matters relating to the Bureau of Immigration.
24. Grant of Visa for India in respect of citizens of Afghanistan, Bangladesh, Pakistan and Sri Lanka, including their long term stay in India and regulation of entry/stay of all foreigners into/ in India.
25. Deportation of citizens of other countries from India.
26. Repatriation of foreigners jailed in India including foreign fisherman apprehended in Indian waters.
27. Government servants having families in Pakistan-cases regarding grant of permission to Government Servants to visit Pakistan.
28. Regulation of the acceptance and utilization of foreign contribution and foreign hospitality by associations and persons.
29. Central Secretariat Security.
30. Prevention of bringing into India of undesirable literature under Section 11 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
31. The Essential Services Maintenance Act, 1981 (40 of 1981).
32. Requisitioning of the services of Government servants for any duty during the period of operation of any Proclamation issued under clause (1) of article 352 of the Constitution.
33. Preventive detentions except to the extent specially allotted to any other Central Ministry or Department.
34. Removal from one State to another State of persons, accused persons and persons subjected to preventive detention.
35. Criminal Law.
36. Criminal Procedure.
37. Criminal offences against women, children and members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, including those under the Protection of Civil Rights Act, 1955 (22 of 1955) and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989), other Backward Classes, Minorities and other vulnerable groups.

38. Matters relating to the State of Nagaland.
39. Matters relating to the State of Sikkim.
40. Parliament Questions relating to crime on Railways other than offences relating to pilferage of railway property.
41. Matters relating to Arms, Fire Arms and Ammunitions.

III. REHABILITATION

42. Residuary work relating to relief to/ rehabilitation of displaced persons from (a) former East Pakistan (b) border areas of Jammu & Kashmir as a result of Indo-Pak Conflict of 1971 and (c) Pakistan occupied areas of Jammu and Kashmir.
43. Relief and Rehabilitation of repatriated Indian nationals.
44. Relief to and rehabilitation of refugees from Tibet.
45. Relief to refugees from Sri Lanka.
46. Dandakaranya Development Scheme and Dandakaranya Development Authority.
47. Residuary work relating to provision of compensation to and rehabilitation of displaced persons from former West Pakistan, other than issue of lease or conveyance deed in respect of Government built properties, conversion of lease deeds, allotment of additional strips of land and correctional areas adjoining the properties which have been allocated to the Ministry of Urban Development.
48. Development of such special areas as may be indicated by Prime Minister from time to time.
49. Administration of the Acts pertaining to administration of evacuee property and compensation to and rehabilitation of displaced persons from former West Pakistan.
50. Negotiations with Pakistan concerning evacuee property left by displaced persons from former West Pakistan.
51. Residuary work relating to disposal of unclaimed moveable property received from former West Pakistan.

52. Coordination of relief measures in the event of natural calamities (other than drought or epidemics) and man-made disasters, excluding specific items of business allocated to other Ministries/Departments.

53. Matters relating to loss of human life and property due to all natural and man-made calamities, other than drought or epidemics.

54. All matters relating to Narcotics Control Bureau set up under the provisions of Section 4(3) of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and coordination of all measures for preventing and combating abuse of and illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances.

55. All matters relating to international conventions, agreements, protocols, etc., in respect of illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances and precursor chemicals which the Ministry of Home Affairs and organizations under it are authorized to deal with except matters allocated to the Ministry of Finance, Department of Revenue.

56. Administration of the following Acts, namely:-

- (a) The Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923);
- (b) The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967);
- (c) The Criminal Law (Amendment) Act, 1961 (23 of 1961);
- (d) The Young Persons Harmful Publication Act, 1956 (93 of 1956);
- (e) The Punjab special Powers (Press) Act, 1956 (38 of 1956);
- (f) The Armed Forces (Assam and Manipur) Special Powers Act, 1958 (28 of 1958);
- (g) The Essential Services Maintenance (Assam) Act, 1980 (41 of 1980);
- (h) The Illegal Migrants (Determination) Tribunal Act, 1983 (39 of 1983);
- (i) The Explosive Substances Act, 1908 (6 of 1908);
- (j) The Prevention of Terrorism Act, 2002 (15 of 2002);
- (k) The Foreigners Act, 1946 (31 of 1946);

- (l) The Passport (Entry into India) Act, 1920 (34 of 1920);
- (m) The Registration of Foreigners Act, 1939 (16 of 1939);
- (n) The Immigration (Carriers Liability) Act, 2000 (52 of 2000);
- (o) The Citizenship Act, 1955 (57 of 1955);
- (p) The Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976).

**B. DEPARTMENT OF STATES
(RAJYA VIBHAG)**

(I) CENTRE-STATE RELATIONS

1. Establishment and formation of new States: matters arising therefrom (excepting those pertaining to allocation of service personnel); integration of Services and other matters relating to State Services allotted to the Department of Personnel and Training and alternation of areas; boundaries and names of existing States.
2. Matters relating to the Rulers of former Indian States referred to in clause (22) of Article 366 of the Constitution and their families.
3. Special provisions in Article 371 of the Constitution with respect to the State of Andhra Pradesh, Maharashtra and Gujarat.
4. Administration of the Acts relating to the reorganisation of States.

(II) INTER-STATE RELATIONS

5. Inter-State Council.
6. Inter-State migration.

(III) UNION TERRITORIES

7. Union Territories with legislature:
 - (a) National Capital Territory (NCT) of Delhi:
 - (i) All matters falling within the purview of the Union Government in terms of provisions contained in Part VIII of the Constitution in so far as these are applicable to the National Capital Territory of Delhi and the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 excepting

matters with respect to Entry 18 of the State List and all such matters as have been specifically assigned under these Rules to any other Ministry or Department of the Government of India;

(ii) all powers and functions of the Central Government as per the provisions of the Municipal Corporation of Delhi Act, 1957 and New Delhi Municipal Council Act, 1994 except matters pertaining to Land and Building Bye Laws;

(b) Union Territory of Pondicherry:

All matters falling within the purview of the Central Government in terms of provisions contained in Part VIII of the Constitution in so far as these relate to the Union territory of Pondicherry and the Government of Union Territories Act, 1963 except all such matters as have been under these rules specifically been assigned to any other Ministry or Department of the Government of India.

8. (a) Making of Regulations under article 240 of the Constitution for peace, progress and good government of the Union Territories.
- (b) Extension of State Acts to the Union Territories.
- (c) Delegation of powers of State Government and Central Government under various enactments to the Administrators of the union Territories under article 239 of the Constitution.
- (d) General Questions relating to public services in the Union Territories and Service matters in so far as these fall within the purview of State Governments relating to-
 - (i) the officers of Indian Administrative Service and Indian Police Service serving in connection with the affairs of the Union Territories;
 - (ii) NCT of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Civil and Police Services (DANICS and DANIPS);
 - (iii) Pondicherry Civil and Police Services.

(e) Appointment of Lt. Governors and Administrators in the Union Territories.

Note:- All above matters relating to Union Territories except those which are specifically allotted to any Ministry/ Department.

9. Union Territories without legislature:

All matters enumerated in the State List and the concurrent List in so far as any such matter is applicable to Union Territories except all such matters as have been under these Rules specifically assigned to any other Ministry or Department of the Government of India including (a) organization and maintenance of mainland-islands and inter-islands shipping services in respect of the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep and (b) forests, education, road and bridges works and ferries thereon in respect of Andaman and Nicobar Islands.

(IV) OTHER SUBJECTS

10. Pension and other facilities to Freedom Fighters.

11. Human Rights:

- (i) to act as the nodal agency for the general policies regarding "Human Rights" matters, including National Human Rights Commission or any other institutional arrangements in this regard;
- (ii) human rights violations relating to alleged excesses by personnel of police and paramilitary forces;
- (iii) interaction with Human Rights Organisations and other related organisations within the country and coordination with various departments and State Governments;
- (iv) coordination of policy relating to Human Rights.

Note:- Ministry of Home Affairs will be the nodal Ministry for overall policy relating to Human Rights. The departments primarily concerned with the welfare and socio-economic development of specific groups like members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, women, minorities, children, and bonded labour, shall be responsible in respect of preservation of Human Rights of the specified groups.

12. Matters relating to Bureau of Police Research and Development, National Civil Defence College, National Fire Service College.

13. Development of Fire Services

14. Extension of the powers and jurisdiction of members of a police force belonging to any State, to any area outside that State, but not so to enable the police of one State to exercise powers and jurisdiction in any area outside that State without the consent of the Government of the State in which such area is situated; extension of the powers and jurisdiction of members of a police force belonging to any State to railway areas outside the State.

15. Police Reforms.

16. Prison Reforms

**C. DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
(RAJBHASHA VIBHAG)**

1. Implementation of the provisions of the Constitution relating to Official Language and the provisions of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963) except to the extent such implementation has been assigned to any other Department.

2. Prior approval of the President for authorising the limited use of a language other than English in the proceedings in the High Court of a State.

3. Nodal responsibility for all matters relating to the progressive use of Hindi as the Official language of the Union, including Hindi teaching schemes for Central government employees.

4. Publication and distribution of publicity literature for progressive use of Hindi as official language of the Union.

5. Coordination in all matters relating to progressive use of Hindi as the official language of the Union including administrative terminology, syllabi, text-books, training courses and equipment (with standardised script) required therefor.

6. Constitution and Cadre management of the Central Secretariat Official Language Service.

7. Matters relating to Kendriya Hindi Samiti including its up-samitis.
8. Coordination of work relating to the Hindi Salahkar Samitis set up by the various Ministries/Departments.
9. Matters relating to the Central Translation Bureau.

**D. DEPARTMENT OF HOME
(GRIH VIBHAG)**

1. Notification of assumption of office by the President and the Vice-President and swearing in ceremony of the President.
2. Grant of pardons, reprieves, suspensions, remission or commutation of a sentence of death and petitions for remission of sentences (other than death) or for pardon from prisoners sentenced by courts in States for offences against any law relating to a matter to which the executive power of the Union extends.
3. Issue of notifications of appointment and resignation of the Prime Minister and other Ministers and Parliamentary Secretaries of the Union.
4. Rules for the authentication of papers in the name of the President.
5. Model Rules of business for State Governments/Union Territory Administrations.
6. Nominations to Rajya Sabha and Lok Sabha.
7. Appointment, resignation and removal of Governors and related matters.
8. Regulations framed by the Governors and reserved for the assent of the President.
9. Bills passed by legislatures of States (except Jammu and Kashmir) reserved by Governors for the consideration of the President; and the prior consultation with the Central Government by the State Governments as regards State Legislation.
10. Prior approval of the President to the promulgation of Ordinances by Governors of States.

11. Property accruing to the Union by escheat or lapse of a bona vacantia.
12. Special provision relating to the language spoken by a substantial proportion of the population of a State.
13. Matters relating to the emergency provisions of the Constitution (other than those relating to financial emergency).
14. Conventions with other countries in judicial matters including questions relating to International Court of Justice and reference from the United Nations Organisations relating to obscene publications.
15. Matters relating to Code of Conduct of Legislatures.
16. Code of Conduct for Ministers.
17. Employment of wives or dependents of Government servants in foreign Missions in India.
18. Exchange of visits between Civil and Military Officers.
19. Lotteries organized by the Government of India or the Government of a State/Union Territory.
20. Census of population, including administration of the Census Act, 1948 (37 of 1948) and the Census (Amendment) Act, 1993 (11 of 1994).
21. Official dress.
22. Emoluments, allowances, privileges and rights in respect of leave of absence of the President and Governors; salaries and allowances of Ministers, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries of the Union.
23. National Anthem.
24. National Flag of India; President's and Governor's Standards.
25. State Emblem.
26. Warrant of Precedence.
27. Awards and decorations.

28. National Festivals.
29. Matters relating to National Integration and Communal Harmony.
30. Changes in geographical names.
31. Action to be taken on the death of high dignitaries.
32. Political pensions.
33. Compassionate allowance to dependents of mutiny veterans.
34. Home Minister's discretionary fund.
35. Poisons.
36. Registration of Births and Deaths, including administration of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969).
37. Newspapers, books and printing presses.
38. Administration of—
 - (a) The Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) – Legislative aspect;
 - (b) The Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 (69 of 1971);
 - (c) The Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act, 1988 (41 of 1988);
 - (d) The Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 (42 of 1991);
 - (e) The Acquisition of Certain Areas at Ayodhya Act, 1993 (33 of 1993).

**E. DEPARTMENT OF JAMMU AND KASHMIR AFFAIRS
(JAMMU TATHA KASHMIR VIBHAG)**

1. Constitutional provisions with respect to the State of Jammu and Kashmir.

2. All matters relating to the State of Jammu and Kashmir, including counter terrorism within Jammu and Kashmir and coordination in respect of subjects/matters specifically allotted to any other Ministry/Department like coordination with Ministry of Defence as regards manning and managing the line of control between India and Pakistan, but excluding those with which the Ministry of External Affairs is concerned.

3. Administration of the Armed Forces (J&K) Special Powers Act, 1990 (21 of 1990).

Note: While the Department of Jammu and Kashmir Affairs would coordinate with various Ministries/Departments, primarily concerned with development and welfare activities in Jammu and Kashmir, respective Ministries/Departments would be responsible in respect of subjects allocated to them.

**F. DEPARTMENT OF BORDER MANAGEMENT
(SEEMA PRABANDHAN VIBHAG)**

1. Management of International Land and Coastal Borders excluding those subjects specifically allocated to Ministry of Defence and Ministry of External Affairs.

2. Coordination with State Governments and other Departments of Government of India in respect of subjects specified in this list.

3. Strengthening of border policing and guarding.

4. Creation of infra-structure like roads; fencing and flood lighting of borders, in coordination with Ministry of Defence and Ministry of External Affairs.

5. Border Area Development Programme excluding the subject specifically allocated to Department of Development of North Eastern Region.

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(MANAV SANSADHAN VIKAS MANTRALAYA)**

**A. DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION AND LITERACY
(PRARAMBHIK SHIKSHA AUR SAKSHARTA VIBHAG)**

1. Pre-Primary Education.

2. Elementary Education.
3. Basic Education.
4. Bal Bhavan, Children's Museum.
5. Social Education and adult education.
6. Audio Visual Education with reference to entries in this list.
7. Books (other than the books with which the Ministry of Information and Broadcasting is concerned) and Book Development (excluding stationery paper and news print industries with which the Ministry of Commerce and Industry is concerned) with respect to the items in the list.
8. Educational Research with respect to items in the list.
9. Publications, information and statistics with reference to the items in the list.
10. Teachers training with reference to the items in the list.
11. National Council for Teacher Education.
12. Charities and Charitable Institutions, Charities and Religious Endowments pertaining to subjects dealt within this Department.

**B. DEPARTMENT OF SECONDARY AND HIGHER EDUCATION
(MADHYMIK AUR UCHCHATAR SHIKSHA VIBHAG)**

1. Secondary Education and Vocational Guidance.
2. University education; Central Universities; Rural Higher Education Foreign Aid Programme relating to Higher Education, Technical Education Planning and Development of School Education.
3. Institutions of higher learning (other than Universities).
4. Books [other than the books with which the Ministry of Information and Broadcasting is concerned] and Book Development (excluding stationery paper and news print industries with which the Ministry of Commerce and Industry is concerned) with respect to the items in the list.

5. Audio Visual Education with reference to the items in the list.
6. Production of University level text-books in Regional Languages.
7. The Copyright Act, 1957 (14 of 1957) and International Conventions on Copyrights.
8. Nodal responsibility relating to World Intellectual Property Organisation (WIPO).
9. Educational research.
10. Publications, information and statistics.
11. Teacher's training with reference to the items in the list.
12. Development and propagation of Hindi, including multi-lingual dictionaries.
13. Grant of Financial assistance for the teaching and promotion of Hindi.
14. Propagation and development of Sanskrit.
15. Rehabilitation and other problems relating to displaced teachers and students.
16. Central Advisory Board of Education.
17. UNESCO and Indian National Commission for Cooperation with UNESCO.
18. Matters relating to all scholarships including those offered by foreign countries and foreign agencies in subjects dealt with by this Department but excluding scholarships to students belonging to scheduled castes and scheduled tribes, denotified, nomadic and semi-nomadic tribes and General Scholarships Schemes and scholarships to foreign students and different schemes.
19. Education and Welfare of Indian Students overseas; Education Departments of Indian Missions overseas; Financial assistance to education institutions and Indian Students' Associations abroad.

20. Educational Exchange Programmes; exchange of teachers, professors, educationists, scientists, technologists, etc.; programme of exchange of scholars between India and foreign countries.
21. Grant of permission to teachers of Universities, colleges and institutions of higher learning to accept assignments abroad.
22. Admission of foreign students in Indian Institutions.
23. Charities and Charitable Institutions, Charities and Religious Endowments pertaining to subjects dealt within this Department.
24. Adhoc scientific research, other than research in higher mathematics, nuclear science and atomic energy, in universities and educational institutions.
25. Vigyan Mandirs.
26. General Policy regarding partial financial assistance to Scientists going abroad for studies in fields other than mathematics, nuclear science and atomic energy.
27. Expansion, Development and Coordination of Technical Education.
28. School of Planning and Architecture.
29. Regional Schools of Printing.
30. Grants-in-aid to State Government institutions, non-Government institutions, professional bodies and technical institutions of Union Territories for technical education. Grants-in-aid for post graduate studies in basic sciences, grants-in-aid for development of higher scientific and technological education and research in educational institutions; Grants-in-aid for fundamental research in science and technology; grants to individuals for fundamental research.
31. All India Council for Technical Education including conduct of its National Diploma and National Certificate Examinations.
32. Practical training facilities for students of engineering and technological institutions.
33. Recognition of professional technical qualification for purposes of recruitment to posts under Government of India.

34. National Research Professorships and Fellowships.
35. Holding of Foreign Examination in the fields of professional and technical education in India.
36. University Grants Commission.
37. National Council for Educational Research and Training.
38. National Book Trust.
39. Administrative Staff College of India, Hyderabad.
40. Indian School of Mines and Applied Geology, Dhanbad.
41. Indian Institutes of Technology at Kharagpur, Mumbai, Kanpur, Chennai, Delhi, Guwahati and Roorkee.
42. Indian Institute of Science, Bangalore.
43. The Tata Institute of Social Sciences, Mumbai.
44. International Students Houses in India and abroad.
45. Schemes for grant of financial assistance to voluntary organisations for promotion of modern Indian languages.

**C. DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
(MAHILA AUR BAL VIKAS VIBHAG).**

1. Welfare of the family.
2. Women and Child welfare and co-ordination of activities of other Ministries and Organisations in connection with this subject.
3. References from the United Nations Organisations relating to traffic in women and children.
4. Care of pre-school children.
5. National Nutrition Policy, National Plan of Action for Nutrition and National Nutrition Mission.
6. Charitable and religious endowments pertaining to subjects allocated to this Department.

7. Promotion and development of voluntary effort on subjects allocated to this Department.

8. Implementation of-

(a) The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (as amended upto 1986);

(b) The Indecent Representation of Women (Prevention) Act, 1986 (60 of 1986);

(c) The Dowry Prohibition Act, 1961 (as amended upto 1986);

(d) The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 (3 of 1988),

excluding the administration of criminal justice in regard to offences under these Acts.

9. Implementation of the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Food (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 (41 of 1992).

10. Coordination of activities of Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE).

11. Planning, Research, Evaluation, Monitoring, Project Formulations, Statistics and Training relating to the welfare and development of women and children, including development of gender sensitive data base.

12. United Nations Children's Fund (UNICEF).

13. Central Social Welfare Board (CSWB).

14. National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD).

15. Food and Nutrition Board.

16. (i) Development and popularisation of subsidiary and protective foods.

(ii) Nutrition extension.

17. Women's Empowerment and Gender Equity.

18. National Commission for Women.
19. Rashtriya Mahila Kosh.

**MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING
(SOOCHANA AUR PRASARAN MANTRALAYA)**

I. BROADCASTING POLICY AND ADMINISTRATION

1. All matters relating to radio and television broadcasting within the Union including regulation of the use of All India Radio and Doordarshan by recognised national and regional political parties during elections to the Lok Sabha and State Assemblies and procedure to be followed by the official electronic media during periods of national mourning on the demise of a high dignitary.
2. The enunciation and implementation of the law relating to radio and television broadcasting in India by private Indian companies or Indian nationals.
3. Broadcast Monitoring and Administration of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990).
4. All matters relating to the Indian Broadcasting (Programme) Service and the Indian Broadcasting (Engineering) Service until they are handed over to Prasar Bharati.

II. CABLE TELEVISION POLICY

5. Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995).

III. RADIO

6. All business connected with All India Radio embracing news services in the home programmes, programmes for the foreign countries and Indians overseas, radio journals, research in the field of broadcasting engineering, monitoring of foreign broadcasts, programme exchange and transcription services, supply of community receiving sets to State Governments under the community listening scheme, etc.
7. Development of radio Broadcasting throughout the Union, installation and maintenance of Radio Stations and Transmitters and operation of broadcasting services.

IV. DOORDARSHAN

8. Exchange including cultural exchange of television programmes.
9. Development of television throughout the Union, including installation, maintenance and operation of television Programme Production Centres and Transmitters, and operation of television services.
10. Promotion of production of television programmes outside Doordarshan.

V. FILMS

11. Legislation under entry 60 of the Union List, viz., 'Sanctioning of Cinematograph films for exhibition'.
12. Administration of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952).
13. Import of feature and short films for theatrical and non-theatrical viewing.
14. Export of Indian films, both feature and short films.
15. Import of unexposed cinematograph films and various types of equipment required by the film industry.
16. All matters relating to film industry, including developmental and promotional activities thereto.
17. Promotion of good cinema by institution of State awards for films produced in India and assistance through the National Film Development Corporation Limited.
18. Production and distribution of documentaries and newsreels and other films and film strips for internal and external publicity.
19. Preservation of films and filmic materials.
20. Organisation of International Film Festivals in India and participation of India in International Film Festivals abroad.
21. Organisation of Film Festivals and Cultural Exchange Programmes.
22. Film society movement.

VI. ADVERTISING AND VISUAL PUBLICITY

23. Production and release of advertisements on behalf of the Government of India.

VII. PRESS

24. Presentation and interpretation of the policies and activities of the Government of India through the medium of the press.

25. Advising Government on information problems relating to the Press, keeping Government informed of the main trends of public opinion as reflected in the Press and liaison between Government and the Press.

26. Publicity to and for the Armed Forces.

27. General conduct of Government relations with the Press excluding the administration of sections 95 and 96 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

28. Administration of the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867) relating to Newspapers.

29. Administration of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978).

30. Allocation of Newsprint to Newspapers.

VIII. PUBLICATIONS

31. Production, sale and distribution of popular pamphlets, books and journals on matters of national importance for internal as well as external publicity, with a view to imparting to the general public at home and abroad upto date and correct information about India.

IX. RESEARCH AND REFERENCE

32. To assist the Media Units of the Ministry of Information and Broadcasting in collection, compilation and preparation of material involving research into published works, etc.

33. Building up of a compendium of knowledge on important subjects and to prepare guidance and background notes on current and other topics for the use of the Media Units of the Ministry.

X. MISCELLANEOUS

34. Publicity for the policies and programmes of Government of India.
35. Administration of Journalists Welfare Fund.
36. Financial assistance to distinguished musicians, both vocal and instrumental, dancers and dramatists who have contributed substantially to the success of All India Radio and other units of the Ministry or their survivors in indigent circumstances.
37. All matters relating to the Asia-Pacific Broadcasting Union, Commonwealth Broadcasting Association and the Non-Aligned News Agency Pool.
38. Cadre management of the Indian Information Service (Groups 'a' & 'b').

XI. ATTACHED AND SUBORDINATE ORGANISATIONS

39. (a) All India Radio;
- (b) Doordarshan;
- (c) Press Information Bureau;
- (d) Directorate of Advertising and Visual Publicity;
- (e) Publications Division ;
- (f) Office of the Registrar of Newspapers for India;
- (g) Central Board of Film Certification;
- (h) Films Division;
- (i) Directorate of Film Festivals;
- (j) National Film Archives of India;
- (k) Directorate of Field Publicity;
- (l) Song and Drama Division;

- (m) Research, Reference and Training Division;
- (n) Photo Division;
- (o) Principal Accounts Office;
- (p) Central Monitoring Service.

XII. AUTONOMOUS ORGANISATIONS

- 40. (a) Film and Television Institute of India, Pune;
- (b) Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata;
- (c) Children Film Society of India;
- (d) Indian Institute of Mass Communication;
- (e) Press Council of India;
- (f) Federation Of Film Society Of India

XIII. PUBLIC SECTOR UNDERTAKING

- 41. National Film Development Corporation Limited.
- 42. Broadcast Engineers Consultants (India) Limited.

MINISTRY OF LABOUR (SHRAM MANTRALAYA)

PART I. UNION SUBJECTS

- 1. In respect of Union Railways - Payment of wages, trade disputes, hours of work from employees not covered by the Factories Act, and regulation of employment of children.
- 2. In respect of Docks - Regulation of safety, health and welfare measures concerning dock labour.
- 3. Regulation of labour and safety in mines and oilfields.

PART II. CONCURRENT SUBJECTS

4. Factories.
5. Welfare of Labour - Industrial, commercial and agricultural conditions of labour; provident funds, family pensions, gratuity, employers' liability and workmen's compensation; health and sickness insurance, including invalidity pensions, old age pensions, improvement of working conditions in factories; canteens in industrial undertakings.
6. Unemployment Insurance.
7. Trade Union; industrial and labour disputes.
8. Labour statistics.
9. Employment and unemployment except rural employment and unemployment.
10. Vocational and technical training of craftsmen.

PART III. ADDITIONAL BUSINESS FOR STATES OF HIMACHAL PRADESH, MANIPUR, TRIPURA AND UNION TERRITORY OF DELHI.

11. Items mentioned in Part II above.

PART IV. INCIDENTAL BUSINESS WITH RESPECT TO ANY OF THE MATTERS MENTIONED IN PARTS I, II AND III ABOVE.

12. The implementing of treaties and agreements with other countries.
13. Jurisdiction and powers of all Central Government Industrial Tribunals/Labour Courts.

PART V. MISCELLANEOUS BUSINESS

14. Employment Exchanges.
15. Schemes for training of instructors, craftsmen, technicians, and foreman at supervisory level, both in India and abroad, apprentice training.

16. International Labour Organisation (ILO).
17. Tripartite Labour Conferences.
18. The War Injuries (Compensation Insurance) Act, 1943 (23 of 1943) and Scheme.
19. Administration of laws connected with safety and welfare in mines other than coal mines; organisations of the Chief Inspector of Mines and Mica Mines Welfare.
20. Administration of the Indian Dock Labourers Act, 1934 and the Regulations made thereunder and the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Scheme, 1961 framed under the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948).
21. Administration of the Tea Districts Emigrant Labour (Repeal) Act, 1970 (50 of 1970) and the Organisation of the Controller of Emigrant Labour.
22. All emigration under the Emigration Act, 1983 (31 of 1983) from India to overseas countries and the return of emigrants.
23. Administration of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948).
24. Administration of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) and the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972).
25. Administration of Labour Laws in central sphere undertakings.
26. Labour Statistics; Organisation of Director Labour Bureau.
27. Organisation of Chief Labour Commissioner and Constitution and administration of Central Government Industrial Tribunal, Central Government Labour Courts, National Industrial Tribunal.
28. Organisation of Chief Advisor Factories, Staff Training Division, including Central Labour Institute, productivity and Training Within Industry Centres and Regional Museums of Safety, Health and Welfare.
29. Plantation Labour and administration of the Plantations Labour Act, 1951 (69 of 1951).

30. Recruitment, posting, transfer and training of Central Government Labour Officers.
31. Administration of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955).
32. Schemes regarding workers' education.
33. Schemes regarding workers' participation in management.
34. Discipline in industry.
35. Constitution of Wage Boards for individual industries.
36. Regulation of working condition of motor transport workers.
37. Evaluation of the implementation of Labour Laws in the country.
38. Administration of laws relating to the working conditions and welfare of cinema workers and cinema theatre workers.
39. Prime Minister Shram Awards, National Safety Awards (for Mines and Factories), Rashtriya Viswakarma Puraskar.
40. The Building and other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) and the Building and other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996 (28 of 1996).
41. Sales Promotion Employees (conditions of Service) Act, 1976 (11 of 1976).

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(VIDHI AUR NYAYA MANTRALAYA)**

**A. DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS
(VIDHI KARYA VIBHAG)**

1. Advice to Ministries on legal matters including interpretation of the Constitution and the laws, conveyancing and engagement of counsel to appear on behalf of the Union of India in the High Courts and subordinate courts where the Union of India is a party.

2. Attorney General of India, Solicitor General of India, and other Central Government law officers of the States whose services are shared by the Ministries of the Government of India.
3. Conduct of cases in the Supreme Court and the High Courts on behalf of the Central Government and on behalf of the Governments of States participating in the Central Agency Scheme.
4. Reciprocal arrangements with foreign countries for the service of summons in civil suits, for the execution of decrees of Civil Courts, for the enforcement of maintenance orders, and for the administration of the estates of foreigners dying in India intestate.
5. Authorization of officers to execute contracts and assurances and of property on behalf of the President under Article 299(1) of the Constitution, and authorization of officers to sign and verify plaints or written statements in suits by or against the Central Government.
6. Indian Legal Service.
7. Treaties and agreements with foreign countries in matters of civil law.
8. Law Commission.
9. Legal Profession including the Advocates Act, 1961 (25 of 1961) and persons entitled to practice before High Courts.
10. Enlargement of the jurisdiction of Supreme Court and the conferring thereon of further powers; persons entitled to practice before the Supreme Court; references to the Supreme Court under Article 143 of the Constitution of India.
11. Administration of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952).
12. Income-tax Appellate Tribunal.
13. Appellate Tribunal for Foreign Exchange.
14. Legal aid to the poor.

**B. LEGISLATIVE DEPARTMENT
(VIDHAYEE VIBHAG)**

1. The drafting of Bills, including the business of the Draftsmen in Select Committees, drafting and promulgation of Ordinances and Regulations; enactment of State Acts as President's Acts whenever required; scrutiny of statutory Rules and Orders.
2. Constitution Orders; notifications for bringing into force Constitution (Amendment) Acts.
3. (a) Publication of Central Acts, Ordinance and Regulations;
(b) Publication of authorised translations in Hindi of Central Acts, Ordinances, Orders, Rules, Regulations and bye-laws referred to in section 5(1) of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963).
4. Compilation and publication of unrepealed Central Acts, Ordinances and Regulations of general statutory Rules and Orders, and other similar publications.
5. Elections to Parliament, to the Legislatures of States, to the Offices of the President and Vice-President; and the Election Commission.
6. Preparation and publication of standard legal terminology for use, as far as possible, in all official languages.
7. Preparation of authoritative texts in Hindi of all Central Acts and of Ordinances promulgated and Regulations made by the President and of all rules, regulations and orders made by the Central Government under such Acts, Ordinances and Regulations.
8. Making arrangements for the translation into official languages of the States of Central Acts and of Ordinances promulgated and Regulations made by the President and for the translation of all State Acts and Ordinances into Hindi if the texts of such Acts or Ordinance are in a language other than Hindi.
9. Publication of law books and law journals in Hindi.

The following subjects, which fall within list III of the Seventh Schedule to the Constitution of India (as regards Legislation only) -

10. Marriage and divorce; infants and minors; adoption, wills; intestate and succession; joint family and partition.
11. Transfer of property other than agricultural land (excluding benami transactions registration of deeds and documents).
12. Contracts, but not including those relating to agricultural land.
13. Actionable wrongs.
14. Bankruptcy and insolvency.
15. Trusts and trustees, Administrators, General and Official Trustees.
16. Evidence and oaths.
17. Civil Procedure including Limitation and Arbitration.
18. Charitable and religious endowments and religious institutions.

**C. DEPARTMENT OF JUSTICE
(NYAYA VIBHAG)**

1. Appointment, resignation and removal of the Chief Justice of India and Judges of the Supreme Court of India; their salaries, rights in respect of leave of absence (including leave allowances), pensions and travelling allowances.
2. Appointment, resignation and removal, etc., of Chief Justice and Judges of High Courts in States; their salaries, rights in respect of leave of absence (including leave allowances), pensions and traveling allowances.
3. Appointment of Judicial Commissioners and Judicial officers in Union Territories.
4. Constitution and organisation (excluding jurisdiction and powers) of the Supreme Court (but including contempt of such Court) and the fees taken therein.
5. Constitution and organisation of the High Courts and the Courts of Judicial Commissioners except provisions as to officers and servants of these courts.

6. Administration of justice and constitution and organisation of courts in the Union Territories and fees taken in such courts.
7. Court fees and Stamp duties in the Union Territories.
8. Creation of all India Judicial Service.
9. Conditions of service of District Judges and other Members of Higher Judicial Service of Union Territories.
10. Extension of the Jurisdiction of a High Court to a Union Territory or exclusion of a Union Territory from the Jurisdiction of a High Court.

**MINISTRY OF MINES
(KHAN MANTRALAYA)**

- 1.(a) Legislation for regulation of mines and development of minerals within the territory of India, including mines and minerals underlying the ocean within the territorial waters or the continental shelf, or the exclusive economic zone and other maritime zones of India as may be specified, from time to time, by or under any law made by Parliament.
- (b) Regulation of mines and development of minerals other than coal, lignite and sand for stowing and any other mineral declared as prescribed substances for the purpose of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) under the control of the Union as declared by law, including questions concerning regulation and development of minerals in various States and the matters connected therewith or incidental thereto.
2. All other metals and minerals not specifically allotted to any other Ministry/Department, such as, aluminium, zinc, copper, gold, diamonds, lead and nickel.
3. Planning, development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Department.
4. Geological Survey of India.
5. Indian Bureau of Mines.
6. Metallurgical Grade Silicon.

**MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES
(APARAMPARIK OORJA SROTA MANTRALAYA)**

1. Research and development of bio-gas and programmes relating to bio-gas units.
2. Commission for Additional Sources of Energy (CASE).
3. Solar Energy - including photovoltaic devices and their development, production and applications.
4. All matters relating to small/mini/micro hydel projects of and below 25 MW capacity.
5. Programmes relating to improved chulhas and research and development thereof.
6. Indian Renewable Energy Development Agency.
7. Research and development of other non-conventional/renewable sources of energy and programmes relating thereto.
8. Tidal Energy.
9. Integrated Rural Energy Programme (IREP).
10. Geothermal Energy.

**MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
(SANSADIYA KARYA MANTRALAYA)**

1. Dates of summoning and prorogation of the two Houses of Parliament: Dissolution of Lok Sabha, President's Address to Parliament.
2. Planning and Coordination of legislative and other official business in both Houses.
3. Allocation of Government time in Parliament for discussion of motions given notice of by Members.
4. Liaison with Leaders and Whips of various Parties and Groups represented in Parliament.
5. Lists of Members of Select and Joint Committees on Bills.

6. Appointment of Members of Parliament on Committees and other bodies set up by Government.
7. Functioning of Consultative Committee of Members of Parliament for various Ministries.
8. Implementation of assurances given by Ministers in Parliament.
9. Government's stand on Private Members' Bills and Resolutions.
10. Secretarial assistance to the Cabinet Committee on Parliamentary Affairs.
11. Advice to Ministries on procedural and other Parliamentary matters.
12. Coordination of action by Ministries on the recommendations of general application made by Parliamentary Committees.
13. Officially sponsored visits of Members of Parliament to places of interest.
14. Matters connected with powers, privileges and immunities of Members of Parliament.
15. Parliamentary Secretaries-functions.
16. Organisation of Youth Parliament Competitions in Schools/Colleges throughout the country.
17. Organisation of all India Whips' Conference.
18. Exchange of Government Sponsored Delegations of Members of Parliament with other countries.
19. Determination of Policy and follow-up action in regard to matters raised under rule 377 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha and by way of Special Mentions in Rajya Sabha.
20. Manual for Handling Parliamentary work in Ministries/Departments.
21. The Salaries and Allowances of Officers of Parliament Act, 1953 (20 of 1953).

22. The Salary, Allowances and Pensions of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954).
23. The Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Act, 1977 (33 of 1977).
24. The Leader and Chief Whips of Recognised Parties and Groups in Parliament (Facilities) Act, 1998 (5 of 1999).

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(KARMIK, LOK SHIKAYAT TATHA PENSION MANTRALAYA)**

**A. DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING
(KARMIK AUR PRASHIKSHAN VIBHAG)**

I. RECRUITMENT, PROMOTION AND MORALE OF SERVICES

1. Reservation of posts in Services for certain classes of citizens.
2. General questions relating to recruitment, promotion and seniority pertaining to Central Services except Railways Services and services under the control of the Department of Atomic Energy, the erstwhile Department of Electronics, the Department of Space and the Scientific and Technical Services under the Department of Defence Research and Development.
3. General policy regarding age limits, medical standards, educational qualifications and recognition of non-technical degrees diplomas for appointment to Government service.
4. General policy matters regarding classification of posts and grant of gazetted status in relation to Services other than Railway Services.
5. Recruitment of ministerial staff for the Government of India Secretariat and its attached offices except that for the Department of Railways, the Department of Atomic Energy, the erstwhile Department of Electronics, and the Department of Space.
6. Appointment of non-Indians to Civil posts under the Government of India except posts under the Department of Railways, the Department of Atomic Energy, the erstwhile Department of Electronics and the Department of Space.
7. General policy regarding employment assistance to persons of Indian origin coming from various countries.

8. Concessions to War Service candidates in respect of appointments to Civil Posts and services.
9. General policy regarding resettlement of displaced Government servants from areas now in Pakistan and retrenched temporary employees.
10. Concessions to political sufferers in the matters of first appointment or reappointment to the public services.
11. General policy regarding grant of extension to or re-employment of superannuated officers.
12. Issue of certificates of eligibility for appointment to Civil Services and posts under the Union in respect of persons other than Indian citizens.
- 13.(a) Deputation of Indian experts abroad under the Indian Technical and Economic Cooperation Programme of the Ministry of External Affairs and on bilateral basis of the developing countries of Asia, Africa and Latin America.

(b) Deputation of officers or placements with the United Nations and its allied agencies as also with other international agencies like ILO, FAO, etc.
14. General policy regarding verification of character and antecedents, suitability of candidates for appointment to Government service.
15. Policy matters relating to issue of No Objection certificate to serving personnel for registration with the Employment Exchange for higher posts.
16. Matters relating to Personal Staff of Ministers.
17. Re-deployment of staff rendered surplus in Central Government offices as a result of-
 - (a) administrative reforms;
 - (b) studies made by the SIU;
 - (c) winding up of long term but temporary organisations.

18. Advising Ministries on proper management of various cadres under their control.

II. TRAINING

- 19.(a) Formation and coordination of training policies for the All India and Central Services;
- (b) Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration and Institute of Secretariat Training and Management;
- (c) Training programmes for the Indian Administrative Service and the Central Secretariat Service;
- (d) Preparation and publication of training material and of the information of training techniques, facilities and programmes;
- (e) Liaison with training institutions within the States and abroad;
- (f) Refresher and special courses of Middle and Senior Management levels.

III. VIGILANCE AND DISCIPLINE

20. (a) Central Vigilance Commission ;
- (b) All policy matters pertaining to vigilance and discipline among public servants;
- (c) Relationship between Members of Parliament and the Administration.

IV. SERVICE CONDITIONS

21. General questions (other than those which have a financial bearing including Conduct Rules relating to All India and Union Public Services except in regard to services under the control of the Department of Railways, the Department of Atomic Energy, the erstwhile Department of Electronics and the Department of Space.
22. Conditions of service of Central Government employees (excluding those under the control of the Department of Railways, the Department

of Atomic Energy, the erstwhile Department of Electronics, the Department of Space and the Scientific and Technical personnel under the Department of Defence Research and Development, other than those having a financial bearing and in so far as they raise points of general service interests.

23.(a) The administration of all service rules including F.Rs. SRs. and C.S.Rs. (but excluding those relating to Pension and other retirement benefits) except--

- (i) proposals relating to revisions of pay structure of employees;
- (ii) proposals for revisions of pay scales of Central Government employees;
- (iii) appointment of Pay Commission, processing of the recommendations and implementation thereof;
- (iv) dearness allowance and other compensatory allowances and travelling allowances;
- (v) any new facility to Government employees by way of service conditions or fringe benefits which involve significant recurring financial implications; and
- (vi) matters relating to amendments to service rules having a predominantly financial character;

(b) Initiation of proposals for new facility to Government employees by way of service conditions and fringe benefits, involving significant recurring financial implications;

(c) Issue of formal orders of the Government of India in matters relating to amendments to service rules including those having a predominantly financial character referred to in item (vi) of clause (a);

(d) Relaxation and liberalisation of any service rules having long-term financial implications in consultation with the Ministry of Finance.

24. Grants to the Indian Institute of Public Administration.

25. Leave travel concession for civil employees other than Railway employees.

26. The Central Services (Temporary Service) Rules, 1949.
27. General policy regarding retrenchment and revision of temporary Government servants except those under the Department of Railways.
28. Administration of the Central Services (Safeguarding of National Security) Rules.
29. Uniforms for Class IV and other Government servants in the Central Secretariat, and its attached offices.
30. Working Hours and Holidays for Government of India offices.
31. Administration of service rules with financial content under specific delegation made by the Ministry of Finance.
32. Advice on proposals in respect of the Ministry of Finance relating to the number or grade of posts to the strength of a service or to the pay and allowances of Government servants or any other conditions of their service having financial implications.
33. General policy regarding reimbursement of legal expenses incurred by Government Servants.
34. Proposals for grant of ex-officio Secretariat status.
35. Honorary appointments of persons in civil posts.
36. Oath of allegiance to the Constitution.

V. SENIOR AND MIDDLE MANAGEMENT

37. All aspects of Senior Management (i.e., Joint Secretaries and above and their equivalents) including developments of personnel for it.
- 38.(a) Establishment Officer to the Government of India;
 - (b) Appointments Committee of the Cabinet;
 - (c) Central Establishment Board;
 - (d) Career Development for Middle Management (i.e. Directors, Deputy and Under Secretaries and equivalents).

**VI. GOVERNMENT EMPLOYEES RELATIONS, INCLUDING
STAFF GRIEVANCES AND WELFARE.**

- 39.(a) Service Associations of the industrial and non-industrial employees of the Government of India;
- (b) Joint Consultative Machinery; Departmental Council for the Department of Personnel and Training (Karmik aur Prashikshan Vibhag);
- (c) machinery for the redress of staff grievances;
- (d) staff welfare including sports, cultural activities, Grih Kalyan Kendras, Canteens, Cooperative Stores, etc;
- (e) all matters relating to Central Administrative Tribunals and State Administrative Tribunals;
- (f) other matters involving Government Employees relations not specifically provided for under any other entry relating to this Ministry.

VII. UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

40. Union Public Service Commission.

VIII. CENTRALISED ASPECTS OF MANAGING IAS, INTER-MINISTRY CADRES INCLUDING A CAREER PLANNING FOR THE MEMBERS THEREOF.

- 41.(a) Creation of new All India Services;
- (b) Rules and regulations under the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951);
- (c) All matters relating to the Indian Administrative Service including the Indian Civil Service;
- (d) All India Civil List and History of Services;
- (e) Central Secretariat Service, Central Secretariat Stenographers' Service and Central Secretariat Clerical Service.

IX. CAREER PLANNING AND MANPOWER PLANNING.

- 42.(a) General Policy questions regarding Career Planning and Manpower Planning for the All India and Central Government Services;
- (b) All matters pertaining to Career Planning and Manpower Planning for the Indian Administrative Service and the Central Secretariat Service.

X. PERSONNEL MANAGEMENT AGENCIES

43. Coordination of the work of personnel management agencies within various Ministries and Departments.

XI. ALLOCATION OF PERSONNEL AND INTEGRATION OF SERVICES AS A RESULT OF STATES RE-ORGANISATION.

- 44.(a) Allocation of service personnel affected by re-organisation of States;
- (b) Division and integration of services affected by the re-organisation of States other than the Union Territories;
- (c) Protection of service conditions of personnel affected by re-organisation of States;
- (d) Other matters relating to State Services affected by the re-organisation of States.

XII. PUBLIC ENTERPRISES SELECTION BOARD

45. Public Enterprises Selection Board (PESB).

B. DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES (PRASHASNIK SUDHAR AUR LOK SHIKAYAT VIBHAG).

1. Administrative Reforms, including e-governance and dissemination of best practices.
2. Organisation and methods.

3. Policy, coordination and monitoring of issues relating to –
 - (a) redress of public grievances in general; and
 - (b) grievances pertaining to Central Government agencies.
4. (a) Research in public management;
 - (b) liaison with State Governments, professional institutions etc. in public management matters.
5. Administration of Central Secretariat Manual of Office Procedure.

**C. DEPARTMENT OF PENSION AND PENSIONERS' WELFARE
(PENSION AUR PENSION BHOGI KALYAN VIBHAG)**

1. Formulation of policy and co-ordination of matters relating to retirement benefits to Central Government employees (Civil, Defence and Railway Pensioners).
2. Administration of –
 - (a) The Central Civil Services (Pension) Rules, 1972; the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981; the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 1939; the All India Services (Death-cum-retirement benefits) Rules, 1958, and
 - (b) any other scheme relating to Central Government pensioners, entrusted to the Department.
3. Pension structure and relief to pensioners.
4. New facilities of fringe benefits to the Central Government pensioners.
5. Matters relating to amendment to, or relaxation of, Pension rules or any other rule concerning retirement benefits.
6. Policy and co-ordination relating to welfare of Central Government Pensioners.

NOTE: The action in respect of 3 above shall be subject to the concurrence of Ministry of Finance. Action in respect of other matters involving recurring financial implications by way of relaxation or liberalisation of any rule shall be subject, to guidelines, as agreed to between the Department of Pension and Pensioners' Welfare and the Ministry of Finance, Department of Expenditure.

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
(PETROLEUM AUR PRAKRITIK GAS MANTRALAYA)**

1. Exploration for, and exploitation of petroleum resources including natural gas and coal bed methane.
2. Production, supply, distribution, marketing and pricing of petroleum including natural gas, coal bed methane and petroleum products.
3. Oil refineries, including Lube Plants.
4. Additives for petroleum and petroleum products.
5. Tube Blending and greases.
6. Planning, development and control of, and assistance to, all industries dealt, with by the Ministry.
7. Planning, development and regulation of oilfield services.
8. Public sector projects falling under the subjects included in this list. Engineers India Limited and Indo-Burma Petroleum Company, together with its subsidiaries, except such projects as are specifically allotted to any other Ministry/Department.
9. The Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948).
10. The Oil and Natural Gas Commission (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 1993 (65 of 1993).
11. The Petroleum Pipelines [(Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962)].

12. The Esso [(Acquisition of Undertakings in India) Act, 1974 (4 of 1974)].
13. The Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974).
14. The Burmah-Shell [(Acquisition of Undertakings in India) Act, 1976 (2 of 1976)].
15. The Caltex [(Acquisition of Shares of Caltex Oil Refining (India) Limited and of the Undertakings in India of the Caltex (India) Limited Act, 1977 (17 of 1977)].
16. Administration of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934) and the rules made thereunder.

**MINISTRY OF PLANNING
(YOJANA MANTRALAYA)**

Responsibility to Parliament in regard to the subjects of national planning.

**MINISTRY OF POWER
(VIDYUT MANTRALAYA)**

1. General Policy in the electric power sector and issues relating to energy policy and coordination thereof (Details of short, medium and long-term policies in terms of formulation, acceptance, implementation and review of such policies, cutting across sectors, fuels, regions and intra country and inter country flows).
2. All matters relating to hydro-electric power (except small/mini/micro hydel projects of and below 25 MW capacity) and thermal power and transmission and distribution system network.
3. Research, development and technical assistance relating to hydro-electric and thermal power, transmission system network and distribution systems in the States/UTs.
4. Administration of the Indian Electricity Act, 1910 (9 of 1910), the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948), the Electricity Regulatory Commissions Act, 1998 (14 of 1998), the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Damodar Valley Corporation Act, 1948 (14 of 1948) and the Bhakra Beas Management Board as provided in the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966).

5. All matters relating to Central Electricity Authority, Central Electricity Board and Central Electricity Regulatory Commission.

6(a) Rural Electrification;

(b) Power schemes and issues relating to power supply/development schemes/programmes/ decentralized and distributed generation in the States and Union Territories.

7. Matters relating to the following Undertakings/Organisations:

(a) The Damodar Valley Corporation;

(b) The Bhakra Beas Management Board (except matters relating to irrigation);

(c) National Thermal Power Corporation Limited;

(d) National Hydro-electric Power Corporation Limited;

(e) Rural Electrification Corporation Limited;

(f) North Eastern Electric Power Corporation Limited;

(g) Power Grid Corporation of India Limited;

(h) Power Finance Corporation Limited;

(i) Tehri Hydro Development Corporation;

(j) Nathpa Jhakri Power Corporation;

(k) Central Power Research Institute;

(l) National Power Training Institute;

(m) Bureau of Energy Efficiency;

(n) Power Trading Corporation of India Limited;

(o) Narmada Hydro Development Corporation (Joint Venture).

8. All matters concerning energy conservation and energy efficiency pertaining to Power Sector.

**MINISTRY OF RAILWAYS
(RAIL MANTRALAYA)**

**RAILWAY BOARD
(RAIL BOARD)**

1. Government Railways- All matters, including those relating to Railway revenues and expenditure, but excluding Railway Inspectorate and Railway Audit.
2. Non-Government Railways – Matters in so far as provision for control by the Ministry of Railways, Railway Board as provided in the Railways Act, 1989 (24 of 1989) or in the contracts between the Government and Railways, or in any other statutory enactments, namely, regulations in respect of safety, maximum and minimum rates and fares, etc. excluding the item of work allocated to the Department of Urban Development.
3. Parliament Questions regarding offences relating to pilferage of railway property other than offences relating to crime on Government Railways and Non-Government Railways.
4. Administration of pension rules applicable to Railway employees.

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(SADAK PARIVAHAN AUR RAJ MARG MANTRALAYA)**

**I. THE FOLLOWING SUBJECTS WHICH FALL WITHIN LIST 1
OF THE SEVENTH SCHEDULE TO THE CONSTITUTION OF
INDIA:**

1. Compulsory insurance of motor vehicles.
2. Administration of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950).
3. Highways declared by or under law made by Parliament to be national highways.

II. IN RESPECT OF THE UNION TERRITORIES:

4. Roads other than National Highways.

5. Administration of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and taxation of motor vehicles.
6. Vehicles other than mechanically propelled vehicles.

**III. OTHER SUBJECTS WHICH HAVE NOT BEEN INCLUDED
UNDER THE PREVIOUS PARTS:**

7. Central Road Fund.
8. Coordination and Research pertaining to Road Works.
9. Road works financed in whole or in part by the Central Government other than those in the North Eastern Region.
10. Motor vehicles legislation.
11. Promotion of Transport Co-operatives in the field of motor transport and inland water transport.
12. Formulation of the privatisation policy in the infrastructure areas of roads.

IV. AUTONOMOUS BODIES:

13. National Highways Authority of India.

V. SOCIETIES/ASSOCIATIONS:

14. National Institute of Training for Highway Engineers.

VI. PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS:

15. Indian Road Construction Corporation.

VII. ACTS:

16. The Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950).
17. The National Highway Act, 1956 (48 of 1956).
18. The Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).
19. The National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988).

**MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
(GRAMIN VIKAS MANTRALAYA)**

**A. DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT
(GRAMIN VIKAS VIBHAG)**

1. All matters relating to panchayati raj and panchayati raj institutions.
2. Public cooperation, including all matters relating to voluntary agencies for rural development, Council of Advancement of People's Action and Rural Technology (CAPART) and National Fund for Rural Development, other than aspects which fall within the purview of Department of Drinking Water Supply.
3. Cooperatives relatable to the items in this list.
4. Road works financed in whole or in part by the Central Government in tribal areas of Assam specified in Part I and Part II of the Table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule to the Constitution.
5. All matters relating to cooperation with the Centre for Integrated Rural Development for Asia and Pacific (CIRDAP) and the Afro-Asian Rural Reconstruction Organisation (AARRO).
- 6.(a) All matters pertaining to rural employment or unemployment such as working out of strategies and programmes for rural employment including special works, wage or income generation and training related thereto.
- (b) Implementation of the specific programmes of rural employment evolved from time to time.
- (c) Micro level planning related to rural employment or unemployment and administrative infrastructure therefor.
7. Integrated rural development including small farmers development agency, marginal farmers and agricultural labourers, etc.
8. Rural housing including Rural Housing Policy and all matters germane and incidental thereto under country or rural planning, in so far as it relates to rural areas.

9. All matters relating to rural connectivity including the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.

**B. DEPARTMENT OF LAND RESOURCES
(BHUMI SANSADHAN VIBHAG)**

1. Land reforms, land tenures, land records, consolidation of holding and other related matters.
2. Administration of the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894) and matters relating to acquisition of land for purposes of the Union.
3. Recovery of claims in a State in respect of taxes and other public demands, including arrears of land revenue and sums recoverable as such arrears, arising outside that State.
4. Land, that is to say, collection of rents, transfer and alienation of land, land improvement and agricultural loans excluding acquisition of non-agricultural land or buildings, town planning improvements.
5. Land revenue, including the assessment and collection of revenue, survey of revenue purposes, alienation of revenues.
6. Duties in respect of succession to agricultural land.
7. National Wastelands Development Board.
8. National Land Use and Wasteland Development Council.
9. Promotion of rural employment through Wastelands Development.
10. Promotion of production of fuelwood, fodder and timber on non-forest lands, including private wastelands.
11. Research and development of appropriate low cost technologies for increasing productivity of wastelands in sustainable ways.
12. Inter-departmental and inter-disciplinary coordination in programme planning and implementation of the Wastelands Development Programme including training.
13. Promotion of people's participation and public cooperation and coordination of efforts of Panchayats and voluntary and non-Government agencies for Wastelands Development.

14. Drought prone area programmes.
15. Desert Development Programmes.

**C. DEPARTMENT OF DRINKING WATER SUPPLY
(PEYA JAL POORTI VIBHAG)**

1. Rural Water Supply (subject to overall national perspective of water planning and coordination assigned to the Ministry of Water Resources), sewage, drainage and sanitation relating to rural areas; International cooperation and technical assistance in this field.
2. Public cooperation, including matters relating to voluntary agencies in so far as they relate to rural water supply, sewage, drainage and sanitation in rural areas.
3. Co-operatives relatable to the items in this list.
4. Coordination with respect to matters relating to drinking water supply projects and issues which cover both urban and rural areas.

**MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(VIGYAN AUR PRAUDYOGIKI MANTRALAYA)**

**A. DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(VIGYAN AUR PRAUDYOGIKI VIBHAG)**

1. Formulation of policies relating to Science and Technology.
2. Matters relating to the Scientific Advisory Committee of the Cabinet (SACC).
3. Promotion of new areas of Science and Technology with special emphasis on emerging areas.
4. Futurology.
5. Coordination and integration of areas of Science & Technology having cross-sectoral linkages in which a number of institutions and departments have interest and capabilities.
6. Undertaking or financially sponsoring scientific and technological surveys, research design and development, where necessary.

7. Support and Grants-in-aid to Scientific Research Institutions, Scientific Associations and Bodies.

8. All matters concerning:

(a) Science and Engineering Research Council;

(b) Technology Development Board and related Acts such as the Research and Development Cess Act, 1986 (32 of 1986) and the Technology Development Board Act, 1995 (44 of 1995);

(c) National Council for Science and Technology Communication;

(d) National Science and Technology Entrepreneurship Development Board;

(e) International Science and Technology Cooperation including appointment of scientific attaches abroad (These functions shall be exercised in close cooperation with the Ministry of External Affairs);

(f) Autonomous Science and Technology Institutions relating to the subject under the Department of Science and Technology including Institute of Astro-physics, Institute of Geo-magnetism and Institute of Tropical Meteorology;

(g) Professional Science Academies promoted and funded by Department of Science and Technology;

(h) The Survey of India, the India Meteorological Department and National Atlas and Thematic Mapping Organisation;

(i) National Spatial Data Infrastructure and promotion of G.I.S.;

(j) The National Innovation Foundation, Ahmedabad.

9. Matters commonly affecting Scientific and technological departments /organisations/institutions e.g. financial, personnel, purchase and import policies and practices.

10. Management Information Systems for Science and Technology and coordination thereof.

11. Matters regarding Inter-Agency/Inter-Departmental coordination for evolving science and technology missions.

12. Matters concerning domestic technology particularly the promotion of ventures involving the commercialization of such technology other than those under the Department of Scientific and Industrial Research.

13. All other measures needed for the promotion of science and technology and their application to the development and security of the nation.

14. Matters relating to institutional Science and Technology capacity building including setting up of new institutions and institutional infrastructure.

15. Promotion of Science and Technology at the State, District, and Village levels for grass-roots development through State Science and Technology Councils and other mechanisms.

16. Application of Science and Technology for weaker sections, women and other disadvantaged sections of Society.

**B. DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH
(VIGYAN AUR AUDYOGIK ANUSANDHAN VIBHAG).**

1. All matters concerning the Council of Scientific and Industrial Research.

2. All matters relating to National Research Development Corporation.

3. All matters relating to Central Electronics Limited.

4. Registration and Recognition of R & D Units.

5. Technical matters relating to UNCTAD & WIPO.

6. National register for foreign collaborations.

7. Matters relating to creation of a pool for temporary placement of Indian Scientists and Technologists.

**C. DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY
(BIOTECHNOLOGY VIBHAG)**

1. To evolve policies and integrated programmes in biotechnology and ensure their implementation and monitoring.

2. To identify specific programmes of Research and Development and manufacturing in biologicals and biotechnology and oversee the initiation and pursuit of related research and manufacturing activities.
3. To identify, set up and support Centres of Excellence for Research and Development in biotechnology and ensure proper dovetailing of their activities as per national priorities and objectives.
4. To act as a screening, advising and approving agent of the Government with regard to import and transfer of new technologies for the manufacture of biologicals, biotechnological products and their intermediates.
5. Evolve safety guidelines for biotechnology Research and Development and manufacturing in India.
6. To act as the central agency for the import of genetically manipulated materials, culture, cells, specimens, tissues and biotech products including DNA and RNA of any type or size and for promoting their production in the country.
7. Serve as the interministerial and interagency nodal point for all specific international bilateral and multilateral Research and Development collaborations and agreements in the area of biotechnology; act as the nodal point for all technology transfers in the area of biotechnology.
8. Manufacture and ensure application of recombinant, cell-based and DNA vaccines, diagnostics and other biotechnological products.
9. To evolve programmes for Human Resource Development in the area of biotechnology.
10. Serve as an administrative and implementing Department of agencies, commissions, boards, etc. specifically formed by the Government for fulfilling the national objectives in biotechnology and also to serve as the nodal point for Bio-informatics including training and creation of infrastructure, collection, dissemination and exchange of information relating to biotechnology.
11. Matters relating to:
 - (a) International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), New Delhi;

- (b) National Institute of Immunology (NII), New Delhi;
- (c) National Centre for Cell Sciences (NCCS), Pune;
- (d) Centre for DNA Fingerprinting & Diagnostics (CDFD), Hyderabad;
- (e) National Centre for Plant Genome Research (NCPGR), New Delhi;
- (f) National Brain Research Centre (NBRC), Gurgaon;
- (g) Institute for Bioresource and Sustainable Development (IBSD), Imphal.

12. Matters relating to:

- (a) Bharat Immunologicals and Biologicals Corporation Limited (BIBCOL), Bulandshahar, Uttar Pradesh;
- (b) Indian Vaccines Corporation Limited (IVCOL), Manesar, Gurgaon.

**MINISTRY OF SHIPPING
(POT PARIVAHAN MANTRALYA)**

**I. THE FOLLOWING SUBJECTS WHICH FALL WITHIN LIST 1
OF THE SEVENTH SCHEDULE TO THE CONSTITUTION OF
INDIA:**

- 1. Maritime shipping and navigation; provision of education and training for the mercantile marine.
- 2. Lighthouses and lightships.
- 3. Administration of the Indian Ports Act, 1908, (15 of 1908) and the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and ports declared as major ports.
- 4. Shipping and navigation including carriage of passengers and goods on inland waterways declared by Parliament by law to be national waterways as regards mechanically propelled vessels, the rule of the road on such waterways.
- 5. Ship-building and ship-repair industry.

6. Fishing vessels industry.
7. Floating craft industry.

II. IN RESPECT OF THE UNION TERRITORIES:

8. Inland waterways and traffic thereon.

III. IN RESPECT OF THE UNION TERRITORIES OF THE ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS AND THE LAKSHADWEEP:

9. Organisation and maintenance of mainland islands and inter-island shipping services.

IV. OTHER SUBJECTS WHICH HAVE NOT BEEN INCLUDED UNDER THE PREVIOUS PARTS:

10. Legislation relating to shipping and navigation on inland waterways as regards mechanically propelled vessels and the carriage of passengers and goods on inland waterways.
11. Legislation relating to and coordination of the development of minor and major ports.
12. Administration of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) and the Schemes framed thereunder other than the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Scheme, 1961.
13. To make shipping arrangements for and on behalf of the Government of India/Public Sector Undertakings/State Governments/State Government Public Sector Undertakings and autonomous bodies in respect of import of cargo on Free on Board/Free along Side and export on Cost and Freight/Cost Insurance and Freight basis.
14. Planning of Inland Water Transport.
15. Formulation of the privatisation policy in the infrastructure areas of ports, shipping and inland waterways.
16. The Development of township of Gandhidham.

17. Prevention and control of pollution:

- (a) Prevention and control of pollution arising from ships, shipwrecks and abandoned ships in the sea, including the port areas;
- (b) enactment and administration of legislation related to prevention, control and combating of pollution arising from ships; and
- (c) monitoring and combating of oil pollution in the port areas.

V. SUBORDINATE OFFICES:

- 18. Directorate General of Shipping.
- 19. Andaman Lakshadweep Harbour Works.
- 20. Directorate General of Lighthouses and Lightships.
- 21. Minor Ports Survey Organisation.

VI. AUTONOMOUS BODIES:

- 22. Traffic Authority for Major Ports (TAMP).
- 23. Port Trusts at Mumbai, Kolkata, Kochi, Kandla, Chennai, Mormugao, Jawahar Lal Nehru (Nhava Sheva), Paradip, Tuticorin, Visakhapatnam and New Mangalore.
- 24. Dock Labour Boards at Kolkata, Kandla and Visakhapatnam.
- 25. Inland Waterways Authority of India.
- 26. Seamen's Provident Fund Organisation.

VII. SOCIETIES/ASSOCIATIONS:

- 27. National Institute of Port Management.
- 28. National Ship Design and Research Centre.
- 29. Seafarers Welfare Fund Society.

VIII. PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS:

30. Shipping Corporation of India.
31. Hindustan Shipyard Limited.
32. Cochin Shipyard Limited.
33. Central Inland Water Transport Corporation Limited.
34. Dredging Corporation of India.
35. Hooghly Dock and Ports Engineers Limited.
36. Ennore Port Limited.

IX. INTERNATIONAL ASPECTS:

37. International Maritime Organisation.

X. ACTS:

38. The Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908).
39. The Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917).
40. The Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948).
41. The Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958).
42. The Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963).
43. The Seamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966).
44. The Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985).
45. The Multimodal Transportation of Goods Act, 1993 (28 of 1993).

**MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES
(LAGHU UDYOG MANTRALAYA)**

1. Coordination of the Development of Small Scale Industries, other than Cottage and Village Industries, and Tiny/Micro Enterprises.

2. Small Industries Board.
3. National Small Industries Corporation Limited.
4. Co-operation in the Industrial sector, excepting Co-operative Sugar Factories.

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
(SAMAJIK NYAYA AUR ADHIKARITA MANTRALAYA)**

PART I

The following subjects which fall within List I of the Seventh Schedule to the Constitution of India:

1. Operation of Indo-US, Indo-UK, Indo-German, Indo-Swiss and Indo-Swedish Agreements for duty free receipt of donated relief supplies/goods and matters connected with the distribution of supplies coming thereunder.

PART II

The following subject which falls within List III of the Seventh Schedule to the Constitution of India (as regards legislation only):

2. Social Security and Social Insurance save to the extent allotted to any other Department.

PART III

For the Union Territories, the following subject which falls within List II or List III of the Seventh Schedule to the Constitution of India, in so far as they exist in regard to such Territories:

3. Relief of the disabled and unemployable and measures relating to social security and social Insurance, save to the extent allotted to any other Department.

PART IV

GENERAL AND CONSEQUENTIAL:

4. Social Welfare : Social Welfare Planning, Project formulation, research, evaluation, statistics and training.

5. Conventions with other countries in matters relating to social defence and references from United Nations Organisation relating to prevention of crime and treatment of offenders.
6. Institutional and non-institutional services for the care and development of children in need including orphans and orphanages.
7. Education, training, rehabilitation and welfare of the physically and mentally handicapped.
8. National Institute for the Physically Handicapped and Mentally Retarded.
9. Rehabilitation of the persons with disabilities and rehabilitation of the mentally ill.
10. National Centre for the Blind including the Central Braille Press, Dehra Dun, Training Centre for the Adult Deaf, and School for the partially deaf children, Hyderabad; Model School for Mentally Retarded Children, New Delhi and other national institutes.
11. Social and Moral Hygiene Programme.
12. Beggary; Juvenile vagrancy, delinquency and other CARE Programmes.
13. Probation of Juvenile offenders.
14. Issues relating to adoption, Central Adoption Resource Agency and Child helpline (Childline).
15. Research, evaluation, training, exchange of information and technical guidance on all social defence matters.
16. All matters relating to alcoholism and substance (drug) abuse and rehabilitation of addicts/families.
17. Promotion of efforts including voluntary efforts to ensure the well being of the older persons.
18. All matters relating to prohibition.
19. Educational and social welfare aspects of drug addiction.

20. Charitable and religious endowments pertaining to subjects allocated to this Ministry.
21. Promotion and development of voluntary effort on subjects allocated to this Department.
22. National Institute of Social Defence.
23. Institute for the Physically Handicapped, New Delhi;
24. National Institute for the Orthopaedically Handicapped, Kolkata;
25. National Institute of Rehabilitation, Training and Research, Cuttack;
26. National Institute for the Mentally Handicapped, Secunderabad;
27. Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped, Mumbai
28. National Institute for the Visually Handicapped, Dehradun.
29. National Handicapped Finance and Development Corporation, Faridabad.
30. Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur.
31. The Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992) and Rehabilitation Council constituted thereunder.
32. The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (01 of 1996).
33. The National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999).
34. Chief Commissioner for Disabilities.
35. Scheduled Castes and other Backward Classes including scholarships to students belonging to such Castes and Classes.
36. National Commission for Scheduled Castes.

37. Development of Scheduled Castes and other Backward Classes.

NOTE: The Ministry of Social Justice and Empowerment will be the nodal Ministry for overall policy, planning and coordination of programmes of development of Scheduled Castes and Other Backward Classes. In regard to sectoral programmes and schemes of development pertaining to these communities, policy, planning, monitoring, evaluation etc. as also their coordination will be the responsibility of the concerned Central Ministries, State Governments and Union Territory Administrations. Each Central Ministry and Department will be the nodal Ministry or Department concerning its sector.

38. Reports of the Commission to Investigate into the conditions of Backward Classes.

39. Matters relating to Linguistic Minorities and of the Office of the Commissioner for Linguistic Minorities.

40. Matters relating to National Commission for Minorities Act and Commission set up thereunder.

41. The Wakf Act, 1995 (43 of 1995).

42. Work relating to the evacuee Wakf properties under the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950).

43. Representation of the Anglo-Indian Community.

44. National Commission for Safai Karamcharis and all matters pertaining thereto.

45. All matters relating to Minority Communities except matters relating to law and order.

46. Implementation of the Protection of Civil Rights Act, 1955, and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, excluding the administration of criminal justice in regard to offences in so far as they relate to Scheduled Castes.

47. Administration of the following Acts:

(a) The Probation of Offenders Act, 1958 (20 of 1958);

- (b) The Children Act, 1960 (60 of 1960);
- (c) The Durgah Khawaja Saheb Act, 1955 (36 of 1955);
- (d) The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (56 of 2000).

**MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION
(SANKHYIKI AUR KARYAKRAM KARYANVAYAN VIBHAG)**

I. STATISTICS WING

1. Act as the nodal agency for planning integrated development of the statistical system in the country.
2. Coordination of statistical work with a view to identifying gaps in data availability or duplication of statistical work in respect of Departments of the Government of India and State Statistical Bureaux (SSBs) and to suggest necessary remedial measures.
3. Laying down and maintenance of norms and standards in the field of statistics, evolving concepts, definitions and methodology of data collection, processing of data and dissemination of results.
4. Advise the Departments of the Government of India on statistical methodology and on statistical analysis of data.
5. Preparation of National Accounts as well as publication of annual estimates of national income, gross/net domestic product, Government and private final consumption expenditure, capital formation, savings, capital stock and consumption fixed capital, quarterly estimates of Gross Domestic Product, preparation of National Input-Output Transactions Table, State level estimates of domestic product and fixed capital formation of supra-regional sectors, preparation of comparable estimates of State Domestic Product (SDP) at current prices.
6. Compilation and release of the Index of Industrial Production (IIP) every month in the form of Quick Estimates, conducting Annual Survey of Industries (ASI) and providing statistical information, to assess and evaluate the changes in the growth, composition and structure of the organised manufacturing (factories) sector.

7. Development of Environment Statistics, development of methodology, concepts and preparation of National Resource Accounts for India.
8. Organisation and conduct of periodic all India economic census and follow-up sample surveys.
9. Conducting nation-wide sample surveys on various socio-economic aspects, such as, employment, consumer expenditure, housing conditions, debt and investment, land and livestock holdings, literacy, education, health, family welfare, unorganised manufacturing and services etc, to provide the database needed for development, research, policy formulation and economic planning.
10. Conducting quality checks and auditing of statistical surveys and data sets through technical scrutiny and sample checks and generate correction factors and alternate estimates, if required.
11. Undertaking the processing of survey data collected through various socio-economic surveys and follow up surveys of Economic Census and Annual Survey of Industries by National Sample Survey Organisation and Central Statistical Organisation.
12. Dissemination of statistical information through a number of regular or adhoc publications to Government, semi-Government or private data users/agencies, and dissemination of data, on request, to United Nations Agencies like United Nations Statistics Division, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, International Labour Organisation and other relevant international agencies.
13. Giving grants-in-aid to registered non-governmental organisations and research institutions of repute for undertaking special studies or surveys, printing of statistical reports and finance seminars, workshops or conferences relating to different subject areas of official statistics.
14. Functioning as the Cadre Controlling Authority and dealing with all aspects of managing the Indian Statistical Service including all matters pertaining to training, career planning and manpower planning.
15. The Indian Statistical Institute and ensuring its functioning in accordance with the provisions of the Indian Statistical Institute Act, 1959 (57 of 1959).
16. Compilation and release of monthly Consumer Price Index Numbers for Urban Non-Manual Employees.

17. Undertaking methodological studies and pilot surveys for evolving better sampling techniques and estimation procedures including small area estimates.

II. PROGRAMME IMPLEMENTATION WING

18. Monitoring of 20 point programme.

19. Monitoring of projects of Rs.20 crores and above.

20. Monitoring of the performance of Infrastructure Sectors.

21. Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS).

MINISTRY OF STEEL (ISPAT MANTRALAYA)

1. Planning, development and facilitation of setting up of iron and steel production facilities including electric arc furnace (EAF) units, induction furnace (IF) units, processing facilities like re-rollers, flat products (hot/cold rolling units), coating units, wire drawing units and steel scrap processing.

2. Development of iron ore mines in the public sector and other ore mines (manganese ore, chrome ore, limestone, sillimanite, kyanite, and other minerals used in the iron and steel industry but excluding mining lease or matters related thereto).

3. Production, distribution, prices, imports and exports of iron and steel and ferro-alloys.

4. The Steel Authority of India Limited and its subsidiaries.

5. Matters relating to the following undertakings, namely:-

- (a) Visvesvaraya Iron and Steel Limited;
- (b) The Bolani Ores (India) Limited;
- (c) The Manganese Ore (India) Limited;
- (d) The Metals Scrap Trading Corporation.

**MINISTRY OF TEXTILES
(VASTRA MANTRALAYA)**

I. GENERAL POLICY

1. Production, distribution (for domestic consumption and exports) research and development of all textiles including cotton, woolens, jute, silk, man-made, produced on handlooms and powerlooms, readymade garments and industries related to the production of cotton, woolen, jute, silk and cellulosic fibres but excluding non-cellulosic synthetic fibres (nylon, polyester, acrylic, etc.).
2. Cotton, including ginning and pressing thereof, domestic supply, inputs and price stabilisation operations.
3. Sericulture.
4. Development and extension of export promotion in relation to textiles, woolens, powerlooms, handlooms, readymade garments, silk and cellulosic fibres, jute and jute products and handicrafts.
5. Jute and jute products.
6. Handicrafts.

II. OFFICES

7. Office of the Development Commissioner (Handlooms), New Delhi.
8. Office of the Development Commissioner (Handicrafts), New Delhi.
9. Office of the Jute Commissioner, Kolkata.
10. Office of the Commissioner of Payments, New Delhi.
11. Commissioner of Payments (Jute), Kolkata.
12. Office of the Textile Commissioner, Mumbai.

III. STATUTORY/AUTONOMOUS BODIES

13. Jute manufactures Development Council, Kolkata.

14. Central Silk Board, Bangalore.
15. National Institute of Fashion Technology, New Delhi.
16. National Centre for Jute Diversification, Kolkata.
17. Indian Institute of Carpet Technology, Bhadohi.
18. National Centre for Design and Product Development, Delhi.
19. Metal Handicrafts Service Centre, Moradabad.
20. Indian Institute of Handloom Technology, Guwahati, Jodhpur Salem and Varanasi.
21. Textiles Committee, Mumbai.

IV. PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS

22. National Handloom Development Corporation, Lucknow.
23. Jute Corporation of India Limited, Kolkata.
24. National Jute Manufacturers Corporation, Kolkata and its subsidiaries.
25. National Textile Corporation Limited and its Subsidiaries.
26. Cotton Corporation of India Limited, Mumbai.
27. Handicrafts and Handlooms Export Corporation, New Delhi.
28. Central Cottage Industries Corporation, New Delhi.
29. British India Corporation Limited, Kanpur, and its subsidiaries.

V. BOARDS

30. Central Silk Board.
31. Central Wool Development Board.
32. Cotton Advisory Board.

33. All India Handloom Board.
34. All India Handicrafts Board.
35. All India Powerloom Board.
36. Jute Advisory Board.

VI. ADVISORY/DEVELOPMENT COUNCILS

37. Central Advisory Council for Textile Industry.
38. Jute Manufactures Development Council, Kolkata.
39. Development Council for Textile Industry.
40. Standing Council on Modernisation of Textile Industry.
41. Coordination Council on Textiles Research Associations.

VII. COUNCILS

42. Handloom Export Promotion Council, Chennai.
43. The Indian Silk Export Promotion Council, Mumbai.
44. Export Promotion Council for Handicrafts, New Delhi.
45. Powerloom Development and Export Promotion Council, Mumbai.
46. The Cotton Textile Export Promotion Council, Mumbai.
47. Carpet Export Promotion Council, New Delhi.
48. The Synthetic and Rayon Textiles Export Promotion Council, Mumbai.
49. Wool and Woollen Export Promotion Council, New Delhi.
50. Apparel Export Promotion Council, Mumbai.

VIII. ASSOCIATIONS

51. Indian Jute Industries Research Association, Kolkata.
52. Ahmedabad Textile Industries Research Association, Ahmedabad.
53. Bombay Textile Research Association, Mumbai.
54. Man-made Textile Research Association, Surat.
55. South India Textile Research Association, Coimbatore.
56. Northern India Textile Research Association, Ghaziabad.
57. The Synthetic and Art Silk Mills Research Association, Mumbai.
58. Wool Research Association, Mumbai.
59. The Association of Corporation and Apex Societies of Handlooms, New Delhi.

IX. INTERNATIONAL ASPECTS

60. International Cotton Advisory Committee.
61. International Institute of Cotton.
62. Asia-Pacific Textiles and Clothing Industry Forum.
63. International Jute Study Group.

X. ACTS

64. The Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948).
65. The Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963).
66. The Jute Manufactures Development Council Act, 1983 (27 of 1983).
67. The Jute Manufactures Cess Act, 1983 (28 of 1983).
68. The Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985 (22 of 1985).

69. The Jute Packaging Materials (Compulsory use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987).

**MINISTRY OF TOURISM AND CULTURE
(PARYATAN AUR SANSKRITI MANTRALAYA)**

**A. DEPARTMENT OF TOURISM
(PARYATAN VIBHAG)**

1. Development and Promotion of Tourism.
2. International Cooperation in the field of Tourism.
3. India Tourism Development Corporation and Autonomous Institutes.

**B. DEPARTMENT OF CULTURE
(SANSKRITI VIBHAG)**

1. Policy matters regarding Library development.
2. National Library, Kolkata; Central Reference Library, Kolkata; Central Secretariat Library, New Delhi; Rampur Raza Library, Rampur; Delhi Public Library, New Delhi; Khudabaksh Oriental Public Library, Patna; Raja Rammohan Roy Library Foundation, Kolkata; India Office Library, London.
3. National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, Lucknow.
4. National Mission for Preservation of Manuscripts.
5. Archaeological Survey of India, New Delhi; Archaeological Site Museums; Excavation and exploration of historical and archaeological remains.
6. Grants of Universities and Research Institutions for excavation and exploration of historical and archaeological remains.
7. International Conventions for the protection of cultural property in the event of armed conflict.

8. History of Freedom Movement.
9. Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi; Nehru Memorial Museum & Library, New Delhi; Jallianwala Bagh National Memorial Trust; Maulana Abul Kalam Azad Institute for Asian Studies, Kolkata; Indian War Memorial.
10. Promotion of Fine Arts and Performing Arts.
11. Sahitya Akademi; Lalit Kala Akademi; Sangeet Natak Akademi.
12. National Museum, New Delhi; Indian Museum, Kolkata, Salar Jung Museum, Hyderabad; Allahabad Museum, Allahabad; National Gallery of Modern Art, New Delhi, Mumbai and Bangalore; Victoria Memorial Hall, Kolkata; Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal; National Council of Science Museum, Kolkata; Museum of Gems and Jewellery; General Development of Museums.
13. National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology, New Delhi.
14. Acquisition of Indian and Foreign Art objects.
15. Open air theatres in rural areas and theatres in State capitals.
16. Financial assistance to authors and artists or their survivors in indigent circumstances, other than those belonging to the categories covered under the scheme of Ministry of Information and Broadcasting; Grants to cultural organizations and institutions; Scholarships and Fellowships including those offered by foreign governments and foreign agencies, in respect of subjects dealt with by this Department; Grants for setting up Multipurpose Cultural Complex.
17. Charities and Charitable institutions, Charities and Religious Endowments pertaining to subjects dealt within this Department.
18. Scholarships, including those offered by foreign Government and foreign agencies, in respect of subjects dealt with by this Department.
19. Publication of rare manuscripts.
20. Safeguarding of Traditional Culture and Folklore.

21. Grants to Indo-foreign Cultural Societies.
22. Cultural Agreements, Cultural Exchange Programmes (CEP) and Friendship Treaties with foreign countries.
23. Distribution of gift books received from abroad.
24. Appointment of Cultural Attaches abroad.
25. Visit of Cultural Delegations, etc. to India, sponsored and unsponsored.
26. Individuals (including cultural lecturers) sponsored by Government for visits abroad.
27. Presentation of books to foreign countries.
28. Establishment of libraries abroad.
29. Translation of Indian classics into foreign languages.
30. Exchange of official publications with foreign Governments and institutions and agreements for such exchanges.
31. Presentation of Indian art objects abroad.
32. Export of antiquities.
33. Admission of Foreign students in Cultural Institutions.
34. Exchange of artists, dancers, musicians, etc. under the Cultural Exchange Programmes.
35. Festivals of India abroad.
36. Revision of Gazetteers.
37. Observance of Centenaries and Anniversaries of important personalities and events.
38. Centre for Cultural Resources and Training, New Delhi.
39. International Congress of Orientalists.
40. Anthropological Survey of India, Kolkata.

41. National Archives of India, New Delhi; Gazetteers; Asiatic Society, Kolkata.
42. Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya.
43. Rabindra Rangshalla.
44. Zonal Cultural Centres.
45. National Council of Culture.
46. Indira Gandhi National Centre for Arts, New Delhi.
47. National School of Drama, New Delhi; National Theatre.
48. National Culture Fund.
49. Gandhi Peace Prize.
50. Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath; Central Institute of Buddhist Studies, Leh; Nav Nalanda Mahavidyalaya, Nalanda.
51. Kalakshetra Foundation, Chennai.
52. Implementation and enforcement of the following Acts, namely:-
 - (a) The Indian Treasure Trove Act, 1878 (6 of 1878);
 - (b) The Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (52 of 1972);
 - (c) The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);
 - (d) The Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (7 of 1904);
 - (e) The Delivery of Books and Newspapers (Public Libraries) Act, 1954 (27 of 1954);
 - (f) Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867) (in so far as supply of books and catalogues to Central Government is concerned);
 - (g) The Public Record Act, 1993 (69 of 1993).

**MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
(JANJATIYA KARYA MANTRALAYA)**

1. Social security and social insurance with respect to the Scheduled Tribes.
2. Tribal Welfare : Tribal welfare planning, project formulation, research, evaluation, statistics and training.
3. Promotion and development of voluntary efforts on tribal welfare.
4. Scheduled Tribes, including scholarship to students belonging to such tribes.
5. Development of Scheduled Tribes.

NOTE:-The Ministry of Tribal Affairs shall be the nodal Ministry for overall policy, planning and coordination of programmes of development for the Scheduled Tribes. In regard to sectoral programmes and schemes of development of these communities policy, planning, monitoring, evaluation etc. as also their coordination will be the responsibility of the concerned Central Ministries/ Departments, State Governments and Union Territory Administrations. Each Central Ministry/Department will be the nodal Ministry or Department concerning its sector.

6. (a) Scheduled Areas;
(b) matters relating to autonomous districts of Assam excluding roads and bridge works and ferries thereon; and
(c) regulations framed by the Governors of States for Scheduled Areas and for Tribal Areas specified in Part 'A' of the Table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule to the Constitution.
7. (a) Commission to report on the administration of Scheduled Areas and the welfare of the Scheduled Tribes; and
(b) issue of directions regarding the drawing up and execution of schemes essential for the welfare of the Scheduled Tribes in any State.
8. The National Commission for Scheduled Tribes.

9. Implementation of the Protection of Civil Rights Act, 1955 (22 of 1955) and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989), excluding administration of criminal justice in regard to offences in so far as they relate to Scheduled Tribes.

**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY
ALLEVIATION (SHAHARI VIKAS AUR GARIBI UPSHAMAN
MANTRALAYA)**

**A. DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT
(SHAHARI VIKAS VIBHAG)**

1. Properties of the Union, whether lands or buildings, with the following exceptions, namely:-
- (a) those belonging to the Ministry of Defence, the Ministry of Railways and the Department of Atomic Energy and the Department of Space;
 - (b) buildings or lands, the construction or acquisition of which has been financed otherwise than from the Civil Works Budget;
 - (c) buildings or lands, the control of which has at the time of construction or acquisition or subsequently been permanently made over to other Ministries and Departments.
2. All Government Civil Works and Buildings including those of Union territories excluding Roads and excluding works executed by or buildings belonging to the Ministry of Railways, Department of Posts, Department of Telecommunications, Department of Atomic Energy and the Department of Space.
3. Horticulture operations.
4. Central Public Works Organisation.
5. Administration of Government estates including Government Hostels under the control of the Ministry. Location or dispersal of offices in or from the metropolitan cities.
6. Allotment of accommodation in Vigyan Bhawan.
7. Administration of four Rehabilitation Markets viz. Sarojini Nagar Market, Shankar Market, Pleasure Garden Market and Kamla Market.

8. Issue of lease or conveyance deeds in respect of Government built properties in Delhi and New Delhi under the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954) and conversion of lease deeds, allotment of additional strips of land and correctional areas adjoining such properties.
9. Stationery and Printing for the Government of India including official publications.
10. Planning and coordination of urban transport systems with technical planning of rail based systems being subject to the items of work allocated to the Ministry of Railways, Railway Board.
11. Fixing of maximum and minimum rates and fares for rail-based urban transport systems other than those funded by the Indian Railways.
12. Tramways including elevated high speed trams within municipal limits or any other contiguous zone.
13. Town and Country Planning; matters relating to the Planning and Development of Metropolitan Areas, International Cooperation and technical assistance in this field.
14. Schemes of large scale acquisition, development and disposal of land in Delhi.
15. Delhi Development Authority.
16. Master Plan of Delhi, Coordination of work in respect of the Master Plan and Slum Clearance in the National Capital Territory of Delhi.
17. Erection of memorials in honour of freedom fighters.
18. Development of Government Colonies.
19. Local Government, that is to say, the constitution and powers of the Municipal Corporations (excluding the Municipal Corporation of Delhi), Municipalities (excluding the New Delhi Municipal Committee), other Local Self-Government Administrations excluding Panchayati Raj Institutions.
20. The Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking of the Municipal Corporation of Delhi.
21. Water supply (subject to overall national perspective of water planning and coordination assigned to the Ministry of Water Resources), sewage, drainage and sanitation relating to urban areas and linkages

from allocated water resources. International cooperation and technical assistance in this field.

22. The Central Council of Local Self-Government.
23. Allotment of Government land in Delhi.
24. Administration of Rajghat Samadhi Committee.
25. All matters relating to Planning and Development of the National Capital Region and administration of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985).
26. Matters relating to the Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH).
27. Matters of the Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) relating to urban infrastructure.
28. Administration of the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 (30 of 1952).
29. Administration of Delhi Hotels (Control of Accommodation Act, 1949 (24 of 1949).
30. The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971).
31. Administration of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957).
32. The Delhi Rent Control Act, 1958 (59 of 1958).
33. The Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (33 of 1976).
34. Delhi Urban Art Commission, the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1973).

**B. DEPARTMENT OF URBAN EMPLOYMENT AND POVERTY ALLEVIATION
(SHAHARI ROZGAR AUR GARIBI UPSHAMAN VIBHAG)**

1. Formulation of housing policy and programme (except rural housing which is assigned to the Department of Rural Development, review of the implementation of the Plan Schemes, collection and dissemination of data on housing, building materials and techniques, general measures for reduction of building costs and nodal responsibility for National Housing Policy.

2. Human Settlements including the United Nations Commission for Human Settlements and International Corporation and Technical Assistance in the field of Housing and Human Settlements.
3. Urban Development including Slum Clearance Schemes and the Jhuggi and Jhonpri Removal Schemes. International Cooperation and technical assistance in this field.
4. National Cooperative Housing Federation.
5. Implementation of the specific programmes of Urban Employment and Urban Poverty Alleviation including other programmes evolved from time to time.
6. All matters relating to the Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) other than those relating to urban infrastructure.

**MINISTRY OF WATER RESOURCES
(JAL SANSADHAN MANTRALAYA)**

I. GENERAL

1. Development, conservation and management of water as a national resource; overall national perspective of water planning and coordination in relation to diverse uses of water.
2. National Water Resources Council.
3. General Policy, technical assistance, research and development training and all matters relating to irrigation, including multi-purpose, major, medium, minor and emergency irrigation works; hydraulic structures for navigation and hydro-power; tube wells and groundwater exploration and exploitation; protection and preservation of ground water resources; conjunctive use of surface and ground water, irrigation for agricultural purposes, water management, command area development; management of reservoirs and reservoir sedimentation; flood (control) management, drainage, drought proofing, water logging and sea erosion problems; dam safety.
4. Regulation and development of inter-State rivers and river valleys. Implementation of Awards of Tribunals through Schemes, River Boards.
5. Water Laws, legislation.
6. Water quality assessment.

7. Cadre control and management of the Central Water Engineering Services (Group A).

II. INTERNATIONAL ASPECTS

8. International organisations, commissions and conferences relating to water resources development and management, drainage and flood control.
9. International Water Law.
10. Matters relating to rivers common to India and neighbouring countries; the Joint Rivers Commission with Bangladesh, the Indus Waters Treaty 1960; the Permanent Indus Commission.
11. Bilateral and external assistance and cooperation programmes in the field of water resources development.

III. ORGANISATIONS AND BODIES UNDER THE MINSITRY

12. Central Water Commission.
13. Central Soil and Materials Research Station.
14. Central Groundwater Board.
15. Central Ground Water Authority.
16. Central Water & Power Research Station.
17. Farakka Barrage Project.
18. Ganga Flood Control Commission.
19. Farakka Barrage Project Control Board.
20. Sardar Sarovar Construction Advisory Committee.
21. Brahmaputra Board.
22. Narmada Control Authority.
23. Betwa River Board.
24. National Institute of Hydrology.
25. National Water Development Agency.

26. Bansagar Control Board.
27. Tungabhadra Board.
28. Upper Yamuna River Board.
29. Water and Power Consultancy Services (India) Ltd. (WAPCOS).
30. National Projects Construction Corporation Limited.

IV. ADMINISTRATION OF ACTS

31. The Northern Indian Canal & Drainage Act, 1873 (8 of 1873).
32. The Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956).
33. The River Boards Act, 1956 (49 of 1956).
34. The Betwa River Board Act, 1976 (63 of 1976).
35. The Brahmaputra Board Act, 1980 (46 of 1980).

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (YUVAK KARYAKRAM AUR KHEL MANTRALAYA)

1. Sports Policy.
2. Sports and Games.
3. National Welfare Fund for Sportsmen.
4. Netaji Subhas National Institute of Sports.
5. Sports Authority of India.
6. Matters relating to the Indian Olympic Association and national sports federations.
7. Participation of Indian sports teams in tournaments abroad and participation of foreign sports teams in international tournaments in India.
8. National Sports Awards, including Arjuna Awards.
9. Sports Scholarships.
10. Exchange of Sports persons, Youth delegation, experts and teams with foreign countries.

11. Sports infrastructure, including financial assistance for creation and development of such infrastructure.
12. Financial assistance for coaching, tournaments, equipment, etc.
13. Sports matters relating to Union Territories.
14. Youth Affairs/Youth Policy.
15. Nehru Yuva Kendra Sangathan.
16. National Reconstruction Corps Scheme.
17. Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development.
18. Scheme for assistance to Rural Youth and Sports Clubs.
19. National Commission for Youth.
20. National Service Scheme.
21. Voluntary Youth Organisations, including financial assistance to them.
22. National Service Volunteer Scheme.
23. Commonwealth Youth Programme and United Nations Volunteers.
24. Youth welfare activities, youth festivals, work camp, etc.
25. Boy-scouts and girl-guides.
26. Youth Hostels.
27. National Youth Awards.
28. Residual work of the erstwhile National Discipline Scheme.
29. Physical Education.

**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
(PARMANU OORJA VIBHAG)**

1. All matters relating to -
 - (a) Atomic Energy Commission (AEC);

(b) Atomic Energy Regulatory Board (AERB).

2. All matters relating to Atomic Energy in India, e.g. -

- (a) administration of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962), including control of radioactive substances and regulation of their possession, use, disposal and transport;
- (b) research, including fundamental research in matters connected with atomic energy and the development of its uses in agriculture, biology, industry and medicine;
- (c) atomic minerals-Survey, prospecting, drilling, development, mining, acquisition and control;
- (d) all activities connected with the development and use of atomic energy, including -
 - (i) projects and industries concerned with substances and minerals prescribed under the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962); their products and by-products;
 - (ii) generation of electricity through the use of atomic energy;
 - (iii) design, construction and operation of research and power reactors; and
 - (iv) establishment and operation of facilities and plants, including diversification -
 - (A) for the production of materials and equipment required for research in and the use of atomic energy and for research in the nuclear sciences; and
 - (B) for the separation of isotopes, including plants adaptable to the separation of isotopes as by-product and the production of heavy water as a main or subsidiary product.
- (e) supervision of State undertakings concerned with prescribed or radio-active substances, including -
 - (i) Indian Rare Earths Limited(IREL);
 - (ii) Electronics Corporation of India Limited (ECIL);

- (iii) Uranium Corporation of India Limited (UCIL);
- (iv) Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL);
- (v) National Fertilizers Limited, in so far as production of heavy water is concerned.

3. Financial assistance for furtherance of studies in nuclear sciences and for building up adequately trained manpower for the development of the atomic energy programmes, including -

- (a) assistance to institutions and associations engaged in scientific work and to Universities for advanced study and research in nuclear sciences;
- (b) grant of scholarships in scientific subjects to students in Universities and other educational institutions and other forms of financial aid to individuals including those going abroad for studies in nuclear sciences; and
- (c) assistance to hospitals and research centres for furtherance of nuclear medicine and research in radiation oncology.

4. International relations in matters connected with atomic energy and nuclear science including -

- (a) matters relating to atomic energy and nuclear sciences in the United Nations Specialised Agencies, the International Atomic Energy Agency, other International Scientific Organisations including the European Organisation for Nuclear Research and relations with other countries; and
- (b) correspondence with institutions, Universities, etc. abroad in connection with foreign fellowships and the training of Indian Scientists.

5. All matters relating to personnel under the control of the Department of Atomic Energy.

6. Execution of works and purchase of land debitable to the capital budget of the Department of Atomic Energy.

7. Procurement of stores and equipment required by the Department of Atomic Energy.

8. Financial sanctions relating to the Department of Atomic Energy.

9. All matters concerned with the advancement of higher mathematics, including-

- (a) matters relating to the promotion and coordination of advanced study and research;
- (b) international relations in higher mathematics, the Indian National Committee for Mathematics and the International Mathematical Union;
- (c) grants to Universities, institutions and associations engaged in the advancement of higher mathematics; and
- (d) grant of scholarships and other forms of financial aid for advanced study and research.

10. All matters relating to the aided institutions under the administrative control of the Department of Atomic energy, namely:-

- (a) The Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai;
- (b) The Tata Memorial Centre, Mumbai;
- (c) The Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata;
- (d) The Atomic Energy Education Society, Mumbai;
- (e) The Institute of Mathematical Sciences, Chennai;
- (f) The Institute of Physics, Bhubaneswar;
- (g) Harish Chandra Research Institute (HRI), Allahabad;
- (h) The Institute for Plasma Research, Gandhinagar.

11. All matters relating to other grant-in-aid institutions concerning activities funded by the Department of Atomic Energy.

**DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT
(MAHASAGAR VIKAS VIBHAG)**

- 1. Matters relating to the Ocean and not specifically allocated to any other Department/Ministry.
- 2. Policy, coordination, and schemes relating to the Oceans and Polar regions covering interalia:

- (a) (i) research (including fundamental research) and the development of uses relatable thereto;
 - (ii) technology development;
 - (iii) surveys to map, locate and assess living and non-living marine resources;
 - (iv) preservation, conservation and protection of marine resources;
 - (v) development of appropriate skills and manpower;
 - (vi) international collaboration and cooperation;
 - (b) laws and regulatory measures relating to the above.
3. Marine environment on the high seas.
 4. Ocean Commission.
 5. The Pan Indian Ocean Science Association.
 6. Ocean Science and Technology Agency or Board.
 7. National Institute of Ocean Technology (NIOT).
 8. National Centre for Antarctic and Ocean Research (NCAOR).
 9. Indian National Centre for Ocean Information Services (INCOIS).

**DEPARTMENT OF SPACE
(ANTARIKSH VIBHAG)**

1. Space Commission and all matters relating thereto.
2. All matters relating to Space Science, Space Technology and Space Applications, including -
 - (a) research (including fundamental research) in matters connected with space and the development of its uses;
 - (b) all matters connected with Space Technology;

- (c) all matters connected with Space Applications; and
 - (d) all activities connected with the development and use of outer Space, including -
 - (i) projects and industries connected with the utilisation of outer Space including commercial exploitation of Space;
 - (ii) Establishment, procurement and use of Space based systems;
 - (iii) the design, manufacture and launching of Rockets and Satellites; and
 - (iv) work connected with Space Applications.
3. Financial Assistance for furtherance of research and study in Space Science, Space Technology and Space Applications and for building up adequate trained manpower for the development of the Space programme including -
- (a) assistance to institutions and associations engaged in scientific work and to Universities for advanced study and research in Space Science, Space Technology and Space Applications;
 - (b) grant of Scholarships to students in educational institutions, and other forms of financial aid to individuals including those going abroad for studies in the field of Space Science, Space Technology and Space Applications.
4. International relations in matters connected with Space, including -
- (a) matters relating to Space in the United Nations specialised agencies and in relations with other countries; and
 - (b) correspondence with Universities and other educational institutions abroad in connection with foreign scholarships and the training of Indian scientists.
5. All matters relating to the personnel under the control of the Department.

6. Execution of works and purchase of lands debitable to the budget of the Department of Space.
7. Procurement of stores and equipment required by the Department of Space.
8. Financial sanctions relating to the Department of Space.
9. All matters relating to the Physical Research Laboratory, Ahmedabad.
10. All matters relating to National Remote Sensing Agency (NRSA).
11. All matters relating to the National Natural Resources Management System including the generation of integrated data mainly based on remote sensing and assistance in the analysis and dissemination of such information.
12. All matters relating to the National Mesosphere, Stratosphere and Troposphere Radar Facility (NMRF).
13. Antrix Corporation Limited.
14. North Eastern Space Applications Centre.

**CABINET SECRETARIAT
(MANTRIMANDAL SACHIVALAYA)**

1. Secretarial assistance to the Cabinet and Cabinet Committees.
2. Rules of Business.
3. The Prevention of Corruption Act, 1947 (2 of 1947); the Central Bureau of Investigation (the Delhi Special Police Establishment including the Legal Division, the Technical Division, the Policy Division, and the Administration Division); the Food Offences Wing; and Economic Offences Wing.

**PRESIDENT'S SECRETARIAT
(RASHTRAPATI SACHIVALAYA)**

1. To provide secretarial assistance to the President.

**PRIME MINISTER'S OFFICE
(PRADHAN MANTRI KARYALAYA)**

1. To provide secretarial assistance to the Prime Minister.

PLANNING COMMISSION (YOJANA AYO)

1. Assessment of the material, capital and human resources of the country, including technical personnel, and formulation of proposals for augmenting such of these resources as are found to be deficient.
2. Formulation of Plan for the most effective and balanced utilisation of the country's resources.
3. Definition of stages in which the Plan should be carried out on a determination of priorities and allocation of resources for completion of each stage.
4. Determination of the nature of the machinery necessary for the implementation of the Plan in all its aspects.
5. Identifying the factors which are tending to retard economic development and determine the conditions which, in view of current social, and political situation, should be established for the successful execution of the Plan.
6. Appraise from time to time the progress achieved in the execution of each stage of the Plan and recommend adjustment of policies and measures that such appraisal may show to be necessary.
7. Public Co-operation in National Development.
8. Specific programmes for area development notified from time to time.
9. Perspective planning.
10. Institute of Applied Manpower Research.
11. The overall coordination of the Pradhan Mantri Gramodaya Yojana.

Note: The overall coordination of the Pradhan Mantri Gramodaya Yojana (PMGY) will be the responsibility of the Planning Commission. However, overall management and monitoring of the individual sectoral programmes under PMGY will be the responsibility of the concerned nodal Ministry/Department.

DEPARTMENT OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (UTTAR POORVI KSHETRA VIKAS VIBHAG)

1. Matters relating to the planning, execution and monitoring of developmental schemes and projects of North Eastern Region including those in the sectors of Power, Irrigation, Roads and Communications.

2. Hill Area Development Programme and Border Areas Development Programme in North Eastern Region.
3. Non-lapsable Fund for the North Eastern Region.
4. North Eastern Council.
5. North East Development Finance Institution (NEDFI).
6. North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited (NERAMAC).
7. The Sikkim Mining Corporation Limited.
8. North Eastern Handloom and Handicrafts Development Corporation (NEHHDC), Shillong.
9. Road works financed in whole or in part by the Central Government in the North Eastern Region. 131/-
10. Planning of Road and Inland Waterways Transport in the North Eastern Region."

A.P.J. ABDUL KALAM
President.

[F. No. 1/22/1/2003-CAB.]
B.B. JAIN, Under Secy.